अमेरिकन जन-शिक्षा का स्वरूप

(तुलनात्मक विवेचन)

लेखक

प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

एम.ए. दर्शन; एम.ए. मनोविज्ञान (कलकत्ता विश्वविद्यालय)

एल.टी., रिसर्च स्कॉलर (मनोविज्ञान)

मनोविज्ञान-प्राध्यापक, आगरा कालेज, आगरा

पूर्व प्राध्यापक, बलवन्त राजपूत कॉलिज ऑव एजूकेशन तथा
बलवन्त राजपूत कॉलेज, आगरा

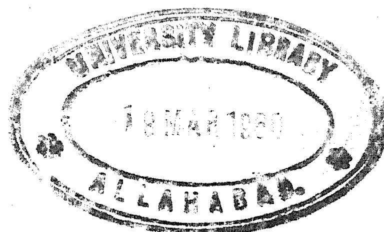
तथा

प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

एम.ए. अंग्रेजी, एम.एड. (इलाहाबाद विश्वविद्यालय)

एम.ए. एजकेशन-स्कॉलर (लन्दन विश्व-विद्यालय)

पूर्व प्राध्यापक, बलवन्त राजपूत कॉलिज ऑव एजूकेशन, आगरा



गया प्रसाद एण्ड संस

पुस्तक प्रकाशक, आगरा

मुख्य वितरक
लायल बुक डिपो
ग्वालियर

प्रथम वार : १९५९
मूल्य : ५.००

जोडियक प्रेस, तिलक मार्ग, दिल्ली से मुद्रित
एवं
गया प्रसाद एण्ड संस, बांके विलास, आगरा से प्रकाशित

शिक्षा के अनन्य साधक तथा मर्मज्ञ

श्रद्धेय गुरुवर, डा० एॅस० बी० अदावल

अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापक, शिक्षा-विभाग

प्रयाग विश्वविद्यालय

के

कर-कमलों में

तुच्छ गुरु-दक्षिणा के रूप में

सादर समर्पित ।

दो शब्द

द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है, और शिक्षा के क्षेत्र में, अभी बहुत ठोस कार्य करने हैं। नवोदित राष्ट्र के इस बड़े उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाने के लिए शिक्षक-वर्ग को, नई चेतना, उत्साह तथा कार्य करने की लगन और अधिक चाहिए। करोड़ों बालक-बालिकाओं को उचित विधि से सुसंस्कृत, प्रगतिशील नागरिक बनाना कोई सरल कार्य नहीं है।

इस बड़े कार्य में, जहाँ दूसरे देशों, देशीय सरकार तथा पितरों के सहयोग की अपेक्षा है, वहाँ यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि हम शिक्षक भी, अपने बदलते समाज को बदलती आवश्यकताओं को ठीक पहिचानें और बालक के व्यक्तित्व के वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे, शिक्षा-क्षे में, नए शिक्षा-प्रयोगों को आगे रखें। शिक्षा का वैज्ञानिक होना परमावश्यक है क्योंकि शिक्षा तथा शिक्षा-संस्थाएं, देश-निर्माण में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग देती हैं।

शिक्षा में नए प्रयोगों के लिए उत्साही शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है। अत्यन्त प्रगतिशील देशों के शिक्षा-संगठनों तथा प्रणालियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना और देश की आवश्यकताओं में उनके उचित-योग को समझा जाना, प्रोत्साहन-वृद्धि का महत्त्वपूर्ण साधन है। हमारा पुस्तक लिखने का प्राथमिक उद्देश्य, इसी प्रेरणा से अनुप्राणित है।

प्राचीन संस्कृति के पालने में न झूलकर बड़ी होने वाली, केवल वर्तमान तथा अपनी क्रियात्मक शक्ति पर भरोसा करने वाली, महान अमेरिकन जनता सदैव ही अति प्रगतिशील रही है और विज्ञान से पुष्ट होने के कारण, उसका शिक्षा-विधान तथा प्रणाली, राष्ट्र की अमूल्य निधि है। अमेरिका में किए गए शिक्षा के वैज्ञानिक प्रयोगों तथा उनके परिणामों ने, विश्व-शिक्षा के विकास तथा निर्माण में, महत्त्वपूर्ण योग दिया है।

हिन्दी भाषा के माध्यम से इस ज्ञान-राशि का परिचय कराना, देश की बड़ी आवश्यकता है। स्वाधीन देश के स्वाधीन भा ा तथा साहित्य में इतनी सामर्थ्य तथा शक्ति होनी चाहिए कि प्रत्येक नागरिक को वह विश्व की संस्कृति-निधि का परिचय दे सके। यह एक बड़ा कार्य है, परन्तु इसे करना परमावश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर, पुस्तक को हिन्दी-माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

शिक्षा के सभी कार के विद्यार्थियों—एम.एड, बी.टी., एल.टी.—को अंग्रेजी-माध्यम से पढ़ने के लिए तो अनेकों ही पुस्तकें, एक विषय पर सुलभ हो जाया करती हैं,

किन्तु हिन्दी-माध्यम से पुस्तकों का अभाव, निरन्तर खटकता ही रहता है। इस अभाव को कम करना भी, पुस्तक-रचना का एक गौण उद्देश्य रहा है।

पुस्तक लिखने में सरल हिन्दी के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए यथास्थान, कोष्ठकों में अंग्रेजी-शब्दों को भी दे दिया गया है। स बात का प्रयत्न किया गया है, कि जहाँ तक सम्भव हो, शिक्षा की समस्याएं तथा उनका महत्त्व, उभार कर रखा जाय और इसीलिए कहीं-कहीं, कई देशों का भी हवाला दिया गया है। यथास्थान भारतीय शिक्षा-क्षेत्रों तथा उनकी समस्याओं की ओर भी संकेत है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को लेकर हम कहाँ तक चल सके हैं, यह आप निश्चित करेंगे। उद्देश्य तक पहुंच चुकने की हम बात नहीं करते, हाँ चल अवश्य पड़े हैं। शिक्षा-अध्यापकों, विद्यार्थियों के अतिरिक्त जन-साधारण, यदि पुस्तक पढ़ने के पश्चात्, पूर्ण तुष्टि से दूर रह कर भी, अमेरिकन शिक्षा को, भारतीय जनता तक लाने में, थोड़ा-सा भी प्रोत्साहित और यत्नशील हुआ, तो पुस्तक का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पूरा हो जायगा। पुस्तक-रचना में,बलवन्त राजपूत कॉलिज ऑव एजूकेशन के पुस्तकालय तथा पुस्तकाध्यक्ष श्री चरणसिंह का विशेष सहयोग रहा है। पुस्तक-प्रकाशन में, व्यक्तिगत रूप से श्री ओम्प्रकाश शास्त्री ने बड़ी सहायता की है। अपने आत्मीय सहयोग के लिए ये सज्जन विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

अन्त में, अमेरिकन शिक्षा-शास्त्रियों तथा विभूतियों, श्रद्धेय गुरुवर डा० अदावल के––जिनके तप तथा त्याग ने, हमें, इस दिशा में विशेष रूप से आकृष्ट किया है, और प्रकाश-स्तम्भ के सदृश, जो सदैव हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहेंगे––हम विशेष आभारी हैं, और चिर कृतज्ञ रहने की बड़ी अभिलाषा भी रखते हैं।

सरस्वती-मन्दिर
कारवाँ, आगरा
वसन्त पंचमी, १९५९

—नरेन्द्र
—राजेन्द्र

विषय-सूची

प्रथम अध्याय

द्वितीय अध्याय

तृतीय अध्याय

चतुर्थ अध्याय

पंचम अध्याय

षष्ठ अध्याय

सप्तम अध्याय

प्रथम अध्याय

रूपरेखा :—

प्रथम चरण :—तुलनात्मक शिक्षा का महत्त्व और संक्षिप्त इतिहास ।

द्वितीय चरण :—अमेरिकन शिक्षा ही क्यों ?

तृतीय चरण :—अमेरिकन शिक्षा के मूल तत्त्व ।

चतुर्थ चरण :—अमेरिका : एक संक्षिप्त परिचय ।

प्रथम चरण

तुलनात्मक शिक्षा का महत्त्व और संक्षिप्त इतिहास

रूपरेखा :—

१. तुलनात्मक शिक्षा का स्वरूप और महत्त्व।

२. तुलनात्मक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं;

अ—प्रबन्ध।

आ—शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली और उसका विकास।

इ—राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्त और उनका प्रयोग।

३. तुलनात्मक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास।

४. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

डॉ० कैन्डेल (I. L. Candel) ने एक बहुत ही सुन्दर बात कही है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक अशान्ति के साथ ही शिक्षा-पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा-योजनाओं और विचार-विनिमयों का भी आरम्भ होता है। शिक्षा में इस प्रकार की अशान्ति और उसमें सुधार की विचारधारा इसलिए होती है कि शिक्षा का विशिष्ट रूप सदैव बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता; अतः समय-समय पर उसमें परिवर्तन होता ही रहता है।

समाज की नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाय ? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है और इस पर दिए गए उत्तर भी कई दृष्टिकोणों पर आधारित हैं।

किसी भी समाज की शिक्षा-प्रणाली को समझने तथा उसके वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए, व्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण हमें तुलनात्मक शिक्षा-शास्त्र से प्राप्त होता है।

उपर्युक्त कथन के महत्त्व को व्यक्त करते हुए तुलनात्मक शिक्षा की परिभाषा डॉ० कैन्डेल ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में इस प्रकार की है: "तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य, तुलनात्मक नियम, तुलनात्मक साहित्य, अथवा तुलनात्मक शरीरशास्त्र के समान ही, शिक्षा-प्रणालियों के अन्तरों को खोजना है, उन अन्तःस्थित सिद्धान्तों को खोजना है जो समस्त राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणालियों के पीछे होते हैं।"[1]

तुलनात्मक शिक्षा के महत्त्व को समझने का दूसरा ठोस ढंग यह है कि शिक्षा की महत्त्वपूर्ण समस्याओं को सामने रखा जाय और फिर देखा जाय कि उन समस्याओं के सुलझाने में तुलनात्मक शिक्षा ने क्या प्रयत्न किया है। संक्षिप्त रूप में हम विचार करेंगे।

डॉ० आई. ऐल. कैन्डेल ने तुलनात्मक शिक्षा की चौबीस प्रमुख समस्याएँ मानी हैं। ये समस्याएँ उनके दृष्टिकोण से, सभी देशों में समान हैं। किन्तु हम केवल कुछ प्रमुख समस्याओं और उनके निदानों पर ही विचार करेंगे। हमारे सामने निम्न समस्याएँ हैं:

१. प्रबन्ध (Administration) की समस्या।
२. शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली और उसका विकास।
३. राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्त और उनका प्रयोग।

---

1 Cited by Hans Nicholas: Comparative Education.

"The purpose of comparative education, as of comparative law, comparative literature or comparative anatomy is to discover the differences in educational systems, to discover the underlying principles which govern the development of all national systems of education" Chapter I.

१. प्रबन्ध :—

प्रबन्ध की समस्या अत्यन्त व्यापक है और कई छोटी समस्याएँ इसके अन्तर्गत आ जाती हैं; जैसे :

अ—कौन प्रमुख—शिशु या विद्यालय ?
आ—कौन प्रमुख—शिक्षु या शिक्षक ?

उपर्युक्त समस्याओं के उत्तर स्वच्छन्दवाद (Naturalism), उपयोगितावाद (Pragmatism) तथा आदर्शवाद (Idealism) ने भिन्न-भिन्न रूपों में दिए हैं।

इ—प्रबन्ध कैसा हो ?—केन्द्रीकृत या विकेन्द्रीकृत, यह प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। तुलनात्मक शिक्षा इसके कई उत्तर देती है, इनमें से कौन ठीक है, यह समाज या देश के चुनाव पर आश्रित है। कोई भी एक उत्तर सम्पूर्ण नहीं हो सकता, और सभी के लिए उपयोगी भी नहीं हो सकता। अमेरिका में शिक्षा-प्रबन्ध विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है, रूस में शिक्षा एकदम केन्द्रित है। कौन ठीक है और कौन ग़लत, यह कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों ही अपने-अपने प्रयोगों में सफल रहे हैं।

२. शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली और उसका विकास :—

सक्रिय विश्व के विकास में, भिन्नत्व, एक नियम है। देशों के पास अपनी-अपनी अलग शिक्षा-प्रणालियाँ होती हैं। इन प्रणालियों में उनके रहन-सहन, सभ्यता आदि के अन्तरों की स्पष्ट छाप होती है। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी शिक्षा-प्रणाली अपनी नहीं है; बल्कि लादी गई है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली उत्पन्न नहीं हुई, लादी गई है। डॉ० कैन्डेल ने शिक्षा-प्रणाली के इस प्रकार के स्थानान्तरण को सर्वथा अनुचित बताया है। क्योंकि इस कार्य के पीछे एक यह मनोवृत्ति प्रधान होती है कि हमारी शिक्षा-प्रणाली ही श्रेष्ठ है।

तुलनात्मक शिक्षा विश्व की प्रमुख शिक्षा-प्रणालियों का दिग्दर्शन कराके तथा प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन करके यह स्पष्ट कर देती है कि भिन्नत्व बुरा नहीं है। सब प्रकार की प्रणालियाँ विकसित होनी चाहिए; उनकी परीक्षा इस बात से होगी कि वे समाज की किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति, किस तरह करती हैं। इस तरह का दृष्टिकोण राष्ट्र-संघ के शिक्षा-विभाग (यूनेस्को) के कार्यों तथा योजनाओं में पूरी तरह से देखा जा सकता है।

३. राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के आधारभूत सिद्धान्त और उनका प्रयोग :—

तुलनात्मक शिक्षा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यही है; किन्तु इसके साथ ही, यह सब से कठिन भी है।

तुलनात्मक शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन शिक्षा के आदर्शों तथा सिद्धान्तों को प्रकाश में लाता है। इस प्रकार के सिद्धान्त तथा आदर्श शिक्षा के दर्शन पर आधारित हुआ करते हैं। भारत, चीन, इंगलैण्ड, अमेरिका, रूस, फ्रान्स आदि देशों ने विश्व की मानवता का नेतृत्व किया है और प्रत्येक ने कुछ न कुछ ऐसे विचार दिए जो बाद में सारी मानवता की अपनी सम्पत्ति बन गए। भारत तथा चीन ने अपने आदर्शों तथा सिद्धान्तों को दर्शन के माध्यम से फैलाया किन्तु डॉ० हैन्स के अनुसार पश्चिम के आदर्श तथा सिद्धान्त सामाजिक तथा राजनीतिक क्रान्तियों द्वारा समाज तक पहुँचाए गए। डॉ० हैन्स लिखते हैं :

"इंगलैण्ड तथा उसकी क्रान्ति ने, औरों से पहिले, 'स्वाधीनता' के नाम पर, परंपरा और परिवर्तन में सामंजस्य स्थापित किया। अमेरिका तथा फ्रान्स में भी, बाद की शती में, क्रान्तियाँ हुईं—'समानता के नाम पर, और सदा के लिए, बचे खुचे सामन्ती अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। एक और शती पश्चात्, रूस ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया और 'बन्धुत्व' के नाम पर सब क्रान्तियों से अधिक शक्तिशाली क्रान्ति हुई। उस आत्मिक भूकम्प की थरथराहट आज भी समस्त विश्व में मालूम हो रही है, और काली जातियों का जागरण उसी का सीधा परिणाम है।"

उपर्युक्त कथन से यह प्रत्यक्ष है कि स्वाधीनता, समानता तथा बन्धुत्व के सिद्धान्त मानवजाति के विकास के लिए कितने आवश्यक हैं। समाज के विकसित जीवन में इन तीनों सिद्धान्तों का आपस में क्या सम्बन्ध हो—किस को सबसे अधिक प्रधानता दी जाय, ये विचारणीय प्रश्न हैं। साथ ही भारत जैसे प्रजातन्त्रीय देशकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि समस्याओं के निदान में इन तीनों सिद्धान्तों का तुलनात्मक महत्त्व क्या हो सकता है, इसका विशेष उत्तर हमें तुलनात्मक शिक्षा से प्राप्त होता है।

उसी प्रकार, 'मानव' तत्त्व तथा प्रजातन्त्र के सिद्धान्त हमें तुलनात्मक शिक्षा से प्राप्त होते हैं। विश्व के सभी प्रमुख देश अपने आप को प्रजातन्त्रीय परम्परा के अनुयायी मानते हैं। सभी 'मानव का कल्याण' अपना उद्देश्य बनाकर चलते हैं। यदि भेद है तो आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में। एक बड़ी समस्या सभी देशों के सामने है और वह यह कि अपनी-अपनी संस्कृति का तथा आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का संतुलन तथा सामंजस्य, शिक्षा-प्रणाली में किस प्रकार लाया जाय? समाजवादी प्रजातन्त्र पर चलने वाला भारत किस शिक्षा-प्रणाली से अपनी सांस्कृतिक परम्परा को लेकर आगे बढ़ सकता है? इंगलैण्ड और फ्रान्स, ऐसे देश हैं जो अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़े हैं। रूस ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को एकदम बदलकर एक नई विचार-धारा को जन्म दिया है और शिक्षा-प्रणाली उसी का अनुसरण करती है। अमेरिका संस्कृति को लेकर ही नहीं चला। उसने उन्हीं वस्तुओं को उचित माना जो उपयोगी थीं। शिक्षा-प्रणाली उपयोगितावाद (Pragmatism) तथा प्रयोगात्मवाद (Experimentalism) पर

आगे बढ़ी। भारत अपने लिए कौन सा मार्ग अपनाए ? यह प्रश्न अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। वह औरों का अनुकरण करे या वस्तुओं को अपने दृष्टिकोण से देखे। अनुकरण तो किसी भी दशा में अभीष्ट नहीं हो सकता। अपना ही स्वस्थ दृष्टिकोण बनाने के लिए भी बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा की प्रणाली ऐसी हो जिसमें अनुशासन और बेरोजगारी बढ़ाने का स्वभाव यदि हो भी तो कम से कम हो। आज की प्रणाली परिवर्तन चाहती है और इस दिशा में हमें सबसे अधिक सहायता तुलनात्मक शिक्षा से प्राप्त हो सकती है।

संक्षिप्त इतिहास—

तुलनात्मक शिक्षा आजकल एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, इस बात को आरम्भ हुए बहुत दिन नहीं हुए। आज सभी का यह विश्वास हो चला है कि अन्य देशों के शिक्षा-प्रबन्धों तथा प्रणालियों का अध्ययन करने से अपने देश की शिक्षा-प्रणाली का उचित मूल्यांकन करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। यदि आज नहीं तो निकट-भविष्य में तुलनात्मक शिक्षा अपने और निखरे रूप में हमारे सामने आएगी, जब हम विश्व-शिक्षाप्रणाली के विषय में सोचना आरम्भ करेंगे। अभी तो यूनेस्को आदि के द्वारा, इस दिशा में हमने आरम्भ ही किया है। तुलनात्मक शिक्षा का यह महत्त्व जो भविष्य में हमारे बड़े काम की वस्तु होगा, और जो इस समय भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक प्रगति का परिणाम है; अतः विषय के महत्त्व को लोगों ने धीरे-धीरे किस प्रकार पहिचाना, यह आवश्यक है कि उसके विकास का इतिहास ध्यान से पढ़ा जाय।

तुलनात्मक शिक्षा के इतिहास में कालानुसार कौन-कौन लेखक आए, इसके लिए हम नीचे एक सारिणी दे रहे हैं :

१. मार्क अन्तोइन जुलियन द पेरिस (फ्रान्स) १८१७ ई०।
२. प्रो० जॉन ग्रिस्कॉम (न्यूयार्क) १८१८-१९ ई०।
३. प्रो० विक्टर कँज़िन (रूस) १८३१ ई०।
४. हौरेस मन (अमेरिका) १८४३ ई०।
५. मैथ्यू आल्डर्नों (इंगलैण्ड) १८५९-६५ ई०।
६. सर माईकेल सैडलर (इंगलैण्ड) १८९८-१९११ ई०।
७. हैनरी बर्नार्ड (अमेरिका) १८५६-८१ ई०।
८. संयुक्त राज्य शिक्षा-कार्यालय १८६८ ई०।
९. पी० मुनरो (अमेरिका) १९११-१३ ई०।
१०. कैन्डेल (अमेरिका) १९२५-४४ ई०।
११. सर्जियस हैसेन (रूस) १९२८ ई०।
१२. निकोलस हैन्स (इंगलैण्ड) १९२९ ई०।

१३. कैण्डेल (अमेरिका) १९३३ ई० ।

१४. निकोलस हैन्स (इंगलैण्ड) १९३६-३८ ई० ।

तुलनात्मक शिक्षा का **प्रथम काल** वह है जो वर्णनात्मक है । १८१७ से १८३१ ई० तक की पुस्तकों में देशी और विदेशी शिक्षा-प्रणालियों का वर्णनमात्र रहा। तुलना और आलोचना आदि का प्रवेश नहीं हुआ था । **दूसरा काल** १८३१ ई० से १९०० ई० तक है । इस काल में विदेशी शिक्षा-प्रणालियों का विशद वर्णन किया गया तथा उनका मूल्यांकन भी। हौरेस मन प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने शिक्षा-प्रणालियों का मल्यांकन आरम्भ किया । **तीसरा काल** १९०० ई० से आरम्भ होता है । इस काल में(१९०० ई०में) माइकेल सैडलर ने प्रथम बार पुष्ट तुलनात्मक शिक्षा का आरम्भ किया। सर्जियस हैसेन ने तो तुलनात्मक अध्ययन करके सिद्धान्तों की भी खोज की। निकोलस हैन्स ने इसी परम्परा का अनुसरण किया। आई० ऐल० कैन्डेल ने ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रीय स्वरूप को उभार कर रखा। आगे चलकर हैन्स ने ऐतिहासिक विधि को और अधिक बल दिया, तथा सिद्धान्त निकाले गए।

इस प्रकार जो तुलनात्मक शिक्षा केवल शिक्षा-प्रणालियों के वर्णनों से आरम्भ हुई, वह वैज्ञानिकता की ओर बढ़ी, उसमें ऐतिहासिक विधि को उचित स्थान मिला और शिक्षा के उन व्यापक सिद्धान्तों की, विश्लेषणात्मक आलोचना के आधार पर खोज की गई; जो सभी शिक्षा-प्रणालियों में बदलती हुई संख्या में पाए जाते हैं और जिनके कारण ही उन प्रणालियों का विकास निश्चित होता है ।

द्वितीय चरण

अमेरिकन शिक्षा ही क्यों ?

रूपरेखा :—

१. तुलनात्मक शिक्षा और अमेरिकन शिक्षा-प्रणाली।

२. भारतीय और अमेरिकन शिक्षा-प्रणालियाँ;

अ—प्रजातन्त्रात्मक।

आ—कृषि की प्रधानता।

इ—विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का समन्वय।

ई—राष्ट्र के लिखित विधान।

उ—शिक्षा-प्रबन्ध : राज्य का उत्तरदायित्व।

३. विकसित अमेरिकन शिक्षा के आधार;

अ—विज्ञान की उन्नति।

आ—उपयोगितावादी दर्शन।

४. भारत के लिए शिक्षा-विकास की कसौटी।

५. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

तुलनात्मक शिक्षा के महत्त्व को फिर से स्थापित करन की आवश्यकता नहीं। उसके आरम्भ के लिए किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन करना उस दिशा में प्रगति का प्रथम चरण हो सकता है और इस दृष्टि से अमेरिकन शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन हमारे लिए जरूरी है।

हम जानते हैं कि संयुक्तराज्य विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है। इस महान् देश की शिक्षा-प्रणाली उसकी अपनी है। संयुक्तराज्य की शिक्षा-प्रणाली में, वहाँ के समाज का,विश्व के प्रति जो सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है,उसके दर्शन होते हैं। संयुक्त-राज्य की प्रजातन्त्रीय चेतना, और उसी वातावरण में पली शिक्षा-प्रणाली हमारे शिक्षा-मर्मज्ञों को एक अवसर प्रदान करती है कि वह इसी प्रजातन्त्रीय प्रकाश में अपनी शिक्षा-प्रणाली को देखें और उसे उन्नत बनाने में एक निश्चित प्रयत्न करें। फ्रान्स की क्रान्ति के अनुरूप ही, अमेरिकन स्वाधीनता-क्रान्ति ने समानता का सिद्धान्त हमारे सामने रखा और शिक्षा में सभी को 'समान अवसर' मिले यह सभी 'शिक्षा-प्रणालियों' का आधार है।

इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय शिक्षा का आधुनिक युग, इंगलैण्ड की शिक्षा-प्रणाली को आधार मान कर चला है किन्तु शिक्षा में हमारे देश में जो आज प्रयोग हो रहे हैं,विशेष रूप से कृषि-क्षेत्र में, वे अमेरिकन परम्पराओं पर आधारित हैं। आज की शिक्षा-प्रगति में अमेरिका अधिक सहायक रहा है, इंगलैण्ड नहीं। किन्तु फिर भी आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में नई योजनाओं को शामिल करने तथा उनका उचित मूल्यांकन करने में अमेरिकन तथा अंग्रेजी शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारत के लिए अमेरिका, इंगलैंड से अधिक समीप है।

प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली पर आधारित अमेरिका एक महान् देश है। राष्ट्रीय साधनों और विज्ञान की सहायता से, पुरानी सभ्यता से बिना सहायता लिए हुए जो उन्नति इस देश ने की है वह आशातीत है। क्षेत्रफल में यह देश हमारे देश के समान ही अत्यन्त विस्तृत है और कृषिप्रधान भी। इस प्रदेश का विस्तृत भू-खण्ड ३०,२६,७८९ वर्गमीलों में फैला हुआ है और सारा प्रदेश ४८ राज्यों में विभक्त है। अपना भारतवर्ष भी उसी प्रकार १२,३८,८४९ वर्गमीलों में फैला हुआ है और इसमें १४ राज्य हैं।

भारतवर्ष और अमेरिका में दूसरी समानता यह भी है कि दोनों में बहुत सी संस्कृतियों और जातियों का सम्मिश्रण है। संयुक्तराज्य में कई जातियाँ जैसे स्पेनियार्ड, अंग्रेज, जर्मन, फ्रान्सीसी, डच, यहूदी आदि रहती हैं किन्तु सबकी अपनी-अपनी सभ्यता नहीं है वरन् वहाँ एक मिश्रित सभ्यता के दर्शन होते हैं। यह प्रजातन्त्रीय सभ्यता, समानता तथा सहनशीलता पर आधारित है। भारत में भी हिन्दू, बौद्ध, जैन, मुसलमान, ईसाई

तथा अन्य जातियाँ रहती हैं। परन्तु यहाँ सभ्यताओं का मिश्रण नहीं हुआ है, फिर भी एक ने दूसरे पर प्रभाव अवश्य डाला है।

इसके अतिरिक्त दोनों देशों के विधान एक से ही हैं। दोनों ही लिखित हैं और दोनों देशों में संघात्मक प्रजातन्त्र (Federal Republic) है। दोनों देशों में सर्वोच्च सत्ता प्रेसीडेन्ट या राष्ट्रपति में निहित है। इतना सब होते हुए भी भारत का विधान संयुक्तराज्य के विधान का अनुकरण नहीं है, यद्यपि उसमें सबसे अधिक छाप संयुक्त-राज्य के तथा आस्ट्रेलिया के विधानों की अवश्य है।

दोनों देशों में एक और बड़ी समानता है और वह है उनके शिक्षागत प्रबन्ध की। यह तो मानना ही पड़ेगा कि संयुक्तराज्य में शिक्षा की सीढ़ियाँ एक सी हैं और सुगठित हैं, फिर भी दोनों देशों में शिक्षा,राज्य का ही मुख्य दायित्व है। केन्द्रीय सरकारें अनुदानों द्वारा राज्यों की सहायता करती हैं।

वस्तुतः, शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों देशों में कौन-सी वस्तुएँ समान हैं और कौन-सी असमान; महत्त्वपूर्ण तो यह है कि दोनों देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन किया जाय, सिद्धान्तों की खोज की जाय, ताकि यथा-स्थान इनका उपयोग भी हो सके।

अपने देश की शिक्षा-प्रणाली के विकास के लिए हम संयुक्तराज्य से बहुत कुछ ले सकते हैं। संयुक्तराज्य का संक्षिप्त इतिहास और विशाल प्रगति इस बात की सूचना देते हैं कि वहाँ की शिक्षा-प्रणाली बहुत प्रगतिशील है। वहाँ की शिक्षा में प्रगति का कारण है,विज्ञान तथा दर्शन का सुन्दर समन्वय। जॉन ड्यूई के उपयोगितावाद (Pragmatism) और अतिविकसित वैज्ञानिक ज्ञान के समन्वय होने से शिक्षा ही क्या, समस्त राष्ट्र के जीवन में एक आशातीत उन्नति हुई है। विकेन्द्रीकरण और शिक्षा-योजनाओं की भिन्नता पर बल देना प्रजातन्त्र के प्राण हैं।

अमेरिकन जीवन की ये विशेषताएँ क्या भारतीय जीवन की भी विशेषताएँ बन सकती हैं ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है। यह भी कहा जा सकता है कि क्या भारतीय जीवन अपने ही ढंग से सम्पूर्ण नहीं बनाया जा सकता ? क्यों नहीं; किन्तु सावधानी से काम लेना पड़ेगा। जो लोग अमेरिकन जीवन की नकल करके अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, वे पूरी तरह गलत हैं और वैसे ही वे लोग भी, जो विज्ञान तथा विश्व की उन्नति से अपना मुँह मोड़ कर प्राचीनता के बल पर समृद्ध होना चाहते हैं। युग की आवश्यकताओं को ठीक-ठीक समझना, एक दूसरे के सहयोग से चलना आज के युग में नितांत आवश्यक है। इस आधार पर यह कहना असंगत न होगा कि भारत की शिक्षा-प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयोगवादी के रूप में, हम उन आदर्शों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्होंने संयुक्तराज्य की शिक्षा-प्रणाली को भली भाँति आगे बढ़ाया है।

तृतीय चरण

अमेरिकन शिक्षा के मूल तत्त्व

रूपरेखा :—

१. विषय-प्रवेश।

२. अमेरिकन शिक्षा के मूल तत्त्व;

अ—प्रजातन्त्रीय शिक्षा।

आ—शिक्षा का स्थानीय प्रबन्ध।

इ—सुधारवाद तथा मानवतावाद पर आधारित शिक्षा।

ई—महती भिन्नता।

उ—उद्योग तथा कृषि की ओर झुकाव।

ऊ—शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप।

३. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

अमेरिकन शिक्षा ही क्यों ? इस प्रश्न का दूसरा उत्तर उसकी शिक्षा-प्रणाली की विशेषताओं तथा उसके मूल तत्त्वों का उल्लेख भी हो सकता है। अमेरिकन शिक्षा का आकर्षण निम्न बातों में परिलक्षित होता है :

१. प्रजातन्त्रीय शिक्षा।
२. शिक्षा का स्थानीय प्रबन्ध ।
३. सुधारवाद तथा मानवतावाद पर आधारित शिक्षा।
४. महती भिन्नता।
५. शिक्षा का उद्योग तथा कृषि की ओर झुकाव।
६. शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप।

(१) प्रजातन्त्रीय शिक्षा :

डॉ० हैन्स के मतानुसार प्रजातन्त्र का अर्थ, अंग्रेजीभाषा-भाषी देशों, विशेषकर अमेरिका में, उस राजनीतिक प्रजातन्त्र से है जो सहनशीलता की अंग्रेजी परम्परा पर आधारित है और जहाँ जन-प्रतिनिधियों की वैधानिक सरकार होती है। इससे प्रत्यक्ष है कि प्रजातन्त्र 'समानता' के सिद्धान्त पर आधारित है ।

अमेरिकन जनता की यह धारणा है कि सम्पूर्ण देश शिक्षित होना चाहिए। इसका मूल कारण यह है कि वे परिवर्तन—नई रचना—सदैव पसन्द करते हैं और इस तरह के विकसित परिवर्तन तभी सफलता और आसानी के साथ लाए जा सकते हैं जब सम्पूर्ण राष्ट्र शिक्षित हो। इसीलिए वे 'सार्वभौम शिक्षा' के पक्ष में हैं। उनका विश्वास है कि प्रत्येक यक्ति को विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए और यह सर्वमान्य तथ्य है कि व्यक्ति के विकास में शिक्षा सबसे अधिक उपयोगी है। डॉ० कैन्डेल के मतानुसार अमेरिकन शिक्षा का विकास दो सिद्धान्तों की अन्तर्क्रिया का परिणाम है—इस बात को स्वीकार करना कि प्रजातन्त्रराज्य की स्थिरता तथा समृद्धि सार्वभौम शिक्षा पर आधारित है, तथा 'समान अवसर' का आदर्श।

(२) शिक्षा का स्थानीय प्रबन्ध :

यह एक सत्य है कि अमेरिकन सरकार की सामान्य प्रवृत्ति, बड़ी-बड़ी अन्वितियों में शक्ति केन्द्रित करने की है। यह भी एक सत्य है कि राज्य शिक्षा पर अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करते जा रहे हैं, परन्तु यह सब होते हुए भी प्रादेशिक अन्विति (Local unit) का, अमेरिकन विद्यालयों के नियन्त्रण में बहुत बड़ा हाथ है। डॉ० कैन्डेल का इस विषय में यह स्पष्ट मत है कि शिक्षा में राज्य द्वारा दखल देने की प्रवृत्ति होते हुए भी, जो इस मौलिक सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा द्वारा ही जनता में स्थिरता तथा उन्नति हो सकती है; अमेरिका में शिक्षा का नियन्त्रण प्रादेशिक (Local) है।

शिक्षा पर जन-नियन्त्रण को रसेल ने काफी ठीक ढंग से रखा है। जन-नियन्त्रण के उन्होंने प्रमुख तीन रूप बताए हैं :

अ—स्थानीय विद्यालय नगर। (Local School District)
आ—कस्बा-प्रणाली। (Town System)
इ—काउन्टी-प्रणाली। (County System)

अ. स्थानीय विद्यालय नगर :

सबसे अधिक पुराना; स्थानीय प्रशासन की सबसे कम कुशल योजना; उच्च अधिकारियों की ओर से बहुत थोड़ा निरीक्षण और नियन्त्रण। इलीनाइस (Illinois) तथा अरकन्सास (Arkansas) राज्यों में यह व्यवस्था प्रचलित है। समाज के धनी वर्ग के लिए उपयोगी और निर्धनवर्ग के लिए कठिन।

आ. कस्बा-प्रणाली :

न्यू-इंगलण्ड में 'टाउन-प्रणाली' और पश्चिमी अमेरिका में 'टाउनशिप-प्रणाली' दोनों ही 'नगर-प्रणाली' के विकसित रूप हैं। 'टाउन' क्षेत्र में शहर तथा ग्राम दोनों ही विभाग आ जाते है और इस देश का शासन-कार्य एक केन्द्रीय संस्था के हाथ में होता है। 'टाउन-प्रणाली' से मिलती जुलती ही 'टाउनशिप-प्रणाली' है।

इ. काउन्टी-प्रणाली :

संयुक्तराज्य में प्रादेशिक प्रशासन में सबसे कुशल अन्विति 'काउन्टी-प्रणाली' है। 'काउन्टी' का क्षेत्रफल बड़ा होता है : लगभग ५०० से १००० वर्गमील तक। शिक्षा के लिए 'काउन्टी बोर्ड' चुना जाता है।

(३) सुधारवाद तथा मानवतावाद पर आधारित शिक्षा :

किसी भी देश की सांस्कृतिक परम्पराएँ उसकी शिक्षा-प्रणाली तथा उसके पाठ्यक्रम में झलकती हैं। अमेरिका के बारे में भी यही बात है। वस्तुत: अमेरिका योरुप के इतिहास तथा संस्कृति से जड़ा हुआ है, अलग नहीं। डॉ० हैन्स ने इस तथ्य का बड़ा ही सुन्दर हवाला दिया है। उनके अनुसार अमेरिका की विशिष्ट बातें योरुप के अल्पसंख्यक आन्दोलनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, वे आन्दोलन जो घर में अस्वीकृत और तिरस्कृत रहे। सुधारवाद (Puritanism) तथा मानवतावाद (Humaenism) दो आधारभूत कारण हैं जिन्होंने अमेरिका की परम्पराओं को जन्म दिया और दोनों ही योरुप के व्यापक आन्दोलन रहे हैं, वहीं उत्पन्न हुए और वहीं पनपे। किसी भी देश की शिक्षा-व्यवस्था कैसी हो? इसको नियन्त्रित करने वाले प्रमुख कारणों में से एक मानववाद (Humaenism) भी है। शिक्षा में मानववाद के दो विशिष्ट रूप हैं :

(१) सूखे धार्मिक आदर्शों के लिए मानव के स्वभाव और रुचियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए।

(२) शिशु का स्वभाव और उसका विकासोन्मुख मस्तिष्क विद्यालय के क्रूर अनुशासन तथा शिक्षा की जड़-विधियों द्वारा दबाया न जाय।

मानववादी परम्परा में अन्तिम प्रतिनिधि डॉ० जॉन डयूई हैं जो विश्व के प्रमुख शिक्षा-विदों में से एक रहे हैं। "विचार से प्रधान कार्य को मानने में उनका दर्शन उपयोगितावादी है। मानवीय अनुभव-प्रवाह में ही सारे मूल्यों को निश्चित करने में वह मानववादी है। वैज्ञानिक प्रयोगात्मक विधियों की श्रेष्ठता-प्रतिपादन में ही वह प्रयोगात्मक है।"

(४) महती भिन्नता :

रसेल के मतानुसार अमेरिकन शिक्षा की सबसे विशिष्ट बात उसकी 'बड़ी भिन्नता' है। संघीय सरकार में सम्पूर्ण नियन्त्रणाधिकार केन्द्रित नहीं है। बहुत सी राज्य-सरकारों के हाथ में उनके विद्यालयों का पर्याप्त संचालन नहीं है। यहाँ तक कि छोटी-छोटी प्रशासकीय अन्वितियों में भी भिन्नता है। संयुक्तराज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं मिल सकता जो और राज्यों के लिए अनुकरण की वस्तु हो।

इस महती भिन्नता के तीन बड़े कारण हैं :

अ—जनसंख्या : अमेरिका की जनता उन लोगों से बनी है जो इंगलैण्ड, स्काटलैण्ड, आयरलैण्ड, जर्मनी, स्कैन्डीनेविया, आस्ट्रिया, इटली, हंगरी रूस, फ्रान्स आदि योरुपीय देशों से आए हैं। अमेरिका की भूमि पर जो पहिले उतरे उन्होंने अपनी परम्पराएँ, अपने विद्यालय स्थापित किए। जो बाद में आते रहे, उन्होंने भी कुछ नई वस्तुएँ दीं, किन्तु वे भी बदलीं। अमेरिका में प्रधान भाषा अंग्रेजी का होना, मुख्य धर्म प्रोटेस्टेन्ट होना, सरकार और राज्य के नियमों का अंग्रेजी परम्पराओं पर आधारित होना इस बात का प्रमाण है कि जो इस भूमि पर पहले उतरे, शक्ति-संतुलन उन्हीं के हाथ रहा।

आ—सरकार में, केन्द्रीकरण की ओर परिवर्तन : जो साहसी लोग, अटलान्टिक महासागर को पार करके उत्तरी अमेरिका में जा बसे, वे आपस में भिन्न थे। विभिन्न देशों से, एक देश की भिन्न जातियों और वर्गों से आए हुए इन लोगों ने, धर्म और राजनीतिक स्वाधीनता के लिए अपनी-अपनी सामाजिक परम्पराओं और अपने-अपने विद्यालयों की स्थापना की और इन्हीं परम्पराओं के प्रति वफादार रहे। मैसाचूसेटस (Massachusetts) राज्य में, जहाँ पर लोग छोटे-छोटे समुदायों में बसे; वहाँ 'टाउन' को ही अधिकांश कार्य सौंपे गए। उसी प्रकार वर्जीनिया (Virginia)

राज्य में 'काउन्टी' प्रधान बनी। जहाँ-जहाँ ये बस्तियाँ एक होकर अंग्रेजी सरकार का नियन्त्रण और आर्थिक नियन्त्रण को हटाने के लिए प्रयत्नशील रहीं, वहीं पर केन्द्रीय संगठन सबसे अधिक अशक्त रहा। लेकिन पिछली शती में एक बदली हुई मनोवृत्ति के दर्शन हुए। स्थानीय अन्विति (Local unit) को प्रधानता न दे कर राज्य को प्रधानता दी गई और राज्यों की अपेक्षा राष्ट्र को प्रधानता दी गई। एक प्रकार से केन्द्रीकरण की ओर मनोवृत्ति बढ़ी है।

इ—राज्य की परिभाषा में परिवर्तन : पहिले कुशल राज्य-सरकार की कसौटी थी आलसी, अचेतन तथा अपढ़ जनता पर चुस्त, पढ़े-लिखे, उदार शासकों द्वारा शासन। परन्तु आज यह सब नहीं रहा। आज मतदान एक व्यापक वस्तु है। बहुत से राज्यों के सरकारी मामलों में, स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार प्राप्त है। बहुत से राज्यों में स्त्रियाँ विद्यालयों के प्रशासन में सहयोग देती हैं।

इन सब भिन्नताओं के होते हुए भी, यह एक तथ्य है कि देश में एकीभूत जनता के प्रजातन्त्रीय जीवन के लिए धीरे-धीरे केन्द्रित शिक्षा-प्रणाली का जन्म हो रहा है।

(५) शिक्षा का उद्योग तथा कृषि की ओर झुकाव

औद्योगिक शिक्षा के प्रसार तथा विकास के लिए संयुक्तराज्य सरकार सदैव ही सचेष्ट रही है। इस विषय में भूमि तथा धन-अनुदानों से उसने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। इन अनुदानों का एक निश्चित उद्देश्य था—कम से कम हर राज्य में एक ऐसा विद्यालय स्थापित करना, जहाँ—

अ—वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक अध्ययनों को न छोड़ते हुए;

आ—सैनिक शिक्षा के साथ-साथ;

इ—ज्ञान की उन शाखाओं को पढ़ाना जो कृषि और यन्त्र-विद्या से सम्बन्धित हैं।

संयुक्तराज्य में ऐसे भूमि-अनुदान महाविद्यालयों की संख्या ६९ है और कृषि, गृह, अर्थशास्त्र, इन्जीनियरिंग आदि क्षेत्रों के विकास में इन महाविद्यालयों ने बहुत ही सहयोग दिया है।

(६) शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप

किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों के कल्याण की प्राप्ति के प्रयत्न, विश्व-कल्याण की प्राप्ति के प्रयत्नों से अलग नहीं होते। और फिर आज के आणविक युग में कोई भी देश केवल अपने लिए नहीं जी सकता। संयुक्तराज्य भी राष्ट्र-संघ का सदस्य है। अमेरिकन शिक्षकवर्ग तो विश्व-शिक्षा में बड़ी ही रुचि रखता है। वे लोग तो शिक्षकों के विश्व-व्यापी संगठन के निर्माण के पक्ष में हैं। बहुत से शिक्षा-विशेषज्ञों ने तो दूसरे देशों के उत्थान तथा यूनेस्को-योजनाओं को सफल बनाने में अपनी सेवाएँ अर्पित की हुई हैं।

चतुर्थ चरण

अमेरिका——एक संक्षिप्त परिचय

रूपरेखा :—

१. अमेरिका——जो कल था——इतिहास।

२. अमेरिका——जो आज है।

अ——भूमि और निवासी।

आ——भौगोलिक तथा आर्थिक घटक।

इ——शिक्षागत वित्त।

ई——सामाजिक समस्याएँ।

३. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

अमेरिका : एक संक्षिप्त परिचय

किसी भी देश की शिक्षा-प्रणाली का अध्ययन तब तक ठोस नहीं कहा जा सकता जब तक कि हम उसके इतिहास और भूगोल, संस्कृति, विज्ञान आदि की दृष्टि से उससे परिचित नहीं हों। अत: अमेरिकन शिक्षा-प्रणाली को आरम्भ करने से पहिले उसका एक संक्षिप्त परिचय अति आवश्यक है। निम्न बातों को लेकर हम अमेरिका का परिचय देने का प्रयत्न करेंगे :

अ—अमेरिका जो कल था—इतिहास।

आ—अमेरिका जो आज है—

१. भूमि और निवासी।
२. भौगोलिक तथा आर्थिक घटक।
३. शिक्षागत वित्त।
४. सामाजिक समस्याएँ।

(अ) अमेरिका जो कल था—इतिहास

मुख्य बातें :—

१.	खोज और प्रथम व्यवस्थापन।	१४९२-१६२०
२.	उपनिवेश-काल।	१६२०-१७७५
३.	क्रान्तिकारी युद्ध।	१७७६-१७८३
४.	शिशु जनतन्त्र।	१७८३-१८२५
५.	पश्चिम की ओर प्रसार।	१८२५-१८६१
६.	नागरिक युद्ध।	१८६१-१८६५
७.	पुर्ननिमाण और आर्थिक विकास।	१८६५-१९१४
८.	विकास में प्रौढ़ता।	१९१४-१९४१
९.	विश्वयुद्ध और उसके बाद	१९४१-१९५८

अमेरिका का पता १४९२ ई० में इटैलियन नाविक क्रिस्टोफर कोलम्बस ने लगाया। अमेरिका तक पहुँचने को सबसे अधिक रुचि इंगलैण्ड की रही और प्रयत्न भी सबसे पहिले आरम्भ हुए। महारानी एलिजाबेथ के समय से ही अंग्रेजों ने बसना आरम्भ कर दिया और वे ही प्रथम निवासी हैं। १५८५ में सर वॉल्टर रैले ने अमेरिका को उपनिवेश बनाने का प्रथम प्रयत्न किया। किन्तु यह प्रयत्न असफल रहा। और सफल प्रयत्न १६०७ में हुआ। १६००-१७७० के बीच में इंगलैण्ड से ७,५०,००० लोग अमेरिका पहुँचे। १७३३ ई० तक तो अंग्रेजों के उपनिवेश में १३ राज्य थे।

इंगलैण्ड के सम्राट् जार्ज तृतीय की अनुचित नीति से, गलत कर-नीति से, फ्रांस

के कमजोर होने तथा कनाडा से हटने से १७७६ में इंगलैण्ड के खिलाफ स्वाधीनता-संग्राम आरम्भ हो गया। यह युद्ध सात वर्ष तक चलता रहा। कई हारों के बाद इंगलैण्ड-सरकार 'युद्धरोको' वार्ता के लिए तैयार हो गई और ३ सितम्बर १७८३ ईसवी में पेरिस में सन्धि हो गई। अमेरिका स्वाधीन माना गया। देश की सीमाएँ विस्तृत हो गई। सितम्बर १७८७ ई० में विश्व का सबसे पुराना लिखित अमेरिका का विधान बना और जार्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। उसके बाद देश ने बड़ी शीघ्रता से उन्नति की।

१८०० के आस पास एक और बड़ी समस्या देश के सामने आई। यह थी दासों की। दासता के विषय में उत्तर और दक्षिण में मतभेद था। दक्षिण वाले दासता के पक्ष में थे। यह मतभेद १८६० में अपनी चरम सीमा को जा पहुँचा जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए। उन्होंने दासता के खिलाफ़ आवाज़ उठाई। उत्तर वालों ने साथ दिया। अप्रैल १८६१ ई० के लगभग नागरिक युद्ध आरम्भ हो गया। संघ में उस समय २३ राज्य थे जब कि दक्षिणी गुट्ट में केवल ११ राज्य थे। इंगलैण्ड तथा फ्रान्स दक्षिणी गुट्ट के पक्ष में रहे। ९ अप्रैल, १८६५ ई० को एक समझौता हो गया और युद्ध रुक गया। किन्तु जिस मसले को लेकर युद्ध हुआ था, वह बिल्कुल हल नहीं हुआ।

२३ राज्य वाले संघ में बाद में २५ राज्य और सम्मिलित हुए। अन्तिम शामिल होने वाले राज्य थे अरीजोना तथा न्यूमक्सिको, जो १९१२ में संघ के सदस्य बने। संयुक्तराज्य का जन्म तभी से हुआ। इसके साथ ही १८६७ ई० में रूस से अलास्का प्रदेश खरीद लिया गया। १८९८ ई० में स्पेन से युद्ध में विजयी होने से प्यूरिटो रिको, ग्वाम तथा फिलिपाइन द्वीपसमूह मिल गए। १८९७ में हवाई द्वीप समूह ले लिये गए।

१९१४ तथा १९३९ ई० के विश्व-महायुद्धों में अमेरिका ने दबाव के कारण भाग लिया क्योंकि देश की नीति एकान्त की थी, किन्तु अपनी गलती उसने बाद में समझी।

आधुनिक इतिहास से सम्बन्ध रखने वाली तीन प्रमुख समस्याएँ अमेरिका के पास रही हैं—

१. विश्व का उत्तरदायित्व।
२. अमेरिकन अर्थ-व्यवस्था।
३. नागरिक अधिकार।

उपर्युक्त समस्याओं में तीसरी समस्या तो ऐसी है जो आज भी समस्या है। प्रत्येक नागरिक को बराबरी के अधिकार अबतक नहीं प्राप्त हुए, यह बात विशेष कर वहाँ साफ है जहाँ राज्य में गोरों से संख्या में नीग्रो अधिक हैं। दक्षिण के अधिकांश राज्यों में शिक्षा, मकान और आने-जाने में नीग्रो लोगों से भारी भेद-भाव बढ़ता जाता है।

आ—अमेरिका जो आज है

१—भूमि और निवासी

संयुक्तराज्य उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग है जिसके उत्तर में कनाडा तथा

दक्षिण में मैक्सिको प्रदेश और मैक्सिको की खाड़ी है। इस देश के पूर्व में अटलान्टिक तथा पश्चिम में प्रशान्त महासागर अवस्थित हैं।

पर्वतों, मैदानों और पठारों से यह देश भरा पड़ा है। इसके पठार तो ३००० मील तक एक किनारे से दूसरे तक फैले हुए हैं। संयुक्तराज्य का क्षेत्रफल ३०,२२,३८७ वर्ग-मील है। यह विस्तृत क्षेत्रफल ४८ राज्यों में विभक्त है जिनकी सूची पुस्तक के अन्त में दी गई है। सब से बड़ा राज्य टैक्सास है जो संयुक्तराज्य के १० % क्षेत्रफल में स्थित है और फ्रान्स जैसे बड़े देश से भी बड़ा है।

संयुक्तराज्य में आठ बड़ी नदियाँ हैं। इन में सबसे बड़ी नदी मिस्सीसीपी २४७० मील लम्बी है। इस महान् राज्य में पाँच बड़ी झीलें भी हैं जो संयुक्तराज्य को कनाडा से अलग करती हैं और इन पाँचों झीलों के पानी का क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है।

७ सितम्बर १९५५ ई० की जनगणना के अनुसार संयुक्तराज्य की जनसंख्या इस प्रकार है—

जनसंख्या — १६,५८,५६,१२३
गाँवों में रहने वाले — कुल संख्या के $\frac{1}{3}$
शहर में रहने वाले — कुल संख्या के $\frac{2}{3}$
स्त्रियों की संख्या मनुष्यों से कुछ अधिक।

१९५०ई० में,

अमेरिकन इन्डियन लोगों की संख्या—४,३५,०००
नीग्रो कुल जनसंख्या का ९.८%

२—भौगोलिक तथा आर्थिक घटक

संयुक्तराज्य और कनाडा के इतिहास में पहिली तीन शताब्दियों तक भूगोल का कोई विशेष प्रभाव न रहा। इंगलैण्ड से जो ऐतिहासिक परम्पराएँ, यहाँ के प्रथम बसने वाले लाए, भूगोल ने उन्हें मजबूत बनाने में सहायता की। प्यूरिटन लोग इंगलैण्ड में राजनीतिक तथा धार्मिक विरोध की अग्नि में जलते रहे थे, उन्हें इंगलैण्ड का पुराना स्थानीय स्वशासन भी याद था। जब वे संयुक्तराज्य में आकर बसे जहाँ चारों ओर घने जंगल तथा भयानक अमेरिकन इन्डियन लोग थे, तो इन लोगों ने अपने समुदाय संगठित किए और जो भी समस्याएँ शिक्षा, धर्म तथा नियमों के विषय में उठीं उन्हें वहीं का वहीं तय कर लिया। इस परम्परा के कारण ही स्थानीय विद्यालय नगर-व्यवस्था का आरम्भ हुआ जो अमेरिका में आज भी जीवित है।

जब अटलान्टिक महासागर से प्रशान्त की ओर बड़ी जनसंख्या का पलायन हुआ, उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को विशेष लाभ हुआ। खेती करने वाले कुटुम्ब हमेशा के लिए बस गए किन्तु धन का वितरण अत्यन्त असमान हो गया। धनिक लोगों

और सम्प्रदायों ने अच्छे विद्यालयों को जन्म दिया और गरीब किसानों की बस्तियों में एक शिक्षकवाले विद्यालय जैसे-तैसे चलते रहे। विधान का यह सिद्धान्त कि शिक्षा का अवसर समान रूप से सभी को मिले, केवल विचारों तक ही सीमित रहा।

३—शिक्षागत वित्त

राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली के विकास में सब से अधिक हाथ शिक्षागत वित्त का रहा करता है। शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत व्यय होता है, केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार कितनी सहायता देती है, सरकार की अनुदान की व्यवस्था किस प्रकार की है; इन सब बातों की झलक राष्ट्र के ढाँचे और उसकी विशेषता में प्राप्त हो जाती है।

उदाहरण के लिए यदि हम १९२७ से १९३० तक के काल में, जो दो महायुद्धों के बीच का समय है और इसलिए स्वस्थ समय है, यह देखें कि विभिन्न देश, शिक्षा पर किस प्रकार व्यय करते रहे, तो हमें निम्न तथ्य प्राप्त होंगे—

	देश का नाम	प्रतिशत
१.	डेन्मार्क	११%
२.	इंगलैण्ड	९·५%
३.	फ्रान्स	७·७%
४.	जर्मनी	१५%
५.	हॉलैन्ड	२१·३%
६.	स्पेन	३·७%
७.	इटली	६·२%
८.	नॉर्वे	१४·२%
९.	रूस	१०·९%
१०.	स्वीडन	१६%
११.	स्विट्जरलैण्ड	१६%
१२.	संयुक्तराज्य	१९%

उपर्युक्त तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्तराज्य, हालैण्ड, स्विटजरलैण्ड तथा स्वीडन जैसे प्रगतिशील और स्पेन जैसे पिछड़े देशों में जो अन्तर है वह उनके शिक्षा पर होने वाले व्यय से कितना स्पष्ट है।

शिक्षा-प्रसार में सरकार का सहयोग नापने की एक सूची और भी है और वह है कि शिक्षा पर केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार किस तरह व्यय करती है। शिक्षा-व्यय का सम्पूर्ण केन्द्रीकरण योरुप में किसी भी देश में नहीं रहा। संयुक्तराज्य तथा कनाडा

में स्थानीय अन्विति तो शिक्षा का ८०% व्यय स्वयं पूरा करती है। फ्रान्स, इटली तथा बेल्जियम में स्थानीय अधिकारी एक-तिहाई से कम देते हैं और शेष केन्द्रीय सरकार देती है।

जिन देशों में शिक्षा में विकेन्द्रीकृत प्रणाली है वहाँ असमानता रहने का भारी डर रहता है। संयुक्तराज्य तथा कनाडा में यह बात ह। शहर के धनी समाज के विद्यालयों का शिक्षा-स्तर और गाँवों के किसानों के समाज के विद्यालयों का शिक्षा-स्तर, एक दम अलग-अलग है। एक बहुत ऊँचा और एक बहुत नीचा।

विकेन्द्रीकरण वाले देशों में अनुदान-क्रम कैसा हो? इसके विषय में डॉ० हैन्स ने तीन मुख्य सुझाव रखे हैं जिन्हें आगे रखकर ही अनुदान की मात्रा निश्चित करनी चाहिए, ताकि अवसर की समानता वाले आदर्श की रक्षा हो सके—

१. आवश्यकता—विद्यार्थियों की संख्या;

२. प्रयत्न—स्थानीय प्रयत्न और उनका व्यय;

३. योग्यता।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि नियम द्वारा, प्रत्येक बालक तथा शिक्षक पर कम से कम व्यय निश्चित कर दे। किन्तु संयुक्तराज्य तथा कनाडा में इस विषय में कुछ भी ठोस बात नहीं हुई और असमानता आज भी जोर पर है।

४—सामाजिक समस्याएँ

आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा-अवसर की असमानता आदि सामाजिक समस्याओं के विषय में तो हम कह ही चुके हैं। एक बड़ी समस्या है 'रंग' की—नीग्रो लोगों की।

दुनियाँ में दो देश हैं जहाँ रंग-भेद की समस्या अपनी चरम सीमा पर है और आज तक उसके बारे में विशेष ठोस प्रगति नहीं हो सकी। डा० हैन्स के अनुसार ये दो देश हैं—दक्षिणी अफ्रीका तथा संयुक्तराज्य।

दक्षिणी अफ्रीका में गोरी जाति अत्यन्त अल्प संख्या में है और उसे इस बात का डर है कि कहीं वह मिट न जाय। संयुक्तराज्य में नीग्रो कुल जन-संख्या के १०% हैं और वे कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोच सकते कि 'एक दिन हम छा कर रहेंगे'।

नीग्रो-समस्या को एक जातीय समस्या कहना बहुत अंश तक भ्रामक मत है। वह एक घरेलू समस्या है। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि 'रंग-रेखा' रंग पर आधारित नहीं दिखाई देती। कुछ ऐसे भी नीग्रो हैं जो औसत योरुपीय मनुष्यों के समान गोरे हैं और ऐसे भी 'गोरे' हैं जो नीग्रो लोगों के समान काले हैं। ऐसी स्थिति में 'काले' और 'गोरे' में भेद, 'रंग' पर नहीं, सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है।

वैज्ञानिक अनुसंधान तो यह व्यक्त करते हैं कि यदि 'गोरों' के साथ 'कालों' का विवाह आदि होता रहे तो कुछ समय पश्चात् 'नीग्रो' रहेंगे ही नहीं। डा० हैन्स के

अनुसार बहुत से ऐसे सफेद अमेरिकन लोग हैं जो यह जानते भी नहीं कि उनमें नीग्रो-रक्त बह रहा है।

यह कहना कि नीग्रो अलग जाति है, उसकी औसत बुद्धि, रंग, अलग है; कोरी कल्पना है। यह एक सामाजिक कल्पना है और पुरानी दासता के इतिहास की अवशिष्ट मनोवृत्ति है। नियम की असमानता तो दक्षिण के १७ राज्यों में ही है किन्तु सामाजिक असमानता सारे राष्ट्र में है। यही अन्तर है कि उत्तर में दक्षिण की अपेक्षा कुछ कम वेग है।

द्वितीय अध्याय

रूपरेखा——

प्रथम चरण:——संघीय सरकार और अमेरिकन शिक्षा ।

द्वितीय चरण:——राज्य तथा शिक्षा ।

तृतीय चरण:——काउन्टी माध्यमिक विद्यालय अन्विर्तियाँ तथा शिक्षा ।

चतुर्थ चरण:——स्थानीय विद्यालय-नगर ।

प्रथम चरण

संघीय सरकार और अमेरिकन शिक्षा

रूपरेखा :—

१. शिक्षा की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय योजना।
२. शिक्षा-योजना का स्वरूप।
३. शिक्षा में संघ-सरकार के कार्य।
४. संयुक्तराज्य : शिक्षा-कार्यालय।
५. संयुक्तराज्य : शिक्षा-कमिश्नर।
६. शिक्षा में संघ सरकार के अन्य क्षेत्र
७. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

संघीय सरकार और अमेरिकन शिक्षा

संघ-सरकार ने देश की शिक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ाने में सहायता की है, इसे देखने के लिए हम निम्नलिखित बातों पर क्रमश: विचार करेंगे—

१. शिक्षा को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय योजना।

२. शिक्षा-योजना का स्वरूप, और शिक्षा में संघ-सरकार के कार्य।

३. संयुक्तराज्य : शिक्षा कार्यालय।

४. संयुक्तराज्य : शिक्षाकमिश्नर।

५. शिक्षा में संघ-सरकार के अन्य क्षेत्र।

(१)

शिक्षा की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय योजना

डॉ० कैन्डेल के मतानुसार शिक्षा में संयुक्तराज्य सरकार का प्रशासन, दो मनोवृत्तियों का अन्तर्द्वन्द्व है। प्रथम, जनता की यह मनोवृत्ति कि 'अपना काम अपने हाथ में' और पहले से प्राप्त इस तरह के अधिकारों का समर्थन और उनकी रक्षा। द्वितीय, जनता के विकास के लिए उचित शिक्षा के नियमों तथा वैज्ञानिक प्रशासकीय विधियों को प्रोत्साहन देना। इसका अर्थ हुआ : शिक्षा का अधिक से अधिक केन्द्रीकरण, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा का उचित अवसर मिल सके। इन मनोवृत्तियों में दोनों ही प्रधान रही हैं अधिक प्रधान पहली ही। यही कारण है कि संयुक्तराज्य की शिक्षा का प्रबन्ध, संघ या संघ सरकार के हाथों में न होकर देश के छोटे-छोटे १,५०,००० स्थानीय विद्यालय-बोर्डों के हाथ में है। ४८ राज्यों में से केवल डेलावेयर ही एक ऐसा राज्य है जहाँ का शिक्षा-प्रबन्ध तथा आर्थिक सहायता, सीधे रूप से तथा पूर्ण रूप में राज्य सरकार के हाथ में है।

किन्तु प्रत्येक राष्ट्र के अपने उद्देश्य भी होते हैं जिन्हें वह शिक्षा की विशेष प्रणाली तथा पाठ्य-क्रम का विशेष स्वरूप निश्चित करके, प्राप्त करना चाहता है। इसका कारण यह है कि उन्नति के सभी साधनों में शिक्षा-साधन सबसे अधिक उत्तम तथा शक्तिशाली है। राष्ट्र के संगठन तथा विकास के लिए, अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग योजनाएँ अधिक उपादेय नहीं हो सकतीं। यही कारण है कि शिक्षा-प्रशासन के जगत् में एक आवश्यकता यह रही कि कई राज्यों को मिलाकर बड़े संघ बनाए जाएँ। केन्द्रीय प्रशासन तथा योजनाओं को शिक्षा-पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाय। यह आवश्यकता आज इसलिए और बढ़ गई है कि संयुक्तराज्य की केवल यही एक आवश्यकता नहीं है कि वह अपने शिक्षा-संगठन को किस भाँति मजबूत तथा विकासगामी बनाएँ, वरन्, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में, शिक्षा के माध्यम से, दूसरे देशों को समझे तथा अपना परिचय

उन्हें दे और इस प्रकार प्रेम और सहयोग के मार्ग से, विश्व के निर्माण तथा विकास में उचित सहयोग दे। इस आवश्यकता के कारण शिक्षा को केन्द्रीकरण के मार्ग पर चलना पड़ेगा। यह उद्देश्य संयुक्तराज्य ने प्राप्त नहीं कर पाया है, यद्यपि शिक्षा धीरे-धीरे केन्द्रीकरण की ओर बढ़ रही है, क्योंकि, जनता केन्द्र से शंकित है, अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी बात धार्मिक तथा आर्थिक प्रवृत्तियों का होना है जो अपना ही भला चाहती हैं, दूसरों का नहीं। डॉ० हैन्स के अनुसार इतिहास इस बात का पोषक है कि केन्द्रीकरण के डर से संघ-सहयोग को सबसे अधिक सशंक होकर दक्षिणी राज्यों तथा देश के सभी धार्मिक समुदायों ने देखा और जब कभी संघ-सरकार से संघर्ष का अवसर आया तो इन समुदायों को दूसरे देशों—इंगलैण्ड तथा फ्रान्स आदि—का समर्थन भी प्राप्त रहा।

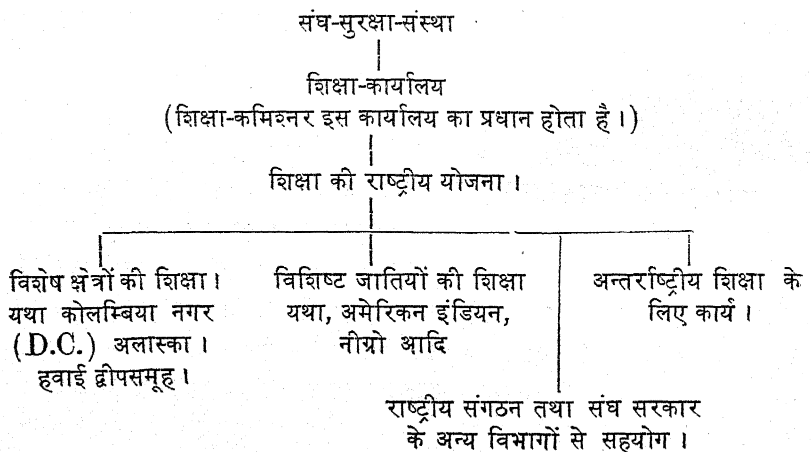
(२,३)

शिक्षा-योजना का स्वरूप तथा संघ सरकार के कार्य

शिक्षा-जगत् में संघ सरकार की योजनाओं का क्या स्वरूप है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि संघ सरकार किस तरह शिक्षा अपने हाथ में लिये हुए है? उसका कौन सा विभाग शिक्षा-योजनाओं और शिक्षा-विकास में सहयोग देता है। उस विभाग के मुख्य-मुख्य कार्य कौन से हैं? क्योंकि तभी हम शिक्षा-योजनाओं का सही मूल्यांकन कर सकते हैं।

उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम एक रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं—

सबसे ऊपर—संघ सरकार का एक विभाग, जिसे कहते हैं—



शिक्षा की उपर्युक्त राष्ट्रीय योजना को ध्यान में रखकर संघ के कार्यों को पाँच विभागों में विभक्त किया जा सकता है—

१. मूल संघीय नियम;
२. राष्ट्रीय सुरक्षा-शिक्षा;
३. संघ-अनुदान : अनौद्योगिक;
४. संघ-अनुदान : औद्योगिक;
५. शिक्षा की अन्य योजनाएँ।

१—मूल संघीय नियम

सन् १७८५ ई० में 'नॉर्थवैस्ट ऑर्डीनेन्स' लागू हुआ, जिसके अनुसार प्रत्येक 'टाउन शिप'—जो ६ वर्गमील की होती है,—का '१६ वां' हिस्सा (Lot No—16) जनता के शिक्षा-विद्यालयों को चलाने के लिए सुरक्षित रहेगा। इसी बात को १७८७ ई० में फिर से दुहराया गया। एक सुन्दर सिद्धान्त सामने आया, "धर्म, नैतिकता तथा ज्ञान, अच्छी सरकार तथा मानवता के सुख के लिए आवश्यक है, अतः विद्यालयों और अन्य शिक्षा-साधनों को सदैव ही प्रोत्साहित किया जायगा।"

सन् १७८९ ई० में संयुक्तराज्य का विधान लागू होगया। विधान शिक्षा के विषय में मौन है। 'शिक्षा' शब्द का भी प्रयोग नहीं है। विधान-निर्माताओं ने शिक्षा को शायद राज्यों का कार्य माना और केन्द्रीय अधिकार से उन्हें भय बना रहा। दूसरे उस समय शिक्षा का प्रबन्ध गिरजे, घरों तथा व्यक्तिगत संस्थाओं के हाथ में था। तीसरे, उस समय शिक्षा से भी बड़ी समस्याएँ यथा अर्थ-व्यवस्था, रैड इन्डियन आदि थीं, जिनके बारे में वे व्यस्त रहते थे।

इन सब बातों के होते हुए भी, शिक्षा में संघ के सहयोग के लिए अप्रत्यक्ष रूप से स्थान अवश्य है।

विधान की प्रस्तावना में "सार्वजनिक भलाई" को प्रोत्साहन देने का उल्लेख है और इस नाते संघ-सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जन-शिक्षा में वह सहयोग दे।

लेकिन विधान का दसवाँ संशोधन इस बात के पक्ष में नहीं है कि शिक्षा का प्रबन्ध संघ-सरकार के हाथ में हो। उसके अनुसार "वे अधिकार, जो संयुक्तराज्य को विधान द्वारा नहीं दिये गए और न उसके द्वारा राज्यों के लिए रोके गये, राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित हैं।"

२—राष्ट्रीय सुरक्षा-शिक्षा

द्वितीय महायुद्ध के समय और इसके बाद सुरक्षा-तैयारी के लिए, प्रशिक्षण-शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सन १९४७ ई० में 'संगठन नियम' पास हुआ और उसके अनुसार सुरक्षामन्त्री के अधिकार में सेना, वायुसेना तथा जलसेना के मन्त्रियों को संगठित किया गया।

न्यूयॉर्क के वेस्ट प्वाइन्ट स्थान पर सन् १८०२ ईसवी में ही सैनिक अकादमी स्थापित की गयी थी और उसका सारा खर्च संघ-सरकार ही देती थी। उसी तरह जल

तथा नभ-सेना के लिए भी प्रशिक्षण-विद्यालय खोले गए।

३–संघ-अनुदान : अनौद्योगिक

१८०३ ई० में जिस समय ओहियो राज्य संघ में सम्मिलित हुआ, संघ-सरकार ने शिक्षा-विकास के लिए एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण परम्परा को जन्म दिया। विद्यालयों के लिए प्रत्येक 'टाउन शिप' को '१ भाग' जो एक जो एक मील का वर्ग था, दिया गया।

१८५० ई० में जब कैलिफोर्निया राज्य संघ में आया तब संघ सरकार ने दो भाग—'१६' और '३६' क्रमसंख्या वाले प्रदान किए। संघ के तीन राज्यों यूटाह, अरीजोना, तथा न्यू मैक्सिको को तो चार भाग—'१६', '३६','२', '३२' क्रम संख्या वाले दे दिए गए। इस तरह विद्यालयों को जो भूमि अनुदान में दी गई उसका क्षेत्रफल १,५०,००० वर्गमील या ६,००,००,००० एकड़ है।

इस तरह के अनुदानों के अतिरिक्त भी और अनुदान दिए गए। ऊसर तथा दलदली भूमि भी शर्त और बिना शर्त के दी गई। भेंटों के रूप में नॉर्मल विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कृषि और मशीनरी-प्रधान भूमि अनुदान-विद्यालयों को धन दिया गया। इस प्रकार धन तथा भूमि की सहायता शिक्षा-प्रसार तथा विकास के लिए संघ-सरकार द्वारा दी गई।

४–अनुदान : औद्योगिक शिक्षा के लिए

भूमि-अनुदान महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय

औद्योगिक शिक्षा-प्रसार तथा विकास संयुक्तराज्य सरकार की एक सुनिश्चित तथा बलवती योजना रही है। इतने बड़े प्रदेश को जो हाल ही में बसाया गया था और अपार मात्रा में जहाँ खनिज पदार्थ आदि उपलब्ध हो सकते थे, ऐसे देश की कृषि तथा औद्योगिक उन्नति ऐसे ही विद्यालयों के प्रसार पर निर्भर थी। और इस तरह का कदम निश्चित रूप से उचित दिशा में उठा हुआ कदम था।

१८६२ ई० के प्रथम मौरिल नियम के अनुसार प्रत्येक राज्य को, कांग्रेस में प्रति सीनेटर ३०,००० एकड़ भूमि के हिसाब से सहायता दी गई। इस तरह का अनुदान इस लिए दिया गया ताकि प्रत्येक राज्य कम से कम एक ऐसे विद्यालय को चलाए जो कृषि तथा मशीनरी के विकास का पाठ्यक्रम लेकर देश के विकास में सहयोग देता हुआ, आगे बढ़े। आज तक ऐसे विद्यालयों की संख्या ६६ है और इन्होंने कृषि, इन्जीनियरिंग तथा गृह-अर्थ-क्षेत्र में बड़ी ही सफलता प्राप्त की है।

१८८७ ई० के है 'ग' नियम के द्वारा कृषि के प्रयोगात्मक विद्यालयों का जन्म हुआ। इस नियम के अनुसार प्रत्येक राज्य को १५,००० डालर वार्षिक अनुदान मिला। इस अनुदान का उद्देश्य था कृषि-विज्ञान के सिद्धान्त तथा प्रयोगों को सामने रखकर वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना। थोड़े ही समय बाद यह प्रत्यक्ष रूप में सामने आगया कि कृषि में बड़े महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान हुए और नये तथ्य सामने आये; किन्तु,

अनुसन्धान के लिए वैज्ञानिकों का जोश इतना अधिक था कि १५००० डालरों का अनुदान बिल्कुल अपर्याप्त रहा। अतः इस कमी को पूरा करने तथा अनुसन्धान के विकास को प्रोत्साहन देने को, अधिक मात्रा में अनुदान एडम-नियम से प्राप्त हुआ।

सन् १९१४ ई० में स्मिथ-लीवर नियम या 'कृषि-प्रसार नियम' पास हुआ। इसके पास होने का उद्देश्य अत्यन्त साधारण था। अनुसन्धान विद्यालयों में कृषि के बड़े महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान हुए किन्तु देश को कृषि-उन्नति के लिए इनका उपयोग न हो सका और एक बड़ी आवश्यकता इस बात की दिखाई दी कि कृषि-अनुसन्धानों के ज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया जाय। उसे किसानों तक पहुँचाया जाय ताकि कृषि की उपज बढ़े। अतः इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए 'कृषि-प्रसार-सेवा' आरम्भ हुई। इसके अन्तर्गत कालेजों, बातचीतों, विद्यालयों, कक्षाओं, तथा बाहर जाने वाले एजेन्टों की सेवाएँ प्राप्त की गई और इस तरह वैज्ञानिक सहायता किसानों तथा घर में गृहस्वामिनी तक पहुँचाई गई। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिए और भी नियम बनाये गये ताकि आर्थिक सहायता अधिक प्राप्त हो सके। इन नियमों में कैपर कैचमैन, क्लार्क, बैंक हैड-जोन्स, नॉरिस-डॉक्सी, तथा बैंक.हैड-फ्लैनागन के नियम प्रमुख हैं।

संघ सरकार ने औद्योगिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर आरम्भ किया तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य किये। औद्योगिक शिक्षा के लिए इस विषय में स्मिथ-ह्ग्स नियम बनाया गया। माध्यमिक स्तर पर इस तरह की शिक्षा बीसवीं शती में ही आरम्भ हुई। सन १९१७ ई० में स्मिथ-ह्ग्स नियम पास हो गया। बाद में अनुदान और भी बढ़ा दिये गये।

शिक्षा में संघ-सरकार के अन्य क्षेत्र

संघ सरकार ने निम्न बातों के लिए भी अनुदान दिये--

१. अ—व्यक्तिगत विद्यालयों को अनुदान।

आ—अन्धे लोगों की शिक्षा में सहायतार्थ अमेरिकन मुद्रण-गृह को सहायता।

इ—कोलम्बिया के वधिर विद्यालय को।

ई—हॉवर्ड विश्वविद्यालय—(कोलम्बिया नगर—D. C.)

२. अधिकारों का जी. आई. बिल—संघ-सरकार का यह बहुत ही बड़ा कदम है। इसके अन्तर्गत सरकार उन लोगों को काम देती है जो युद्ध में लड़ते-लड़ते अपाहिज हो जाते हैं और उन लोगों को शिक्षा देती है जो अपाहिज नहीं हैं, ताकि अन्य नये कामों पर लग सकें।

शिक्षा-कार्यालय के कार्यों को आधुनिक प्रकाश में देखने के लिए कुछ नये नियमों तथा योजनाओं को समझना भी आवश्यक है।

१९३८ ई० में 'न्यू डील पॉलिसी' (New Deal Policy) आरम्भ हुई। प्रेसीडेन्ट रूजवेल्ट ने शिक्षा के लिए एक सलाहकार कमैटी को चुना और इस कमैटी

की राय पर ही यह नई योजना आधारित थी। इस योजना के अन्तर्गत दो विशेष बातें की गई—

१. 'राष्ट्रीय युवक प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा सेना' का संगठन, बेकार युवकों को काम देने तथा औद्योगिक शिक्षा देने के लिए आरम्भ किया गया।

२. युद्ध तथा उससे सम्बन्धित सभी शिक्षाओं का परिचालन तथा नियन्त्रण शिक्षा-कार्यालय ने अपने हाथ में ले लिया।

१९४० ई० में ई. डी. टी. (E.D.T.) नियम आरम्भ हुआ। इसके अनुसार सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग प्रशिक्षण देने की योजना रखी गई। इस योजना ने युद्ध-काल में बड़ी सहायता दी।

संघ-सरकार का शिक्षा में सक्रिय सहयोग जो १९४५ ई० से पहले ६,५०,००,००० डालर था, बढ़कर २५,००,००,००० डालर हो गया। यह सब होते हुए भी गत वर्षों से यह मनोवृत्ति दिखाई देती है कि सरकार की जो अन्य संस्थाएँ शिक्षा-कार्यालय के द्वारा स्थानीय विद्यालयों से सम्पर्क रखती थीं, अब सीधा सम्पर्क रखने लगी हैं। इसका परिणाम श्री मोरफेट के अनुसार यह हुआ है कि संयुक्तराज्य शिक्षा-कार्यालय तथा राज्यों के शिक्षा-विभाग कमजोर होते जा रहे हैं।

(४)

संयुक्तराज्य का शिक्षा-संचालन

कार्यालय का विकास

शिक्षा-विभाग की स्थापना में बहुत से महत्त्वपूर्ण कारण रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कार्यों के लिए देश के विधान में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था।

अ—मैसाचूसेट्स राज्य में १८४० ई० के आसपास हॉरेस मन ने 'जन-विद्यालयों के पुनरुत्थान' के लिए बड़ा प्रशंसनीय किया कार्य था।

आ—शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संस्था हो, इसके लिए हेनरी बर्नार्ड ने जन-आन्दोलन का नेतृत्व किया।

इ—नागरिक युद्ध के बुरे परिणामों और राज्यों के संघ में सम्मिलित होने से राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक नई रुचि उत्पन्न हुई।

ई—'शिक्षा का एक अलग विभाग हो' इस सम्बन्ध में जेम्स ए. गारफील्ड ने एक बिल रखा और वह २ मार्च १८६७ ई० को पास हो गया।

शिक्षा-विभाग के उद्देश्य

अ—विभिन्न राज्यों में शिक्षा की क्या दशा है ? कितनी उन्नति हुई ? इसके लिए आवश्यक तथ्यों का संकलन करना;

आ—संयुक्तराज्य की जनता के कल्याण के लिए, प्रशिक्षण-विधियों, विद्यालयों

के संगठन तथा नियन्त्रण तथा विद्यालय-प्रणाली के लिए इस सूचना को फैलाना;

इ—देश भर में शिक्षा की प्रगति के लिए प्रयत्न करना।

बाद के परिवर्तन

१. दो वर्ष बाद ही 'शिक्षा-विभाग' को शिक्षा-कार्यालय बना दिया गया और यह कार्यालय संघ के 'आन्तरिक विभाग' में सम्मिलित कर लिया गया।
२. १८७० ई० में शिक्षा-कार्यालय को 'शिक्षा-ब्यूरो' में बदल दिया गया।
३. आजकल इसका नाम 'शिक्षा-कार्यालय' ही है, ब्यूरो नहीं रहा।
४. १९३९ ई० को पहिली जुलाई को, शिक्षा-कार्यालय को आन्तरिक विभाग से स्थानान्तरित कर दिया गया और उसे संघीय सुरक्षा संस्था में मिला दिया गया।

शिक्षा-कार्यालय तथा वित्त

कार्यालय के पास दो तरह का वित्त रहता है—

१. शिक्षा-कार्यालय के प्रशासन तथा परिचालन के लिए नियमित व्यय, जो लगभग २,००,००,००० डालर प्रति वर्ष है।
२. सहायतार्थ अनुदान, जो राज्यों को देना होता है, इसी कार्यालय के द्वारा दिया जाता है। यह धन भूमि अनुदान महाविद्यालयों, औद्योगिक शिक्षा, औद्योगिक पुनर्वास और सुरक्षा-शिक्षा पर व्यय किया जाता है। इस धन की मात्रा लगभग २०,००,००,००० डालर प्रति वर्ष है।

शिक्षा-कार्यालय के कार्य

१. शिक्षाविषयक तथ्यों तथा आँकड़ों का संकलन;
२. रेडियो, प्रदर्शनी, प्रकाशन, सभाओं द्वारा संकलित ज्ञान का प्रसार;
३. शिक्षा का प्रसार करना। पुस्तकालय, राष्ट्रीय सूचना-केन्द्र तथा विद्यालयों को प्रमुख समस्याओं पर लिखी गई थीसिसें उधार देना, आदि शिक्षा-कार्यालय के ऐसे कार्य हैं जो, शिक्षा-प्रसार में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं।

(५)

संयुक्तराज्य का शिक्षा-कमिश्नर

शिक्षा-कमिश्नरों की परम्परा सन् १८६७ ई० से आरम्भ हुई और हेनरी बर्नार्ड, संयुक्तराज्य के शिक्षा-कार्यालय के प्रथम कमिश्नर थे। आजकल शिक्षा-कमिश्नर अर्ल जेमैकग्राथ महाशय हैं। अपनी सिनेट की अनुमति से संयुक्तराज्य के राष्ट्रपति शिक्षा-कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। नियुक्त की कोई विशेष अवधि नहीं होती।

शिक्षा-कमिश्नर के प्रमुख कार्य

१. शिक्षा-कार्यालय के सभी कार्य;

२. वार्षिक तथा द्विवार्षिक रिपोर्टों को तैयार करना;
३. अनेकों शिक्षा-संस्थाओं से सम्पर्क रखना।

(६)

संघ सरकार के अन्य शिक्षा-क्षेत्र

१. संघ के विशिष्ट अधिकृत प्रदेश—
अ—वाशिंगटन (कोलम्बिया नगर D.C.)
आ—अमेरिकन उपनिवेश।
इ—गिरवी रखे प्रदेश।
ई—संघ के सुरक्षित प्रदेश।

२. विशेष समुदायों वाले प्रदेश।

अ—अमेरिकन ंडियन—सबसे पहिले शिक्षा के क्षेत्र में मिशनरी लोगों ने सहायता की, ईसाई बनाने के लिए। १८८० ई० के आसपास संघ सरकार ने आर्थिक अनुदान दिये। व्यक्तिगत अनुदान भी प्राप्त हुए।

१९२४ ई० में २ जून को पास हुए नियम के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन इण्डियन को नागरिक होने के अधिकार दिये गए। संयुक्त-राज्य में लगभग सवा तीन लाख अमेरिकन इण्डियन रहते हैं। ओक्ला-होमा, अरीजोना, न्यू मैक्सिको, तथा साउथ डकोटा राज्यों में ये लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।

आ—नीग्रो—संयुक्तराज्य की कुल जन-संख्या का दसवाँ भाग नीग्रो जाति का है। उनका अधिकांश भाग दक्षिणी राज्यों में रहता है। १७ राज्य तथा कोलम्बिया नगर में गोरों और कालों के अलग अलग शिक्षा-संस्थाएँ खुली हुई हैं। हॉवर्ड विश्वविद्यालय नीग्रो लोगों का है। इस विश्व-विद्यालय को संघ सरकार से अनुदान प्राप्त है।

इ—अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा—अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा में अमेरिकन जनता को बड़ी रुचि है क्योंकि अन्य राष्ट्रों के लोगों तक वह अपने प्रजातन्त्रीय जीवन को फैलाना चाहती है। साथ ही इस तरह के सहयोग से उसे बहुत-सी अच्छी नई बातों के सीखने का अवसर मिलता है।

इसीलिए विकेन्द्रीकरण पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा-योजना अमेरिका में धीरे-धीरे विकसित हो रही है।

द्वितीय चरण

राज्य तथा शिक्षा

रूपरेखा :—

१. विभिन्न राज्य तथा उनकी शिक्षा-प्रणाली।
२. शिक्षा के प्रति राज्य के कर्त्तव्य।
३. राज्य की शिक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था।
४. राज्य-शिक्षा-बोर्ड।
५. सदस्यों की योग्यता।
६. बोर्ड के कर्त्तव्य।
७. राज्य-शिक्षा का कमिश्नर अथवा सुपरिन्टेन्डन्ट, उसकी योग्यता तथा उसके कर्त्तव्य।
८. राज्य का शिक्षा-विभाग।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

संयुक्तराज्य अमेरिका में शिक्षा की बागडोर सदैव से ही राज्यसरकारों के हाथों में रही है। प्रारम्भ से ही, जबकि बाहर के रहने वाले वहाँ आकर बसे, शिक्षा की देख-रेख राज्य-सरकारें करती रहीं। यद्यपि स्थानीय संस्थाएँ काफी मात्रा में स्वतन्त्रता का उपयोग सदैव से ही करती आई हैं। इसका कारण राज्य-सरकारों की सहमति रही है।[1] वैसे तो स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारें, सभी शिक्षा के विषय में सहयोग देती हैं और इस प्रकार की एक-दूसरे पर निर्भरता इस बात की परिचायक है कि शिक्षा के विषय में सभी की बराबर दिलचस्पी है। स्थानीय संस्थाओं की प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा में रुचि देखकर कहना ही पड़ता है कि वहाँ की शिक्षा के केन्द्र (स्कूल) वास्तव में जन-साधारण के लिए हैं और वह भी उस सीमा तक जो प्रायः दूसरे राष्ट्रों में असम्भव है।[2] हम इस बात को भली भाँति जानते हैं कि उन राष्ट्रों में, जहाँ के शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित हो चुकी है, वहाँ स्वतन्त्रता की कल्पना, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा शिक्षा का, असम्भव होगी। पर १९४० में नेशनल ऐजूकेशन ऐसोसिएशन के एजूकेशनल पॉलिसीज कमीशन ने कहा था कि प्रजातन्त्रवादी राष्ट्र अमेरिका (U.S.A.) को "प्रजातंत्र का अर्थ तथा उसके उद्देश्यों का समझना आवश्यक है।" मुक्त वातावरण में राष्ट्र स्थानीय संस्थाओं को छूट तो देगा ही जिसके कारण सब स्थानों पर एक-सी व्यवस्था असम्भव होगी। किसी राज्य का स्थायी होना इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में उस राज्य की शिक्षा-व्यवस्था राज्य के हाथ में है। "Aristotle in the Politics recognized that the permanence of the Constitutions or stability of the State can be assured by adapting education to their forms."[3] एक राज्य बहुत दिन तक चले, इसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ परिवर्त्तन तथा स्थायित्व दोनों ही उचित मात्रा में सन्तुलित रहें। इस सिद्धान्त के अनुसार संयुक्तराज्य अमेरिका में हम यह देख सकते हैं कि राज्य-सरकारें स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा के सम्बन्ध में छूट भी देती हैं तथा उन पर अनुशासन भी रखती हैं। किन्तु इन दोनों बातों में एक बात का सदैव ध्यान रखा जाता है कि वहाँ प्रजातन्त्र की आत्मा का हनन न हो। यद्यपि हम इस नियम का अपवाद डेलावर (Delawaere) राज्य में पाते हैं जहाँ कि शिक्षा का प्रबन्ध राज्य के हाथों में ही है किन्तु हमें विश्वास है कि प्रजातन्त्र की आत्मा वहाँ भी सुरक्षित है।

संयुक्तराज्य अमेरिका में सबसे प्रथम मैसासेचुसेट्स (Massachussets) में शिक्षा

---

1. Brubacher. I.S.; A History of the problems of Education, P.575.
2. Richmond, W.K.; Education in the U.S.A., P. 60.
3. Kandel, I.L.; The New Era in Education, P. 21.

के क्षेत्र में चेतना जागृत हुई। धन की मंजूरी के साथ-साथ ही शीघ्र वहाँ पर स्थानीय संस्थाओं को कानूनी मान्यता मिल गई। शिक्षा के क्षेत्र में ये स्थानीय संस्थाएँ शीघ्र ही बड़ी शक्तिशाली हो गई। उन दिनों जबकि तीव्र आवागमन के साधन न थे, स्थानीय संस्थाओं की स्वतन्त्रता प्राकृतिक थी। १८२० तथा १८३० के लगभग नई माँगें, ऊँचे शिक्षा के स्तर, छात्रों की अधिक संख्या इत्यादि ऐसी समस्याएँ उपस्थित हो गईं जिनका हल इन छोटी-छोटी स्थानीय संस्थाओं द्वारा सम्भव न था। इन्हीं दिनों बाहर से आकर बसने वालों की संख्या भी बढ़ गई। नई सामाजिक चेतना की लहर शिक्षा में और भी दिलचस्पी पैदा करने में सफल हो गई।

इन सब कारणों से राज्यों की सरकारों को शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक जिम्मेदारी लेनी पड़ी। यह करीबन बिल्कुल खुलासा हो गया कि राज्य ही शिक्षा के वास्तविक केन्द्र हैं। केन्द्रीय सरकार (Federal Government) का तो शिक्षा से केवल नैतिक सम्बन्ध ही रहा है क्योंकि दसवें संशोधन द्वारा वहाँ का संविधान सन् १७६१ में इस बात को कहता है :—"The powers not delegated to the United States by the constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively or to the people."

अर्थात् जो शक्तियाँ संविधान द्वारा केन्द्र को नहीं दी गई हैं या जिन पर केन्द्र ने रोक नहीं लगाई है वह जनता अथवा वहाँ के राज्यों द्वारा उपयोग करने को सुरक्षित हैं। साथ-साथ राज्य की सरकारों के पास धन इकट्ठा करने के साधन भी स्थानीय संस्थाओं की अपेक्षा काफी हैं और राज्यों को अपने अधिकारों के उपयोग करने में कोई रुकावट भी नहीं थी, अतएव सन् १७८४ में न्यूयार्क राज्य में शिक्षा के लिए कुछ आफीसरों की नियुक्ति हुई। 'बोर्ड आफ रीजेन्ट्स' के नाम से स राज्य में एक संस्था स्थापित की गई जो आज सम्पूर्ण शिक्षा-क्षे में उस राज्य की नीति बनाने वाली, तथा कानून बनाने वाली संस्था है। १८१२ में न्यूयार्क में पहली बार सुपरिन्टेंडेंट आफ ऐजूकेशन की नियुक्ति भी हुई जिसका कार्य केवल यह निश्चित किया गया कि वह राज्य के धन की व्यवस्था करे तथा स्कूलों को धन वितरित करे।

ये सब बात केवल इस बात की ओर शारा कर रही हैं कि राज्यों का शिक्षा-व्यवस्था में हाथ बढ़ता गया। १८३० में मसाचुसेट्स तथा कोनेक िकट में राज्य के शिक्षा-मन्त्री पद (Secretary) पर दो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति आये। वह थे होरेस मान तथा हेनरी बर्नार्ड। इनके लेख, पत्रिकाएँ इत्यादि जनता में शिक्षा के प्रति अभिरुचि आकर्षित करने में सफल हो गईं।

राज्यों ने धन को एकत्रित करने तथा वितरित करने की नीतियाँ बना डालीं और शीघ्र ही स्थानीय संस्थाओं को धन लेने के लिए राज्य द्वारा निर्धारित स्तर को मानना पड़ने लगा। १८५० तक ऐसा लगा कि राज्य ही पूर्ण धन देने लगेंगे और स्थानीय संस्थाओं

का शिक्षा-विषयक धन का उत्तरदायित्व समाप्त हो जायेगा लेकिन इसे रोकने के लिए (Matching System) अर्थात् एक नियम लगाना पड़ा जिससे राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं के धन का अनुपात बराबर हो।

आज की जटिल सभ्यता की उन्नति तथा मशीनों की तरक्की ने राज्य के शिक्षा-सुपरिन्टेंडेन्ट के पद को और भी महत्त्वपूर्ण तथा जटिल बना दिया है।

शिक्षा के प्रति राज्य के कर्तव्य—विलियम कैम्प द्वारा निर्धारित निम्न कर्त्तव्य एक सही चित्र उपस्थित करते हैं—

(१) स्कूलों की स्थापना के लिए नियम तथा शिक्षा के स्तर का निर्धारण करना।

(२) राज्य के प्रत्येक बालक के लिए स्कूलों के द्वार खोलना।

(३) धार्मिक तथा संकुचित विचारों से सुरक्षित स्कूलों की स्थापना करना।

(४) यह बताना कि स्कूल भिखारियों (Paupers) के लिए नहीं, वरन् सम्भावित नागरिकों के बालकों के लिए हैं।

(५) ऐसे स्कूलों की स्थापना करना, जहाँ अधिकार तथा कर्त्तव्य समान रूप से माने जाते हों।

(६) स्कूलों के विषय में राज्य को प्रथम अधिकार है, इस बात को स्पष्ट करना।

(७) स्थानीय संस्थाओं की मजबूरी के समय स्वयं स्कूल खोलना।

आज ये बातें नवीन नहीं लगतीं, कारण, इतने कर्त्तव्य तथा अधिकार तो हम राज्यों के मानते ही हैं। परन्तु राज्य के ये अधिकार एक लम्बी लड़ाई के फल हैं। इंडियाना राज्य के कमिश्नर आफ एजूकेशन को इंडियाना राज्य ने अधिकार दिया (१८९० में) कि वह पाठ्य-पुस्तकों की एक ऐसी सूची छापे जो राज्य के स्कूलों में पढ़ाने योग्य हों। दूसरी महत्त्वपूर्ण घटना सन् १८९७ में न्यूयार्क राज्य में घटी जिसके द्वारा वहाँ के सुपरिन्टेंडेंट आफ एजुकेशन का जनता की इच्छा के विरुद्ध भी स्कूल खोलने का अधिकार मान लिया गया, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।

आज राज्य के पास दो स्पष्ट अधिकार हैं : (१) स्थानीय संस्थाओं की सहायता करना, तथा (२) स्थानीय शिक्षा-केन्द्रों का निरीक्षण तथा नियम बनाने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य करना ।[1]

राज्य की शिक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था—संयुक्तराज्य अमेरिका में ४८ राज्य हैं और प्रत्येक राज्य के नियम भिन्न हैं, किन्तु हम यह चेष्टा करेंगे कि यह पता लगाएँ कि किस सीमा तक राज्य निम्न आधारों पर व्यवस्थित हैं। कहना न होगा कि शिक्षा देना राज्य-सरकार का कर्त्तव्य है, जिसका अर्थ है कि नियम बनाना उसी का काम है। जी. आई. बिल्स द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लड़ाई से लौटे हुए व्यक्तियों को शिक्षा के विषय में यह स्पष्ट कर

1. Lee, G.C.; An Introduction to Education in Modern America. (P. 223-230)

दिया कि उनकी शिक्षा की बात राज्य-सरकारें निश्चित करेंगी। राज्य की शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार-सीमा क्रमश: विस्तृत हुई है। १७वीं शताब्दी से लेकर, जिस समय मैसाचुसेट्स तथा कोनेक्टीकट में शिक्षाविषयक नियम बने और १७७६ में जब पेनसिलवानियाँ ने यह नियम बनाया कि प्रत्येक काउन्टी को शिक्षा के लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे इत्यादि; आज तक राज्य-सरकारों के अधिकारों की सीमा विस्तृत ही होती रही है। आज कोई भी राज्य विधानसभाओं द्वारा शिक्षा का प्रवन्ध नहीं करता, सभी राज्यों ने अपने अधिकार स्थानीय संस्थाओं को अथवा राजकीय बोर्डों को ही दे रक्खे हैं। वहाँ की शिक्षा का साधारणतया राज्य-स्तर पर प्रवन्ध इस प्रकार है : (१) राज्य-शिक्षाबोर्ड (२) राज्य-शिक्षासुपरिन्टेंडेंट, जो कि बोर्ड का मुख्य पदाधिकारी होता है तथा, (३) राज्य-शिक्षाविभाग, जो बोर्ड द्वारा बनाये गये कानूनों को, सुपरिन्टेंडेंट की संरक्षता में क्रियान्वित करता रहता है।

राज्य का शिक्षा-बोर्ड—स्थानीय बोर्डों की भाँति यह संस्था भी कानून बनाने वाली तथा शिक्षापद्धति निर्धारित करने वाली होती है। पहले तो इसकी स्थापना ही बड़ी कठिनाई से हुई थी क्योंकि लोगों को भय था कि शिक्षा-क्षेत्र में यह निरंकुश न हो जाय; किन्तु न्यूयार्क ने 'बोर्ड आफ रीजेन्ट्स' (१७८४) कायम करके सकी नींव डाली। आज केवल ईलीनोइज, नार्थ डकोटा तथा विसकौन्सिन के अतिरिक्त इस प्रकार के बोर्ड प्रत्येक राज्य में हैं, हो सकता है कि उनके नामों में अन्तर हो।

बोर्ड के सदस्य तीन प्रकार के होते हैं : (१) अपने पद के कारण (Ex-Officio) (२) चुनाव द्वारा या (३) निर्वाचित होने के कारण

(१) पद के कारण (Ex-officio)—ऐसे सदस्य जो केवल पद के कारण मेम्बर हो जाते हैं जैसे राज्य के गवर्नर। आज इस प्रकार के पदाधिकारियों से दूर रहने की नीति है।

(२) चुनाव द्वारा—जैसे टैक्सास में सदस्य चुनाव द्वारा चुने जाते हैं।

(३) निर्वाचित—जैसे न्यूयार्क स्टेट में सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं।

सदस्यों की योग्यता—योग्यताओं वाला प्रश्न जटिल है तथा विवादपूर्ण भी। कतिपय लोगों का मत है कि विशेषज्ञ चुने जाने चाहिए तथा कुछ लोग साधारण जनता के सदस्यों में से निर्वाचन करने के पक्ष में हैं। कुछ राज्यों में ऐसा नियम है कि एक राजनीतिक दल से चार से अधिक सदस्य न चुने जाएँ। व्योमिंग तथा कुछ अन्य में ऐसा नियम है कि राज्य के हर क्षेत्र से सदस्यों का चुनाव हो।

बोर्ड के कर्त्तव्य—एक राज्य के बहुत से बोर्ड भी हो सकते हैं। ऐसे बोर्ड शिक्षा के विभिन्न स्तरों तथा क्षेत्रों के लिए होंगे। प्राय: एक मुख्य बोर्ड को इस प्रकार का कार्य सौंप दिया जाता था जो धन-वितरण सम्बन्धी नीति बनाये तथा कार्य करे। वैसे साधारणतया कार्य-नीति का निर्धारण यह है कि वह राज्य के कानूनी वृत्त से बाहर न हो। वैसे राज्य के विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न बोर्ड भी हो सकते है परन्तु वर्तमान प्रवति ऐसे बोर्ड्स की संख्या कम करने की ओर है।

राज्य का शिक्षा-कमिश्नर अथवा सुपरिटेंडें—बहुत से राज्यों में राज्य-बोर्ड का अध्यक्ष अथवा मंत्री राज्य का मुख्य शिक्षा-पदाधिकारी होता है। बहुत से स्थानों पर बोर्ड से पूर्व भी यह पद तथा पदाधिकारी था। सर्वप्रथम न्यूयार्क (१८१२) में राज्य शिक्षा-पदाधिकारी नियुक्त हुआ। मैसाचुसेट्स में होरेस मान की नियुक्ति (१८३७) ने ऐसा प्रभाव डाला कि इस पद की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। कमिश्नर अथवा सुपरिटेंडेंट किसी भी नाम से आज स कार का पदाधिकारी पुकारा जा सकता है। किन्तु किन्हीं राज्यों (व्योमिंग आदि) में दोनों ही हो सकते हैं। स्पष्ट है कि नाम, पद्धति, नियम प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होंगे।

(१) इसका निर्वाचन गवर्नर द्वारा भी हो सकता है;

(२) सका निर्वाचन राज्यबोर्ड द्वारा भी संभव है;

(३) यह व्यक्ति चुना भी जा सकता है।

कौन सा तरीका अच्छा है, यह वादविवाद का विषय है।

उसकी योग्यता तथा अवधि—किसी-किसी राज्य (यथा मेरीलैन्ड) में यह नियम है कि उसे तिष्ठित कालेज का ग्रेजुएट होना चाहिए। तथा उसकी दो वर्ष की अपनी पद-सम्बंधी विशेष योग्यता भी अच्छे विश्वविद्यालय द्वारा होनी चाहिए, इत्यादि। प्रायः वह एम. ए. होता है पर ऐसा कोई नियम नहीं है।

उसकी अवधि १ साल से लेकर ६ वर्ष तक की है किन्तु प्रायः वह २ वर्ष से लेकर ४ वर्ष तक रहता है।

उसके कर्त्तव्य—(१) स्कूल-बोर्ड तथा काउंटी के सुपरिटें इत्यादि से सलाह करना, (२) स्कूलों तथा शिक्षा के स्तर का निरीक्षण करना, (३) धन-वितरण करना तथा (४) अन्य राज्यों की बैठकों में जाना तथा अपने राज्य की बहुत-सी संस्थाओं को एक सूत्र में बाँधना।

संयुक्तराज्य अमेरिका के कमिश्नर आफ एजूकेशन द्वारा बुलाये जाने पर राष्ट्रीय स्तर पर जाना तथा राष्ट्र-सम्बन्धी शिक्षा में योग देना भी उसके कर्त्तव्य हैं। उसे राज्य-स्तर का तथा स्थानीय संस्थाओं की शिक्षाप्रणाली के स्तर इत्यादि का ध्यान भी रखना पड़ता है।

राज्य का शिक्षा-विभाग—शिक्षा-विभाग का कार्य कानूनों तथा कार्य की जटिलता के कारण क्रमशः बढ़ा तथा अब, क्योंकि, केवल उच्च पदाधिकारी ही सब कार्य करने में समर्थ न रहा, इसलिए कर्मचारी बढ़े, वैसे १८९० तक वहाँ केवल दो ही कर्मचारी थे। १९१७ में स्मिथ ह्यूजेस ऐक्ट द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के कारण, प्रथम विश्व-युद्ध के समय शारीरिक, मानसिक तथा अन्य कारणों से कार्य बढ़ गया और कर्मचारी भी बढ़ गये।

कमिश्नर के नीचे सहायक कमिश्नर आदि होते हैं तथा बहुत-से सुपरवाइज़र क्लर्क आदि भी रहते हैं। इनका कार्य कानून को नियमित करना, उन नियमों की कार्य-

प्रणाली को देखना तथा शिक्षा-सम्बन्धी नेतृत्व करना आदि है। प्रायः उच्च शिक्षा-प्राप्त अधिकारियों के अतिरिक्त साधारण टाइपिस्ट आदि भी होते हैं।

आधुनिक प्रवृति है कि कम आय वाली स्थानीय संस्थाओं की कमी को राज्य-सरकारें पूरा करें। राज्य-सरकारें जो योजनाएँ बनाती हैं उनमें उच्चस्तरीय शिक्षा के केन्द्र तथा अन्य विद्वान् व्यक्तियों की सहायता भी ले ली जाया करती है।

तृतीय चरण

काउन्टी, माध्यमिक विद्यालय अन्वितियाँ, तथा शिक्षा

रूपरेखा :—

१. काउन्टी तथा माध्यमिक विद्यालय की अन्वितियाँ—एक परिचय।

२. काउन्टी-विद्यालय की अन्वितियाँ।

३. काउन्टी-बोर्ड।

४. काउन्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ स्कूल्स;
—योग्यता, अधिकार तथा कर्त्तव्य।

५. टाउनशिप तथा टाउन की अन्वितियाँ;
—व्यवस्था।

६. विद्यालयों का पुनर्गठन—भविष्य की ओर एक क़दम।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

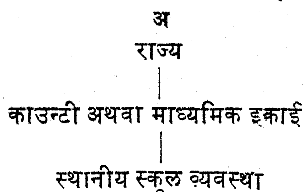
[illegible]

[illegible]

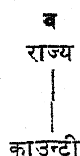
परिचय––जिन राज्यों में काउन्टी स्कूल-व्यवस्था की इकाइयाँ नहीं हैं वहाँ पर माध्यमिक इकाइयाँ (Intermediate units) हैं। इस व्यवस्था के, दो राज्य अपवाद भी हैं : डेलावर तथा नेवादा राज्य। ये माध्यमिक इकाइयाँ राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं के बीच की कड़ी हैं। २३ राज्यों में काउन्टी ही इस प्रकार की माध्यमिक इकाइयाँ है, तथा ७ सुपरवाइजरी इकाइयाँ हैं। जहाँ ये माध्यमिक इकाई हैं, वहाँ के पदाधिकारी का नाम काउन्टी सुपरिन्टेंडें आफ स्कूल्स है। अन्य में उसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेंडेंट कहते हैं। ८ राज्यों में किसी न किसी प्रकार का बोर्ड, काउन्टी सुपरिन्टेंडेट को परामर्श दिया करता है।

कुल मिलाकर ऐसे ११ राज्य हैं जहाँ काउन्टी ही स्थानीय स्कूल व्यवस्था (Local School units) हैं। वहाँ के राज्यों के पश्चात् काउन्टी ही छोटी इकाई है तथा उसके नीचे अन्य कोई इकाई नहीं। उटा (Utah) को छोड़कर इस प्रकार की व्यवस्था प्राय: दक्षिणी राज्यों में ही है।

अ



ब



काउन्टी, स्थानीय संस्था के रूप में तथा काउन्टी, माध्यमिक इकाई के रूप में भ्रम उत्पन्न न करें इसलिए छात्रों को हम पुन: कहे देते हैं कि जहाँ काउन्टी स्थानीय संस्था के रूप में है वहाँ किसी प्रकार की अन्य माध्यमिक इकाई नहीं है।[1] वैसे प्राय: यह माध्यमिक इकाई स्थानीय तथा राज्य-व्यवस्था के मध्य आती है।

जूलियन बटरवर्थ के अनुसार माध्यमिक इकाई के निम्न गुण हैं––

(१) एक बोर्ड जो माध्यमिक इकाई का प्रतिनिधित्व कर सके।

(२) एक सुपरिन्टेंडेंट जो अपने नीचे की संस्थाओं का योग्यता से नेतृत्व कर सके।

(३) स इकाई की कानून द्वारा स्पष्ट मान्यता होनी चाहिए ताकि उसे अपने कार्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय संस्था के साथ झंझट न करना पड़े।

(४) अपना कार्य करने के लिये पर्याप्त धन की मात्रा।

यह माध्यमिक इकाई बड़े महत्त्व की है और कम से कम ग्रामीण शिक्षण के क्षेत्र में। भविष्य में इस व्यवस्था के कारण लाभ भी होगा तथा केन्द्रीकरण की कमियाँ इससे दूर हो जाएँगी।

राज्यों को विभिन्न इकाइयों के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता

1. Alaxander and Saylor : Secondary Education. P. 142.

है :.(१) स्थानीय संस्थाओं वाले २६ राज्य; (२) टाउन तथा टाउनशिप वाले ९ राज्य; (३) काउन्टी वाले १२ राज्य तथा राज्य में केन्द्रित सत्ता वाला १ राज्य। स्पष्ट है कि बहुत-सी इकाइयों का एक ही राज्य में मेल-जोल पाया जाता है। स्थानीय स्कूल-संस्थाओं की संख्या ६०,००० है।

काउन्टी स्कूल की इकाइयाँ––संयुक्तराज्य अमेरिका में ३००० काउन्टी हैं तथा इनकी सीमा २२ वर्गमील से लेकर २०,१७५ वर्गमील तक की है और जन-संख्या ५० से लेकर ५ लाख तक की है। किसी न किसी रूप में प्रायः सभी राज्यों में स्कूल-व्यवस्था के लिए काउन्टियाँ हैं। धन की मात्रा पर ही काउन्टी की स्कूल-व्यवस्था निर्भर है; राज्यों को काउन्टी स्कूल-व्यवस्था के आधार पर तीन समूहों में बाँटा जा सकता है––

(१) वे राज्य, जो स्थानीय संस्था के रूप में काउन्टी को हस्तक्षेप नहीं करने देते।

(२) वे राज्य, जो टाउन या टाउनशिप को मुख्य इकाई मान कर कुछ अधिकार काउन्टी को भी दे देते हैं। तथा––

(३) वे राज्य, जो काउन्टी को स्कूल-व्यवस्था की मुख्य इकाई मानकर कार्य करते हैं।

प्रथम श्रेणी में न्यू इंग्लैंड के राज्य हैं जहाँ न काउन्टी हैं न काउन्टी पदाधिकारी। द्वितीय श्रेणी में इलीनोइज़ है जो कुछ अधिकार काउन्टी को देता है तथा शेष अपनी अन्य स्थानीय संस्थाओं के हाथ सुरक्षित रखता है, यहाँ काउन्टी का कार्य ग्राम-शिक्षा का निरीक्षण तथा उसके लिए धन-वितरण करना है। तृतीय श्रेणी में काउन्टी-प्रणाली वाले राज्य हैं, इनकी संख्या कुल १२ है।

काउन्टी बोर्ड––प्रायः कुछ काउन्टियाँ एक सर्वोपरि बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स द्वारा एक सुपरिन्टेंडेंट नियुक्त करती हैं जिसका कर्त्तव्य स्कूल के व्यवस्थापकों के साथ कार्य करना है। चाहे शक्तिशाली काउन्टी-व्यवस्था हो या कमज़ोर, किसी न किसी प्रकार का काउन्टी बोर्ड तो वहाँ रहता ही है। मिशीगन राज्य में तो काउन्टी या सुपरवाइजर्स का बोर्ड, स्कूलों के लाथ-साथ सड़क, जेल, प्रकाश इत्यादि का प्रबन्ध भी करता है।

काउन्टी सुपरिन्टेंडेन्ट आफ स्कूल्स––ज्यों-ज्यों राज्यों की शिक्षा के विषय में रुचि बढ़ी, स्कूलों के लिए एक उच्च पदाधिकारी सुपरिटेंडेंट आफ़ स्कूल्स के नाम से नियुक्त होने लगा। विभिन्न राज्यों में भिन्न रूपों से इस पद का विकास हुआ। प्रारम्भ में इसका कार्य क्लर्की तथा सांख्यिकीकरण ही था किन्तु आज गौरव बढ़ने के साथ-साथ इसका कार्य भी जटिल हो गया है। फिर भी यह "राजनीतिक पद" के रूप में प्रायः राज्यों में माना जाता है क्योंकि इस पद पर चुनाव होता है।

चुनाव या नियुक्ति––प्रायः यह दो वर्ष के लिए चुना जाता है किन्तु जहाँ नियुक्ति होती है वहाँ उसकी कार्य-अवधि बढ़ जाती है।

अधिकार तथा कर्त्तव्य––उसके आफिस के द्वारा ही धन का वितरण होता है; उसकी आज्ञा के बिना अध्यापक उस राज्य में पढ़ा नहीं सकता; वह राज्य के कानूनों का

अर्थ बताता है तथा स्थानीय संस्थाओं को उचित परामर्श देता है। वह ग्रामों के अध्यापकों तथा वहाँ के बोर्ड के बीच झगड़ों में मध्यस्थ का कार्य करता है। उसके परामर्श के आधार पर ही स्थानीय संस्थाओं का केन्द्रीकरण (Consolidation) सम्भव है। स्कूलों को वह मूल्यांकित (क्रेडिट) करता है। वैसे प्रत्येक राज्य में उसके अधिकार तथा कर्त्तव्य भिन्न-भिन्न हैं।

ग्राम्य शिक्षा के प्रति उसके विशेष कर्त्तव्य हैं क्योंकि ग्रामों की उन्नति राष्ट्र की उन्नति है; यद्यपि आज अमेरिका में यह प्रवृति है कि स्थानीय छोटी-छोटी इकाइयों को केन्द्रित करके बड़ी इकाइयाँ बनाई जायँ तथा पठन-पाठन का अच्छा प्रबन्ध हो सके, किन्तु फिर भी छोटी-छोटी इकाइयाँ रहेंगी तथा काउन्टी सुपरिन्टेंडेंट का कार्य तो महत्त्वपूर्ण रहेगा ही। आज भी बहुत-से स्थानों पर योग्य अध्यापक, उच्च वेतन, अच्छी पढ़ाई इत्यादि बातें सम्भव नहीं हैं।

टाउनशिप तथा टाउन की इकाइयाँ

टाउनशिप, टाउन से बड़ी किन्तु काउन्टी से छोटी इकाई है। यह काउन्टी की विभक्त इकाई है। प्रायः इसका क्षेत्र ६ वर्गमील का होता है तथा इसकी संख्या २०,००० है। १६४७ के एक्ट के अनुसार प्रत्येक टाउनशिप, जिसमें ५० व्यक्ति थे, उसे एक अध्यापक नियुक्त करने का अधिकार मिल गया था। सन् १८५१ में इंडियाना राज्य ने यह कानून बनाया कि प्रत्येक टाउनशिप में एक स्कूल-डिस्ट्रिक्ट अवश्य होना चाहिए। इसके पूर्व भी पेन्सिल्वानियाँ राज्य में नगरों तथा बड़े ग्रामों को छोड़कर स्कूल-व्यवस्था के लिए टाउनशिपें थीं। ग्राम्य शिक्षा के लिए आज इनका महत्त्व बहुत है। टाउनशिप-व्यवस्था में बहुत से नगरों ने ग्रामों को अपने में मिलाकर और कुछ समुचित स्कूल (Consolidated) स्वतन्त्र स्कूल-डिस्ट्रिक्ट के नाम से अलग कर दिये हैं। यदि सभी प्रतिनिधि केन्द्रीकरण या समुच्चय के लिए मत दें जैसे मिशीगन राज्य में हुआ तो टाउनशिप का जन्म सम्भव है। इलीनोइज़ में बहुत से, टाउनशिपों के हाई स्कूल हैं। इंडियाना में भी बहुत-से टाउनशिपों के स्कूल-डिस्ट्रिक्ट हैं।

व्यवस्था—पूर्ण या आंशिक टाउनशिपों का अपना एक बोर्ड आफ़ एजूकेशन है जिसमें ३ सदस्य समस्त क्षेत्र से चुनकर आते हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में इनके अधिकार भिन्न हैं; प्रायः टाउन स्कूल का प्रिंसिपल या सुपरिन्टेंडेंट वही कार्य करता है जो स्थानीय सुपरिन्टेंडेंट। काउन्टी सुपरिन्टेंडेंट का वह सूक्ष्म रूप है।

न्यू इंग्लैंड के नगर प्रायः भौगोलिक कारणों से स्वतन्त्र हैं तथा उनकी स्कूल की इकाई एक छोटा नगर (टाउन), पड़ोसी समूह तथा जातियाँ ; ग्राम तथा ग्रामीण इलाके हैं। इस टाउन-व्यवस्था से कुछ केन्द्रीकरण (Consolidation) हुआ है तथा विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) के दुर्गुण दूर हुए हैं।

स्कूलों की पुनर्व्यवस्था—(भविष्य की ओर एक चरण) कहना न होगा कि

६०,००० स्कूल-डिस्ट्रिक्ट संयुक्तराज्य अमेरिका की शिक्षा के केन्द्र तथा आधार हैं। इनकी पुनर्व्यवस्था निम्न कारणों से आवश्यक हो गई है : (१) इकाइयाँ प्रायः इतनी छोटी हैं कि वहाँ न अच्छे स्कूल ही हैं और न उनकी आवश्यकता हो है; तथा (२) छोटी इकाइयों में धन की अधिकता ही सम्भव है; और कम धन से रुचि, वयस तथा योग्यता के आधार पर शिक्षा देना भी सम्भव नहीं है। वैसे कुछ इकाइयाँ (न्यूयार्क राज्य में) इतनी बड़ी हैं कि उन्हें छोटा करने की आवश्यकता है। इस पुनर्व्यवस्था से लाभ तो उन्हीं स्थानों को सम्भव है जहाँ स्कूल-डिस्ट्रिक्ट छोटे-छोटे हैं। न वहाँ अधिक छा हैं न अच्छे स्कूल। (१) स्वेच्छा (२) कानून तथा (३) राज्य के समस्त स्कूल-डिस्ट्रिक्ट पुनर्व्यवस्थित (Re-organised) किये जा सकते हैं।

जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था सम्भव न हो वहाँ आपसी ौर पर सहयोग से कार्य किया जा सकता है।

सन् १८३८ में मैसाचुसेट्स ने इस केन्द्रीकरण के कार्य को प्रारम्भ किया था और सहस्रों छोटी इकाइयाँ तब से समाप्त भी हो चुकी हैं फिर भी ६०,००० ऐसी इकाइयाँ आज भी हैं। आज छोटे-छोटे स्कूलों (Red-Brick Schools) के स्थान पर कम्यूनिटी तथा रीजनल उच्च-स्तरीय स्कूल खुल रहे हैं। ये स्कूल उन छात्रों को सहायता देंगे जिन्हें हाई-स्कूल तक न पहुँच सकने के कारण यह शिक्षा मिलना सम्भव न थी। ये कम्यूनिटी स्कूल उच्चस्तरीय हैं तथा इनके कारण सामाजिक व्यवस्था, पठन-सामग्री, छात्रों की संख्या, आने-जाने की सुविधा इत्यादि का ध्यान रखकर पठन-पाठन होता है। इन स्कूलों की इकाइयाँ काउन्टी-व्यवस्था से छोटी होने के कारण स्थानीय समाज के अधिक निकट हैं तथा उसकी भलाई का काम भी अच्छा कर सकती हैं।

चतुर्थ चरण

स्थानीय विद्यालय-नगर (Local School Districts)

रूपरेखा :—

१. स्थानीय विद्यालय-नगर : एक परिचय।
२. स्थानीय विद्यालयों के भद।
३. स्थानीय-बोर्ड ।
४. बोर्ड के सदस्यों की योग्यताएँ।
५. शिक्षा-बोर्ड के कार्य और अधिकार ।
६. स्थानीय विद्यालय-सुपरिन्टेन्डेन्ट ।
—योग्यताएँ, कार्य, अन्य लोगों से सम्पर्क ।
७. उपसंहार ।

ले० : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

स्थानीय विद्यालय-नगर

डॉ० कैन्डेल ने संयुक्तराज्य की शिक्षा- णाली का उचित मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि संयुक्तराज्य में शिक्षा-संगठन तथा शासन, शिक्षा में परम्पराएँ, श्रद्धा तथा शिक्षा के समान अवसरवाले सिद्धान्त पर आधारित, बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार हुआ। अमेरिका और इंगलैंड, दोनों ही देश स्थानीय स्वाधीनता पर सदैव बल देने के पक्ष में रहे हैं, यद्यपि आधुनिक समय में, केन्द्रीय संरक्षण की ओर झुकाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

स्थानीय विद्यालय-नगर उन परम्पराओं में श्रद्धा के परिणाम हैं जो स्वाधीनता की ओर थीं, 'अपना काम अपने द्वारा ही' जहाँ का मूल मन्त्र था। इसीलिए प्रसिद्ध लेखक क्रिस ए० डी० यंग ने इस परम्परा को 'होमरूल' का एक प्रतिरूप माना है। देश के प्रशासन की दृष्टि से यह सबसे छोटी अन्विति है जो अपने क्षेत्र में शिक्षा की देखभाल तथा विकास के लिए उत्तरदायी होती है।

क्रॉफर्ड ग्रीन तथा ए. आर. मीडोज ने स्थानीय विद्यालय-नगर की सुन्दर रूपरेखा खींचने का प्रयास किया है। उनके अनुसार स्थानीय विद्या नगर, सरकार द्वारा विभक्त एक टुकड़ा है। यहाँ के नागरिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षा स्वयं निर्धारित करते हैं। उसका प्रशासन और विकास, उनके चुने ३ प्रतिनिधियों आदि पर ही रहता है। इस प्रकार के स्थानीय विद्यालय-नगर और उपस्थिति-अन्विति से भिन्न होते हैं। जिन नगरों में सभी विद्यार्थी एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ की प्रशासकीय अन्विति, उपस्थिति-अन्विति कहलाती है।

राज्यों में फैले हुए इस प्रकार के स्थानीय विद्यालय-नगरों में प्रशासन एक ही प्रकार से नहीं होता बल्कि १०—१५ प्रकार तक पाये जाते हैं।

१९४१-४२ ई० की गणना के अनुसार संयुक्तराज्य में, स्थानीय विद्यालय-नगरों की संख्या १,१२,७२३ है। सबसे अधिक स्थानीय विद्यालय-नगरों की संख्या इलीनोइज़ राज्य में है, जहां पर वे १२,०२७ हैं और सबसे कम वे डिलावेयर राज्य में हैं जहाँ पर केवल १६ ही हैं। स्थानीय विद्यालय-नगरों के क्षेत्रफल के विषय में भी एक बात नहीं कही जा सकती। इलीनोइज राज्य में ग्रामीण विद्यालय-नगर क्षेत्रफल में ५ वर्गमील हैं जबकि यूटा राज्य में उनका क्षेत्रफल २००० वर्गमील तक है।

यह होते हुए भी कि विधान के दसवें संशोधन से राज्य के हाथ में ही शिक्षा आती है, और राज्य ने स्थानीय प्रशासन को यह भार सौंप रखा है, यह होते हुए भी कि इस तरह का स्थानीय प्रशासन विकेन्द्रीकरण का प्रतीक और जनतन्त्र का प्राण है, इन स्थानीय विद्यालय-नगरों के कारण शिक्षा की प्रगति भी बहुत रुकी है। डॉ० हैन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी इन्हीं स्थानीय विद्यालय-नगरों की प्रधानता है और उनमें तथा नगरों के

विद्यालयों में बड़ी भारी विषमता वर्तमान है। इस विषमता और अवसर की असमानता को लोगों ने कड़ी आलोचना की है।

(२)

स्थानीय विद्यालयों के भेद

हम ऊपर कह आए हैं कि संयुक्तराज्य में स्थानीय विद्यालयों के १० से १५ भेद तक पाए जाते हैं। इन विद्यालयों की भिन्नताएँ बहुत-सी बातों पर आधारित हैं, किन्तु प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

क—प्रशासन।

ख—जन-संख्या।

क— प्रशासन

इस दृष्टिकोण से स्थानीय विद्यालयों में दो प्रकार की अन्वितियाँ दिखाई देती हैं:

१. उपस्थिति अन्विति (Attendance unit);

२. प्रशासकीय अन्विति (Administrative unit)।

जब स्थानीय बोर्ड नगर को कई छोटे क्षेत्रों में बाँट देता है तो इन छोटे क्षेत्रों में केवल एक स्कूल कार्य करता है। यह अन्विति 'उपस्थिति अन्विति' कहलाती है। किन्तु जहाँ इस तरह की एक या अनेक अन्वितियां हों, लेकिन उनका प्रशासन एक ही प्रकार का हो; तो उस पूरे क्षेत्र को 'प्रशासकीय अन्विति' कहते हैं।

ख—जन-संख्या

२५०० से नीची जनसख्या को सामने रखते हुए स्थानीय विद्यालय-नगरों को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं—

अ—ग्रामीण नगर (Rural Districts)

आ—ग्राम-नगर (Village districts)

इ—नगर-नगर (City districts)

ई—कस्बा-नगर (Suburban districts)

अ—ग्रामीण-नगर

क्षेत्र के दृष्टिकोण से सबसे छोटा नगर होता है। यहाँ पर एक शिक्षक वाला विद्यालय पाया जाता है। शिक्षकों की संख्या कभी-कभी तो इतनी कम होती है कि पूरे विद्यालय

1. Generations of local support and local domination of public schools finds the richest nation on the earth denying multitudes of the childrens any educational opportunity whatever, and barding thousands upon thousands of others in dismal and unsanitary hovels, under the tutelage of wretchedly underpaid and negative teachers." Prof. F.H. Swift, quoted by Hans: Compacetive education.

में केवल एक ही शिष्य होता है। कहीं-कहीं ग्रामीण प्रारम्भिक विद्यालयों में दो शिक्षक भी पाए जाते हैं। आज के युग में, अनेकों दुर्गुणों के कारण इन विद्यालयों का लोप होता जा रहा है।

स्थानीय निवासी अपना शिक्षा-बोर्ड स्वयं चुनते हैं। इस बोड को यह अधिकार होता है कि वह शिक्षक का चुनाव स्वयं करे ताकि बच्चों को शिक्षा का समुचित प्रबन्ध हो सके।

आ—ग्राम-नगर

क्षेत्र की तथा जनसंख्या की दृष्टि से गाँव-नगर, ग्रामीण-नगर से, बड़ा होता है। गाँव का विद्यालय बड़ा होता है। उसमें एक इमारत भी हो सकती है। प्रायः एक से अधिक शिक्षक होते हैं।

विद्यालयों का प्रशासन भी अधिक सुगठित होता है। शिक्षा-बोर्ड एक अधिकारी को नियुक्त करता है। इस अधिकारी को सुपरिन्टेन्डेन्ट कहते हैं। इसको सहायता के लिए एक प्रधान शिक्षक या प्रिंसीपल हो सकता है।

इ—नगर-नगर

नगर के जितने भी शिक्षा-संगठन हैं, उनमें सबसे अधिक प्रगतिशिल नगर-नगर है। इस प्रगतिशीलता का कारण है कि नगर-नगर एक ठोस क्षेत्र होता है और फिर सुयोग्य शिक्षा-नेताओं का इसे सहयोग प्राप्त होता है।

नगर छोटे भी हो सकते हैं जहाँ की जनसंख्या केवल २५०० हो और न्यूयॉर्क नगर स्कूल-नगर के समान बड़े भी, जिसकी विद्यार्थी-संख्या दस लाख से भी अधिक है।

क्षेत्र-विकास के कारण प्रशासन भी अधिक विस्तृत हो जाता है। जनता शिक्षा-बोर्ड का चुनाव करती है। और शिक्षा-बोर्ड एक अधिकारी या सुपरिन्टेन्डेन्ट का चुनाव करता है। सुपरिन्टेन्डेन्ट सारे विद्यालयों के प्रशासन तथा देखभाल के लिए तीन विभाग बनाता है :

(१) व्यापार—बजट आदि की तैयारी;
(२) शैक्षणिक—निरीक्षण तथा खोज के कार्य;
(३) पाठ्यक्रम—शिक्षण तथा शिक्षा : सभी स्तरों पर।

इस प्रकार सारा कार्य अधिक सुगठित रूप से चलता है।

सयुक्तराज्य की शिक्षा के बारे में एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि सर्वत्र भिन्नता मिलेगी। अनुकरण का विरोध होता है। उपर्युक्त कथन, जो नगर-नगर के बारे में है; केवल कैलीफोर्निया राज्य के सेन्टा मॉनिका विद्यालय के विषय में है।

ई—कस्बा-नगर

विद्यालयों का यह नगर आज बड़ी उन्नति पर है। घने बसे शहरों में, जहाँ का जीवन अत्यन्त महँगा है, करों की भरमार है, उन से हटकर पास ही में, इस कार के नगर लोकप्रिय बनते जा रहे हैं।

शिक्षा-व्यवस्था भी इनकी प्रगतिशील है। कभी उसका आधार ग्रामीण, कभी गाँव तथा कभी नगर की शिक्षा-व्यवस्था जैसा हो सकता है। कोई एक विशेष व्यवस्था का आधार मान्य नहीं है।

(३)

स्थानीय शिक्षा-बोर्ड[1] (Local Board of Education)

संयुक्तराज्य के सभी विद्यालयों का प्रबन्ध वहीं के जन-प्रतिनिधियों के हाथ में है। ये जन-प्रतिनिधि, यह आवश्यक नहीं कि शिक्षाविद् ही हों; उन्हें मात्र जन-समर्थन प्राप्त हो। इस प्रकार के प्रतिनिधियों की संख्या लगभग २,२५,००० है।

शिक्षा-बोर्ड का चुनाव, आकार और अवधि

किसी भी बोर्ड में कितने सदस्य हों या उन सदस्यों का कार्य-काल कितना हो, इन प्रश्नों का कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। आधुनिक प्रवृत्ति इस बात की ओर है कि बोर्ड में चुने हुए अधिक से अधिक नौ सदस्य रखे जाएँ।

सदस्यों के चुनाव के बारे में कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं। मुख्य निम्न हैं—

अ—प्रार्थनापत्र द्वारा चुनाव,

आ—प्रारम्भिक चुनाव,

इ—व्यक्तिगत घोषणा,

ई—नागरिक-कमेटी सभा द्वारा,

उ—जन-सभा द्वारा,

ऊ—विद्यालय-नगरसभा द्वारा।

साधारणतया सदस्य चुने ही जाते हैं यद्यपि उन्हें मेयर, काउन्सिल, काउन्टी कमिश्नर द्वारा भी चुना जा सकता है।

विद्यालय-बोर्ड के सदस्यों का कार्य-काल भी अलग है। एक बोर्ड में भी सदस्यों का कार्य-काल भिन्न हो सकता है। सामान्यतः यह अवधि सात वर्ष भी होती है।

(४)

बोर्ड के सदस्यों की योग्यताएँ

बोर्ड का कोई भी सदस्य, जो २१ साल से ऊपर की आयु वाला, कानूनी मतदाता तथा विद्यालय-नगर का निवासी हो, निम्न योग्यताएँ रखता हो—

---

1. इन बोर्डों को कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है :—

1. The Selectmen.
2. The Board of Education.
3. The School Board.
4. The Board of Trustees.
5. The School Committee.
6. The county Board of Education.
7. The Township Board of Education.

१. विद्यालयों में रुचि रखता हो,
२. विद्यालयों में उसके बच्चे पढ़ते हों,
३. विद्यालयों के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण हो,
४. नगर की आर्थिक स्थिति का ज्ञान रखता हो,
५. विद्यालयों के मामलों को बुद्धिमत्तापूर्वक विचार सके,
६. पढ़ा-लिखा हो,
७. व्यक्तिगत तथा जनहित-कार्यों को करने की क्षमता हो,
८. कर-दाता हो,
९. समाज की भलाई देखने वाला, चरित्रवान् व्यक्ति हो,
१०. समाज पर जिसे गर्व हो,
११. जिस पद पर हो, उसके लिए समय तथा शक्ति दे सकता हो,
१२. सहयोगी पुरुष हो।

(५)

शिक्षा-बोर्ड के कार्य तथा अधिकार

शिक्षा-बोर्ड एक ऐसा क्रियाशील समूह है जो सदैव शिक्षा की नीति तथा उसका मूल्यांकन करता है। इस बोर्ड का प्रमुख कार्य है सुपरिन्टेन्डेन्ट का निर्वाचन, जो प्रशासक अफसर होता है। शिक्षा-बोर्ड को, राज्य की ओर से बड़े अधिकार प्राप्त होते हैं और यदि कहीं आवश्यकता पड़े तो वह स्वयं भी अपना नियम बना सकता है।

बोर्ड में एक प्रेसीडेन्ट, एक सेक्रेटरी या क्लर्क होता है। प्रेसीडेन्ट सभाओं का सभापति होता है और मन्त्री कोषाध्यक्ष का भी कार्य करता है।

बोर्ड की जो सभा होती है, उसके विषय में आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि सभी सदस्य भाग लेते हैं और तत्सम्बन्धी बातें सभी सदस्यों को बता दी जाती हैं।

शिक्षा-बोर्ड विद्यार्थियों, शिक्षकों, समाज, देश तथा राज्यों की सरकारों से भी सम्पर्क रखते हैं। समय-समय पर सभाएँ होती हैं। इनमें विद्यार्थी तथा शिक्षक भी सम्मिलित होते हैं। टेलीविज़न से विशिष्ट प्रोग्राम प्रसारित किये जाते हैं। इस प्रकार इन का सम्पर्क जीवित सम्पर्क है। इसके अतिरिक्त विद्यालय-बोर्डों के संगठन भी हैं। कुछ संगठन राज्य तथा देश-व्यापी तक हैं।

(६)

स्थानीय विद्यालय सुपरिन्टेन्डेन्ट

योग्यताएं—

१. कम से कम एम० ए० पास हो,
२. उत्तरी केन्द्रीय संघ (North Central Association) के अनुसार उसे दो साल का शिक्षण या निरीक्षण अनुभव भी होना चाहिए,

३. प्रशिक्षण-शिक्षा, शिक्षा की नई योजनाओं आदि से उसका खूब परिचय हो,
४. सच्चरित्र, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से सम्पन्न, कुशल वक्ता, सन्तोषी, नीति-पटु एवं उचित निर्णयदाता हो,
५. स्वार्थों से दूर, विद्वान्, परिश्रमी, मिलनसार, कुशल कार्यवाहक हो,
६. शिक्षा-दर्शन से भली भाँति परिचित हो,
७. स्वाधीन विचारक हो,
८. कुशल नेता हो।

कार्य—

१. शिक्षा-बोर्ड का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी,
२. शिक्षा की योजना बनाना तथा प्रगति का मूल्यांकन करना,
३. शिक्षा का संगठन करना,
४. शिक्षा-क्रम को सरल करने को अपने नीचे के अधिकारियों को, विद्यालय की इमारतों आदि की उचित देखभाल करना,
५. जन-सम्पर्क रखने के लिए सूचना तथा सलाह देने का कार्य करना,
६. समस्त योजनाओं, तथा लोगों के सहयोग से समन्वित रूप से आगे बढ़ना,
७. सर्वत्र प्रजातन्त्रीय दृष्टिकोण रखना।

और लोगों से सम्पर्क

जो उत्तरदायित्व शिक्षा सुपरिन्टेन्डेन्ट को सौंपा गया है, उसे सुचारु रूप से पूरा करने तथा शिक्षा के वास्तविक महत्त्व को समझते हुए और छोटे शिशुओं को कल के एक सफल नागरिक के रूप में देखने के लिए, यह नितान्त आवश्यक है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट का दूसरे लोगों से भी उचित सम्पर्क हो क्योंकि, अलग रहकर अकेले ही वह अपने उत्तरदायित्व को उचित रूप से नहीं निभा सकता। अतः निम्नांकित समाजों तथा समूहों से सम्पर्क रखना उसके लिए आवश्यक है—

अ—शिक्षा-बोर्ड,
आ—स्थानीय प्रबन्ध-अधिकारीवर्ग,
इ—शिक्षकवर्ग,
ई—शिष्यवर्ग,
उ—समाज,
ऊ—अन्य सुपरिन्टेन्डेन्ट,
ए—विद्यालय प्रशासक—अमेरिकन संघ American Association of School Administration.

तृतीय अध्याय

रूपरेखा :—

प्रथम चरण :—पूर्वप्राथमिक शिक्षा ।

द्वितीय चरण :—प्राथमिक शिक्षा ।

तृतीय चरण :—माध्यमिक शिक्षा ।

चतुर्थ चरण :—उच्च शिक्षा ।

पंचम चरण :—प्रौढ़ शिक्षा ।

षष्ठ चरण :—असाधारण बालकों की शिक्षा ।

सप्तम चरण :—प्रशिक्षण-शिक्षा ।

प्रथम चरण

पूर्वप्राथमिक शिक्षा

रूपरेखा :—

१. भूमिका—शिक्षा का स्वभाव।

२. पूर्वप्राथमिक शिक्षा।

अ—आवश्यक अंग।

आ—मनोविज्ञान का प्रभाव।

इ—प्रवेश और समाप्ति की आयु।

ई—इतिहास ।

३. पूर्वप्राथमिक शिक्षा के अंग—घर, नर्सरी विद्यालय, किण्डरगार्टन, विद्यालय।

४. घर—

क—गृह-शिक्षा का महत्त्व।

ख—पितर और बालक।

ग—पितर-शिक्षा।

५. नर्सरी विद्यालय—

क—परिचय।

ख—भेद।

ग—नर्सरी-शिक्षा के उद्देश्य।

घ—लाभ।

६. किण्डरगार्टन विद्यालय—

क—नर्सरी तथा किण्डरगार्टन।

ख—भेद।

ग—किण्डरगार्टन शिक्षा के उद्देश्य।

घ—शिक्षा-योजना।

ङ—आज का किण्डरगार्टन विद्यालय।

७. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिह चौहान

(१)

शिक्षा जीवनपर्यन्त होती है, क्योंकि जीवन कभी पूर्ण नहीं होता; लेकिन पूर्णत्व के लिए निरन्तर प्रयत्न सदैव उसे गतिशील रखता है। शिक्षा भी, इसीलिए गतिशील तथा विकासमयी है। यदि शिक्षा, जीवन के त्येक क्षण में हमें समर्थ करने में असमर्थ रहे तो वह अनुपयुक्त शिक्षा है। अमेरिकन शिक्षा अत्यन्त व्यापक है। वह गर्भावस्था से मनुष्य की अन्तिम श्वास तक चलती है। निरन्तर विकासमयी होने के कारण वह एक उपयुक्त शिक्षा है।

(२)

शिक्षा के चार प्रमुख स्थानों—पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, तथा उच्च-स्तरीय में,—पूर्वप्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्न बातें आती हैं—

अ—बच्चे की पूर्वोत्पत्ति-काल की रचना तथा देखभाल;

आ—जन्म के पश्चात् की रक्षा तथा देखभाल;

इ—बच्चे का आरम्भिक पोषण तथा शिक्षा।

पूर्वप्राथमिक शिक्षा का इतिहास पुराना नहीं है। यह कहना असत्य न होगा कि बाल-मनोविज्ञान तथा शिक्षा-मनोविज्ञान के परिणामों तथा अनुसन्धानों के कारण, यह आवश्यक समझा गया कि बालकों की शिक्षा छः सात वर्ष से आरम्भ न करके उनके जन्म और उससे भी पहले से आरम्भ करनी चाहिए।

मनोविज्ञान ने हमारे सामने स्पष्ट शब्दों में निम्न तथ्य रखे हैं—

१. जीवन-निर्माण के लिए, प्रारम्भिक वर्ष ही सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं।
२. बच्चे का जीवन मुख्य रूप से बीजारोपण के समय से ही आरम्भ हो जाता है।
३. बच्चे के जीवन के प्रथम छः वर्ष शेष सब वर्षों से अधिक महत्त्व के होते हैं। एक सफल जीवन में जो सुन्दर आदतें दिखाई देती हैं, उनकी नींव इसी काल में पड़ा करती है।
४. जीवन के प्रति आधारभूत दृष्टिकोण की नींव भी इसी काल में पड़ती है अतः यह परमावश्यक है कि घर तथा स्कूल का सम्पर्क अत्यन्त सुव्यवस्थित तथा संगत हो।

इन तथ्यों से प्रत्यक्ष है कि हम बच्चे के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काल को उस तरह से नहीं छोड़ सकते जैसे कि अब तक छोड़ते रहे। यही कारण है कि विश्व में प्रायः सभी प्रगतिशील देशों में पूर्वप्राथमिक शिक्षा का श्रीगणेश हो चुका है।

पूर्वप्राथमिक शिक्षा कब आरम्भ, और कब समाप्त होनी चाहिए ? इस विषय में विश्व के प्रमुख देश एकमत नहीं हैं, यद्यपि अधिकांश देश बालक के आरम्भिक छः वर्षों तक मानते हैं, और शिक्षा आरम्भ करने के विषय में उनका मत है कि उसे द्वितीय वर्ष में आरम्भ किया जाय। इन वर्षों तथा उनकी भिन्नताओं के विषय म हम विश्व के प्रमख

देशों के आंकड़े नीचे देते हैं और इस बात को प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करेंगे कि किस देश में पूर्वप्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बालकों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है।

देश	शिक्षा-काल	शिक्षा-क्रम
इंगलैण्ड	२—५ वर्ष	नर्सरी, किण्डरगार्टन या घर।
फ्रांस	२—६ वर्ष	इकोल मैटर्नल, व्यक्तिगत किण्डरगार्टन या घर।
जर्मनी	२—६ वर्ष	किण्डरहोम, किण्डरगार्टन या घर।
इटली	२—६ वर्ष	२—६ वर्ष स्कोला मैटर्नी; २-३ वर्ष नर्सरी।
रूस	—८ वर्ष	—३ वर्ष—नर्सरी।
		३—८ वर्ष किण्डरगार्टन तथा पूर्वविद्यालय संस्थाएँ।
अमेरिका	२—६ वर्ष	२—४ वर्ष नर्सरी } या घर ४—६ वर्ष किण्डरगार्टन }

इस सारिणी से स्पष्ट है कि इतली और रूस को छोड़ कर शेष सभी देशों में पूर्वप्राथमिक शिक्षा व्यक्तिगत है, अनिवार्य नहीं। इसका परिणाम उचित नहीं निकल सकता क्योंकि,

१. या तो बच्चे घर पर रहेंगे क्योंकि वह नर्सरी या किण्डरगार्टन विद्यालयों में पढ़ नहीं सकते—आर्थिक अभाव के कारण।

२. या बच्चे घर पर रहेंगे क्योंकि वह नर्सरी या किन्डरगार्टन से भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं—बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण।

दोनों ही दशाओं में अवसर की समानता का सिद्धान्त नहीं ठहरता, उससे अवसरों की विषमता बढ़ती है।

विश्लेषण के आधार पर और बातें कहते हुए, इतना तो कह ही सकते हैं कि विश्व के सभी उन्नतिशील देश पूर्वप्राथमिक शिक्षा के मूल्य को मान चुके हैं और ऐसे विद्यालयों का बन्ध कर दिया गया है। अपना देश इस दिशा में बहुत पीछे है। यहाँ पूर्वप्राथमिक शिक्षा के महत्त्व की चेतना भले ही हो सकती है परन्तु प्रयत्न बिलकुल नहीं के बराबर है।

इस बात के कहने में अत्युक्ति न होगी कि पूर्वप्राथमिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान् रूसो का एक बड़ा हाथ रहा है। रूसो ने बच्चों की शिक्षा में प्रकृति को सबसे अधिक महत्त्व दिया। मातृ-विद्यालय (Ecols maternelles) खोले गये। इंगलैण्ड में ऑवेन, ग्रोव्ज तथा मेरो आदि ने सराहनीय कार्य किए। जर्मनी में फॉवेल ने सफल नेतृत्व किया। १८३७ ई० में फ्रॉवेल ने जर्मनी में, विश्व का प्रथम किन्डरगार्टन खोला। अमेरिका में प्रथम किण्डरगार्टन विसकाउन्सिन राज्य के वाटरटाउन में १८५६ में खोला गया। प्रथम नर्सरी विद्यालय अमेरिका में १६१६ ई० में खोला गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आज पूर्वप्राथमिक शिक्षा का महत्त्व संसार जानने लगा है। मनोविज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन के प्राथमिक वर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और माँ-बाप भी समझने लगे हैं कि सफल नागरिक बनाने के लिए बच्चे का समाजीकरण स्वस्थ होना चाहिए। अमेरिका जैसे देश में एक यह भी समस्या है कि बालक के विकास के लिए साथी और खेल के मैदान घर में प्राप्त नहीं हो सकते। माँ तथा बाप को काम पर भी जाना है अतः बच्चे की उचित देखभाल करना एक बड़ी समस्या है। कलयुगीन इस समस्या ने नर्सरी स्कूलों को जन्म दिया है और उनका विकास किया है।

संयुक्तराज्य में प्रथम नर्सरी विद्यालय १९१९ ई० में स्थापित हुआ। किन्तु १९३३ तक इन विद्यालयों की संख्या ३०० के आस-पास जा पहुँची। तब से इस दिशा में बड़ी आशातीत उन्नति हुई है और उसने पूर्वप्रारम्भिक शिक्षा को भली भाँति प्रभावित किया है।

(३)

जैसा कि हम आरम्भ में कह आये हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के तीन मुख्य अंग हैं :—

क—घर;

ख—नर्सरी विद्यालय;

ग—किंडरगार्टन विद्यालय।

(४)

क—घर

शिशु का प्रथम विद्यालय घर ही होता है। यहीं पर आधारभूत आदतें पड़ती हैं और विकास के साथ मजबूत होती चलती हैं। माता-पिता ही बालक के प्रथम शिक्षक हुआ करते हैं। अतः यह परम आवश्यक है कि माँ-बाप—दोनों को अपने कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। बच्चे को सुन्दर आदतें किस प्रकार डाली जानी चाहिए—उनका जीवन में क्या महत्त्व होता है? बच्चे की भावनाएँ उसके जीवन-विकास को किस तरह नियन्त्रित करती हैं? इन भावनाओं को किस प्रकार स्वस्थ रखा जा सकता है? आदि ऐसी बातें हैं जिनका पूरा ज्ञान माता-पिता को होना चाहिए। किन्तु क्या सभी माँ-बाप इन बातों को जानते हैं? नहीं, इसीलिए, माँ-बाप की शिक्षा परम आवश्यक है। घर के कुशल माँ-बाप, जो बच्चे को ठीक रास्ते पर ले जा सकते हैं, वे किसी भी योग्य शिक्षक से अधिक आवश्यक तथा मूल्यवान् हैं। इस प्रकार की शिक्षा का परम उद्देश्य तो 'बालक' ही है, किन्तु प्रत्यक्ष उद्देश्य 'माँ-बाप' ही ह।

इस प्रकार की शिक्षा कब से आरम्भ करनी चाहिए? उस समय नहीं जब बालक जन्म ले चुका, हो बल्कि बालक के जन्म से पहिले, ठीक विवाह के पश्चात्। इसके साथ ही वे माँ-बाप, जिनके अब तक कई बच्चे हो चके ह, उन्हें भी स लाभ से वंचित नहीं रखना चाहिए।

इस प्रकार की शिक्षा राष्ट्र के विकास में जो महत्व रखती है, संयुक्तराज्य उसे भलीभाँति समझता है और इसीलिए माँ-बाप को वहाँ शिक्षा प्रदान करने का काफी अच्छा प्रबन्ध है। विभिन्न संस्थाएँ तथा संघ इस दिशा में बड़े उत्साह के साथ कार्य करते हैं, फिर भी इस प्रकार की सहायता अभी बहुत अधिक चाहिए। प्रमुख संस्थाएँ, जो इस दिशा में कार्य करती हैं, निम्नलिखित हैं—

अ—माता-पिता-शिक्षक संघ (Parent Teacher Association), यह जनता का ही संगठन है।

आ—राज्यों के स्वास्थ्य-विभाग।

इ—विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा अनुचालित बहुत से अनुसन्धान-केन्द्र तथा चिकित्सा-गृह।

(५)

ख—नर्सरी शिक्षा

संयुक्तराज्य में नर्सरी तथा किण्डरगार्टन विद्यालयों को चले हुए अधिक दिन नहीं हुए। देश के अधिकांश प्रौढ़ लोग कभी इन विद्यालयों में नहीं गए।

नर्सरी विद्यालय बच्चों का अपना घर न होते हुए भी घर ही है। वहाँ बच्चे रहते हैं और उनकी सारी देख-भाल, नियमित रूप से खान-पान, पेशाब-पाखाना, का उचित ध्यान रखा जाता है। आरम्भ से ही अन्य बच्चों के साथ रखकर उन्हें समाजीकरण के रास्ते पर, बिना किसी पक्षपात के, लाने का महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किया जाता है।

शिशुओं को ही इस विद्यालय में लिया जाता है। फ्रान्स, रूस, जर्मनी आदि देशों में नर्सरी-शिक्षा उन बालकों को दी जाती है, जो तीन साल की आयु से कम होते हैं, किन्तु संयुक्तराज्य में इन शिशुओं को चार साल की आयु तक रखा जाता है।

नर्सरी-शिक्षा, संयुक्तराज्य में, हमें दो रूपों में प्राप्त होती है—

अ—दिवस नर्सरी—वे विद्यालय हैं, जो शिशु को केवल दिन में ही अपने पास रखते हैं। सन्ध्या होते ही, माँ-बाप उन्हें अपने घर ले जाते हैं। इन विद्यालयों को 'दिवस नर्सरी' (Day Nursery) के नाम से पुकारते हैं। ऐसे विद्यालय विशेषतः उन माताओं के लिए होते हैं, जो दिन में अपने काम पर जाने के कारण, बच्चे को अपने पास नहीं रख सकतीं।

आ—नर्सरी विद्यालय—१८ महीने की आयु से ४ वर्ष तक के बच्चों के लिए होते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नर्सरी विद्यालय बच्चे के आरम्भिक विकास में बड़े सहायक होते हैं। इस विद्यालय को हम किंडरगार्टन (शिशु-उद्यान) का निम्नगामी विकास भी मान सकते हैं, क्योंकि किंडरगार्टन में तो बच्चों पर चार अथवा तीन साल के पश्चात् ध्यान दिया जाता है, किन्तु युग की समस्याओं को देखते हुए, उन पर और

भी पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरे छोटी आयु से ही घर से दूर के वातावरण में रहकर वह अपने साथियों के साथ रहना सीखते हैं। सहनशीलता (Tolerance) तथा सहयोग की शिक्षा उन्हें अपने-आप स्वाभाविक रूप से मिलती रहती है।

नर्सरी विद्यालयों के कई रूप संयुक्तराज्य में पाए जाते हैं——

१. **प्रारम्भिक विद्यालय के अन्तर्गत नर्सरी**——इस प्रकार का क्रम अधिक उपयुक्त दिखाई देता है।
२. **नर्सरी तथा माध्यमिक विद्यालय**——जूनियर हाई स्कूल की आयु वाले लड़के और लड़कियाँ दोनों ही छोटे-छोटे शिशुओं की देखभाल में रुचि लेते हैं। वही शिशुओं की देखभाल करते हैं।
३. **प्रारम्भिक शैशवीय शिक्षा की नवीन प्रशासकीय अन्विति का एक भाग नर्सरी विद्यालय**——नर्सरी किंडरगार्टन तथा प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए बहुत से शिक्षा-विशेषज्ञ एक अन्विति के रूप में काम करते हैं।
४. **स्वाधीन नर्सरी विद्यालय**——व्यक्तिगत तथा सरकारी दोनों ही प्रकार के वित्तीय सहायता को ध्यान में रखते हुए नर्सरी तथा किंडरगाटन विद्यालयों के निम्न तीन प्रकार पाए जाते हैं——

अ——सरकारी——स्थानीय, राजकीय, तथा संघीय। संख्या बहुत कम है।
आ——धार्मिक।
इ——व्यक्तिगत।

नर्सरी शिक्षा के उद्देश्य

१. व्यक्ति के लिए सम्मान——समूहों में रहते हुए शिशुओं की आवश्यकताएँ तथा रुचियाँ ही, इन विद्यालयों के पाठ्यक्रमों की आधार-शिलाएँ हैं।
२. स्वाधीन, निर्भय तथा रचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना। आधुनिक सुसज्जित नर्सरी विद्यालय शिशुओं की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनमें शिशु, अनुसन्धान तथा प्रयोग के सहारे समस्याओं का निदान करना सीखता चलता है।
३. समस्याओं के निदान तथा निर्णय करने म सहयोग पर आधारित प्रयत्नों पर बल दिया जाता है।

नर्सरी-शिक्षा के लाभ

१. समृद्ध वातावरण के शारीरिक प्रभाव——स्वास्थ्य तथा चरित्र-निर्माण।
२. समृद्ध वातावरण के मानसिक प्रभाव——प्रौढ़ लोगों से सम्पर्क, जो शिश के प्रश्नों का उचित समाधान करते हुए उसकी रुचि का विकास करने मे सहायता करते हैं।

३. सामाजिक परिपक्वता का लाभ—प्रौढ़ लोगों के सुन्दर सामाजिक व्यवहारों, आदतों तथा कार्यों से बच्चे प्रतिपल सुन्दर बातें सीखते चलते हैं ।
४. समृद्ध संवेगात्मक जीवन—घर के तनाव तथा कलहपूर्ण वातावरण से मुक्ति ।
५. घर की प्रशंसा में विकास—खिलौनों आदि में रुचि-विकास के आधार पर ।

(६)

ग—किण्डरगार्टन शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहिले का काल किण्डरगार्टन शिक्षा का काल है। इस विद्यालय में आने वाले शिशु की आयु संयुक्तराज्य में चार साल तथा रूस में तीन साल है। उसी प्रकार किण्डरगार्टन शिक्षा अमेरिका में छः वर्ष की आयु में समाप्त होती है, इंगलैण्ड में पाँच वर्ष की आयु में, जर्मनी में छः वर्ष की आयु में, फ्रांस में भी छः वर्ष की आयु में, रूस में आठ वर्ष की आयु में (किन्तु इसमें पूर्वविद्यालय-शिक्षा भी सम्मिलित है) । संयुक्तराज्य में कुछ ऐसे उप-किंडरगार्टन विद्यालय भी हैं जो शिशु को और भी कम आयु में प्रविष्ट कर लेते हैं।

किण्डरगार्टन की तुलना में, नर्सरी विद्यालय कम आयु वाले शिशुओं को लेता है। प्रायः इनकी आयु २ से ४ वर्ष तक होती है। ये विद्यालय पूरे दिन का प्रोग्राम लेकर चलते हैं। घरों से अत्यन्त निकट सम्पर्क रखते हैं क्योंकि बच्चा छोटा होता है, माँ-बाप की शिक्षा के लिए अधिक सुविधाएँ जुटाते हैं। बच्चों को खाने, सोने, नहाने आदि की आदतों पर विशष ध्यान देते हैं। आत्म-संयम की शिक्षा अधिक देते हैं। प्रति शिक्षक कम बच्चे रखते हैं किन्तु सामग्री अपेक्षाकृत कम ही उनके पास होती है।

जैसे ही बच्चा नर्सरी से किण्डरगा न विद्यालय में पदार्पण करता है, उसके अनुभवों के जगत् का विस्तार होता चलता है। नर्सरी तथा किण्डरगार्टन दोनों ही में बच्चे के विकास की रिपोर्ट रहा करती है साथ ही बच्चे को उस शिक्षा-दर्शन का सुन्दर स्वाभाविक ज्ञान कराया जाता है जो उसको प्रौढ़-शिक्षा तक निरन्तर चलता रहता है।

किण्डरगार्टन विद्यालयों के भेद

पाठ्य-विधि के अनुसार किण्डरगार्टन विद्यालय चार रूपों में हमारे सामने आते हैं—

क—फ्रोबेलीय ।

ख—मान्टेसरीय ।

ग—प्रगतिशील ।

घ—कट्टरपंथी (Conservative)

नाम कुछ भी अथवा कितने भी हों, किन्तु जो रूप अत्यन्त लोकप्रिय है, वह वही है जो चार से छः वर्ष की आयु तक सम्पूर्ण शिक्षा देने का प्रयत्न करता है और शिक्षा ो

सम्पूर्ण बनाने में जो घर, नर्सरी तथा अन्य संस्थाओं से घनिष्ठ सम्पर्क, सहयोग बनाए रखता है।

किण्डरगार्टन विद्यालय प्रायः उन स्थानों में पाये जाते हैं जिनकी जनसंख्या २,५०० या इससे अधिक है। ग्रामीण बस्तियों की ओर भी किण्डरगार्टन पहुँचने लगे हैं। किन्तु अभी तक ऐसे विद्यालयों की देश में बहुत कमी है क्योंकि देश के पाँच वर्ष वाले ५० प्रतिशत तथा छः वर्ष की आयु वाले ७० प्रतिशत बालक ही इन विद्यालयों में हैं।

किण्डरगार्टन शिक्षा के उद्देश्य

किण्डरगार्टन शिक्षा के उद्देश्य, राष्ट्रीय शिक्षा संघ (National education Association) के अनुसार सात हैं—

१. बच्चों का स्वास्थ्य;
२. उनकी रक्षा;
३. दूसरों के होते हुए भी स्वयं कार्य करने की प्रवृत्ति;
४. समूहों में दूसरों के साथ, कार्य करने की विधियाँ;
५. अन्य बालकों तथा प्रौढ़ों से सम्पर्क के लिए विस्तृत सुविधाएँ;
६. अनुभवों की बहुलता जो उनकी रुचि और रुझान को व्यक्त करे;
७. प्रारम्भिक शिक्षा की प्रथम कक्षा में जो वह पढ़ने, लिखने तथा हिसाब का काम करेंगे उसके लिए पहिले से तैयार होना।

किण्डरगार्टन शिक्षा-योजना

१. किण्डरगार्टन शिक्षा-योजना लचकदार होती है, जड़ नहीं। उसके निश्चित विषय नहीं होते।
२. सीखने का सिद्धान्त 'करके सीखना' है। बच्चे स्वयं कार्य करते हैं, वस्तुएँ बनाते हैं, पर्यटनों पर जाते हैं, कहानी सुनते हैं और गाते हैं।
३. पा यक्रम सदैव शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास के आधार पर बनाया जाता है।
४. तत्परता की शिक्षा।
५. अनुभव-समृद्धि—बोलने के शब्दकोष की वृद्धि, बोलना सिखाना, शब्दोच्चारण पर बल, पुस्तकों में चि उत्पन्न करना, लिखने में सुविधा उत्पन्न करने के लिए, चित्रकारी आदि को प्रोत्साहन आदि।

आज का किण्डरगार्टन विद्यालय

किण्डरगार्टन की संख्या में वृद्धि, शिशु-संख्या की वृद्धि की तुलना में, बहुत ही कम रही है। परिणाम यह हुआ है कि किण्डरगार्टन का आकार बढ़ गया है।

बहुत से विद्यालयों में माँ-बाप से सम्पर्क रखने के लिए विशष कायक्रम समाविष्ट कर दिए गए हैं।

शिक्षा में सम्मिलन की ओर झुकाव है जिसमें किण्डरगार्टन, नर्सरी तथा प्रारम्भिक शिक्षा की प्रथम दो या तीन कक्षा सम्मिलित हैं। किण्डरगार्टन अलग और स्वाधीन रहें, यह प्रवृत्ति तेज़ी से कम होती चली जा रही है ।

रचनात्मक आत्मविकास की ओर अत्यन्त बल दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम म इसीलिए चित्र, संगीतकलाओं का काफी प्रचलन है।

शिक्षा-साधनों में ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन, फोटोग्राफ आदि का खूब प्रयोग होने लगा है। इससे 'माँ-बाप' से सम्पर्क स्थापित करना भी सरल हो गया है।

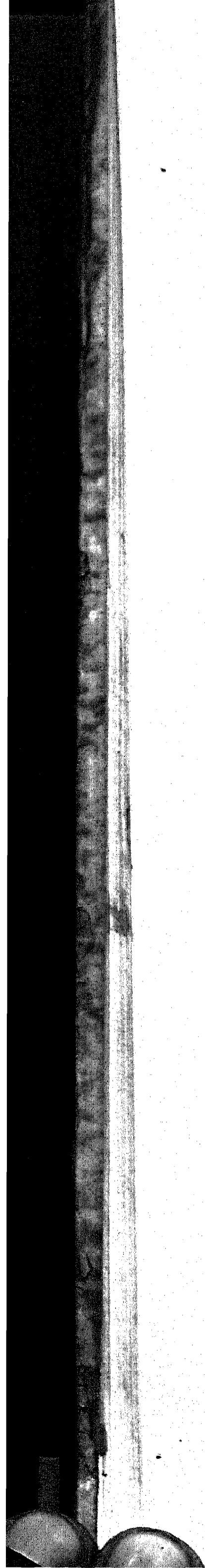
द्वितीय चरण

प्राथमिक शिक्षा

रूपरेखा :--

१. प्राथमिक शिक्षा--महत्त्व तथा राष्ट्र-विकास में योग।
२. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार ।
३. प्राथमिक शिक्षा के ता--ऐतिहासिक विकास।
४. प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य।
५. ाथमिक शिक्षा के भेद ।
६. ाथमिक शिक्षा- ोजनाएँ।
७. प्राथमिक शिक्षा : आज।
८. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान



(१)

किसी भी देश के नागरिकों का चरित्र-निर्माण जहाँ तक शिक्षा पर आधारित है, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा वह एक बहुत बड़े भाग तक निर्मित होता है। अच्छे राष्ट्र-निर्माण के लिए अच्छे प्राथमिक विद्यालय होना वैसे ही आवश्यक है जैसे कि अच्छे अनाज के लिए अच्छी पृथ्वी तथा खाद। प्राथमिक शिक्षा सभी देशों में प्रायः अनिवार्य है। देश के सभी छोटे-छोटे बालक विद्यालयों में प्रवेश करते हैं ताकि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय, ऐसी बातें सिखाई जाएँ, ऐसी आदतें डाली जाएँ कि वे देश तथा विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध हों। उनका उचित समाजीकरण किया जाय तथा साथ ही उनके खेल-कूद के जीवन में पढ़ना-लिखना लाया जाय। घर के स्वच्छन्द और प्यार के जीवन में अनुशासन और परिश्रम के कार्य आरम्भ किये जायँ।

इन प्राथमिक विद्यालयों में आये सभी छात्रों के सामने ये समस्याएँ एक-सी नहीं होतीं। बहुत से ऐसे होते हैं कि जो नर्सरी तथा किण्डरगार्टन शिक्षा प्राप्त करके आते हैं। उन्हें प्रवेश में कठिनाई नहीं होती, किन्तु संख्या का बहुत बड़ा भाग पहिली बार यहाँ आकर विद्यालय के दर्शन करता है क्योंकि नर्सरी और किण्डरगार्टन शिक्षा सबके लिए अनिवार्य नहीं है।

इसीलिए इन विद्यालयों में नये विद्यार्थियों का, जो विद्यालय में प्रथम आते हैं, एक दम प्रवेश नहीं किया जाता। उन्हें कक्षा में देखने-भालने के लिए पहिले कुछ दिन बिठाया जाता है, ताकि विद्यालय से उनका परिचय बढ़े और विद्यालय के कार्यों तथा योजनाओं में उनकी रुचि का लगना आरम्भ हो। इस तरह की बातें उन विद्यार्थियों के लिए नहीं होतीं जो किण्डरगार्टन से प्रथम कक्षा में पदार्पण करते हैं। किन्तु प्रवेश से पूर्व सभी विद्यार्थियों की शारीरिक परीक्षा अवश्य की जाती है ताकि उनके शारीरिक दोषों को समझते हुए उन्हें अधिक से अधिक सहायता दी जा सके।

इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय कोई अलग विद्यालय नहीं है। बालक के विकास के लिए वह एक ऐसी विशेष योजना लेकर चलता है जो उसकी आयु-विकास के अनुकूल होती है, उसी प्रकार जैसे नर्सरी और किण्डरगार्टन। इसीलिए प्राथमिक विद्यालय किण्डरगार्टन से जुड़ा हुआ है। और उसे यदि किण्डरगार्टन का बढ़ा हुआ रूप कह दें तो अत्युक्ति नहीं होगी।

(२)

प्राथमिक शिक्षा का विस्तार

प्राथमिक शिक्षा के संगठन, प्रशासन तथा पाठ्यक्रम में बड़ी भिन्नता होने के कारण प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार को निश्चित करना अत्यन्त कठिन कार्य है। फिर भी, इसके विभिन्न अंगों को सामने रखते हुए, हम इसके विस्तार के विषय में विचार करेंगे।

प्रथम बात है, कि किस आयु से प्राथमिक शिक्षा आरम्भ होती है ? और कब तक चलती है ? नीचे हम पाँच बड़े देशों में प्रचलित इस शिक्षा-आयु के आँकड़ों को उद्धृत करेंगे। यहाँ एक बात दृष्टव्य है कि प्रारम्भिक शिक्षा को प्राय: दो नामों से सम्बोधित किया जाता है, १. प्राइमरी (Primary), २. तथा एलीमेन्टरी (Elementary)।

देश	कब से कब तक ?	किस नाम से ?
इंगलैण्ड	८–११ वर्ष की आयु	प्राइमरी विद्यालय।
फ्रान्स	६–१३ ,,	जनता एलीमेन्टरी विद्यालय।
टली	६–१० ,,	एलीमेन्टरी विद्यालय।
रूस	८–१२ ,,	प्राइमरी विद्यालय।
अमेरिका	६–१२	(नई योजना)
	६–१४	(पुरानी योजना)

उपर्युक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि कम से कम आयु ६-८ वर्ष तक है और उसी तरह अधिक से अधिक आयु १०-१४ वर्षों के बीच में है। अमेरिका में छ: वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है और १२ या १४ वर्ष तक की आयु तक उसकी प्राथमिक शिक्षा चलती रहती है। नई योजना के अन्तर्गत जहाँ माध्यमिक शिक्षा दो वर्ष नीचे की ओर और उतर आई है वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा बारह साल की आयु में समाप्त हो जाती है। किन्तु जहाँ पुरानी योजना चालू है, वहाँ १४ वर्ष में ही प्राथमिक शिक्षा समाप्त होती है।

द्वितीय प्रश्न है कि सामूहिक जीवन की शिक्षा के विषय में प्राथमिक विद्यालय क्या सहयोग देता है ? सामूहिक जीवन के विकास में प्राथमिक विद्यालय का प्रमुख स्थान है। विद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी, पहिली बार, समूह से मिलते हैं। उस समय तो समूह छोटे ही होते हैं किन्तु आयु विकास के साथ, वे बढ़ते चलते हैं; अत: सामूहिक जीवन को उचित बनाना एक बड़ी आवश्यकता है। सहयोग, त्याग और प्रेम को साथ लेकर जन-जीवन की शिक्षा यहीं से आरम्भ होती है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है—बालक को एक सफल व्यक्ति तथा नागरिक बनाना।

इन प्राथमिक विद्यालयों में पाँच बातों की शिक्षा दी जाती है जिन्हें पाँच 'आर' (Five Rs.) कहते हैं।

१. पठन (Reading) २. लेखन (Riting) ३. हिसाब (Rithmatic)	मानसिक विकास,
४. मनोरंजन (Recreation)	शारीरिक विकास;
५. सम्बन्ध (Relationships)	सामाजिक विकास।

संयुक्तराज्य में प्राथमिक शिक्षा के साधारण विभाग तीन हैं —

१. प्राथमिक —१ से तीन ३ (कक्षा)
२. माध्यमिक—४ — ६ (,,)
३. उच्च —७ — ८ (,,)

लेकिन कहीं-कहीं इन तीन भागों में कुछ परिवर्तन भी पाए जाते हैं। कहीं-कहीं किण्डरगार्टन को भी प्राथमिक विभाग में सम्मिलित कर लिया जाता है और जूनियर हाई स्कूल (सातवीं-आठवीं कक्षा) को माध्यमिक शिक्षा में मिला दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा की संगठन-विषयक विभिन्न योजनाएँ निम्न हैं—

अ—पुरानी आठ कक्षा वाली योजना।
आ—तीन विभागों वाली।
इ—दो पुनर्गठित विभागों वाली।
ई—एक संगठित अन्विति।

(अ)	(आ)	(इ)	(ई)
कक्षा ८	कक्षा ८	कक्षा ६	कक्षा ६
,, ७	,, ७	,, ५	,, ५
,, ६	,, ६	,, ४	,, ४
,, ५	,, ५	,, ३	,, ३
,, ४	,, ४	,, २	,, २
,, ३	,, ३	,, १	,, १
,, २	,, २		किण्डरगार्टन
,, १	,, १		
८	३–३–२	३–३	२–६

उपर्युक्त प्राथमिक शिक्षा के विभाग—प्राथमिक, माध्यमिक, तथा उच्च और उसके संगठन के विभिन्न स्वरूप—भिन्न दिखाई देते हुए भी एक ही वस्तु के विभिन्न स्वरूप हैं, अलग-अलग नहीं। इस तरह की भिन्नताएँ, व्यक्ति-विकास को सामने रखकर की गई हैं—व्यक्ति, एक इकाई के रूप में विकसित होता है।

संयुक्तराज्य में प्रजनन-गति के विकास के साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए—

१९४० — '५० ई० तक विद्यालयों की की संख्या थी २,००,००,०००
१९५० — '६० ई० तक —— हो जाएगी) ३,३०,००,०००

(३)

प्राथमिक शिक्षा के नेता

संयुक्तराज्य में प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है ? कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं। बल्कि इन प्राथमिक विद्यालयों का जन्म उन महान् विभूतियों के अथक परिश्रमों का परिणाम है जो अमेरिका में भी थीं और उसके समुद्रों से दूर भी स्थित थीं। इन विशिष्ट विभूतियों के नाम हैं—

१. कॉमीनियस (१५९२-१६७०)
२. रूसो (१७१२-१७७८)
३. पेस्तालॉजी (१७४६-१८२७)
४. हरबार्ट (१७७६-१८४१)
५. हॉरेस मन (१७९६-१८५९)
६. हेनरी बर्नार्ड (१८११-१९००)
७. फ्रान्सिस पार्कर (१८३७-१९०२)
८. जॉन ड्यूई (१८५९-१९५२)
९. किल पैट्रिक (१८७१-)

कॉमीनियस ने शिक्षा को यथार्थ के धरातल पर खड़ा किया और उसे सहानुभूति-पूर्ण तथा रोचक बनाते हुए सार्वभौमिक शिक्षा की दुहाई दी। रूसो ने प्राथमिक शिक्षा को बाल-केन्द्रित बताते हुए, प्रकृति के अनुसार शिक्षा का अमर घोष किया। पेस्तालॉजी ने शिक्षा में व्यक्ति के सिद्धांत के स्वाभाविक और संगत विकास पर बल दिया और शिक्षा को वैज्ञानिक बनाने के लिए पर्यवेक्षण (Observation) को नितान्त आवश्यक माना। किण्डरगार्टन के जन्मदाता हरबार्ट ने शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण माना और प्रथम बार शिक्षा को वैज्ञानिक बनाने का सफल प्रयत्न किया। संयुक्तराज्य में हॉरेस मन ने 'जन-विद्यालय' के लिए सफल आन्दोलन किया। पार्कर ने 'क्विन्सी' आन्दोलन का नेतृत्व करके, विद्यालयों को बच्चे के अनुसार बनाने पर बल दिया। जॉन ड्यूई, महान शिक्षा-शास्त्री तथा प्राथमिक शिक्षा की नीति के निर्माता के रूप में हमारे सामने आए और उनसे प्रोत्साहन पाकर विन्नेटका (Winnetka) तथा गैरी (Garry) जनविद्यालय-योजनाएँ शिक्षा-जगत् में आईं। किलपैट्रिक ने प्रोजैक्ट प्रणाली (Project Method) के रूप में आधुनिक शिक्षा तथा शिक्षा को एक अमूल्य भेंट दी।

(४)

प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

बच्चे का शरीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, तथा सौन्दर्यानुभूत्यात्मक विकास ही ाथमिक शिक्षा का उद्देश्य है।

१. विद्यालय की पहिली आवश्यकता यह है कि वह उन मूल्यों पर आधारित हो जो उपयोगी (Good) हैं, जो कल्याणकारी हैं।

२. इन मूल्यों के प्रोत्साहन तथा विकास में विद्यालय कुशल हो।

इन उद्देश्यों के अतिरिक्त, प्रजातन्त्र के निम्न तीन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति भी प्राथमिक विद्यालयों में होनी चाहिए :—

१. देश के नागरिक अपनी समस्याओं का सामना स्वयं आत्मनिर्भर होकर, आत्मप्रेरणा के साथ करें । और अपना जीवनयापन इस प्रकार करें कि उन्हें अपने साथी नागरिकों पर न रहना पड़े । इस आदर्श के अनुसार नव-नागरिक को विभिन्न शिक्षाओं में पारंगत होना चाहिए । अतः प्राथमिक विद्यालय की सफलता इस बात में होगी कि वे सफलतापूर्वक, बालकों में आत्मनिर्भरता तथा आधारभूत कुशलता का उचित विकास करें, ताकि समस्याओं का स्वयं निदान करके वे भविष्य में बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण उत्साह और अनुभव के साथ आगे आ सकें।

२. प्रजातन्त्र में, प्रत्येक नागरिक जनकल्याण के लिए सचेष्ट रहता है। उसके मन में सामाजिक नियमों तथा संस्थाओं के प्रति सम्मान होता है। इसी से अपने तथा दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है । अतः प्राथमिक विद्यालयों में बालक की सभी रचनात्मक योग्यताओं का प्रदर्शन तथा विकास होना आवश्यक है।

३. प्रजातान्त्रिक समाज में, प्रत्येक नागरिक को, समूह को—जिसका वह स्वयं सदस्य है—प्रभावित करने वाले सभी सामाजिक निर्णयों में, बुद्धिपूर्वक तथा स्वाधीनतापूर्वक भाग लेना चाहिए। अतः एक अच्छे प्राथमिक विद्यालय का यह कर्त्तव्य है कि वह सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दे, और सामाजिक संस्थाओं को विकासित करने वाले सहयोगजन्य योग्यताओं को, उनके विकास में, सजग होकर सहयोग-दान दे ।

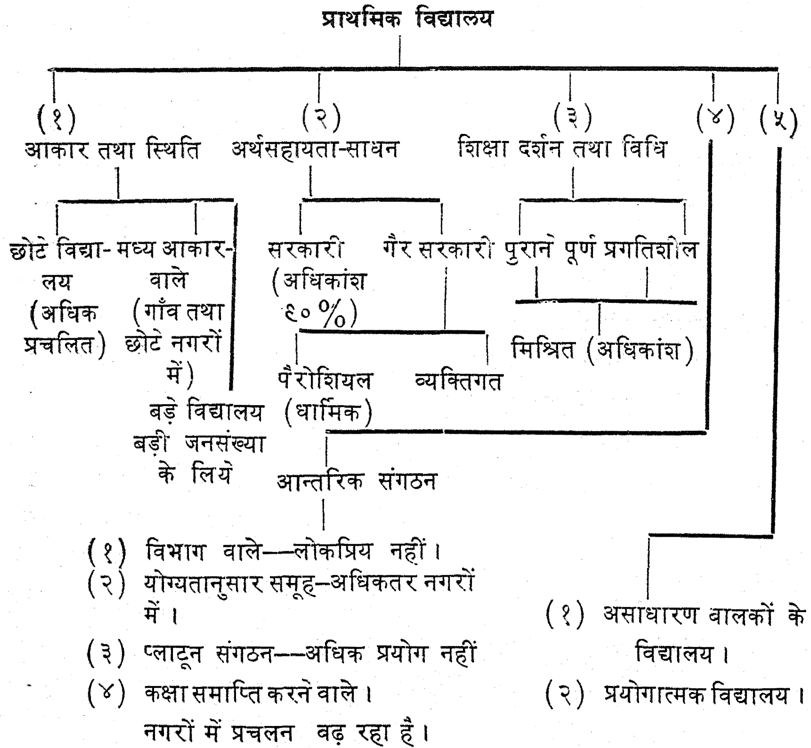
(५)

प्राथमिक विद्यालयों के भेद

प्राथमिक विद्यालयों के विभिन्न प्रकारों के आधार हैं—

१. आकार तथा स्थिति। एक या दो शिक्षक (गाँव का)।
२. आर्थिक सहायता का साधन। सरकारी या व्यक्तिगत।
३. शिक्षण—पुरानी, प्रगतिशील—मध्य की।
४. आन्तरिक संगठन—तथा प्लाटून ढंग वाले।
५. विशिष्ट विद्यालय—असाधारण बालकों के लिए ।

इन आधारों को सामने रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों का वर्गीकरण इस प्रकार है :-



(६)

प्राथमिक शिक्षा-योजनाएँ

आठ कक्षाओं के स्थान पर आज के प्राथमिक विद्यालय में छः कक्षा तथा किण्डरगार्टन होता है। प्राथमिक विद्यालय की तीनों सीढ़ियों में शिक्षा-योजना इस प्रकार रहती है :—

१. **प्राथमिक कक्षा**—प्रथम तीन कक्षाओं में किण्डरगार्टन शिक्षा ही चलती रहती है, क्योंकि अधिकांश ऐसे बालक आते हैं जिन्हें किण्डरगार्टन का पूर्वानुभव नहीं होता।

२. **माध्यमिक कक्षा**—चौथी, पाँचवीं, तथा छठी कक्षा, इसके अन्तर्गत आती हैं। इनमें पठन पर ही बल दिया जाता है।

३. **उच्चस्तर**—सातवीं तथा आठवीं कक्षा दोनों ही माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत आ जाती हैं और इन दोनों कक्षाओं को 'जूनियर विद्यालय' के नाम से भी पुकारते हैं।

(७)

प्राथमिक शिक्षा : आज

आज की बदलती हुई प्राथमिक शिक्षा की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं—

१. विद्यालयों का संगठन तथा प्रशासन सरल तथा लचकदार होता जा रहा है।

२. विद्यालय की इमारत तथा उसका सामान इस प्रकार का होने पर बल दिया जा रहा है, कि वह लचकदार हो और काम भी अधिक दे सके।

३. पाठ्यक्रम लचकदार हो गया है। अब तक छूटे हुए स्थलों और नई वस्तुओं पर बल दिया जा रहा है।

४. विद्यालय की शिक्षा, सहयोगजन्य प्रक्रिया का परिणाम है।

५. शिष्यों को व्यक्तिगत ध्यान अधिक दिया जाता है और उनके व्यक्तित्व-विकास तथा उचित नियन्त्रण पर बल दिया जाता है।

६. सामाजिक कार्यों के करने को प्रोत्साहन के रूप में शिष्यों को अधिक अवसर दिए जाते हैं।

(८)

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता राष्ट्र के उन्नयन के लिए कितनी आवश्यक है, इस बात को समझते हुए संयुक्तराज्य ने काफी प्रगति तथा प्रयत्न किये हैं। लाखों शिक्षाविदों के प्रयत्न, अनुसन्धान तथा अथक परिश्रम, बहुत अंश में राष्ट्र को ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। और उनकी इस तरह की प्रगति इस बात की साक्षी है कि वे कुछ समय के बाद राष्ट्र की शिक्षा-गत असमानताओं के निराकरण में अवश्य ही सफल होंगे।

तृतीय चरण

माध्यमिक शिक्षा (अमेरिकन हाई स्कूल)

रूपरेखा :—

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—लेटिन ग्रामर स्कूल—एकेडेमी—सार्वजनिक हाई स्कल—बढ़ाई हुई माध्यमिक शिक्षा।

२. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य।

३. माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था।

४. स्कूलों के प्रकार।

५. स्कूलों का परिमाण (Size) तथा समस्याएँ।

६. पाठ्य-क्रम ।

७. जूनियर हाई स्कूल ।

८. जूनियर कालेज ।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि--कई अवस्थाओं म होकर गजर आज के अमेरिकन हाई स्कूल का अपना एक इतिहास है। गोर्डन ली[1] के अनुसार सन् १९५०-५१ म २८००० हाई-स्कूल तथा Preparatory School या प्रारम्भिक शिक्षा-संस्थाएँ थीं जिनमें लगभग ६१,४६,००० छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थ। इनम ३००० ाइवेट स्कल भी सम्मिलित हैं जिनमें उज्ज्वल भविष्य की सोचन वाले माता-पिता अपनी संतानें भेजते हैं। "......that these are the ones in which the discerning parent nowadays invests his money.[2] फिर भी आज इन सावजनिक स्कूलों में, जहाँ न कोई फ़ीस ली जाती है तथा न कोई वर्ग का बंधन है, प्रायः छात्र जाते हैं। फ़ीस के साथ २ अन्य सभी पाठन-सामग्री सुविधा के साथ मिल जाती है। संयुक्तराज्य में अनिवार्य शिक्षा की आयु १८+ है। कतिपय विद्वानों का मत है कि इस अनिवार्य अवस्था के अपेक्षा-कृत अधिक होने के दो मुख्य कारण हैं: १. संयुक्तराज्य का धन; तथा २. बकारी की समस्या को हल करने का एक साधन अधिक समय तक छात्रों को स्कूलों में रखना भी है।

लैटिन ग्रामर स्कूल—माध्यमिक शिक्षा का विकास धनीवर्ग (प्यूरिटन) के पुत्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के रूप में हुआ था। इन प्यूरिटन मतावलम्बियों को भय था कि वे अपना धर्म कहीं अमरीकी बीहड़ में भूल न जाएँ इसीलिए लटिन भाषा तथा धर्म की शिक्षा देना उन्होंने इन्हीं संस्थाओं में प्रारम्भ किया। लैटिन उच्च शिक्षा के लिए भी आवश्यक थी। इन्हीं संकुचित उद्देश्यों को लेकर ये स्कूल खोले गये। सन् १६३५ में बोस्टन नगर में प्रथम लैटिन ग्रामर स्कूल खुला। इन स्कूलों का सार्वजनिक रूप था अर्थात जो भी फीस देने की सामर्थ्य रखता था वह उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकता था। धार्मिक शिक्षा के कारण इनकी लोकप्रियता को शीघ्र ही धक्का पहुँचा। इनके संकीर्ण उद्देश्य तथा संकुचित पाठ्य-क्रम भी इनकी समाप्ति के कारणों में से थे। १९ वीं शताब्दी तक ये स्कूल उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पढ़ाते रहे तथा इनका प्रभाव बना रहा।

२. **एकेडमी** (Academies)—अधिक वास्तविक तथा जीवन के अधिक निकट होने के कारण ये एकेडेमियाँ अमरीकी माध्यमिक शिक्षा का द्वितीय चरण बनीं। उक्त पाठ्य-क्रम के साथ-साथ यहाँ बुक-कीपिंग, नौसेना, राजनीतिक दर्शन इत्यादि की भी पढ़ाई प्रारम्भ हो गई। अधिक व्यावसायिक तथा जीवन

---

1. Lee, G.C; An Introduction to Education in Modern Ameria. P. 140
2. Kenneth Richmond; Education in the U.S.A. P. 142

के अधिक निकट होने के कारण इनकी लोकप्रियता १८४० तथा १८५० के लगभग चरम सीमा पर पहुँच गई। बेन्जामिन फ्रैन्कलिन के एक पैम्फलेट Proposal Relating to the Education of youth in Pennsylvania के द्वारा इन एकेडेमियों का सूत्रपात हुआ और सन् १७५१ में एक किराये के मकान में प्रारम्भ होकर वही एकेडेमी एक दिन पेनसिल्वानिया का विश्वविद्यालय हो गई। स्त्रियों की शिक्षा का प्रारम्भ इन एकेडेमियों की विशेषता थी।

३. **सार्वजनिक हाई स्कूल**—बिना फ़ीस का यह हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षा का तृतीय चरण है। १८२१ में बोस्टन नगर में सर्वप्रथम इस कार के हाई स्कूल की स्थापना हुई। यद्यपि यह नाम स्काटलैंड से उधार लिया गया है फिर भी यह स्कल अमरीकी जीवन का विशेष प्रतिनिधि है। १८७० के प्रसिद्ध कलामाज़ू (Kalamazoo) केस के, जो मिशीगन राज्य में लड़ा गया, निर्णय ने इसकी प्रतिष्ठा को चार चाँद लगा दिये। उक्त केस ने यह तय कर दिया कि जनता यदि चाहे तो माध्यमिक स्कूल खोल सकती है तथा कर द्वारा उसे चला भी सकती है, इसके अतिरिक्त किसी भी न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार भी नहीं है। प्राकृतिक शक्तियों का समुपयोजन (Exploitation) व्यावसायिक उन्नति, तथा धन की प्रचुरता ने इस हाई स्कूल की प्रगति में सहायता दी। एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्विता को भावना तथा शान जताने की वृत्ति ने भी इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी (Socio-economic laddes) पर चढ़ने की प्रबल आकांक्षा, विविध व्यवसायों में जाने का अवसर, खुली जाति की व्यवस्था (अर्थात् कोई भी धन के कारण अपनी जाति बदल सकता था) और उच्च शिक्षा के इच्छुकों की कामना की पूर्ति—इन सभी कारणों ने न स्कूलों को उत्तरोत्तर वृद्धि में सहायता की। विशेष (Specific) तथा सामान्य (General) का प्रश्न जो सुकरात के समय से प्रारम्भ हुआ तथा इंगलैण्ड में बहुत दिनों पश्चात् ही तय हो पाया, अमेरिका में वह अभी तक वादविवाद का विषय बना हुआ है। उदारशिक्षा (Liberal Education) की बात, जो रूढ़िगत विशेषता पर ही निर्भर थी, अमरीकी रुचि के विरुद्ध थी। केनेथ रिचमंड के शब्दों में बेचैन, महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति ोशीघ्र तथा मूर्त परिणाम चाहते थे। (A restless, aspiring people looked for quick returns. tan gible results.) वैसे १८९० तक ये हाई स्कूल कालेज के प्रारम्भिक चरण ही रहे। जब तक जनता इनके लिए कर देने को तैयार थी यह ८ वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जुड़े रहे। छात्रों को कालेज के

लिए तैयार करने के विरुद्ध प्रायः सभी थ। १६०० तक जैसे समुद्री बाढ़ आई तथा सहस्त्रों की संख्या में छात्र एक साथ बढ़े।

सन्	छात्र-संख्या	स्कूल
१८६०	३,५७,०००	
१६४०	७१,१३,०००	
१६५०	७१,४६,०००	२८,५००
१६५२-५३	७३,००,०००	
१६६० (अनुमान)	८०,००,०००	

४. **बढ़ाई हुई माध्यमिक शिक्षा**—आज इस शिक्षा का चतुर्थ चरण चल रहा है। नीचे की ओर बढ़ कर प्रारम्भिक शिक्षा की उसने ७ तथा ८ कक्षा ले ली हैं और ऊपर १३ और १४ कक्षा तक बढ़ गई है। जूनियर हाई स्कूल तथा जूनियर कालेज इसके नये बढ़े हुए रूप हैं। १६०२ में यह जूनियर कालेज जोलियट (इलीनोइज़ राज्य) में खुला। १६१० में बर्कले (केलीफोर्निया राज्य में) में प्रथम जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हुई। १८६८ में एक जूनियर कालेज डक्टयोर वैपटिस्ट कालेज के नाम से खुल चुका था पर वह धार्मिक कारणों से सर्वमान्य नहीं हो सका था।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य—केनेथ रिचमंड ने हमें चेतावनी दी है कि अमरीकी माध्यमिक शिक्षण का क्षेत्र वादविवाद का सबसे अधिक अवसर देता है जहाँ बहुत सँभल कर बात करने पर भी भूल हो ही जाती है। इसलिए इस क्षेत्र के प्रति हमारी भूल अस्वाभाविक न होगी। माध्यमिक शिक्षा के इतिहास के आधार पर जीवन तथा कालेज की तैयारी से निकल कर हम बोस्टन हाई स्कूल की स्थापना के मूल उद्देश्यों पर आते हैं जहाँ सभ्यता तथा व्यावहारिकता का ज्ञान कालेज जाने वाले विद्यार्थियों को देना निश्चित किया गया। वस्तुतः कालेज की तैयारी का उद्देश्य भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं रहा। आज भी "जीवन के लिए समायोजक शिक्षा" (Life adjustment Education) तथा केवल सैद्धान्तिक (Academic) शिक्षा के वादविवाद अनजाने नहीं हैं।

गार्डन लो के अनुसार हाई स्कूल के चार मुख्य उद्देश्य हैं—

१. **अन्तिम शिक्षा**—(Terminal Education)—जैसा कि बोस्टन हाई स्कूल का उद्देश्य था—कालेज न जाने वाले छात्रों को शिक्षा देना जो प्रायः व्यावसायिक (Professional) थी। व्यापक हो जाने पर भी व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य आज भुलाया नहीं जा सका है।

२. **सामान्य शिक्षा**—यह शिक्षा अन्तिम शिक्षा भी हो सकती है और नहीं भी। शास्त्रीय (Classical) विषयों से कुछ पाठ्य-सामग्री छाँट ली जाती है

और व्यावसायिक शिक्षा के साथ पढ़ा दी जाती है। कभी-कभी इसका रूप भी बदल जाता है तथा अधिक वास्तविक हो जाती है।

३. **पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा**—यह सामान्य तथा आंशिक रूप से व्यावसायिक होती है। इसका अर्थ होता है कि उच्च शिक्षा-संस्था में छात्र को जाकर उसी विषय का और अध्ययन करना है।

४. **व्यक्तिगत विकास की शिक्षा**—यद्यपि सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है किन्तु २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ से दी गई शिक्षा विशेषकर व्यक्तिगत विकास में केन्द्रित हो गई है तथा व्यक्ति की कलात्मक, रचनात्मक तथा सामाजिक चेतनाओं को विकसित करना चाहती है।

जीवन-समायोजक शिक्षा अमरीकी शिक्षा का नवीन मोड़ है। इसकी उत्पत्ति के कारण: १. हाई स्कूलों ने नौकरियों से अधिक छात्रों को नौकरियों के लिए तैयार किया है; तथा २. कालेज की तैयारी को पाठन-सामग्री द्वारा बहुत से छात्रों को बर्बाद किया गया है। १९४७ के एक कमीशन के आधार पर निम्न आवश्यकताएँ निश्चित की गईं तथा शिक्षा को उन्हें पूरा करने का आदेश दिया गया। यह माध्यमिक शिक्षा के द्वितीय आधार पर कहे गये उद्देश्य हैं।

प्रत्येक नवयुवक की प्रजातंत्र में सामान्य तथा अनिवार्य आवश्यकताएँ—

१. प्रत्येक छात्र को उन कौशलों (Skills) की आवश्यकता है जिन्हें बेच कर वह बुद्धिमान तथा समाज के आर्थिक जीवन के लिए उपयोगी बन सके। इसलिए उन व्यवसायों तथा कौशलों को शिक्षा देना है;
२. स्वास्थ्य-शिक्षा;
३. नागरिक अधिकार तथा कर्त्तव्यों की शिक्षा;
४. अच्छी वस्तुओं की खरीद तथा उनके प्रयोग की शिक्षा;
५. सफल गार्हस्थ्य जीवन का ज्ञान;
६. विज्ञान, विज्ञान का मनुष्य-जीवन पर प्रभाव, तथा मनुष्य और विश्व के विषय में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान;
७. कला, साहित्य इत्यादि का आनन्द उठाने की शिक्षा;
८. अवकाश का सद्-उपयोग;
९. अन्य व्यक्तियों का आदर, नैतिक सिद्धान्तों का ज्ञान तथा समाज में सहयोग के साथ रहना।
१०. तर्क-पूर्ण चिन्तन, अपने विचारों को स्पष्ट कहना, तथा समझ के साथ सुनना तथा पढ़ना।

गाडन ली के उक्त चारों उद्देश्यों से कहीं अधिक व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण ये उद्देश्य हैं। शास्त्रीय विषयों के विरुद्ध यह एक नवीन आवाज़ है।

नेशनल एजूकेशन एसोसिएशन (N.E.A.) की एक रिपोर्ट[1] के आधार पर हम तीसरे रूप से भी उक्त उद्देश्यों को कह सकते हैं--

१. आत्म-बोध का उद्देश्य,

२. मानव-सम्बन्धी उद्देश्य,

३. आर्थिक सफलता-सम्बन्धी उद्दश्य,

४. नागरिक जिम्मेदारी-सम्बन्धी उद्देश्य।

हरबर्ट स्पेन्सर से मिलते-जुलते उद्दश्य जो उक्त एसोसियेशन ने १६१८ में दिय थे उनका दुहराना भी अनुचित न होगा---

१. स्वास्थ्य; २. आधारभूत प्रक्रियाओं का पूर्ण ज्ञान; ३. गृह की कुशल सदस्यता; ४. व्यवसाय; ५. नागरिक; ६. अवकाश का सदुपयोग; ७. नैतिक चरित्र।

इस प्रकार हमने जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हुए उद्देश्यों का वर्णन कर डाला है।

माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्था---प्रारम्भ से ही संयुक्तराज्य में माध्यमिक शिक्षा की संस्थाएँ ६, १०, ११ तथा १२ रही हैं। कई कारणों से इनका पुनःसंघटन (Reorganisation) हुआ है। ६ वर्ष की प्रारम्भिक, ३ वर्ष की जूनियर हाई स्कूल और ३ वर्ष सीनियर हाई स्कूल (या ६-३-३ प्रथा) का चलन वहाँ शीघ्र ही हो गया। इसका प्रथम कारण था कि कक्षा ९ में आने वाला किशोर अपनी नवीन समस्याओं का समाधान चाहता था; और वह कक्षा ७ या ८ के छात्र से भिन्न तथा कक्षा १० के छात्र के समान ही था, इसलिए उसके लिए अलग स्कूल या अलग पाठ्य-क्रम आवश्यक हो गया। सभ्यता की जटिलता ने माध्यमिक शिक्षा के वर्षों पर प्रभाव डाला क्योंकि अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अधिक कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता थी। जीवन के लिए सफल नेता इसी शिक्षा के पश्चात् हो पाते थे। प्रारम्भिक शिक्षा को और अधिक काम का बनाने के लिए उसके वर्षों को कम करना था। इस प्रकार जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना हुई। कभी-कभी जूनियर तथा सीनियर हाई स्कूल एक ही इमारत में होते हैं और उनका ३-३ का पाठ्य-क्रम भी भिन्न नहीं होता। किन्तु प्रायः बड़े-बड़े नगरों में जहाँ छात्र अधिक आते हैं और पुराने हाई स्कूलों की इमारतें भी इस योग्य नहीं हैं कि वहाँ ६ वर्षों की शिक्षा दी जा सके; या नवीन पाठ्यक्रमों की नवीन आवश्यकताओं के लिए जूनियर तथा सीनियर स्कूल अलग-अलग खुलें। इसी आधार पर उन्हें ६-६ या ६-३-३ व्यवस्था के अनुसार बाँट सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा में लिबरल आर्ट्स कालेजों के २ वर्ष काट कर जोड़ दिये गये हैं

1. Alexander and Saylor, Secondary Education. P. 106.

तथा उनका नाम जूनियर कालेज कर दिया गया है। इस प्रकार इस व्यवस्था को ६-३-३-२ या ६-६-२ कह सकते हैं।

एक और व्यवस्था भी संयुक्तराज्य में प्रचलित है उसे ६-४-४ व्यवस्था या ६ वर्ष प्रारम्भिक शिक्षा, ४ वर्ष जूनियर माध्यमिक स्कूल तथा ४ वर्ष सीनियर माध्यमिक स्कूल का रूप दिया गया है। उचित संकलन तथा परिवर्त्तन (Tranition) के लिए यह व्यवस्था ठीक समझी जाती है। लो महोदय के अनुसार इस व्यवस्था ने एक समस्या सुलझाकर सैकड़ों उलझा दी हैं।

एक बात हमें यहाँ समझ लेनी है कि कोई भी व्यवस्था न पूर्ण-रूपेण बदली गई है न चालू की गई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा अभी परीक्षण (Experimentation Stage) की अवस्था में है। और परीक्षण अमरीकी दर्शन तथा जीवन के सानुरूप है। साधारण रूप से सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा का अधिक महत्त्व होने के कारण व्यावसायिक स्कूलों की संख्या वहाँ अधिक हो गई है। वैसे १९५२ में कुल हाई स्कूल २३,७४६ थे। ४२.८% ८-४ व्यवस्था के; १३.६% जूनियर हाई स्कूल, ७.४०% सीनियर हाई स्कूल तथा ३६.२% जूनियर-सीनियर हाई स्कूल थे।[1]

चित्र १.

स्कूल के वर्ष	४ वर्ष (पुराना)	६ वर्ष नीचे की ओर बढ़ा हुआ	६ वर्ष ऊपर की ओर बढ़ा हुआ	८ वर्ष (४-४)	८ वर्ष (३-३-२)
१४			जूनियरकालेज तथा हाईस्कूल		जूनियरकालेज
१३				उच्च माध्यमिक स्कूल	
१२					सीनियर हाई स्कूल
११	हाई स्कूल (४ वर्ष)	६ वर्षीय हाई स्कूल			
१०					
९				निम्न माध्यमिक स्कूल	
८					जूनियर हाई स्कूल
७					

(Introduction to American Public Education, De Young P. 188)

उक्त माध्यमिक स्कूलों के प्रकारों के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार हैं।

पाठ्य-क्रमों के आधार पर स्कूलों के प्रकार—

१. सामान्य (General)

1. Kandel, I. L; The New Era in Education P. 304.

(अ) सीमित (Limited)

(ब) व्यापक (Comprehensive)

२. विशेष (Specialised)

(अ) पुस्तकीय (Academic)

(ब) कृषि

(स) वाणिज्य

(द) टैक्नीकल

(इ) व्यापार

३. थोड़े समय के स्कूल (Part-time School)

(अ) सांतत्य स्कूल (Contination)

(ब) सान्ध्यकालीन (Evening)

१. **सामान्य हाई स्कूल**—अधिकतर हाई स्कूल इसी प्रकार के हैं। इनका प्रोग्राम एक सीमा के अन्दर बालकों की रुचि के आधार पर होता है। किन्तु सीमा का विस्तार धन, स्कूल का परिमाण (Size), उस स्थान के मनुष्यों की सहायता पर निर्भर रहता है। लेकिन यहाँ विशेष (Specilized) क्षेत्र के लिए विषयों क चुनाव का अवसर नहीं होता इसलिए इन्हें सीमित स्कूल भी कहा जा सकता है।

जब स्कूल का परिमाण (Size) बढ़ जाता है तथा चुने हुए क्षेत्रों में बहुत से प्रारम्भिक कोर्स भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं उस समय उन्हें विशेष स्कूल कहा जा सकता है। पर ध्यान रहे कि सामान्य विषय यहाँ भी पढ़ाये जाते हैं, यद्यपि बल सदैव विशेष विषयों पर ही रहता है। ऐसे स्कूल भी हैं जैसे वाइस टैक्नीकल स्कूल, टैक्नीकल हाई स्कूल ओहाम इत्यादि जहाँ अँगरेजी, सामाजिक विषय, विज्ञान इत्यादि की शिक्षा दी जाती है।

व्यापक स्कूल—जब स्कूल व्यापक हो जाता है और ऐसा केवल बड़े नगरों में ही सम्भव है; वहाँ दो सौ विषय तक एक साथ पढ़ाये जा सकते हैं। इन विषयों के समूह (Groups) पढ़ाने के विभागों (Department) में बाँट दिये जाते हैं तथा छात्र अपनी इच्छा पर विषय चुन लेते हैं। विषय इस प्रकार होते हैं, कालेज की तैयारी के विषय; कृषि, व्यापार, कलात्मक विषयों के समूह इत्यादि।

एक व्यापक स्कूल की व्यापकता उसके विभिन्न पाठ्य-विषयों में शिक्षा देने में है। जहाँ प्रत्येक प्रकार की शिक्षा एक ही स्कूल में दी जाती हो; जहाँ सामान्य तथा रुचि के विषय सभी को एक ही स्थान पर पढ़ाये जाते हों। यही वह व्यापक स्कूल है जिसकी प्रशंसा कानेन्ट से लेकर प्रत्येक अमरीकी नागरिक करता है।[1] यहाँ न लिंग-भेद है, न जाति या वर्गभेद। बिना फ़ीस वाले ये स्कूल प्रत्येक बद्धि-स्तर (Transition) के लिए

1. Conant, I. B. Education and Liberty. P. 50.

समान रूप से खुले हैं। सामान्य तथा विशेष विषयों में शिक्षा यहाँ एक ही छत के नीचे दी जाती है। यही अमरीकी आदर्श है तथा इसे महान प्रजातान्त्रिक परीक्षण की संज्ञा मिल चुकी है। इन्हीं स्कूलों पर अमरीकी एकता का भार है। यही राष्ट्र की उच्च अभिलाषाओं तथा आदर्शों के प्रतीक हैं। हम यहाँ इंगलैंड के त्रि-वर्गीय स्कूल से इस व्यापक स्कूल की तुलना कर सकते हैं ।[1]

यह भी प्रायः कहा जाता है कि बिना किसी भेद के ये स्कूल अधिक प्रजातान्त्रिक हैं तथा इंगलैंड के सार्वजनिक स्कूलों (जो वास्तव में सार्वजनिक नहीं हैं) से अच्छे हैं क्योंकि यहाँ सभी वर्ग के छात्र एक साथ पढ़ते हैं। कानेन्ट महोदय का कथन है कि अमरीकी हाई स्कूल वैसे ही नागरिक उत्पन्न करेंगे जैसे इंगलैंड के सार्वजनिक स्कूल करते रहे हैं।

(If the battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton, it may well be that the ideological Struggle with Communism in the next fifty years will be won on the playing fields of the public high Schools of the united States.) [2].

प्रो० जेफ्रेज के एक पत्र का उद्धरण देकर यह देख सकते हैं कि ये व्यापक स्कूल इंगलैण्ड के ग्रामर स्कूलों से किसी भाँति श्रेष्ठ नहीं हैं। हाँ, एक बात अवश्य सत्य है कि ग्रामर स्कूलों में सब बुद्धि-स्तर के छात्र नहीं आते न वहाँ प्रत्येक विषय पढ़ाने की सम्भावना ही है ।

"The comprehensive school is not necessarily a more democratic community from the point of view of social class. It has been pointed out by Sir Eric James of Manchester. Grammar school that a grammar school drawing its pupils from a vide area is likely to bring together children from more widely differing social groups than a large comprehensive school which caters for the locality sorrounding it" (a letter from Prof. Jeffreys of Birminghim University to my colleague and friend."

एक प्रकार से उक्त कथन सत्य है क्योंकि प्रायः एक क्षेत्र के बालक उन व्यापक स्कूलों में आते हैं। फिर भी अमेरिकन व्यापक स्कलों में जहाँ अधिक रुचि के विषयों की व्यवस्था है; जहाँ भिन्न-भिन्न मस्तिष्क-स्तर वाले छात्र आते हैं और भिन्न स्तर के भविष्य के नागरिकों से जहाँ भेंट हो जाती है जो समाज का जीवन अधिक सुखमय करेगी एक अच्छी व्यवस्था है। इन स्कूलों में प्रत्येक विषय समान मूल्य का है, तथा मनोविज्ञान की, विशेषकर थार्नडाइक की, खोजों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि लैटिन तथा कपड़ा धोने के विषयों में ोई अन्तर नहीं है, कम से कम बुद्धि की ट्रेनिंग के सम्बन्ध

1. Pedley, Robin, Comprehensive Education—A New Aproach London. Victor Gollancz. Ltd, 1956.

2. Conant, I. B, Education and Liberty. P. 50.

में। यद्यपि आज उनकी खोजों पर संदेह उत्पन्न हो चुका है फिर भी अमरीकी मस्तिष्क ने उन्हें परम सत्य मान रखा है।

इन व्यापक स्कूलों में कुछ दोष भी हैं, जैसे १. अधिक छात्रों के कारण अध्यापकों का छात्रों से कम सम्बन्ध रह पाता है; २. अधिक विभागों के कारण अध्यापकों का स्वयं ही एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता; ३. दूर-दूर से छात्रों को लाने के लिए आवा-गमन की समस्या तथा व्यय; ४. प्रत्येक विषय के लिए योग्य अध्यापक का मिलना सम्भव नहीं है; ५. अधिक योग्यता वाले छात्र तथा कम योग्यता वाले छात्रों की पढ़ाई का उचित प्रबन्ध न हो सकना, (कैण्डल महोदय के अनुसार (P.३०५) केवल २०% पुस्तकीय रुचि वाले तथा २०% विशेष व्यवसायों में जाने वाले छात्रों को छोड़ कर शेष ६०% के लिए ये व्यापक स्कूल व्यर्थ हैं।) ऐसे छात्रों के लिए जीवन-समायोजन-शिक्षा की बात सोची जा रही है; ६. सह-शिक्षा के दोषों का उनमें आ जाना।

हम उपर्युक्त वर्णन के पश्चात् अपना मत किसी के पक्ष में न देकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस विषय में अधिक वाद-विवाद सम्भव है जिसके लिए अपने में योग्यता हमें जँचती नहीं।

यहाँ प्राय:, छात्र पढ़ना छोड़कर चले जाते हैं इसलिए शिक्षा को अधिक मनोरंजक बनाया जा रहा है; तथा कठिन विषयों को अप्रजातान्त्रिक की संज्ञा दी जा रही है। इस प्रकार अमरीकी हाई स्कूल का छात्र समाज के विषय में तो अपनी ही वयस वाले अन्य योरुपीय छात्र से दो वर्ष आगे है पर पढ़ाई में उतना ही पीछे है। यही कारण है कि ये स्कूल एक अनवरत वादविवाद के कारण बने हुए हैं।

३. विशेष स्कूल—इन विशेष (Specialized) स्कूलों के पक्ष म निम्न बातें कही जाती हैं तथा उनकी संख्या भी कुछ कम नहीं है: १. प्रत्येक व्यापक स्कूल हर प्रकार की खर्चीली विशेष व्यवस्था नहीं रख सकता, २. एक रुचि के छात्र भली भाँति एक ही स्थान पर रह सकते हैं तथा प्रगति कर सकते हैं। इनके विरुद्ध निम्न बातें कही जाती हैं: १. ये अप्रजातान्त्रिक हैं क्योंकि यहाँ सब प्रकार के छात्र एक स्थान पर नहीं आते, तथा सब विषयों को एक सी महत्ता नहीं मिलती। २. कुछ विषयों का मूल्य बढ़ जाता है। ३. यहाँ एक प्रकार की जातीयता की भावना उत्पन्न हो जाती है, ४. ये समय से पूर्व ही व्यवसाय की छाँट करने का अवसर देते हैं। ५. तथा ये व्यापक स्कूलों की महत्ता कम करते हैं और उनके पाठ्य-क्रमों का मूल्य घटाते हैं। इन आरोपों के होते हुए भी ये स्कूल वहाँ हैं ही।

४. अर्ध-सामयिक स्कूल (Part-time School)—प्राय: यहाँ वे छात्र, जो पहले हाईस्कूल छोड़ चुके होते हैं उन्हें पुन: पढ़ने का अवसर मिलता है। यहाँ सप्ताह में केवल कुछ ही समय पढ़ाई होती है। ये प्राय: अन्य हाई स्कूलों की इमारतों से बाहर ही आयोजित किये जाते हैं। इन सांतत्य स्कूलों को अन्य स्कूलों की व्यवस्था से भिन्न ही समझना चाहिए।

५. सान्ध्य-कालीन स्कूल प्रायः प्रौढ़ शिक्षा के लिए हैं। यहाँ कामों में लगे हुए व्यक्ति ही पढ़ने आते हैं और पाठ्य-क्रम प्रारम्भिक कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का होता है।

इन स्कूलों का परिणाम (Size) तथा कुछ समस्याएँ—प्रायः २०० छात्रों का ही एक हाई स्कूल होता है किन्तु बहुत से कारणों से १० छात्रों से लेकर ५००० छात्र तक उनमें सम्भव हैं। व्यापक स्कूलों में जो धनी नगर-क्षेत्रों में हैं प्रायः उन स्कूलों की योजना, छात्रों की संख्या, अध्यापकों की शिक्षा तथा वेतन, भिन्न विषयों के अध्यापन का अच्छा प्रबन्ध रहता है। किन्तु विकेन्द्रीकरण (Decentralisation) के कारण धनी तथा गरीब स्कूल की उक्त बातों की भिन्नता स्पष्ट रहती है।

प्रत्येक स्कूल अपना-अपना पाठ्य-क्रम, अध्यापकों का वेतन और उनकी शिक्षा; स्कूल की परीक्षा इत्यादि के विषय में नियम बनाता है। इस प्रकार उनके भिन्न-भिन्न शैक्षिक स्तरों को समान करने का भार'स्तरांकन अभिकरण' (Accrediting Agencies) पर है। यह व्यवस्था केवल यहीं पाई जाती है।

छोटे-छोटे स्कूलों, अयोग्य अध्यापकों, कम विषयों इत्यादि की समस्याएँ प्रमुख हैं। अधिक योग्य छात्रों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध एक समस्या है क्योंकि बुद्धि के आधार पर वर्गों की कल्पना अमरीकन मस्तिष्क कर भी नहीं सकता। १९५० में एजूकेशनल पालिसीज़ कमीशन ने इस दिशा में ध्यान आकृष्ट किया था। आशा है कि भविष्य में इस दिशा में कुछ काम अवश्य होगा।

व्यापक स्कूल स्वयं एक समस्या है तथा अभी आदर्श व्यापक स्कूल की स्थापना नहीं हुई है। द्वितीय महायुद्ध में हाई स्कूल के छात्र बड़ी संख्या में फौजी परीक्षा में फेल हुए; यहाँ तक कि अच्छे कालेजों तक के छात्र गणित की परीक्षा में पास नहीं हुए। यह बात अमरीकी शिक्षा के स्तर की समस्या की ओर इंगित करती है।

पाठ्य-क्रम (Curriculum)—यह हम भली भाँति जानते ही हैं कि अमरीकी मस्तिष्क किसी भाँति भी शास्त्रीय विषयों की महत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। उनके सम्मुख प्रश्न उपयोगिता का है। मस्तिष्क की शिक्षा या ट्रेनिंग जैसी वस्तु कोई नहीं होती और फिर विश्व के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए भी उक्त विषय पूर्ण नहीं। सभी विषय जो जीवन में सफल बनाने में सहायक होते हैं, प्रजातन्त्र के लिए अच्छे हैं। विशेषकर ६० छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा देने की समस्या है उनके लिए जीवन-समायोजन पर विचार हो रहा है यद्यपि यह बात सभी के लिय उचित जँचती है।

हम केन्द्रीय सरकार की १९५१ की विज्ञप्ति के आधार पर जीवन-समायोजन शिक्षा की परिभाषा दे सकते हैं। इस शिक्षा में "सामान्य, व्यक्तिगत, राजनैतिक. सामाजिक तथा

आर्थिक व्यक्तिगत समस्याएँ और साथ-साथ राष्ट्र, राज्य तथा क्षेत्र की समस्याएँ विशेष रूप से पढ़ाई का विषय बन जाती हैं। यहाँ छात्रों तथा अध्यापकों द्वारा आयोजन पर, जीवन म अनुभवों के सीधे-सीधे उपयोग पर, और व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनैतिक समस्याओं के समाधानों पर बल दिया जाता है। यहाँ पाठ्य-क्रम के अतिरिक्त कार्यों को छोड़ कर, यात्रा, अध्ययन, समुदाय का आपरीक्षण (Community survey), स्कूल के कार्यक्रम, या जीवन के अन्य अनुभवों को स्कूल के प्रोग्राम का आन्तरिक भाग बना लिया जाता है।"

इसके अतिरिक्त आन्तरिक पाठ्य-क्रम का भी आयोजन है जहाँ सीखने योग्य सभी बातें इकट्ठी कर ली जाती हैं। और इस पाठ्य-क्रम को अनिवार्य कर दिया जाता है। इस प्रकार विशेष विषयों के साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाती है।

कालेज के लिए जाने वाले छात्रों के अतिरिक्त शेष छात्रों का पाठ्य-क्रम बताना कठिन है। स्थानीय समस्याओं का प्रभाव वहाँ के पाठ्य-क्रम पर स्पष्ट रहता है। ६ वर्ष की माध्यमिक शिक्षा की सफलता के लिए १५ इकाइयों को इकट्ठा करना आवश्यक होता है। १ इकाई ४ या ५ घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से किसी एक विषय के काम पर मिल जाती है। यह इकाई एक बार मिलने पर छिनती नहीं है भले ही छात्र उस विषय को भूल जाय, सलिए पढ़ाई का मापदंड मात्रा है न कि किस्म।

वैसे हाई स्कूलों की परीक्षा कालेज के लिए तैयारी के उद्देश्य से प्रभावित है। १८९९ में स्थापित कालेज एण्ट्रेन्स एक्जामिनेशन के कारण कालेजों में जाने के लिए छात्रों को इस परीक्षा को पास करना होता है। पहली बार १८७० में मिशीगन विश्वविद्यालय ने माध्यमिक संस्थाओं का स्तरांकन करना प्रारम्भ किया और आज लगभग पाँच भागों में बँटे हुए संयुक्त राज्य के समस्त राज्य इस बात को मानते हैं, भले ही इन दोनों में से कोई भी प्रकार स्कूलों का माना गया हो प्रायः अंगरेजी में ३, हिसाब २, सामाजिक शिक्षा (social studies) २, विज्ञान २, और एक विदेशी भाषा २—अर्थात् ११ इकाइयों को तो सभी को एकत्रित करना पड़ता है।

छात्रों को समाजोन्मुखी बनाने की योजनाएँ तथा स्कूल के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने की क्रियाएँ उक्त संस्थाओं में समुचित मात्रा में हैं। साधन तथा सुविधाएँ प्रत्येक राज्य में भिन्न हैं फिर भी यही वहाँ की शिक्षा के मजबूत आधारस्तम्भ हैं। यहाँ अधिक से अधिक समय तक रहने के लिए छात्रों को लालच दिया जाता है। सभ्यता की जटिलता तथा नौकरियों की कमी एक समस्या हो चुकी है।

स्थानीय स्कूल-डिस्ट्रिक्ट, राज्य-सरकार, के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार भी काफी धन माध्यमिक शिक्षा के लिए व्यय करती है। विशेषकर कृषि के लिए, स्कूल के मध्यान्तर में भोजन इत्यादि के लिए केन्द्र धन देता है। माध्यमिक शिक्षा सब के लिए, व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए।

जूनियर हाई स्कूल—छात्रों को समान रुचि वाले छात्रों और प्रायः समान वयस वाले छात्रों के साथ रखने के लिए, किशोरों की समस्याओं की पूर्ति के लिए, उनकी चि के अनुसार शिक्षा और स्कूलों के स्थानों की कमी को पूरा करने के लिए इन स्कूलों का जन्म हुआ था। बहुत से जूनियर हाई स्कूल केवल ७ या ८ कक्षा को मिलकर बने हैं तथा किसी भी तरह वे प्रारम्भिक शिक्षा से भिन्न नहीं हैं। जूनियर हाई स्कूल न किसी इमारत का नाम है और न यह कोई पुनःसंघटन है। पाठ्य-क्रम, पाठन-विधि इत्यादि के आधार पर इनकी भिन्नता निश्चित हो जाती है। पहले इसका नाम माध्यमिक स्कूल था और फिर जूनियर हाई स्कूल पड़ा।

नेशनल सर्वे आफ सैकन्डरी एजूकेशन ने एक जूनियर हाई स्कूल के लिए निम्न रूप-रेखा दी है :—

१. उसमें प्रवेश तथा उन्नति की सुविधा होनी चाहिए,
२. शिक्षण की व्यवस्था,
३. पढ़ाने का प्रोग्राम,
४. पाठ्यर्यातिरिक्त योजना,
५. शैक्षणिक तथा व्यावसायिक परामर्श,
६. सन्धियोजन की विशेषता,
७. विशेष रूप से पढ़ा-लिखा अध्यापक-वर्ग,
८. पढ़ाई का पर्यवेक्षण,
९. पृथक् बिल्डिंग तथा अध्ययन की सामग्री।

जूनियर हाई स्कूल आज माध्यमिक शिक्षा की पहली सीढ़ी हैं। ग्रिगिल महोदय ने इसकी परिभाषा दी है, "जूनियर हाई स्कूल ७वीं, ८वीं, तथा ९वीं कक्षाओं की व्यवस्था है जिसे पढ़ाई तथा योग्यता के अनुसार बदलती शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रकृति के आधार पर अपरिपक्वों, परिपक्वों तथा इस क्रिया के छात्रों को उचित शिक्षा देना है"। सीनियर हाई स्कूल ९, १०, ११, १२ कक्षाओं को मिलाकर बना है। प्रायः जहाँ जूनियर हाई स्कूल हैं वहाँ ९वीं कक्षा जूनियर हाई स्कूल में चली गई है। फिर भी उक्त चारों कक्षाओं के हाई स्कूल का महत्त्व अमरीकी शिक्षा में अवश्य ही रहेगा।

जूनियर कालेज—परम्परा के अनुसार २ वर्ष का जूनियर कालेज ४ वर्ष के कालेज की पहले दो वर्षों के समान ही है क्योंकि वह उन्हीं से बनाया गया है। आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार २ वर्ष का जूनियर कालेज माध्यमिक शिक्षा का अंग होता जा रहा है। केलीफोर्निया में इसे माध्यमिक शिक्षा का अंग मान कर व्यवस्था की गई थी अतः वहाँ इनकी संख्या सबसे अधिक है। चाहे वह माध्यमिक शिक्षा के भाग हों या उच्चतर शिक्षा के, उन्हें इन दोनों से ही सम्बन्धित रहना पड़ेगा और सन्धि-योजन दोनों ओर ही करना पड़ेगा। इलीनोइज और टक्सास राज्यों से प्रारम्भ होकर यह २०वीं शताब्दी की देन अपने

को बढ़ाती ही गई। निम्न अंकों से इनकी प्रगति का अनुभव हो सकता है :—

वर्ष	कालेजों की संख्या	छात्रों की संख्या
१९२२	२०७	१६,१२१
१९३४	५१४	१,०३,५९२
१९४६	५९१	२,५१,२९०
१९५८	७००	७,००,०००

ये जूनियर कालेज जनता, धार्मिक संस्थाओं या प्राइवेट संस्थाओं के हाथों में हो सकते हैं। प्राइवेट कालेज अधिक हैं तथा वे सह-शिक्षा देते हैं।

प्रेसीडेन्ट कमीशन जो उच्चतर शिक्षा के विषय में बैठा था उसने इन कालेजों के महत्त्व को बता कर इनका होना अनिवार्य बताया। इनका नाम समुदाय कालेज (Community College) होना चाहिए तथा इन्हें स्थानीय संस्थाओं से ही आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इन बातों पर भी वल दिया। कुछ स्थानों में जैसे न्यूयार्क राज्य में ये उच्च व्यवसायिक शिक्षा भी देते हैं और कहीं कहीं सामान्य शिक्षा ही देते हैं।

जूनियर कालेजों की उत्पत्ति—प्रारम्भ में ये केवल दो वर्ष के लिए ही थे पर अब ये ४ वर्ष के लिए हो सकते हैं। अपनी स्थापना के आधार पर इनकी विभक्ति कई प्रकार से सम्भव है, १. हाई स्कूल में ही दो वर्ष जोड़ कर, २. कालेज से २ वर्ष घटाकर, ३. कालेजों और यूनिवर्सिटी से जोड़ कर, या ४. एक नई इकाई के रूप में खोल कर। राज्य भर में नियमानुसार या विशेष नियम द्वारा इनकी स्थापना सम्भव है।

इनकी कार्य विधि—ये उच्च शिक्षा को अधिक लोकप्रिय बनाते हैं; कालेज के लिए छात्रों को तैयार करते हैं; अवसान-शिक्षा देते हैं और सलाह देते हैं। इन कालेजों को नवयुवकों और प्रौढ़ों सभी के लिए उपयोगी बनाना है।

पाठ्य-क्रम—इन कालेजों में वैसे सामान्य शिक्षा भी दी जानी चाहिए अन्यथा एकांगी प्रगति से व्यक्तित्व का विकास भी एकांगी ही रह जायगा। इसीलिए न्यूयार्क राज्य के रोजेन्ट प्लान ने यह कहा था "कि हमारी संस्था को बहुमुखी कार्य करने होंगे और यहाँ टैक्नीकल के साथ-साथ सामान्य शिक्षा भी दी जायगी।"

प्रायः बहुत से छात्र इन जूनियर कालेजों से आगे नहीं जाते फिर भी वे अवसान-शिक्षा (Terminal Education) नहीं लेते। व्यावसायिक और अर्धव्यावसायिक के साथ-साथ उन्हें इस अवसान-शिक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।

इन उपर्युक्त सामान्य तथा अवसान-शिक्षा के अतिरिक्त भी वे कालेजों की तैयारी वाले अन्य पाठ्य-क्रमों का आयोजन रखते हैं ताकि भविष्य की उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को तैयार किया जा सके।

जूनियर कालेजों का भविष्य—व्यापार की मंदी के समय में, युद्ध तथा युद्धान्त पर इन कालेजों को एक जीवन मिला है। और आज वे मजबूत आधारशिला पर खड़े हैं। बहुत से

राज्यों में इनकी संख्यावृद्धि अप्रत्याशित रूप से हुई है। आज उनका राष्ट्रीय एसोसिएशन भी है। इस एसोसिएशन का कथन है कि यदि ये जूनियर कालेज परम्परागत ४ वर्षीय कालेजों की नकल न करें और छात्रों की अभिरुचि के अनुसार ही शिक्षा दें, तो अमरीकी शिक्षण-व्यवस्था में इनको गौरवपूर्ण स्थान मिल सकता है। १९३० ई० में नार्थ कैरोलिक राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि कोई भी स्थानीय संस्था उन्हें कर द्वारा चला सकती है। यह कलामाजू-केस के निर्णय के समान ही है।

क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का विचार केवल हाई स्कूल तक ही समाप्त नहीं होता, इसलिए इनका भविष्य उज्वल है।

चतुर्थ चरण

उच्च शिक्षा

रूपरेखा :—

१. परिभाषा।

२. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

३. उच्च शिक्षा के उद्देश्य।

४. आर्थिक सहायता।

५. छात्रों तथा उच्च विद्यालयों की संख्या।

६. उच्च शिक्षा-संस्थाओं के प्रकार।

७. पाठ्य-क्रम।

८. परीक्षा।

९. उच्च शिक्षा का भविष्य।

१०. उच्च शिक्षा की समस्याएँ और उभयापत्ति।

११. उच्च शिक्षा में आधुनिक प्रवृत्तियाँ।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

'कालेज' तथा 'विश्वविद्यालय' दोनों शब्द ही उच्च शिक्षा के सूचक हैं किन्तु व समानार्थी नहीं हैं। कालेज में प्राय: बी० ० की डिग्री मिलती है किन्तु विश्वविद्यालय उच्च व्यवसाय (Profession) की डिग्री भी देता है और कालेज से बहुत बड़ा होता है। कभी-कभी वह कई कालेजों का संकलन भी हो सकता है और विभागों के हिसाब तो वह बहुत बड़ा होता ही है। वैसे उदार शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तो दोनों ही देते हैं। जेम्स ब्रियान्ट कानेन्ट[1] के अनुसार अमरीकी विश्वविद्यालय ऐसे स्थान हैं जहाँ ज्ञान ज्ञान के लिए ज्ञान दिया जाता है; जहाँ उच्च व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है; जहाँ उदार कलाओं में ज्ञान कराया जाता है और जहाँ सामूहिक भावना (Gregarious Impulse) के कारण लोग पढ़ने आते हों। यही बातें एक आदर्श विश्वविद्यालय में होनी चाहिए। राब ̕ हचिन्स[2] के अनुसार उच्च शिक्षा का अर्थ सत्य की खोज करना है तथा पुरुषों और स्त्रियों को जीवन के लिए तैयार करना है। आरटेगा गेसेट[3] विश्व-विद्यालय को १. उच्च व्यवसायों की शिक्षा का केन्द्र, २. सत्य की खोज का स्थान और ३. सामान्य शिक्षा (General education) देने की जगह मानते हैं।

कालेज और विश्वविद्यालय उक्त कथनों के आधार पर भिन्न मानने ही चाहिए। डो यंग महोदय इन संस्थाओं को विदेशों के लिए बड़ी भ्रामक मानते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—ईसा से चार या पाँच शताब्दी पूर्व ग्रीस में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी तब से आज तक न जाने कितने विश्वविद्यालयों की ससार में स्थापना हो चुकी है। संयुक्तराज्य में प्रथम बार हारवर्ड कालेज सन् १६३६ में खुला था। इस कालेज के उद्देश्य थे : १. साहित्य, कला, तथा विज्ञान की प्रगति के लिए, २. छात्रों की उन्नति, और ३. अमरीकी नवयुवकों और भारतीयों (Red Indians) की शिक्षा। इसके पश्चात् १६९३ में कालेज आफ विलियम एड मेरी खुला। यह औपनिवेशिक युग था। १८१९ में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट संस्थाओं को भी कालेज खोलने की आज्ञा दे दी। फिर क्या था, कालेजों की बाढ़ आ गई। सन् १८६० में २६४ विद्यालय उच्च शिक्षा के लिए थे, उनमें केवल १७ को ही राज्य की सहायता मिलती थी।

सन् १८३८ में माउन्ट हालयोक नामक स्थान में प्रथम बार स्त्रियों के लिए कालेज खुला। इंगलैण्ड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सन् १९२० तक स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था।

---

1. Conant, I.B.; Education in a Divided World. Cambridge, Harvard 'varsity Press 1948 P. 159
2. Hutchins, R.M.; The Higher learning in America. New Haven, Yale Unversity Press, 1952 P. 33
3. Singh, R.P.; Universities in India—Past and Present. Allahabad 'varsity Magazine "उन्मे ", 1957

१८६५ तक स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत सी सुविधाएँ हो चुकी थीं । आज महिला-डाक्टर (Ph.D.)तो कम हैं पर शिक्षा के क्षेत्र में वे पुरुषों से अधिक संख्या में हैं ।

केन्द्रीय सरकार के तीन पग उच्च शिक्षा की तीव्र प्रगति का कारण बने : १. १७८५ और १७८७ में कुछ भूमि कालेजों के लिए सुरक्षित कर दी गई, २. डार्टमाउथ केस (१८१९) का सुप्रीम कोर्ट का फैसला; और ३. लैंड कालेजों की मौरिल एक्ट के अनुसार सन् १८६२ से स्थापना। म्यूनिसिपल विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण-केन्द्रों ने इसकी प्रगति को और भी तीव्र कर दिया है। युद्ध-काल में सेना विभाग की खोजों में विश्वविद्यालय की सहायता मिली। नौसेना की शिक्षा, अणु-सम्बन्धी खोज, सहस्रों प्राध्यापकों का उधार लिया जाना उस समय की विशेष बातें थीं, जिनके कारण प्रगति होती ही गई।

कानेन्ट महोदय[1] की निम्न संख्याओं से ज्ञात हो जायगा कि संयुक्तराज्य में बहुत बड़ी संख्या में छात्र काफी उम्र तक पढ़ते हैं। निम्न चित्र तुलनात्मक है और उससे स्पष्ट हो जायगा कि संयुक्तराज्य में ११ प्रतिशत (लगभग) छात्र उच्च शिक्षा लेते हैं जबकि इंग्लैण्ड में ३ या २ प्रतिशत। इसका कारण वहाँ मनोरंजन, खेल-कूद इत्यादि का अवसर भी हो सकता है।

चित्र १†

(संख्याएँ प्रतिशत में हैं ।)

उम्र	इंग्लड	स्काटलैंड	आस्ट्रेलिया*		न्यजीलैण्ड		संयुक्तराज्य
१३	९८×	९८×	९८×	९८×	९६	९८×	९५
१४	९८	९५	९९	९५	९३	९८	९३
१५	३१	३७	४२	३८	३५	६०	८८
१६	१६	१४	२२	१८	१८	३३	७६
१७	७.५	९	११	१४	१२	१५	६१

× य संख्या १९४० की हैं ।

* १. दक्षिणी आस्ट्रेलिया २. न्यू साउथ वेल्स ३. विक्टोरिया।

† ये संख्याएँ प्रायः × को छोड़कर सभी १९५० के स्कूल खुलने के समय की हैं।

उच्च शिक्षा के उद्देश्य—उच्च शिक्षा के आर्थिक कमीशन के आधार पर उसके चार मुख्य अनीक (facets) हैं।

१. उदार शिक्षा—जिसका उद्देश्य मस्तिष्क को प्रखर बनाना तथा ज्ञानार्जन कराना है जो स्वतन्त्र समाज के लिए आवश्यक है।

1 Conant. I.B,; Education and liberty. P. 8.

२. उच्च व्यावसायिक शिक्षा जो ज्ञान पर आधारित होती है ।

३. ग्रेजुएट-शिक्षण तथा खोज ।

४. उच्च सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी ।

इस कमीशन के अनुसार उक्त चारों कार्यों का संकलन ही आदर्श है। छात्रों द्वारा स्वयं बताये गये उद्देश्यों के संकलन से निम्न अंश के आधार पर अमरीकी उच्च शिक्षा वहाँ की विचित्र वस्तु है--

१. उपाधि-प्राप्ति के लिए,

२. पत्नी या पति की तलाश,

३. समाज में गोरव-प्राप्ति के लिए,

४. काम से बचने के लिए,

५. व्यावसायिक रुचि उत्पन्न करने के लिए ।

एडलाई स्टीवेन्सन के अनुसार उच्च शिक्षा सत्य की खोज करने के लिए और सभ्यता की सुरक्षा के लिए नये व्यक्तियों को उससे परिचय कराने के लिए है ।

आर्थिक सहायता--१९४७-४८ में इन उच्च शिक्षा के केन्द्रों की आय १,५६१,८९०,००० डालर थी। इसमें २९.३% आन्तरिक सूत्रों द्वारा जैसे ट्यूशन फीस; ११.४% दान द्वारा ; ५९.३% केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा होती थी। और आज १. जनता की संस्थाओं (सार्वजनिक शिक्षा-केन्द्रों) में लगभग ५०.७% छात्र आते हैं और ५२.७% कुल शिक्षा की आय इन पर खर्च होती है; २. ३०% आय छात्रों के द्वारा प्राइवेट कालेजों तथा १०% सार्वजनिक कालेजों में आती है; ३. प्राइवेट संस्थाओं को सार्वजनिक संस्थाओं की अपेक्षा १० गुना दान अधिक मिलता है; ४. केन्द्रीय सरकार, जो १९२८ में इस आय में ५% धन देती थी, आज ४२.६% धन देती है। सन ४७-४८ में केन्द्र ने कुल ५२६० लाख डालर दिये थे। ह्विर्वाि क रिपोर्ट के आधार पर, "आज उच्च शिक्षा की संस्थाओं के अधिकार और सहायता का भेद क्रमशः घट रहा है[1]........." क्योंकि सार्वजनिक स्कूलों को दान, और प्राइवेट स्कूलों को सार्वजनिक धन अधिक मिल रहा है ।

छात्रों तथा उच्च विद्यालयों की संख्या

इस क्षेत्र में हम उत्तरोत्तर प्रगति देख सकते हैं।

सन्	छात्रों की संख्या	विद्यालय
१८२८	३२००	२५
१८४०	१६,२३३	१७३

1 Lee, G. C., An Introduction to Education in Modern America P. 165.

सन्	छात्रों की संख्या	विद्यालय
१८६०	५६,१२०	४६७
१९५०	२,५००,०००	१७८८
१९५५	ज्ञात नहीं	१८५०

(ली तथा डो यंग के आधार पर)

शीघ्र ही यह भी आशा की जा रही है कि इनकी संख्या में अधिक वृद्धि होगी।

उच्च शिक्षा की संस्थाओं के प्रकार :

१. **जूनियर कालेज**—यद्यपि इनका स्थान निश्चित नहीं हो पाया है फिर भी क्योंकि परम्परागत इन्हें कालेज के पहले दो वर्षों के आधार पर ही बनाया गया है इसलिए ये उच्च शिक्षा में ही सम्मिलित हैं। इनके प्रकार भी हैं, केवल स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए इत्यादि।

२. **कम्यूनिटी या टैक्निकल कालेज**—इन्हीं जूनियर कालेजों को कम्यूनिटी कालेजों की संज्ञा उन स्थानों पर मिली है जहाँ जूनियर कालेज शब्द पसन्द नहीं किया जाता। इन्हीं कम्यूनिटी कालेजों की एक किस्म टैक्नीकल कालेज भी हैं। जैसे न्यूयार्क राज्य में व्यवसायों की शिक्षा इन्हीं कम्यनिटी कालेजों में दी जाती है तथा इसी कारण उनका नाम वहाँ बदल दिया गया है।

अधिकतर जूनियर कालेज, टैक्नीकल या कम्यूनिटी कालेज निम्न प्रोग्राम के अनुसार ही कार्य करते हैं: १. अर्ध-व्यावसायिक या पूर्ण व्यावसायिक। (सीनियर कालेज की शिक्षा-सहित) तैयारी कराते हैं, २. किसी व्यापार या दक्षता (Skill) में भी शिक्षा देते हैं। ३. प्रौढ़-शिक्षा, और ४. सामान्य शिक्षा का प्रबन्ध भी करते हैं।

३. **सामान्य कालेज**—हम ऊपर देख आये हैं कि उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य सामान्य शिक्षा भी है इसलिए कालेज के प्रथम दो वर्षों में वे यही शिक्षा देते हैं। कहीं-कहीं जैसे बोस्टन यूनिवर्सिटी में इस दो वर्ष की सामान्य शिक्षा के बाद परामर्शदात्री समिति के परामर्श पर छात्रों को और आगे की शिक्षा के लिए अन्य विभागों में भेजा जाता है।

४. **लिबरल आर्ट्स कालेज**—ये कालेज स्वतन्त्र भी हो सकते हैं या किसी विश्वविद्यालय के विभाग के रूप में भी हो सकते हैं। इनका उद्देश्य उदार शिक्षा, अर्धव्यावसायिक, व्यावसायिक या किसी भी पक्ष में दक्षता देना इत्यादि हैं। जहाँ इनका आयोजन ४ वर्ष के लिए होता है वहाँ क्रमशः विशेष शिक्षा पर बल दिया जाता है। विशेष विषय को महत्त्व देते हुए भी मानवीय विषय (Humainities) सामाजिक विज्ञान, और प्राकृतिक विज्ञान के पाठ्य-

क्रमों में शिक्षा दी जाती है। ये कालेज प्रायः प्राइवेट हैं और इनके छात्रों की संख्या भी बहुत है। विशेष शिक्षा (Specialisation) के साथ-साथ सामान्य शिक्षा भी आवश्यक है, अतः इन कालेजों के पक्ष में अधिक लोकमत है।

५. **म्यूनिसिपल या नगर कालेज और विश्वविद्यालय**—इनकी आर्थिक सहायता स्थानीय सूत्रों से ही आती है और ये ४ वर्ष के कोर्स में शिक्षा देते हैं। किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर जैसे डेट्रोइट वेन यूनिवर्सिटी की सहायता राज्य तथा स्थानीय सूत्र, दोनों से आती है। न्यूयार्क का उच्च शिक्षा का बोर्ड है, जो विश्व के सबसे बड़े चार कालेजों का प्रबन्ध करता है। विभिन्न कारणों से इन विद्यालयों का प्रभाव है।

६. **विश्वविद्यालय**—यहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के उच्च व्यवसायों में डॉक्टरेट (Ph.D.) दी जाती है। ये सार्वजनिक तथा प्राइवेट सभी प्रकार के हैं। केन्द्र की सहायता से ये अनुसंधान-कार्य करते हैं। इनके छात्रों की संख्या उच्च कक्षा के कुल छात्रों की संख्या की आधी है।

७. **राज्य-विश्वविद्यालय**—ये जनता के एक या अधिक बोर्डों के हाथ में हैं जिनके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ राज्य के छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती और ये सार्वजनिक शिक्षा के अन्तर्गत ही आते हैं। इनका क्षेत्र राज्य से लेकर समस्त विश्व है। यही ऐसी संस्थाएँ हैं जहाँ किसी छात्र का प्रवेश रोका नहीं जा सकता। और इनका मुख्य कार्य छात्रों को इकाइयों (units) के आधार पर डिग्री देना है।

८. **लैंड ग्रांट कालेज और विद्यालय**—मौरिल एक्ट के अनुसार (१८६२) ३०,००० एकड़ भूमि प्रत्येक सीनेटर (राज्य-सभा के सदस्य) को दी गई थी ताकि वह अपने राज्य में कृषि तथा मशीनी शिक्षा दे। आज यह फंड संयुक्तराज्य के शिक्षा विभाग द्वारा बाँटा जाता है। उन सभी कालेजों को प्रति वर्ष रिपोर्ट देनी होती है जो आर्थिक सहायता पाते हैं। आज ऐसे २४ कालेज और २८ विश्वविद्यालय हैं जहाँ कृषि, इंजीनियरिंग, गृह-अर्थ-शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। केवल १७ कॉलेज नीग्रो छात्रों के लिए सुरक्षित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या ६९ है। लैन्ड ग्रान्ट कालेज आदर्श पढ़ाई; खोज, तथा प्रसार-सेवा (Extension Services) सभी की सुविधा देते हैं। आज १९१४ के स्मिथ-लीवर एक्ट के अनुसार इन कालेजों का मुख्य कार्य प्रसार-सेवा तथा अपने स्थान से बाहर शिक्षा देना है। यहाँ योग्य व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है और कृषि, मशीन इत्यादि का शिक्षण तथा काम सिखाया जाता है ताकि उससे सब लाभ उठा सकें। इन कालेजों ने अमरीकी

प्रजातन्त्र को सहायता दी है, अतः ये शिक्षा के अभिन्न अंग हो चुके हैं। इसने सहशिक्षा को विस्तृत किया है तथा बहुत से विश्वविद्यालयों के पुनःसंगठन में भी हाथ बँटाया है। इनका माध्यमिक शिक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज इसके राष्ट्रीय आधार पर एसोसिएशन हैं और विशेषकर नीग्रो विद्यालयों का संगठन बहुत ही अच्छा है।

९. **उच्च व्यावसायिक स्कूल**—यहाँ अध्यापन, औषधि तथा चिकित्सा इत्यादि की विशेष शिक्षा दी जाती है। ये उच्च शिक्षा के एक उद्देश्य को पूरा करते हैं। कुछ राज्यों ने इंजीनियरिंग या टैक्नीकल स्कूल भी खोले हैं जैसे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी तथा कुछ लैन्ड ग्रांट कालेज भी इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए प्रारम्भ हुए थे।

१०. **ग्रेजुएट स्कूल**—बहुत से कालेज आज ग्रेजुएट कोर्स में शिक्षा देते हैं; वे इनमें विशेष शिक्षा या उच्च व्यावसायिक (Professional) शिक्षा पर बल देते हैं।

प्रायः उक्त विद्यालयों में १ या २ वर्ष की पढ़ाई, खोज तथा पर्चों के आधार पर M.A. की डिग्री दे दी जाती है। डाक्टरेट (Ph.D.) के लिए प्राय. एम्० ए० के बाद २ वर्ष पढ़ना होता है। किन्तु इनके लिए भिन्न-भिन्न कोर्स हैं।

अन्य उच्च शिक्षा-संस्थाएँ—केन्द्रीय या अर्ध-केन्द्रीय कालेजों तथा विश्वविद्यालयों का समूह संयुक्तराज्य में ही है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में विशेष रुचि होते हुए भी वहाँ केन्द्र ने एक भी विश्वविद्यालय नहीं खोला है। हावर्ड यनिवर्सिटी, वाशिंगटन (जो नीग्रो छात्रों के लिए है); मिलटरी एकेडेमी वेस्ट पाइन्ट; नौसेना शिक्षण-केन्द्र, अनापोलिस इत्यादि केन्द्रीय सरकार की संस्थाएँ हैं।

ग्रीष्म-कालीन स्कूल, जहाँ अध्यापक शिक्षा लेते हैं, वे प्रायः शिक्षकों के लिए ही होते हैं तथा वहाँ पढ़ने पर धन मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ झूठे (False) विद्यालय भी हैं जिनका पता एक विशेष संस्था लगाती है।

पाठ्य-क्रम—माध्यमिक शिक्षा के वर्णन में हम यह कह चुके हैं कि थार्न डाइक की खोजों ने हर विषय को क्योंकि समान स्तर दे दिया है इसलिए वहाँ प्रत्येक विषय को समान गौरव ही प्राप्त है। सजावट, कपड़े पहनना तथा पहनाना, भोजन के तरीके तथा अतिथि-सत्कार, कुश्ती इत्यादि विषय भी पढ़ाये जाते हैं, जिनकी लैटिन, दर्शन, साहित्य इत्यादि से कम महत्ता नहीं है। चूँकि अमरीकी अध्यापकों की नौकरियाँ लोकप्रियता पर निर्भर करती हैं इसलिए वे इस पक्ष की ओर शिक्षण से अधिक ध्यान देते हैं। खोज (Research) के विषयों का उदाहरण लीजिये जैसे—"Photographic studies in Boiled Icing" "Style cycles in Women's under-garments". Or "An analysis of Paring Knives in terms of time and material wastes in paring

potatoes". इत्यादि। यह सत्य है कि जीवन के लिए यह विषय केवल खोज (Pure Research) से अच्छे हैं। आज की अमरीकन यूनिवर्सिटी प्रायः भौगोलिक कारणों से ही एक है अन्यथा इतने अधिक छोटे-छोटे विभाग हैं कि उसे पहचानना भी कठिन है। उपर्युक्त खोजों के तथा विषयों के अतिरिक्त साधारण खोज तथा विषय भी चुने जा सकते हैं जिन से हम भारत में परिचित हैं। कुछ हो, वहाँ की डिग्रियाँ जीवन के लिए अधिक उपयोगी हैं अपेक्षाकृत भारत के। आज की प्रवृति यह है कि नवीन विषयों के साथ-साथ धर्म तथा पुराने विषयों को भी पुनः स्थान दिया जाय। नवीन प्रकार की विधियों जैसे टेलीविज़न द्वारा अध्यापन भी होता है।

परीक्षा--वहाँ परीक्षा का अर्थ छात्र की इकाइयों को जोड़ना है। मापदंड मात्रा का है, किस्म का नहीं। प्रत्येक विद्यालय अपनी डिग्री देता है इसलिए उनका मूल्य भी एक-सा नहीं हो सकता। कानेन्ट[1] के शब्दों में बहुत सी अमरीकन डिग्रियों का मूल्य कुछ नहीं है : "America had started down the road which in the twentieth Century. led the situation where American degrees are almost without meaning." परीक्षा के तरीकों की निष्पक्षता (Objectivity) इस सीमा तक पहुँच गई है कि प्रत्येक विषय में नवीन पद्धति पर परीक्षा की जाती है। प्रत्येक को एक (Grade) या स्तर दिया जाता है। अंगरेजी साहित्य की परीक्षा का उदाहरण[2] देखिये—

1. View point : Under score one — Objective / Subjective / dramatic
2. Types of Poem — 23 types given.
3. Method — Classic, romantic, realistic (Mark one)
4. Rhythm — Character of rising or falling; regular or irregular; double or triple; free (Mark one)
5. Striking phrases
6. Ornament — Indicate if present.
   a. Alliteration — *g* Hyperbole
   b. Onomatopoeia — *h* Ballad Commonplace
   c. Allusion — *i* Pictorial Phrases
   d. Simile — *j* Musical Phrases
   e. Metaphor — *k* Anti thesis
   f. Personification — *l* Climax इत्यादि

---

1. Conant, I.B. ; Education and liberty. pp. 38-39
2. Kenneth Richmond, Education in U.S.A. p. 212

उच्च शिक्षा का भविष्य——अधिक छात्र और उच्च स्तर, दो बातें हैं; इसे प्रायः सभी शिक्षा-शास्त्री जानते हैं। बुद्धि के विकास, उच्च शिक्षा का उद्देश्यों का पुनःकथन और सुधार, सभी आवश्यक हो चुके हैं——सब विषयों की समानता और प्रत्येक प्रकार के छात्र का उच्च शिक्षा में प्रवेश सोचने के विषय बन चुके हैं। विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा को साथ-साथ देना ही उचित है। अभी छात्रों की संख्या और बढ़ेगी। इस शिक्षा का भविष्य उज्वल है, परंतु बहुत-सी समस्याओं का अभी सामना करना होगा।

उच्च शिक्षा की समस्याएँ और उभयापत्ति (Dilemma)

१. ली[1] के अनुसार उच्च शिक्षा का अर्थ मनुष्य का पूर्ण रूप से सम-विकास है; आज अमरीकी विशेष-शिक्षा (Specialisation) का परिणाम है कि विकास एकांगी (Lop-Sided) होकर रह गया है। इसके लिए आज सामान्य शिक्षा का मत्र दिया गया है, जो १. अत्यधिक विषयों के बाँटे जाने के विरुद्ध है; २. सभी को समान रूप से जीवन के लिए कुछ शिक्षा देना आवश्यक है चाहे उनके व्यवसाय कितने ही भिन्नक्यों न हों; और ३. मूल्यों (Ualues), रुचि और दक्षता में शिक्षा देंना ताकि जीवन में सफलता मिले और व्यक्तित्व का विकास हो।

यह सामान्य शिक्षा (General education) उसी उदार शिक्षा का नवीन रूप है। इस कथन का अर्थ हुआ कि उभयापत्ति है विशेष-शिक्षा अथवा सामान्य शिक्षा के साथ विशेष शिक्षा का देना।

२. उच्च शिक्षा के लिए अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रेसी`न्ट कमीशन (१९४७) ने बता दिया था। यह सत्य है कि अमरीकी विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत है और बहुत अवसर देने का अर्थ होगा जैसे फोर्डाम विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा था कि——"By multiplying college Facilities until they can care for every high school graduate who does not want to go to work, the Commission is not doing any favour...This programme threatans us with tides of mediocrity" अर्थात् कमीशन की रिपोर्ट का परिणाम साधारण बुद्धि वाले छात्रों द्वारा विश्वविद्यालयों को भर देना होगा। यह द्वितीय उभयापत्ति है।

३. राबर्ट मैनार्ड हचिन्स[2] के अनुसार उच्च शिक्षा में भ्रान्ति (Confusion) है।

(१) उसका प्रथम कारण है अत्याधिक धन से प्रेमः अधिक छात्र

1. G.C. Lee, Op. Cif. P. 172-178.
2. Hutchins, R.M.; The Higher learning in America. pp.1-119

होंगे तो अधिक आय होगी। जनता की माँग पर नवीन विषयों की शिक्षा देकर अधिक से अधिक धन कमाना और साधारण बुद्धि वाले छात्रों को अधिक समय तक विश्वविद्यालयों में रखकर उनका मनोरंजन करना—इत्यादि उच्च शिक्षा की बुरी प्रवृत्तियाँ हैं।

(२) प्रजातन्त्र के अर्थ की भ्रांति भी एक उभयापत्ति है। प्रत्येक को उसकी रुचि तथा योग्यता के बिना भी उच्च शिक्षा देने का अवसर ही प्रजातन्त्र समझा जाता है। यद्यपि प्रत्येक उस शिक्षा से लाभ नहीं उठा सकता। The democratic view that the State may determine the amount of money to be spent on education and may regulate education and educators by law, has nothing to do with the wholly democratic nation that citizens may tell educators how to conduct eductaion and still less with the fantastic position that they may tell them how to live, vote, think and speak. अर्थात् जन-साधारण के व्यक्तियों को शिक्षा से सम्बन्धित व्यक्तियों के कार्य में बाधा डालने या सलाह देने की क्या आवश्यकता है ?

(३) आज धन-लोलुपता और प्रत्येक को उच्च शिक्षा देने की प्रवृत्ति का बुरा परिणाम हुआ है। आज चूँकि विश्वविद्यालयों पर कोई विशेष कार्य-विधि और कार्य-क्रम तो है नहीं, सलिए विश्वविद्यालय अपने हरे-भरे मैदानों, अच्छी इमारतों, तथा मनोरंजन की सामग्रियों का विज्ञापन करते हैं। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य—सत्य की खोज—ऐसे वातावरण में धुँधला होता जा रहा है।

(४) अत्यधिक व्यावसायिक शिक्षा की हानि को पूरा करने के लिए अब सामान्य शिक्षा देकर असफल प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(५) उन शास्त्रीय विषयों का, जिनमें प्रत्येक सत्य निहित है, पढ़ाना उचित है। पढ़े-लिखे व्यक्तियों में थोड़ी बहुत तो समानता होनी चाहिए। इसलिए उनकी शिक्षा का कुछ अंश तो एक-सा होना ही चाहिए। विकास मशीनों का बहुत हुआ है पर मस्तिष्क के विकास के प्रति उन्हें संदेह है, इसलिये हचिन्स का कथन है कि नवीन विषयों के पीछे न भाग कर शुद्ध ज्ञान की जानकारी प्राप्त करनी चाहि । सामान्य शिक्षा ही इसका उपचार है। विभिन्न विभागों में बँ ज्ञान को तत्त्व-ज्ञान के सहारे संकलित करके शिक्षा देना, यह ज्ञान को पुनः संगठित करने का एकमात्र तरीका है।

१. सामान्य शिक्षा का प्रबन्ध;

२. उच्च शिक्षा का क्रमशः अधिक आयोजन;

३. शिक्षा के विषयों में संकलन (Integration);

४. प्रादेशिक (Regional) कालेज के प्रबन्धों का जहाँ बिना अधिक खर्चे के पुस्तकें इत्यादि एकत्रित कर ली जाती हैं और उनसे लाभ उठाया जाता है;

५. कालेज के शिक्षकों को भी उचित प्रशिक्षण देना और उनका ठीक चुनाव करना।

पंचम चरण

प्रौढ़-शिक्षा

रूपरेखा :—

१. परिभाषा, कारण तथा उद्देश्य।
२. क्या प्रौढ़ कुछ सीख सकते हैं ?
३. अमरीकी प्रौढ़-शिक्षा का इतिहास।
४. आज की प्रौढ़-शिक्षा का संगठित रूप।
५. प्रौढ़-शिक्षा : अध्यापन।
६. प्रौढ़-शिक्षा-सामग्री।
७. आधुनिक प्रवृत्तियाँ।
८. आज की प्रौढ़-शिक्षा की माँग।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

परिभाषा, कारण तथा उद्देश्य——मालकाम नॉलेस[1] ने प्रौढ़-शिक्षा की परिभाषा दी है "अपने विस्तृत अर्थों में इसमें वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जो प्रौढ़ पुरुषो और स्त्रियों को समझ, दक्षता, अभिवृत्ति, रुचि तथा मूल्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं।"

अमरीकी जीवन में इसका मूल्य बढ़ने के निम्न कारण हैं——

१. मशीन तथा टैक्नोलोजी की प्रगति;

२. प्रौढ़ों की संख्या में बढ़ोतरी——१८५० में २० वर्ष से कम आयु के युवकों की संख्या कुल आबादी की आधी थी किन्तु १९३० में वह घटकर केवल ⅖ रह गई। और १९५० तक वह एक-चौथाई ही रह गई। इससे स्पष्ट है कि प्रौढ़ों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

३. कम कार्य तथा अधिक अवकाश;

४. विभिन्न नवीन तरीकों की वृद्धि, जिनसे अधिक से अधिक व्यक्तियों से कम से कम समय में सम्बन्ध स्थापित किया जा सके जैसे रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि।

निरक्षरता को समाप्त करना; विदेशियोंको जो अमरिका में आकर बसे थे उन्हें अमरीका जीवन से परिचित कराना, पुनः शिक्षा देना, व्यावसायिक तथा रुचि के हेतु सलाह देना इत्यादि उद्देश्य लेकर प्रौढ़-शिक्षा में जीवनसंचार हुआ। इन उद्देश्यों में कुछ तो केवल अमरीकी जीवन के लिए ही उपयुक्त लगते हैं, किन्तु अधिकतर सभी देशों में इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर ही प्रौढ़-शिक्षा प्रायः दी जाने लगी है।

क्या प्रौढ़ कुछ सीख सकते हैं ?—इस वि य में यह कहा जाता है कि प्रौढ़ प्रायः सीख नहीं सकते; किन्तु ऐसा कहते ही हम बहुत से उन व्यक्तियों के विषय में भूल जाते हैं जो काफी देर में पढ़ना प्रारम्भ करके विश्व के बड़े व्यक्तियों में सम्मलित हो गये। यह सत्य है कि बालकों को भाँति उन्हें रंगीन चित्रों से आकर्षित करके नहीं पढ़ाया जा सकता। थार्न डाइक की महान खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है[2] कि सीखना जीवनपर्यन्त सम्भव है। नॉलेस का कथन है कि हाल की खोजों ने जिनमें सीखने पर परीक्षण हुए हैं यह सिद्ध कर दिया है कि सीखने की शक्ति कम नहीं होती वरन् सीखने का अनुपात कम हो जाता है। ("More recent experiments involving actual learning

1. Knowles, M.S.; Adult Education in the United States—The Hindustan Times Weekly, 7 August 1955.
2. De Young; An Introduction to American Public Education. p.265

situations reveal, however, that it is not the capacity to learn that declines, but the rate of learning.")

अमरीकी प्रौढ़-शिक्षा का इतिहास--विश्व के प्रारम्भ से आज तक प्रौढ़ सीखता ही रहा है, अस्तु, इस शिक्षा का इतिहास मानव-इतिहास के समान ही पुराना है। नियमित रूप से लाइसियमों (Lyceums, १८२०) ने व्याख्यान-पद्धति से पढ़ाना प्रारम्भ किया किन्तु इससे भी पूर्व सन् १७०० के लगभग, यद्यपि इस प्रकार के नाम से संस्थाएँ नहीं थीं, राजनैतिक तथा सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठन थे। १८७४ में शोटोकुआ (Chautauqua) की प्रथम बार स्थापना हुई। इन में भी लाइसियम-पद्धति का ही अनुकरण हुआ और प्रायः इनका पढ़ाने का समय ग्रीष्म का अवकाश था। १८९० तक तो विश्वविद्यालयों ने भी प्रसारकार्य प्रारम्भ कर दिया तथा डाक-द्वारा शिक्षा देने लगे। डो यंग महोदय का कथन है कि संगठित रूप में प्रौढ़-शिक्षा प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् ही प्रारम्भ हुई। सन् १९२४ में क्लीवलैन्ड में इस प्रकार की शिक्षा को व्यवस्थित रूप मिला और इस शब्द का प्रचलन हुआ। उसी समय बाहर से आये हुओं के विभाग का नाम प्रौढ़-शिक्षा-विभाग रख दिया गया।

आज की प्रौढ़-शिक्षा का संगठित रूप—निम्न समूहों[1] में प्रौढ़-शिक्षा-समस्याओं को बांटा जाता है--

१. सार्वजनिक स्कूल (सामान्य तथा व्यावसायिक स्कूल);
२. कालेज, टैक्नीकल इन्स्टीट्यूट तथा विश्वविद्यालय;
३. पुस्तकालय तथा अजायबघर;
४. स्थानीय, राज्य तथा केन्द्रीय इकाइयाँ;
५. जेल, अस्पताल और क्षयरोग-स्थान;
६. सामुदायिक प्रौढ़शिक्षा-केन्द्र और स्कूल (पब्लिक स्कूलों को छोड़कर);
७. धार्मिक संगठन;
८. रेडियो तथा टेलीविज़न (मुख्यतः व्यावसायिक);
९. कारपोरेशन तथा श्रम-यूनियन;
१०. उपभोक्ता सहकारिताएँ;
११. सेटिलमैन्ट्स;
१२. क्लब तथा सोसाइटी (वादविवाद, गायनकला इत्यादि);
१३. स्वैच्छिक संगठन (जनता के लाभ के लिए) जैसे राष्ट्रीय क्षय संघ; विदेशी नीति संघ, इत्यादि;
१४. प्राइवेट व्यावसायिक तथा डाक-स्कूल।

---

1. International Directory of Adult Education, P. 276 (U.N.E.S.C.O. 1652.)

आर्थिक सहायता के आधार पर प्रौढ़-शिक्षा का आयोजन निम्न रूप से हो सकता है; यद्यपि सार्वजनिक तथा प्राइवेट, दोनों प्रकार की सहायता इस प्रकार दी जाती हैं कि प्रौढ़ दोनों से ही लाभ उठाते हैं।

सार्वजनिक शिक्षा--(१) स्कूलों का कार्य : स्कूल-बोर्ड्स द्वारा संचालित प्रौढ़-शिक्षा-सम्बन्धी कार्य बहुत बड़ी संख्या में फैले हुए हैं। स्थानीय शिक्षाबोर्ड स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस शिक्षा का आयोजन करते हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न नाम के पदाधिकारी इसके संचालक रहते हैं। प्रत्येक प्रौढ़-शिक्षा पाने वाला स्कूल में नहीं आता, क्योंकि क्लब, घर, चर्च, सार्वजनिक इमारतों इत्यादि में भी वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए इस प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं। स्थानीय व्यापारिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएँ इस शिक्षा में सहयोग देती हैं। प्रौढ़-शिक्षा के बड़े-बड़े केन्द्रों से लेकर छोटे-छोटे सभी प्रकार के केन्द्र वहाँ पाये जाते हैं। बहुत सी सुविधाएँ स्थानीय संस्थाओं के धनी या निर्धन होने पर ही निर्भर हैं। धनी संस्थाएँ बड़ी-बड़ी इमारतों में हवाई जहाज से लेकर साधारण मशीनों तक की शिक्षा देती हैं। फ्रेंक विगिंस ट्रेड स्कूल, लास ऐन्जिलस; न्यूयार्क सिटी इवनिंग ट्रेड स्कूल इत्यादि उक्त प्रकार के बड़े-बड़े स्कूल हैं। किन्तु अब भी काफी संख्या में ग्रामीण तथा नगरों में इस प्रकार की सुविधाएँ नहीं हैं।

राज्य की आर्थिक सहायता--प्रत्येक राज्य अलग-अलग प्रौढ़-शिक्षा के लिए सहायता देता है इसलिए धनी तथा निर्धन राज्यों की प्रौढ़-शिक्षा की सुविधाओं में अन्तर है। कुल ४८ राज्यों में से १० अधिक (जैसे न्यूयार्क, केलीफोर्निया, पेनसिल्वानिया इत्यादि), १५ साधारण तथा शेष २३ राज्य बिल्कुल सहायता नहीं देते।

राज्यों की सहायता के कारण प्रौढ़-शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि हो जाती है तथा स्थानीय इकाइयों का बोझ कम हो जाता है। केलीफोर्निया राज्य में १.८ % प्रौढ़ों की फीस से, १६.८% स्थानीय करों द्वारा तथा ६३.८ % धन राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता है। इसके विपरीत मिशीगन राज्य के ६ स्कूलों में ४२.५ % फीस, ४२.७% स्थानीय तथा ४.७ % राज्य द्वारा प्रौढ़-शिक्षा पर व्यय होता है। इसी प्रकार प्रौढ़ शिक्षार्थी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न संख्या में शिक्षा-हेतु आते हैं।

राज्य तथा विश्वविद्यालय—राज्यों द्वारा आर्थिक सहायता के अतिरिक्त कालेजों और विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रौढ़-शिक्षा के लिए बहुत से कार्य प्रारम्भ कर रखे हैं। कुछ विषय साधारण छात्रों जैसे तथा कुछ भिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती हैं। सामान्यतया उनके पढ़ने का समय भी अपना अलग ही होता है। १९४८ की खोज के आधार पर ४३१ कुल शिक्षा-संस्थाएँ हैं जो प्रसार-कोर्स पढ़ाती हैं। उनम बहुत से प्राइवेट विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक कालेज हैं। कम समय से लेकर अधिक अवधि तक की शिक्षा उन केन्द्रों

में दी जाती है। राज्य के अन्य विभाग तथा संस्थाएँ भी इस प्रकार के आयोजनों में सामूहिक रूप से सहायता करती हैं।

ग्रामों के लिए शिक्षा—प्रत्येक कृषि-विद्यालय का प्रसार-डायरेक्टर अपने क्षेत्र में संयुक्तराज्य के कृषिविभाग के लिए कार्य करता है। यह शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रारम्भ की गई है। केन्द्र ही उसके लिए धन देता है। किन्तु केन्द्र के धन के बराबर ही स्थानीय तथा राज्य मिलकर धन खर्च करते हैं और ग्रामीण शिक्षा के लिए भोजन से लेकर सफाई तथा कृषि-शिक्षा तक के लिए कार्य होता है। कृषिशिक्षा-प्रसारविभाग के अतिरिक्त भी कृषकों को सहायता देने के लिए अन्य विभाग हैं।

युद्ध से लौटे हुए व्यक्तियों को, चाहे सेना में हों या बाहर, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा (प्रारम्भ से लेकर उच्चतर शिक्षा) दी जाती है; यहाँ वे मशीनों, व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिक्षा लिबरल आर्ट्स कालेजों में प्राप्त कर सकते हैं।

पुस्तकालयों का कार्य—नगरों तथा ग्रामों सभी में प्रायः पुस्तकालयों का आयोजन हैं जहाँ अच्छी-अच्छी पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें आती रहती हैं। यहाँ प्रौढ़ों की सहायता भी पुस्तकों के चुनाव में ली जाती है। चलते-फिरते पुस्तकालयों का प्रबन्ध भी वहाँ पर है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, एटोमिक एनर्जी कमीशन, संयुक्तराज्य का बच्चों का ब्यूरो इत्यादि इस कार्य में हाथ बटाते हैं।

अ—सार्वजनिक संस्थाएँ—जिस प्रकार की शिक्षा तथा प्रबन्ध हम सार्वजनिक संस्थाओं के अन्तर्गत देख चुके हैं लगभग उसी प्रकार का कार्य यहाँ होता है। जो संस्थाएँ दान द्वारा चलाई जाती हैं वहाँ सार्वजनिक संस्थाओं जैसी ही शिक्षा दी जाती है। यहाँ ऊँची फीस ली जाती है इसलिए उनका क्षेत्र व्यापक नहीं है। यहाँ के प्रौढ़-शिक्षा-व्यय पर लोकसभा में सदस्यों के स्थान पर बोर्ड आफ ट्रस्टीज मत देते हैं। प्रयोगों की सफलता के विषय में न्यूयार्क विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है; इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होते रहते हैं। श्रमिकवर्ग के नेताओं की शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। हारवर्ड विश्वविद्यालय ट्रेड यूनियन फेलोशिप आयोजित करता है ताकि उच्च पदों के योग्य श्रमिक-नेता तैयार किये जा सकें। अन्तर्राष्ट्रीय स्त्रियों की पोशाक बनाने वालों की संख्या भी अपनी ट्रेनिंग देती है। इसी प्रकार बहुत-सी अन्य संस्थाएँ भी अपनी-अपनी ट्रेनिंग देने का कार्य करती हैं। बहुत-सी व्यापारिक तथा व्यावसायिक संस्थाएँ भी प्रौढ़-शिक्षा देती हैं। सन् १९४८ में लगभग ३००० व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा ले रहे थे।

केन्द्र से रेडियो द्वारा शिक्षा का लाइसेन्स मिल जाने पर, पढ़ाई के डाक-कोर्स भी दिये जाते हैं। तथा उन पर डिग्री भी मिलती हैं जैसे लूसाविले विश्वविद्यालय इस प्रकार डिग्री देता है। कुछ धार्मिक संस्थाएँ भी इस प्रकार के कोर्स में शिक्षा देती हैं। बहुत सी संस्थाएँ डाक-कोर्स केवल धनार्जन के लिए देती हैं। माता-पिता (Parents) की समस्याओं पर भी वहाँ शिक्षा दी जाती है। १९५१ से फोर्ड फाउन्डेशन ने बहुत अधिक

मात्रा में धन देना प्रारम्भ कर दिया है जिससे प्रौढ़-शिक्षा म प्रगति हुई है।

कई संस्थाओं ने अब सामूहिक रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, ताकि प्रौढ़-शिक्षा भली भाँति संगठत हो जाय। जैसे, १९५० में अमेरिकन एसोसियेशन आफ एडल्ट एजूकेशन तथा नेशनल एजूकेशन एसोसियेशन का प्रौढ़-शिक्षा-विभाग मिल कर एडल्ट एसोसियेशन आफ यू. एस. ए. हो गये। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं को भी एक कर दिया—दोनों ने मिलकर 'एडल्ट एजूकेशन' नाम की पत्रिका निकालना प्रारम्भ कर दिया। इनके अतिरिक्त और भी इस प्रकार के उदाहरण हैं।

प्रौढ़-शिक्षा : अध्यापन—प्राय: समूहों, कक्षाओं, कान्फ्रन्सों इत्यादि में शिक्षा दी जाती है। किन्तु व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षा अपवाद नहीं है। पुस्तकें, चाट, फिल्म, भाषण, वादविवाद सभी का प्रौढ़-शिक्षा में उपयोग होता है। लेकिन अब भी शिक्षा-सामग्री तथा योग्य अध्यापकों की कमी है।[1] श्रव्य-दृश्य शिक्षा आज व्यर्थ सी लगती है यदि उसके पश्चात् वादविवाद, गोलमेजों इत्यादि का प्रबन्ध न हो। विविध नवीन विधियों को इस शिक्षा में काम में लाया जाता है। टेलीविजन लोक-प्रिय माध्यम बन चुका है।

अब चार विश्वविद्यालय (कोलम्बिया, शिकागो, केलीफोर्निया तथा मिशीगन) प्रौढ़-शिक्षा के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देते हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों के अपने-अपने नियम हैं। फिर भी प्रत्येक राज्य में इस प्रशिक्षण के पश्चात् भी ट्रेनिंग प्राय: अनिवार्य है जो लगभग सदैव ही दी जाती रहती है।

प्रौढ़-शिक्षा-सामग्री

१. आधार-भूत विषयों की कमी को दूर करना जैसे भूगोल, हिसाब, अंगरेजी इत्यादि।
२. सामान्य शिक्षा, विज्ञान, मानवीय विषय तथा उच्च अंगरेजी इत्यादि;
३. व्यावसायिक दक्षता—अर्ध, पूर्ण तथा उच्च व्यावसायिक;
४. कला, हस्त तथा अन्य कलाएँ इत्यादि। जैसे गान, चित्र आदि-आदि;
५. गृह-शिक्षा—होने वाली माँ के लिए, माँ-बाप बनने की समस्याएँ इत्यादि;
६. स्वास्थ्य-शिक्षा;
७. नागरिकता की शिक्षा;
८. अंतर्राष्ट्रीय विवेक के लिए शिक्षा;
९. प्रौढ़ शिक्षक, अधिकारी इत्यादि की शिक्षा के लिए सामग्री;
१०. भिन्न-भिन्न सभ्यताओं तथा व्यक्तियों के प्रति विवेक के लिए; तथा,
११. घायलों एवं लंगड़े-लूलों के पुन:व्यवस्थापन के लिए।

यह पाठ्य-सामग्री भिन्न-भिन्न संस्थाओं में भिन्न क्षे त्रों में दी जाती है तथा एक ही कार की शिक्षा भी भिन्न संस्थाएँ प्राय: देती हैं।

---

1. Directory of Cir. p. 276.

आधुनिक प्रवृत्तियाँ

१. जन-शिक्षा के स्तर के ऊँचे होने के साथ-साथ प्रौढ़-शिक्षा की माँग बढ़ रही है;
२. युद्ध के कारण सैनिक तथा अन्य सभी व्यक्ति अधिक से अधिक शिक्षा लेना चाहते हैं;
३. उचित रूप से आयोजित शिक्षा तो युद्ध-काल में ही प्रारम्भ हुई है; तथा,
४. आर्थिक, मशीनी एवं अन्य प्रगति ने इस शिक्षा की माँग को बढ़ा दिया है।

निम्न प्रकार की प्रौढ़-शिक्षा की माँग बढ़ रही है

१. बहुत से नवयुवकों ने आर्थिक समस्याओं तथा युद्ध के कारण पढ़ना छोड़ दिया था, आज उनमें उच्च शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में युद्ध से लौटे हुए सैनिकों को केन्द्रीय सहायता मिल रही है;
२. नागरिकता की शिक्षा—क्योंकि प्रजातंत्र के लिए योग्य नागरिकों की आवश्यकता है;
३. अन्तर्राष्ट्रीय समझ के लिए—विश्वशान्ति के लिए यह शिक्षा आवश्यक हो चुकी है;
४. ग्रामवासियों के लिए, क्योंकि अब वे धनी हो चुके हैं;
५. गृह-सम्बन्धी समस्याओं के दूर करने के लिए क्योंकि गार्हस्थ्य जीवन वहाँ जटिल हो गया है;
६. ४० वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए।

भविष्य में प्रौढ़-शिक्षा की उन्नति के लिए निम्न परिवर्तन होने सम्भव हैं—

१. विश्वविद्यालयों का काम बढ़ेगा;
२. श्रमिकों की शिक्षा का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार करेगी;
३. केन्द्रीय सहायता से ग्रामीण पुस्तकालय अच्छे बनेंगे;
४. सामहिक उन्नति के लिए खोजों के आधार पर प्रौढ़ शिक्षकों को सहायता मिलेगी;
५. सार्वजनिक स्कूल विश्वविद्यालयों के हाथ से अधिक कार्य छीन लेंगे तथा उनमें प्रौढ़-शिक्षा-सम्बन्धी खोजों में एक-सूत्र होकर काम करना प्रारम्भ करेंगे।

यद्यपि प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति अपूर्व है फिर भी आज बहुत सी कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने की चेष्टा की जा रही है।[1]

---

1. Selected Approaches to Adult Education Bulletin. 1950, No. 16- by Homer Kempfer, Federal Security Agency; OFFICE OF EDUCATION.

षष्ठ चरण

असाधारण या अतिरिक्त (Exceptional) बालकों की शिक्षा

रूपरेखा :—

१. राष्ट्र-निर्माण और अतिरिक्त बालकों की समस्या।

२. व्यक्तित्व का विकास और अतिरिक्त बालक।

अ—मानसिक क्षेत्र;

आ—शारीरिक क्षेत्र।

३. अतिरिक्त बालकों की आवश्यकताएँ और शिक्षा।

अ—मानसिक क्षेत्र—शिक्षा में सुविधाएँ;

आ—शारीरिक क्षेत्र—शिक्षा में सुविधाएँ।

४. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

राष्ट्र-निर्माण और अतिरिक्त बालकों की समस्या

(१)

"हमें चाहिए कि हम अपने बीच में बच्चे को सबसे बड़ा धन, और सबसे महान् उत्तरदायित्व समझें। हमें चाहिए कि हम उसे कारखानों, व्यापार, राजनीति, तथा अन्य साधारण तथा स्वार्थपूर्ण वस्तुओं से—जो राष्ट्र को कमजोर तथा नष्ट करती हैं, ऊपर मानें। हमें जानना चाहिए कि राष्ट्र सदैव आगे बढ़ता है, बच्चों के बल पर तथा ईश्वर की कृपा से—जो हमारे मुखों को प्रभात की ओर करती है (ताकि हम) फिर से बचपन के कल्याण तथा सेवा में अपने आप को समर्पित कर दें!"

—जॉय एॅल्मर मॉर्गन

अमेरिकन जन-शिक्षा के सदैव परिवर्तित स्वरूप में केन्द्रविन्दु बालक ही है। बालक साधारण हो या असाधारण, उसी पर माँ-बाप तथा शिक्षकों की रुचि तथा प्रयत्न केन्द्रित रहते हैं।

हमारे विद्यालय तथा उनके पाठ्यक्रम सदैव साधारण बालकों के लिए ही बनाए जाते हैं। किन्तु प्रत्येक विद्यालय में कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो साधारण विद्यार्थियों से बिल्कुल अलग होने के कारण, शिक्षकों और विद्यालय से विशिष्ट सेवाएँ तथा कुशलताएँ चाहते हैं। यदि ये विशिष्ट वस्तुएँ उन्हें न मिलें तो विद्यालय में रहना उनके लिए अत्यन्त कठिन हो जाता है। वे औरों के साथ चल नहीं सकते। इनमें से कुछ विद्यार्थियों में शारीरिक रुकावटें, यथा—अन्धापन, बहिरापन, मिर्गी, अपाहिजपन आदि होती हैं। कुछ में मानसिक भिन्नता रहती है, यथा—मन्द-बुद्धि तथा कुशाग्रबुद्धि। कुछ विद्यालयों का भाव-जगत् इतना अशान्त होता है कि वे सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते और समस्या बन जाते हैं। इन्हीं में से कुछ तो अपराधी के रूप में दिखाई देने लगते हैं।

असाधारण या अतिरिक्त (Exceptional) बालक हम उन्हें मानते हैं जो व्यवहार में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, तथा सामाजिक लक्षणों की साधारण सीमा से दूर होते हैं और इसीलिए अपनी योग्यताओं के चरम विकास के लिए जो शिक्षा की विशिष्ट सेवाएँ चाहते हैं।

साधारण बालकों के समान ही असाधारण बालकों के भी जीवन-विकास के चार लक्ष्य होते हैं, यथा,

अ—आत्मविकास (Selfrealization);

आ—(सफल) मानव-सम्बन्ध (Human Relationship);

इ—आर्थिक कुशलता (Economic Efficiency);

ई—नागरिक उत्तरदायित्व (Civic Responsibility); और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, ये विद्यार्थी प्रजातन्त्र के मूल सिद्धान्तों—अधिकारों की समानता तथा

व्यक्तित्व-विकास के अधिकार---के अनुसार शिक्षकों के विशेष ध्यान, अध्यापन की विशिष्ट शैलियों तथा विशिष्ट शिक्षा के अधिकारी हैं।

अन्य देशों की भाँति संयुक्तराज्य में भी असाधारण बालकों की संख्या कुछ कम नहीं है। बाल-स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर हुई व्हाईट हाउस कॉन्फ्रेन्स (Whilt House Conference) के अनुसार १९३० ई० में असाधारण बालकों की संख्या---३०,००,००० थी। इस संख्या में उन बच्चों को सम्मिलित नहीं किया गया जो कुपोषित (Malnuitrited) तथा निर्बलहृदय थे। कुपोषितों की संख्या---६०,००,००० थी, और निर्बल-हृदयों की संख्या ---६२,५०,००० थी।

हाल की प्रकाशित, संयुक्तराज्य शिक्षा-कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार,

१. विशिष्ट कक्षा चाहने वाले, कुल संख्या का---१२.४%;
२. इन विद्यार्थियों की संख्या, लगभग---४०,००,०००;
३. प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय-आयु वालों में 'अतिरिक्त विद्यार्थियों' की संख्या कुल संख्या का---१०-१२%

संयुक्तराज्य में इन असाधारण बालकों की शिक्षा के लिए पर्याप्त अच्छे प्रयत्न हुए हैं। १९४८ ई० में जिन असाधारण विद्यार्थियों को शिक्षा दी गई उनकी संख्या ४,२५,००० थी जबकि १९४० ई० में ३८,५०० तथा उससे भी पहिले १९३२ ई० में ३३,५०० थी।

फिर भी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या की ११-१२% संख्या को विशिष्ट अध्यापकों द्वारा, विशिष्ट शिक्षा-प्रणालियों द्वारा, तथा विशिष्ट विद्यालयों में, प्रशिक्षित करना एक बड़ी समस्या है। प्रगति अवश्य संतोषजनक हुई है किन्तु अभी बहुत करना बाकी है।

(२)

व्यक्तित्व का विकास और अतिरिक्त बालक

अतिरिक्त बालकों, जो आघात या अभाव या अत्यन्त धीमे या तेज विकास के कारण अपने साथियों से एक बड़ी सीमा तक भिन्न दिखाई देते हैं, के व्यक्तित्व-विकास को समझने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसका मूल कारण यह है कि बिना इस तरह के ज्ञान के हम उनकी सहायता तथा शिक्षा के लिए एक स्वस्थ, दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं बना सकते। अतः संक्षेप में ही हम इन विशिष्ट अतिरिक्त बालकों के विकास-क्रम में विशिष्ट बातों का अवलोकन करेंगे।

(अ) अतिरिक्त बालक---मानसिक क्षेत्र

इस वर्ग में दो प्रकार के अतिरिक्त बालक आते हैं, प्रथम तो वे जो कुशाग्रबुद्धि हैं, तथा दूसरे वे जो मन्द-बुद्धि हैं।

शारीरिक विकास में मन्दबुद्धि बालक प्रायः साधारण बालक के समान होते हैं। ऊचाई और शारीरिक भार उनका वैसा ही होता है। कुशाग्रबुद्धि बालकों का शारीरिक विकास भी साधारण बालकों से कुछ ऊपर होता है। किन्तु कुशाग्रबुद्धि बालकों का शारीरिक विकास मानसिक विकास की तुलना में कुछ भी नहीं के बराबर होता है। विशिष्ट मानसिक विकास के कारण ही कुशाग्रबुद्धि बालक शीघ्रता बोलना से सीखते हैं। पढ़ने तथा कक्षापरिणाम उनका सुन्दर रहता है। मन्द-बुद्धि बालकों में मानसिक विकास साधारण बालकों से भी पीछे होता है और इसके अतिरिक्त चलना भी वह देर से आरम्भ करते हैं। पेशाब रोकना उन्हें देर में आता है। बोली उनकी दोषपूर्ण होती है और पढ़ने में वह साधारण बालकों से पीछे रहते हैं।

(आ) अतिरिक्त बालक—शारीरिक क्षेत्र

इस वर्ग में हम तीन प्रकार के अतिरिक्त बालकों पर विचार करेंगे। प्रथम तो वे जिनके 'अतिरिक्त' होने का कारण अन्तःस्रावी ग्रन्थियाँ हैं (Endocrine Glends); दूसरे वे, जो बोलने में दोषी हैं। तीसरे वे जो क्षीण शक्ति (Lowered Vitality) वाले हैं। जहां तक मिर्गीवाले, अपंग तथा कुसामाजिक अतिरिक्त बालकों का प्रश्न है, उनके विकास-क्रम में कोई विशिष्ट बात नहीं होती।

अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के अतिरिक्त बालकों का मानसिक विकास धीमा होता है और इसका परिणाम यह होता है कि उपलब्धि (Acheivement) में हमें वे पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। इन अतिरिक्त बालकों में एक बात और देखी जाती है कि वे चलना भी देर में आरम्भ करते हैं, मूत्र पर नियन्त्रण भी देर में ही कर पाते हैं और बुद्धियुक्त भाषा भी वे देर में ही बोलना आरम्भ करते हैं।

वाक्‌दोषी या तोतला बोलने वाले अतिरिक्त बालकों का, शरीर की ऊँचाई, शरीर-भार, दाँतों का निकास आदि में विकास, साधारण बालकों जैसा ही होता है। किन्तु सबसे बड़ा दोष जो दिखाई देता है कि ये लोग लापरवाही से पुस्तकें पढ़ते हैं। पढ़ना उचित नहीं होता। जहाँ तक इनके जन्म के विषय में शोध हुई है उससे पता चला है कि इन बालकों का जन्म उचित समय से पहिले ही हो चुकता है। इसके अतिरिक्त ये लोग बोलना भी देर में ही आरम्भ करते हैं और साथ ही माँ-बाप की ओर से इन पर बराबर दबाव पड़ता रहा कि जल्दी और ठीक बोलें।

क्षीण शक्ति वाले अतिरिक्त बालकों की माताओं में देखा गया है कि उनमें किशोरावस्था का आगमन (Puberty) देर में हुआ। यही नहीं, इसका परिणाम यह हुआ कि लड़कों और लड़कियों में भी किशोरावस्था देर से आई। अतः ये बालक देर से किशोरावस्था को प्राप्त होते हैं। इन बालकों का शारीरिक विकास भी धीमा ही होता है; किन्तु यह बात सर्वत्र लागू नहीं होती। कुछ क्षीण शक्ति वाले बालकों का विकास साधारण लोगों से भी

तेज होता है। यह बात अवश्य है कि ये बालक अत्यन्त भावुक होते हैं। छोटी बातों से भी इनकी भावनाओं को ठेस लगने की आशंका बनी रहती है।

(३)

अतिरिक्त बालकों की आवश्यकताएँ और शिक्षा

(अ) मानसिक क्षेत्र

मानसिक स्तर के अनुसार बालकों का निम्न वर्गीकरण किया जा सकता है:

बुद्धिलब्धि-विस्तार (I.Q)	श्रेणी
१४० से ऊपर	कुशाग्रबुद्धि (Genius)
१२०—१४०	अति उच्च (Very Superior)
११०—१२०	उच्च (Superior)
९०—११०	साधारण (Normal)
८०—९०	मन्द (Dull)
७०—८०	बुद्धिहीन (Borderline)

उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार अतिरिक्त बालक दो प्रकार के हुए—

१. जिनकी बुद्धिलब्धि-सीमा १४० है या उससे ऊपर;
२. जिनकी बुद्धिलब्धि सीमा ९० से नीचे है।

(१) कुशाग्रबुद्धि अतिरिक्त बालक

कुशाग्र बुद्धि वाले बालक प्रत्येक राष्ट्र के लिए वरदान होते हैं अतः इनके विकास के लिए आरम्भ से ही सचेष्ट होना नितान्त आवश्यक है। ये बालक नेता होने की क्षमता रखते हैं और राष्ट्र के सफल कर्णधार हो सकते हैं। ये बालक स्वाधीनताप्रिय होते हैं और चरित्र अतिरिक्तप्रिय होता है, इसके साथ ही विनम्र तथा दयालु भी होते हैं।[1]

संयुक्तराज्य में इन कुशाग्रबुद्धि बालकों के—जो संख्या में बालकों की कुल संख्या के १ प्रतिशत से भी कम हैं—व्यक्तित्व-विकास के लिए अनेक साधन दिये जाते हैं।

शिक्षा में जो विशेष सुविधाएँ इन बालकों को दी जाती हैं, वे निम्न हैं—

१. कक्षाओं में जल्दी चढ़ाना;
२. विशिष्ट कक्षाओं या विद्यालयों में रखना;
३. उनके अनुभवों में वृद्धि के लिए उपयुक्त साधन जुटाना—क्लबों, वर्कशापों, पुस्तकालयों का उपयोग करना;
४. सामाजिक सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करना;
५. स्वेच्छा से चुने गए पाठ्यक्रमों से शिक्षा देना।

---

1. Baltimore Bulletin of Education.

२—मन्दबुद्धि अतिरिक्त बालक

ये बालक सीखने में सदैव मन्द होते हैं। कठिन चीजें नहीं सीख सकते । समाज के लिए कुशाग्रबुद्धि बालक के समान वरदान नहीं होते किन्तु प्रजातन्त्र में इन्हें भी रहने का अधिकार प्राप्त है और उस सहायता की इन्हें औरों के बराबर ही अपेक्षा है जो इनकी सामर्थ्य के अनकूल इन्हें योग्य बना सके।

संयुक्तराज्य में, मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा के जन्मदाता इटार्ड (Itard) के शिष्य सेगुइन (Seguin) के प्रयत्नों के फलस्वरूप सेमुएल होवे की अध्यक्षता में मैसाचुसेट्स राज्य में १८४८ में प्रथम विद्यालय स्थापित किया गया। इस दिशा में टरमन आदि ने सराहनीय कार्य किया ।

संयुक्तराज्य में मन्द बद्धि वाले अतिरिक्त बालकों को निम्न सुविधाएँ दी जाती हैं—

१. अधिकतर इन बालकों की शिक्षा के लिए जन-विद्यालय (Public Schools) हैं।
२. इन विद्यालयों में कक्षाएँ नहीं होतीं।
३. यहाँ इन बालकों को अपनी सामर्थ्य के अनसार कार्य करना सिखाया जाता है ।
४. कार्य करने की गति तीव्र है या मन्द, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । कार्य का पूरा होना मुख्य है।
५. इन बालकों के लिए कुछ विशिष्ट विद्यालय भी हैं।
६. बहुत से विद्यालय व्यक्तिगत (Private) हैं तथा कुछ ऐसे भी हैं जहाँ ऐसे बालक रह कर पढ़ते हैं।
७. इनको शिक्षा में विशेष बल सफलता पर दिया जाता है—असफलता का कोई स्थान नहीं। बालकों की योग्यता, रुचि आदि को देखकर ही उन्हें कार्य दिया जाता है।

आ—शारीरिक क्षेत्र

शारीरिक क्षेत्र के अतिरिक्त बालक प्रायः कई प्रकार के पाए जाते हैं, यथा दृष्टि-दोष, श्रवण-दोष, वाणी-दोष, अपंग, क्षय, मिर्गी रोग तथा अन्तःस्रावी ग्रन्थि वाले दोष। आगे इन्हीं पर हम क्रम से विचार करना आरम्भ करेंगे।

१—दृष्टि दोष

आँखों द्वारा किसी व्यक्ति को जितने अनुभव होते हैं वे उन अनुभवों की कुल संख्या से अधिक हैं जो उसे अन्यसाधनों से प्राप्तहोते हैं। इसतथ्यसे आँखों की महत्ता को समझा

जा सकता है। और जिन्हें बिल्कुल ही या कम दिखाई देता है उनके लिए विशेष सुविधाओं वाली शिक्षा-योजना कितनी मूल्यवान हो जाती है।

शिक्षा-सुविधाएँ किसे दी जाएँ, इसके लिए सभी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक दोषों की जाँच नितान्त आवश्यक है। नहीं तो सुविधाओं का प्रयत्न ही व्यर्थ है।

दृष्टि-दोष वाले अतिरिक्त बालकों को संयुक्तराज्य में निम्न शिक्षा-सुविधाएँ दी जाती हैं—

१. चिकित्सा-परीक्षा;
२. अन्धे बालकों के लिए स्पर्श विधि द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध है। इस विधि को ब्रेल (Braille) प्रणाली कहते हैं;
३. ब्रेल-पुस्तकालयों से अन्धे विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें भेजी जाती हैं। किन्तु यह प्रणाली श्रम बहुत चाहती है, यही कारण है कि संयुक्तराज्य के अन्धों की चौथाई संख्या ही इस विधि से लाभ उठा पाई है;
४. 'बोलती पुस्तक' से अन्धे बालकों को शिक्षा देने पर विशेष जोर दिया जाता है। ग्रामोफ़ोन रिकार्ड की तरह, इस पुस्तक के बड़े पत्रे होते हैं जो मशीन की सहायता से बोलते हैं और अन्धे बालक सुनकर उसे याद करते चलते हैं;
५. इसके अतिरिक्त संयुक्तराज्य में कुत्तों, या 'दृष्टि बचत योजना' से भी इन बालकों की शिक्षा में सहायता ली जाती है।

२—श्रवण-दोष

विद्यालय जाने वाले लाखों विद्यार्थियों में यह दोष पाया जाता है। इस दोष वाले अतिरिक्त बालक दो प्रकार के होते हैं। एक—बहिरे, तथा दूसरे— ऊँचा सुनने वाले।

यह अनुमान लगाया जाता है कि विद्यालय जाने वालों की संख्या का २१.२% भाग कर्ण-दोषी होता है। साधारण रूप में विद्यालय जाने वाले ३,००,००,००० विद्यार्थियों में ५ प्रतिशत श्रवण-दोषी हैं। इनमें से १५,००,००० बालक तो ऐसे हैं कि जो विशेष विद्यालयों के विद्यार्थी हैं।

संयुक्तराज्य में इन विद्यार्थियों के लिए निम्न शिक्षा-सुविधाएँ हैं—

१. चिकित्सा-परीक्षा;
२. कक्षा में रेडियो-कर्ण की सुविधा। रेडियो-कर्ण (Radio ear) वाणी को बहुत बढ़ा देता है;
३. प्रत्येक विद्यार्थी की मेज पर शीर्ष-श्रावक (Head Phone) का प्रबन्ध।

३—वाणी-दोष

शारीरिक दोषों वाले बालकों की संख्या में सबसे अधिक वाणी-दोष वाले विद्यार्थी आते हैं। विद्यार्थी, वस्तुतः विद्यालय में तथा उससे बाहर, लिखने तथा पढ़ने की अपेक्षा बोलते अधिक हैं। वाणी पारस्परिक व्यवहार में तथा सामाजिक वातावरण में बड़े मूल्य

की होती है। अतः वाणी-दोष वाले अतिरिक्त बालकों को सहायता देना नितान्त आवश्यक हो जाता है।

इन बालकों को शिक्षा-सुविधाएँ निम्न हैं—

१. चिकित्सा-परीक्षा;
२. बोलने की विशेष शिक्षा तथा अभ्यास;
३. विशेष अभ्यास जो विद्यालय तथा घर को लिख दिए जाते हैं;
४. चिकित्सा-गृहों (Clinics) की स्थापना;
५. सुधार के लिए बालकों में, इच्छाशक्ति, धैर्य तथा परिश्रम को बढ़ावा देना;
६. शल्य-चिकित्सा (Surgical opration) की सहायता;
७. आचरण-शुद्धि के लिए अपनी ही वाणी ग्रामोफ़ोन रिकार्ड में भर कर स्वय को ही सुनाना;
८. दर्पण में अपनी आकृति देखते हुए बोलने का अभ्यास करना।

४—अपांग दोष (Crippled—**अंगविशेष-हीनता**)

अपांग दोष वाले अतिरिक्त बालकों की संख्या, संयुक्तराज्य में काफी है। १९४७ की गणना के अनुसार उनकी संख्या ४,४६,५४५ थी (२१ साल की आयु से नीचे)। इस संख्या में, यदि सभी अपांग बालकों को लिया जाता तो ७०,००० और जोड़ना होता। आजकल नकी संख्या ५,५०,००० है और २१ साल से नीचे जनसंख्या के ये लोग १% हैं। हृदय के रोगियों की संख्या, इनके अतिरिक्त, ५,००,००० है।

इन अतिरिक्त बालकों के लिए संयुक्तराज्य की शिक्षा में निम्न सुविधाएँ हैं—

१. चिकित्सा-परीक्षा;
२. पढ़ाई घर पर, अस्पताल या विद्यालय में होती है—
३. सामूहिक अनुभवों में भाग लेने को प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि बालक अपने रोग को भूल जाए;
४. शिक्षा देते समय खेल-प्रणाली का यथा-स्थान उपयोग किया जाता है;
५. आने-जाने की सुविधा के लिए उचित सवारी का प्रबन्ध होता है;
६. विद्यालय के कार्यों में माँ-बाप के सहयोग को प्रोत्साहन देना।

५—क्षय, मिर्गी, क्षीण शक्ति वाले रोग-जन्य दोष

संयुक्तराज्य के बच्चों में क्षय तथा मिर्गी आदि रोगों वाले अतिरिक्त बालकों की काफी संख्या है। मिर्गी के बालक संख्या में ७,००,००० हैं और प्रति १,००० बालकों पीछे ५ बच्चे रोगग्रस्त हैं। इसी प्रकार क्षयरोग से प्रभावितों की संख्या भी ५% है।

इस वर्ग को जो शिक्षा-सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे इस प्रकार हैं—

१. चिकित्सा-परीक्षा;

२. विशेष व्यक्तिगत सहायता;
३. सिनेटोरियम आदि का प्रबन्ध;
४. उचित आराम का प्रबन्ध;
५. पढ़ाई के लिए दीवालों का प्रयोग;
६. क्षीण शक्ति वालों को ग्रीष्म-कैम्प आदि का प्रबन्ध।

इ——सामाजिक क्षेत्र

प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी समय अतिरिक्त सामाजिक होता है। कभी वह अतिसामाजिक होता है और बराबर समूहों के साथ रहना चाहता है। कुछ लोग कभी समूह से अलग रहना चाहते हैं अतः वे असामाजिक होते हैं। कुछ समाज के नियमों तथा परम्पराओं के विरुद्ध जाते हैं और हम उन्हें समाज-विरोधी कहते हैं। इन्हीं को हम अतिरिक्त सामाजिक कहते हैं।

ऐसे अतिरिक्त बालकों की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, फिर भी अनुमान लगाया जाता है कि संयुक्तराज्य के प्राथमिक विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों में इनकी संख्या तीन प्रतिशत है।

इनके सुधार के लिए शिक्षा में निम्न सुविधाओं का समावेश है——

१. नकी पहिचान में शिक्षक ही सबसे अधिक सहायक होता है। वैसे तो अन्य तथ्य भी हैं, यथा——
   अ——बहुतों में शारीरिक कमियाँ होती हैं;
   आ——कुछ विद्यालय की गड़बड़ी से होते हैं;
   इ——अपराध तथा बुरे घरों से सीधा सम्बन्ध होता है।
२. ऐसे बालकों में रचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयत्न;
३. ऐसे बालकों को उनकी समस्याओं में व्यक्तिगत सहायता दी जाती है। इससे इन दुर्गुणों के प्रसार में रुकावट पड़ती है;
४. सहायता रोग के हिसाब से दी जाती है। कोई एक प्रकार की निश्चित सहायता नहीं है।

(४)

अन्त में इतना कहना पर्याप्त होगा कि देश के उत्थान में जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए नित्य नये रास्ते खुलते हों, और ऊषा नित्य एक नया सन्देश लेकर आती हो, वहाँ लाखों असहाय——अतिरिक्त——बालकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

संयुक्तराज्य की शिक्षा-व्यवस्था इस दिशा में काफी जागरूक है और उसके प्रयत्न, इस दिशा में प्रशंसनीय हैं। यह बात अवश्य है कि यह क्षेत्र विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र है जो विशेषतः दो वास्तविकताओं पर आधारित है——देश में बढ़ा हुआ चिकित्सा-विज्ञान तथा

मनोविज्ञान और इनके साथ धन की उचित व्यवस्था; क्योंकि विद्यालय, सामग्री तथा अध्यापक सभी मूल्यवान हैं।

इन तीनों वस्तुओं की सुविधा संयुक्तराज्य में पर्याप्त है। किन्तु इसके अर्थ यह नहीं कि वहाँ अब इस दिशा में कोई समस्या नहीं रही। अनेकों समस्याएँ हैं और सदैव रहेंगी भी। इस दिशा में अभी प्रत्येक व्यक्ति को उतनी सहायता नहीं मिल पाई है जितनी कि मिलनी चाहिए। फिर भी प्रगति सराहनीय है। यदि हम अपने देश को इस दृष्टिकोण से देखें तो बात बहुत स्पष्ट हो जायगी।

सप्तम चरण

अध्यापक—उसका प्रशिक्षण, सेवा तथा स्थान

रूपरेखा :—

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
२. प्रशिक्षण-केन्द्रों के प्रकार।
३. पाठ्य-क्रम।
४. प्रमाण-पत्र।
५. शिक्षण-काल में प्रशिक्षण।
६. प्रशिक्षण-केन्द्रों की संख्या तथा शिक्षक का स्थान।
७. शिक्षकों की सेवाएं।
८. अध्यापकों के एसोसियेशन।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

पश्चिमी संस्कृति के इतिहास में प्रशिक्षण बहुत ही हाल की बात है। कहीं-कहीं इस विषय में एक-आध वाक्य रूसो, लाक या प्लेटो तक में मिल जाता है किन्तु १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक विषय का ज्ञान और अध्यापन एक ही बात समझी जाती थी। उसकी कला नाम की कोई चीज पृथक् न थी। १८३९ में लेक्सिगटन, मैसाचुसेट्स राज्य में नार्मल स्कूल की स्थापना ने प्रशिक्षण के महत्त्व को बताया। अच्छे चरित्र, प्राचीन भाषाओं का ज्ञान, विषय का ज्ञान तथा पढ़ाने की इच्छा इन्हीं की अध्यापन के लिए आवश्यकता थी। आज प्रत्येक राज्य-सरकार ने कुछ नियम बना रक्खे हैं। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक प्रशिक्षण इतना अधिक टैक्नीकल नहीं हो पाया था किन्तु हरबार्ट, हाल तथा डीवी के लेखों ने इसको टैक्नीकल बनाने में सहायता की।

अपने स्थान तथा गौरव के लिए विषय-विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षित अध्यापक में सदैव युद्ध होता रहा है, ऐसा कानेन्ट महोदय का कथन है; परन्तु हमारे विचार से दोनों का ही मेल होना चाहिए; क्योंकि दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं।

आज लगभग १० लाख अध्यापक संयुक्तराज्य में कार्य कर रहे हैं और उनमें प्रायः स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। डी यंग के अनुसार प्रशिक्षण निम्न अवस्थाओं से होकर गुज़र चुका है——

१. अध्यापकों का प्रशिक्षण;
२. अध्यापकों की तैयारी;
३. अध्यापकों की शिक्षा।

१. प्रशिक्षणकाल प्रायः एक वर्ष का था; १८२३ में प्राइवेट नार्मल स्कूल की स्थापना हुई और १८३९ में लेक्सिगटन में एक और नार्मल स्कूल खुल गया।
२. धीरे-धीरे यह अनुभव होने लगा कि अध्यापकों को एक ही वर्ष में प्रशिक्षित करना सम्भव नहीं है इसलिए इस अवधि के विस्तृत होने के साथ-साथ पाठ्य-क्रम भी विस्तृत कर दिया गया। १८५७ में इलीनोइज राज्य का नार्मल विश्वविद्यालय खुला और उसके पश्चात ही बहुत से स्थानों पर एक शिक्षा-विभाग कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में जोड़ दिया गया। प्रशिक्षण का महत्त्व तथा आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ़ती गई।
३. इस शिक्षा का तृतीय अंग है अध्यापक की शिक्षा। किलपैट्रिक ने कहा था कि प्रशिक्षण कुशाग्रबुद्धियों को दिया जाता है सलिए अध्यापकों को

शिक्षा मिलनी ही चाहिए। इसकी तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।

प्रशिक्षण को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

१. अध्यापन से पूर्व (Pre-service Teacher Education)

२. अध्यापन के साथ-साथ (In-service Teaching)

शिणक्ष से पूर्व—शिक्षकों की कमी के विषय में राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी दुख प्रकट किया था। शिक्षण उच्च व्यवसाय है इसलिए उसमें छाँट की आवश्यकता है। छाँट का तरीका बहुधा छात्र के शिक्षा-काल का रिकार्ड, स्वास्थ्य-परीक्षा, बुद्धि तथा अन्य परीक्षाएँ हैं। रुचि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि बिना रुचि के अध्यापन सम्भव नहीं है।

प्रशिक्षण-केन्द्रों के प्रकार

१. **नार्मल स्कूल**—यहाँ से प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार किये जाते हैं। पहले यहाँ का कोर्स केवल एक वर्ष का था किन्तु आज ४ वर्ष का हो गया है। आज इनका स्थान टीचर्स कालेज लेते जा रहे हैं।

२. **टीचर्स कालेज**—यहाँ से प्रायः एक डिग्री मिलती है, और चूँकि शिक्षण-विधियों का विकास हो रहा है इसलिए इनकी अवधि ४ से ५ वर्ष हो गई है। बहुत से कालेज तो विश्व में ख्याति-प्राप्त हैं। प्रत्येक राज्य में अपने-अपने टीचर्स कालेज हैं। इसमें बहुत से शिक्षा में M.A.और Ph.D. तक की उपाधि देते हैं।

३. **शिक्षा-विभाग**—यह प्रायः लिबरल आर्ट्स कालेजों के विभाग हैं, यहाँ टीचर्स कालेज की अपेक्षा कम घंटे अध्यापन को मिलते हैं। बहुत से विश्व-विद्यालयों में तो किसी एक विभाग का छोटा भाग प्रशिक्षण भी है जैसे भारत में आर्ट्स फैकल्टी में प्रशिक्षण।

शिक्षा के स्कूल या कालेज—यहाँ कालेज की दो वर्ष की शिक्षा के पश्चात् प्रवेश सम्भव है। इन कालेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ प्रशिक्षण की विशेष शिक्षा दी जाती है। कहीं-कहीं पर अन्तिम दो या तीन वर्षों में शिक्षण-कला के विषयों पर बल दिया जाता है और इसके पूर्व केवल सामान्य शिक्षा दी जाती है। सभी यह मानते हैं कि शिक्षक को संस्कृति, सभ्यता, भाषा इत्यादि का ज्ञान भी आवश्यक है। केवल पढ़ाने की कला तथा शिक्षा का दर्शन ही नहीं।

पाठ्य-क्रम (विविध स्थानों के पाठ्य-क्रमों के संक्षिप्त रूप)

१. चारों वर्षों के प्रशिक्षण में सामान्य तथा व्यावसायिक (Professional) शिक्षा;

२. प्रथम दो वर्षों में सामान्य तथा अन्तिम वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा;

३. एक या दो व्यावसायिक विषय प्रथम दो वर्षों में और अन्तिम वर्षों में अन्य व्यावसायिक विषय;

४. ५ वर्षों के प्रोग्राम जिसमें छात्र ने बी. ए. की उपाधि ले ली हो, उसे केवल १ वर्ष की विशेष व्यावसायिक शिक्षा।

प्रमाणपत्र—अध्यापक को इस शिक्षा के पश्चात् एक लाइसेंस या माणपत्र दिया जाता है ताकि वह पढ़ा सके । यह शिक्षक को अप्रशिक्षित शिक्षक की प्रतियोगिता से बचाता है। प्रायः ४ या ५ वर्ष के प्रशिक्षण के पश्चात् ही यह प्रमाणपत्र मिलता है। ऐसे प्रमाणपत्र-प्राप्त शिक्षक एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं। गुणों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है फिर भी इन अच्छी बातों के अपवाद प्रत्येक पग पर सम्भव हैं।

अध्यापन-काल में प्रशिक्षण (Inservice Training)—नई विधियों, नई खोजों और शिक्षा की जटिलता के कारण इसकी महत्ता प्रायः सभी ने मानली है । चासर के अध्यापक की भाँति प्रत्येक शिक्षक को सदैव ज्ञानार्जन के लिए उत्सुक रहना चाहिए :

"And Gladly Woulde he lerne, aud gladly teche."

प्रशिक्षण-केन्द्रों की संख्या तथा शिक्षक का स्थान—सन् १९५२ में ४३२ प्रशिक्षण-केन्द्र जनता के हाथ में थे। उनमें से ३१५ राज्यों के हाथ में, २७ काउन्टी या टाउनशिप के हाथ में, ६१ म्यूनिसिपल तथा २९ स्कूल डिस्ट्रिक्ट के हाथों में थे। इनके अतिरिक्त प्राइवेट प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या ६६१ थी । इनमें १६६ को छोड़ कर शेष सभी धार्मिक संस्थाओं के हाथ में थे।[1] यद्यपि नमें प्रवेश-प्राप्ति के नियम भिन्न-भिन्न हैं फिर भी १२ वर्षीय शिक्षा प्रायः अनिवार्य सी है।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए ४ वर्ष और माध्यमिक के लिए ५ वर्ष के प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है । सामान्य तथा व्यावसायिक दोनों शिक्षा ही प्रायः इस प्रशिक्षण-काल में दी जाती हैं।

केन्डेल[2] का कथन है कि भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न योग्यता के अध्यापकों की आवश्यकता होती है इसलिए प्रायः वह एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा-सकता। शिक्षा अब क्रमशः व्यापार (Trade) से उच्च व्यवसाय (Profession) होता जा रहा है;[3] किन्तु फिर भी अध्यापकों की न्यूनता से यह प्रकट हो रहा है कि आर्थिक दृष्टि से वह किसी उच्च पद पर नहीं है।[4]

शिक्षकों की सेवाएँ—प्रायः अध्यापकों की एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति

1,2, Kandel, I.L.; The New Era in Education. p. 359.
3. Ibid. p. 363. 4. Ibid. p. 367.

होती है; ८०% शिक्षक स्त्रियाँ हैं क्योंकि विवाह के लिए च्छुक स्त्रियों को एक या दो वर्ष का पढ़ाना कुछ कम आकर्षण नहीं है।[1]

अध्यापकों का वेतन प्रत्येक राज्य में भिन्न है यहाँ तक कि ग्राम तथा नगर के अध्यापक के वेतन में भी अन्तर है। प्रायः अध्यापक अध्यापन-कर्म छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ उच्च नौकरी वेतन द्वारा मापी जाती है न कि नाम से। अध्यापकों की कमी, युद्ध-कालीन बालकों की वृद्धि के कारण, और भी अधिक बढ़ चुकी है। इसका यह अर्थ नहीं कि उनका गौरव बढ़ चुका है। क्योंकि रिचमंड का कथन है कि अध्यापक जनता का सेवक है इस बात को अमरीकी नागरिक कभी नहीं भूलता। यहाँ तक कि उसकी नियुक्ति के समय उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी जानकारी कर ली जाती है। इस बात में भारत-वर्ष की तुलना वहाँ से भली भाँति हो सकती है। उसकी धूम्रपान की आदत, धर्म त्यादि की जानकारी एक आवश्यक शर्त्त है। अमरीकी शिक्षक को शिक्षण में किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं है। भारत में भी एक अध्यापक को केन्द्रीय चपरासियों से कम वेतन मिलता है। एक शिक्षक की नियुक्ति तथा निकाले जाने की बात में; प्रायः उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं हो सकती। दोनों देशों में प्रगति के लिए अभी बहुत काम बाकी है।

नौकरी की अवधि, रिटायर होने के नियम, वेतन इत्यादि के विषय में संयुक्तराज्य में प्रगति हो रही है। हाल ही में एक प्रश्न-संकलन द्वारा पता लगाये जाने पर छात्रों ने उत्तर में कहा कि शिक्षण अच्छा व्यवसाय है (५१%); अन्य व्यवसायों के समान ही है (४१%); शेष ने शिक्षा की बात ही नहीं की। यह उसके प्रति आदर का सूचक है; आशा है शिक्षक का महत्त्व भविष्य में बढ़ जायगा।

अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए बहुत से एसोसियेशन बन गये हैं जो भविष्य के अध्यापकों को एक सूत्र में बाँधना चाहते हैं जैसे Future Teachers of America Association)। विज्ञान के अध्यापकों की विशेष कमी है। अध्यापक अमरीकी जनतन्त्र के स्तम्भ हैं इसलिए उन्हें अधिक कार्य करना है तथा समाजोन्मुखी होना है।

गार्डन ली[2] के साथ हम यह कह सकते हैं (१) अध्यापकों के प्रमाण-पत्रों के विषय में प्रत्येक राज्य के नियम अलग हैं, और, (२) उनके प्रशिक्षण-काल की अवधि भी एक-सी नहीं है।

उदाहरण के लिए प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्रों की माँग दो राज्यों में भिन्न-भिन्न

---

1. Kenneth Richmond; Education in U.S.A. p.58.
2. Lee, G.C. ; An Introduction to Education in Modern America. p. 310

है, इसका परिचय निम्न सूची[1], से ज्ञात हो जायगा—

Arkansas *Elementary School*

1. Completion of a minimum of 30 semester hour of the six-year Elementary Certificate Curriculum in an approved College.

II. General requirements (must include a course in conservation of Natural Resources or Nature study)

A.	English	Semester hours
B.	Social studies	6
C.	Science (Nature study)	3
D.	Physical Education	2

III. Basic Professional Courses

A.	Introduction and orientation	(2)
B.	Psychology	(2)
C.	General Methods and for observation	(2)

Note:— Numbers in parenthesis indicate approximate number of hours.

IV. Professional Content Requirements

A.	Public School Art and Crafts	4
B.	Public School Music	4
	(1) Fundamentals of Music	(2)
	(2) Materials and Methods	(2)
C.	Juvenile literature	2
D.	Geography (may be counted in general requirements.)	(3)

New York (Elementary School)

Permanent Certificate:—

1. Bachelors degree (approved 4 year curriculum for elementary school teachers) or equivalent

2. Professional requirements—in semester hours 36

a. Observations and supervised teaching in elementary schools, including conferences on teaching problems. 12-15

b. Elementary School Methods and Materials of 8-12

---

1. Ibid pp. 317-324

c. Psychology for teachers and child Development or child psychology 6-10
d. History, Psychology, Problems and or Principles of Education. 2-6

आवश्यकता पड़ने पर विशेष समय के लिए भी प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं। ये प्रति वर्ष बदलवाने पड़ते हैं जैसे भारतवर्ष में रिक्शा चलाने का लाइसेन्स।

शिक्षकों की नौकरियाँ—शिक्षकों को नौकरी देना काउन्टी या अन्य स्थानीय संस्थाओं के हाथ है। कुछ तो कालेज ही नौकरी दिलाने का प्रबन्ध रखते हैं अन्यथा निम्न साधनों से नौकरी मिलती है—

१. प्राइवेट एजेन्सी में रजिस्ट्रेशन द्वारा, जहाँ भावी शिक्षक की योग्यता, आयु, रुचि इत्यादि सभी का ब्यौरा लिख लिया जाता है और उसी के आधार पर इच्छुक अधिकारियों को सूचना देकर शिक्षक की नियुक्ति करा दी जाती है। यहाँ नौकरी दिलाने की फीस देनी होती है।

२. ऐसी संस्थाएँ जो बिना फ़ीस लिए ही नौकरी दिलाती हैं।

या तो शिक्षक का इन्टरव्यू एजेन्सी में ही अधिकारी ले लेता है या अपने यहाँ बुला कर। व्यक्तिगत जीवन की सूचना देने के पश्चात् शिक्षक को कुछ शर्तें मन्जूर करनी पड़ती हैं। कहना न होगा कि उस समय राज्य का प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

अध्यापकों के एसोसियेशन—भिन्न-भिन्न सीमा के भिन्न-भिन्न एसोसियेशन आज संयुक्तराज्य में हैं। राष्ट्रीय स्तर के एसोसियेशन हैं नेशनल एजूकेशन एसोसियेशन—लगभग ४०% शिक्षक इसके सदस्य हैं।

कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एसोसियेशन भी हैं। इस प्रकार अध्यापकों की दशा अब बहुत कुछ सुधर चुकी है।

चतुर्थ अध्याय

रूपरेखा :—

प्रथम चरण :—पाठ्यक्रम ।

द्वितीय चरण :—सार्वजनिक शिक्षा की आर्थिक सहायता ।

प्रथम चरण

पाठ्य-क्रम

रूपरेखा :—

१. परिचय।

२. पाठ्य-क्रम के विकास के सिद्धान्त।

३. पाठ्य-क्रम-निर्माण में उपगमन।

४. पाठ्य-क्रम-निर्माण में विशिष्ट पद।

५. पाठ्य-क्रम के विषय में वादविवाद।

६. पाठ्य-क्रम के प्रकार।

७. भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के लिए पाठ्य-क्रम।

८. पाठ्य-क्रम-सम्बन्धी समस्याएँ।

९. भ्रान्तियाँ तथा मतभेद।

१०. आधुनिक प्रवृत्तियाँ।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

पाठ्य-क्रम के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है इसलिए हम केवल अमरीकी स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्य-क्रमों के विषय में ही कहेंगे जिससे पाठकों को उनके सिद्धान्त, प्रकार तथा उपगमनों से परिचय हो जाय।

पाठ्य-क्रम की निरन्तर नवीन परिभाषा होती रही है, किन्तु सदैव उसे सामान्य रूप से लैटिन भाषा से निकला शब्द मान कर उसका अर्थ "घुड़दौड़ का मार्ग" (Race-course) ही बताया जाता रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्कूल रूपी घुड़दौड़ के मैदान पर जो भी कुछ होता है उसे ही पाठ्य-क्रम कहेंगे। अमरीकी विद्वान् इसे छात्रों के अनुभवों का क्रम कहेंगे जिनमें वह स्कूल की अवधि में भाग लेते हैं। अलेक्जेंडर तथा सेलर[1] उसे स्कूल का जीवन तथा प्रोग्राम मानकर लगभग उन सभी बातों को उसमें सम्मिलित कर देते हैं जिनमें छात्र स्कूल में भाग लेते हैं। किसी भी शिक्षा-शास्त्री का मत लेने पर यह ज्ञात हो जायगा कि पाठ्य-क्रम शिक्षा के उद्देश्यों पर निर्भर है जो अभी तक सब स्थानों, कालों तथा व्यक्तियों के एक समान नहीं हो सके हैं।[2] इसलिए जो पाठ्य-क्रम अमरीकी शिक्षा-संस्थाओं का होगा वह वहीं की आवश्यकताओं के आधार पर होने के कारण किसी अन्य देश के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। डी यंग[3] ने पाठ्य-क्रम के विकास के कुछ सिद्धान्तों का वर्णन किया है––

१. पाठ्य-क्रम विस्तृत तथा व्यापक होता है अर्थात् उसमें छात्रों के लगभग सभी अनुभव आ जाने चाहिएं।

२. पाठ्य-क्रम शिक्षा-दर्शन पर आधारित रहता है।

३. पाठ्य-क्रम सामूहिक तथा प्रजातान्त्रिक कार्य है जिसमें प्रायः सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। अमरीकी विश्वास है कि 'प्रजातन्त्र' शासन का आदर्श सिद्धान्त है। सार्वजनिक आवश्यकताओं तथा उनके मतों के आधार पर पाठ्य-क्रम में परिवर्त्तन वहाँ एक मानी हुई वस्तु है।

४. व्यवस्था तथा शासन लचीला तथा परिवर्तन के प्रति सहृदय होना चाहिए। अध्यापक को पाठ्य-क्रम में परिवर्त्तन के लिए स्वतन्त्रता होनी चाहिए। भारत में इस सिद्धान्त के समझने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ परिवर्त्तन आवश्यकता पर नहीं शिक्षा-संचालक की इच्छा पर निर्भर होता है। इसलिए

---

1. Alexander and Saylor, Secondary Education. p. 254
2. Nunn, T.P., Education : Its data and First Principles. ch. I
3. De Young, Chris; An Introduction to American Public Education. pp. 412-416

नवीन प्रयोग प्रायः असम्भव हैं। यद्यपि इस दिशा में अब केन्द्र तथा राज्य की स्वीकृति पर प्रयोग सम्भव है।

५. स्कूल की इमारत तथा पाठ्य-क्रम में समानता होनी चाहिए। बहुत से अमरीकी स्कूल अब भी छोटे हैं जहाँ स्थानाभाव है तथा योग्य अध्यापकों की वहाँ कमी है। भारत में भी ऐसे स्कूल कम नहीं हैं जहाँ वे एक व्यवसाय के रूप में कार्य करते हैं और शिक्षा-निरीक्षक उनका कुछ नहीं कर पाते।

६. मनोविज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है कि बालकों की रुचि, बुद्धि तथा प्रयत्नों में भिन्नता होती है—इसलिए पाठ्य-क्रम में व्यक्तिगत भेदों को स्थान मिलना चाहिए। यह आदर्श है किन्तु इसकी प्राप्ति का प्रयास सभी देश कर रहे हैं।

७. रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। बालक स्वभाव से रचनात्मक होता है इसलिए उसकी शक्तियों का उपयोग होना चाहिए।

८. मार्ग-प्रदर्शन या सलाह (Guidance) पाठ्य-क्रम से ही सम्बन्धित होनी चाहिए। सलाह का कार्य इतना व्यापक हो चुका है कि ब्रूयर का उद्धरण देते हुए ब्रूबेकर[1] ने कहा है कि "यह विशेष आश्चर्य की बात नहीं कि शिक्षा तथा सलाह (Guidance) एक-अर्थी हो गये हैं।"

९. पाठ्य-क्रम का जीवन-केन्द्रित होना चाहिए।

१०. व्यापक अर्थों में परीक्षा पाठ्य-क्रम के लिए आवश्यक है क्योंकि परीक्षा के द्वारा ही पाठ्य-क्रम की पूर्णता या अपूर्णता, तथा सफलता या असफलता का अनुमान सम्भव है।

११. पाठ्य-क्रम में अनवरत परिवर्त्तन आवश्यक है क्योंकि परिवर्त्तन के कारण ही आवश्यकताओं की पूर्त्ति सम्भव है।

पाठ्य-क्रम निर्माण में उपगमन (Approaches)

निम्न तीन प्रकारों की व्यवस्था से पाठ्य-क्रम निर्मित होता है—

१. केन्द्रित (Centralized);
२. विकेन्द्रित (Decentralized); तथा
३. केन्द्रीय समन्वित उपगमन (Centrally co-ordinated approaches)

यही तृतीय व्यवस्था है जिसमें कि अधिकारी तथा शिक्षक वर्ग साथ-साथ कार्य करते हैं इसलिए इसी की मान्यता अधिक है।

पाठ्य-क्रम के विषय में दूसरों का सहयोग, उसके लिए व्यक्तियों का संगठन, विधियाँ बनाना, छात्रों की आवश्यकताओं (Needs) का पता लगाना, खोजों के आधार पर

---

1. Brubacher, I.S. ; A History of the Problems of Education. p. 317

सामग्री एकत्रित करना; पाठ्य-वस्तु को छाँटना तथा उसे क्रम में रखना इत्यादि पाठ्य-क्रम के विविध मुख्य पद हैं जो अमेरिका में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।

पाठ्य-क्रम निर्माण में विशिष्ट पद

१. सेवि-वर्ग (Personnel) का संघटन—क्योंकि अच्छे पाठ्य-क्रम के लिए विभिन्न व्यक्तियों के दक्ष (Expert) मत की आवश्यकता होती है।
२. कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति—समय-समय पर बने हुए कानूनों के आधार पर जो विषय आवश्यक हो चुके हैं उनका पाठ्य-क्रम-निर्माण में ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे, संयुक्तराज्य का इतिहास, नागरिक शास्त्र इत्यादि जो विधानतः अनिवार्य विषय हैं।
३. समाज की शक्तियों की खोज तथा उनका उपभोग—स्कूलों को समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है इसलिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज की शक्तियों की खोज भी आवश्यक है ताकि वह उनका उपभोग कर सके।
४. नौकरियों का पता लगाना जिसमें कि नौकरी सम्भव हो, और उन्हीं के लिए शिक्षा देना। कोलम्बिया तथा मिसूरी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के पाठ्य-क्रमों का निर्माण हो चुका है।
५. पाठ्य-क्रम के विकास के लिए नवीन खोजें होनी चाहिएं क्योंकि अभी तक की खोजें प्रायः अमनोवैज्ञानिक रही हैं।

इस प्रकार जीवन-दर्शन पर निर्भर, बच्चों तथा किशोरों की आवश्यकताओं से प्रेरित तथा समाजोन्मुखी पाठ्य-क्रम ही आदर्श हो सकता है।

पाठ्य-क्रम के विषय में वादविवाद[1]—मानव-सभ्यता के प्रारम्भ से ही उपयुक्त विषयों का पठन-पाठन एक विवादग्रस्त विषय रहा है। ग्रीक तथा रोमन-काल से आज तक कुछ विषयों को सदैव ही प्राथमिकता मिलती रही है। किन्तु हम प्राचीन काल के विषय में प्रायः यह बात भूल जाते हैं कि धनी व्यक्ति ही पढ़ते थे क्योंकि अवकाश उन्हें ही सम्भव था। प्रजातन्त्र का उपासक प्लेटो भी दो प्रकार की शिक्षा का वर्णन कर गया है, एक ऊँचे खानदान के धनी तथा कार्य-मुक्त प्राणियों के लिए तथा अन्य साधारणतया सैनिक वर्ग के लिए। मिलती-जुलती विचार-धारा भारत में भी प्रचलित रही है यद्यपि यहाँ की सभ्यता की कड़ियाँ इतनी कठोर न थीं। स्वार्थवश शासकों ने राष्ट्रीयता की भावना की जागृति के लिए देशी भाषाओं को लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं से अधिक महत्त्व दिया।[2] इसी प्रकार तथाकथित मानवीय विषयों (Humainties) तथा शास्त्रीय विषयों का महत्त्व भी कम या अधिक होता रहा है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने शिक्षा के उद्देश्य

1. Brubacher, I.S.; Op. Cir. pp. 249-317
2. Ibid; p. 259.

भी भिन्न-भिन्न बताये हैं तथा उन्हीं के अनुरूप भिन्न-भिन्न पाठ्य-क्रमों की ओर संकेत किया है। यह बात अरस्तू के युग से नेशनल एसोसियेशन के ऐजूकेशनल पॉलिसीज कमीशन (१९४४) तक भिन्न-भिन्न रूप से सुलझाई गई है।[1] यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है किन्तु अमरीकी व्यवहारिकतावादी (Pragmatic) मस्तिष्क सदैव जीवन के निकट ही रहा है। उक्त कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में नवयुवकों की दस आवश्यकताओं का वर्णन किया है तथा उनकी पूर्ति के लिए उचित पाठ्य-क्रम-निर्माण की सलाह दी है।

पाठ्य-क्रम के प्रकार

(१) तर्कसंगत या मनोवैज्ञानिक पाठय-क्रम—मनोवैज्ञानिक पाठ्य-क्रम रुचि, वयस तथा योग्यता का ध्यान रक्खेगा; इस प्रकार वह परम्परागत पाठ्य-क्रम के विपरीत होगा। परम्परावादी तर्क-संगत (Logical) पाठ्य-क्रम को ही अधिक बता देंगे क्योंकि पाठ्य-क्रम युगों के कठिन मानवीय परिश्रम का फल है। डीवी ने अपने "बालक तथा पाठ्य-क्रम" नामक पुस्तक में परम्परागत पाठ्य-क्रम को आधुनिक दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक बता कर उसे पढ़ाने की स्वीकृति दी है किन्तु परिवर्तनशील विश्व में समस्या-सुलझाव (Problem solving) की रुचि तथा योग्यता का निर्माण भी आवश्यक है इसलिए छात्र की रुचि, वयस तथा योग्यता का ध्यान रखकर आधुनिक विषयों को भी पढ़ाना होगा। डीवी की इसी बात से प्राय: अमरीकी मस्तिष्क सहमत है।

(२) परस्पर-सम्बन्ध तथा संकेन्द्रित पाठ्य-क्रम (Correlation and Concentration)—हरबार्ट के समय तक विषयों को इस सीमा तक अलग-अलग कर दिया गया कि उनका परस्पर सम्बन्ध असम्भव सा हो गया। इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने विषयों के परस्पर-सम्बन्ध तथा संकेन्द्रित होने पर बल दिया है। द्वितीय युद्ध के पश्चात् ही परस्पर सम्बन्ध और संकलन (Integration) का अर्थ अलग-अलग माना जा सका है। भारतीय बुनियादी शिक्षा भी इसी प्रकार (संकलन) पर बल देती है, किन्तु एक सीमा से बाहर उसका कोई महत्त्व नहीं रह जाता।

(३) विस्तृत-क्षेत्रीय पाठ्य-क्रम[2] (Broad-field curriculum) इस प्रकार के पाठ्य-क्रम में एक विषय के अन्तर्गत कई विषय आ जाते हैं। इस प्रकार विषयों को संकीर्ण सीमाएँ व्यापक क्षेत्रों में खो जाती हैं, जैसे भाषा के अन्तर्गत—पढ़ाना, साहित्य, व्याकरण, भाषण इत्यादि सभी आ जाते हैं।

(४) आन्तरिक पाठ्य-क्रम (Core-curriculum)—इस प्रकार के पाठ्य-क्रम में कुछ विषयों के प्रति चुनाव की स्वतंत्रता रहती है तथा कुछ अनिवार्य होते हैं, उन

1. Alexander and Saylor of Cir. P. 305.
2. De Young; Op. Cir. pp. 422-423.

अनिवार्य विषयों की पाठ्य-सामिग्री इस विशेष तरीके से चुनी जाती है इसलिए इसका नाम आन्तरिक पाठ्य-क्रम पड़ा है ।

(५) अनुभव-केन्द्रित पाठ्य-क्रम (Experience-centred & curriculum)—इसमें अर्थ-पूर्ण अनुभवों के द्वारा छात्र अपनी रुचि के अनुसार वातावरण तथा सभ्यता में भाग लेता है तथा इस पाठ्य-क्रम का आधार छात्र के निकटवर्ती जीवन की समस्याओं तथा अवस्थाओं पर होता है।

भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्य-क्रम—एक विद्वान[1] का कथन है कि बालक की तीन आवश्यकताएँ होती हैं—

१. विश्व की खोज करना (२) अपने ढूँढे हुए की आलोचना करना तथा (३) उसे खोज के लिए शिक्षा देना तथा समझ बढ़ाना। इसलिए उसे भाषा तथा किसी कला (Craft) पर अधिकार होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित कामों (Correlated activities) से परिचय कराना चाहिए। अब हमारा प्रारम्भिक शिक्षा के विषय में विचार बदल चुका है क्योंकि अब हम उसे केवल निर्धनों के लिए ही नहीं मानते। इसलिए उसके पाठ्य-क्रम का क्षेत्र बढ़ चुका है।

२. अभी माध्यमिक शिक्षा का वर्णन करते समय हम यह देख चुके हैं कि किशोर की १० आवश्यकताएँ होती हैं जिनकी पूर्ति पाठ्य-क्रम को करनी ही चाहिए। वैसे माध्यमिक शिक्षा प्रायः कालेज की तैयारी के उद्देश्य से प्रभावित रही है किन्तु आधुनिक प्रवृत्ति है कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं एक कड़ी होनी चाहिए और उसे अपने में ही पूर्ण शिक्षा (Terminal education) देनी चाहिए।

३. विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ उच्च व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए क्योंकि इसी पाठ्य-क्रम के कारण अमरीकी विश्वविद्यालयों पर विशेष शिक्षा (Specialisation) का आरोप हट जायगा। यहाँ छात्र को सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा अपनी सभ्यता से परिचय इत्यादि की शिक्षा देनी चाहिए। आज अमरीकी विश्वविद्यालय इस प्रकार नवीन विषयों की शिक्षा देने लगे हैं कि वह मानवीय गुणों का विकास करना भी प्रायः भूल गये हैं।

कहना न होगा कि पाठ्य-क्रम का कार्य अब इतना सरल नहीं रह गया है कि उसे प्रत्येक व्यक्ति निर्माण कर सके।[2] बालक के विकास तथा आवश्यकताओं का ज्ञान, भिन्न-

1. Jacks, M.L; Total Education. p. 78: Kegan Paul, Trench Trubner and Co. Ltd., London, 1946.

2. Walter S. Monroe, Encyclopedia of Educational Research. P.307.

भिन्न शिक्षा के उद्देश्यों की समीचीनता; समाज तथा सभ्यता के विषय का ज्ञान इत्यादि आज पाठ्य-क्रम-निर्माण को जटिल बना चुके हैं। उपर्युक्त पाठ्य-क्रमों के विकास के साथ-साथ समाज तथा प्रजातन्त्र पाठ्य-क्रम को प्रतिक्षण नवीन मोड़ दे रहे हैं।

पहले विषयों को भिन्न-भिन्न शीर्षक (Topics) दे कर बाँट दिया जाता था। आज उसी इकाई के भिन्न-भिन्न भेद हो चुके हैं उनमें ३ मुख्य इकाइयाँ हैं (१) विषय की इकाई (Subject matter unit), जो परम्परा के अनुसार विषय तथा उसके शीर्षक के अनुरूप ही बनती है; (२) रुचि की इकाई, जो बालक की आवश्यकताओं तथा रुचि के आधार पर बनती है; तथा (३) संकलित अनुभवों की इकाई, जो छात्र को वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता को विकसित करती है तथा व्यवहार को परिवर्तन-शील बनाने की शक्ति को बढ़ाती है। इस प्रकार पाठ्य-क्रम क्रमशः जटिल होता जा रहा है और केवल दक्ष (Specialist) व्यक्ति ही इसके निर्माण का कार्य कर सकता है।

पाठ्य-क्रम सम्बन्धी समस्याएँ—अलेक्जेण्डर तथा सेलर[1] ने निम्न बातों पर ध्यान रखने का सुझाव रखा है—

१. पाठ्य-क्रम-निर्माण में छात्रों तथा समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शक्ति का विकास ही समाज को आदर्श बना सकेगा।
२. पाठ्य-क्रम-निर्माण में प्रौढ़ों के साथ-साथ अब नवयुवकों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को स्थान मिलना चाहिए।
३. माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जातीय प्राप्ति (Racial achievements) या सभ्यता के पदों से परिचय के साथ वर्तमान युग की समस्याओं को भी स्थान मिलना चाहिए।
४. माध्यमिक शिक्षा को कालेज की तैयारी तथा व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए पर सामान्य ज्ञान की उपेक्षा भी उसे नहीं करनी चाहिए।

भ्रान्तियाँ तथा मतभेद—उक्त लेखकों ने पाठ्य-क्रम-निर्माण का परिचय भ्रान्तियों तथा मतभेदों से भी कराने की चेष्टा की है। हम माध्यमिक शिक्षा के वर्णन पर अधिक बल इसलिए दे रहे हैं कि इसी अवस्था (Stage) से समाज के नेताओं की प्रायः उत्पत्ति होती है।

१. पाठ्य-क्रम को इतना लचीला अवश्य होना चाहिए कि वह व्यक्तिगत भेदों तथा समस्याओं पर समुचित ध्यान दे सके। यद्यपि यह सम्भव नहीं है कि पाठ्य-क्रम नवयुवकों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
२. पाठ्य-क्रम-निर्माण के समय क्या नवयुवकों की भविष्य की आवश्यकताओं का भी अनुमान किया जा सकता है? यद्यपि यह तो सम्भव नहीं है किन्तु

1. Alexander Saylor; Op.Cir. p. 264-266.

सामान्य रूप से यदि नवयुवकों की सभी आवश्यक माँगों का ध्यान रक्खा जाय तो उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का सुलझाना भी आसानी से ही सम्भव हो जायगा।

३. जिस ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक को जीवन की समस्याओं के सुलझाने के समय होती हो उसे हम सभी की सामान्य (Common) आवश्यकताएँ कह सकते हैं; अन्यथा वह ज्ञान, जो कभी-कभी किसी-किसी के जीवन में प्रयुक्त होता हो उसे हम व्यक्तिगत आवश्यकताएँ कहेंगे। यद्यपि इन दोनों के विषय में प्रायः बहुत से मत हैं, किन्तु उक्त बात ही हमें अधिक ठीक जँचती है।

आधुनिक प्रवृत्तियाँ—आज का पाठ्य-क्रम कहाँ से कहाँ आ पहुँचा है, निम्न वर्णन[1] के आधार पर उसका कुछ अनुमान सम्भव है—

	कहाँ से (From)	कहाँ (To)
१. पाठ्य-क्रम-विकास का उद्देश्य	सूचना तथा मस्तिष्क के अनुशासन के लिए	बालक के विकास तथा वृद्धि के प्रति चिन्ता, आधुनिक समस्याओं का वर्णन, अच्छी पढ़ाई
२. पाठ्य-क्रम-विकास में नेतृत्व	विषय-ज्ञाता तथा कालेज प्राध्यापक	अध्यापक, मनोवैज्ञानिक तथा विषय के ज्ञाता (सामूहिक रूप में)
३. विधि	कुर्सी पर बैठ कर	विकास तथा अनुभव-केन्द्रित
४. पाठ्य-सामिग्री	विषयों का रटना (कंठाग्र करना)	विषय का क्रियात्मक रूप तथा प्रायोगिक रूप
५. परीक्षा	विषय-परीक्षा	अभिरुचियों का मापन, सोचने की शक्ति का व्यवहार से सम्बन्ध जोड़ना इत्यादि।

मुख्य-मुख्य आधुनिक प्रवृत्तियाँ—डी यंग[2] के अनुसार वे निम्न हैं—

१. पाठ्य-क्रम का व्यापक विचार जिसमें प्रत्येक अनुभव आ सके।
२. दर्शन तथा मनोविज्ञान के अनुसार छात्र के विकास, रुचि इत्यादि का ध्यान।
३. परस्पर-सम्बन्धविषयक पाठ्य-क्रम द्वारा एक संकलित (Integrated) बालक का निर्माण करना।

---

1. Monroe, W. S. ; Op. Cir & P. 30S
2. De Young. ; Op. Cir. pp. 428-430.

४. कक्षा के कार्य को समाज की शक्तियों तक के उपभोग से सम्बन्धित रखना।

५. छात्रों की कमी को जानना तथा उसे दूर करना।

६. अच्छी स्कूल की इमारत बनाना।

७. मनुष्य की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखना इत्यादि।

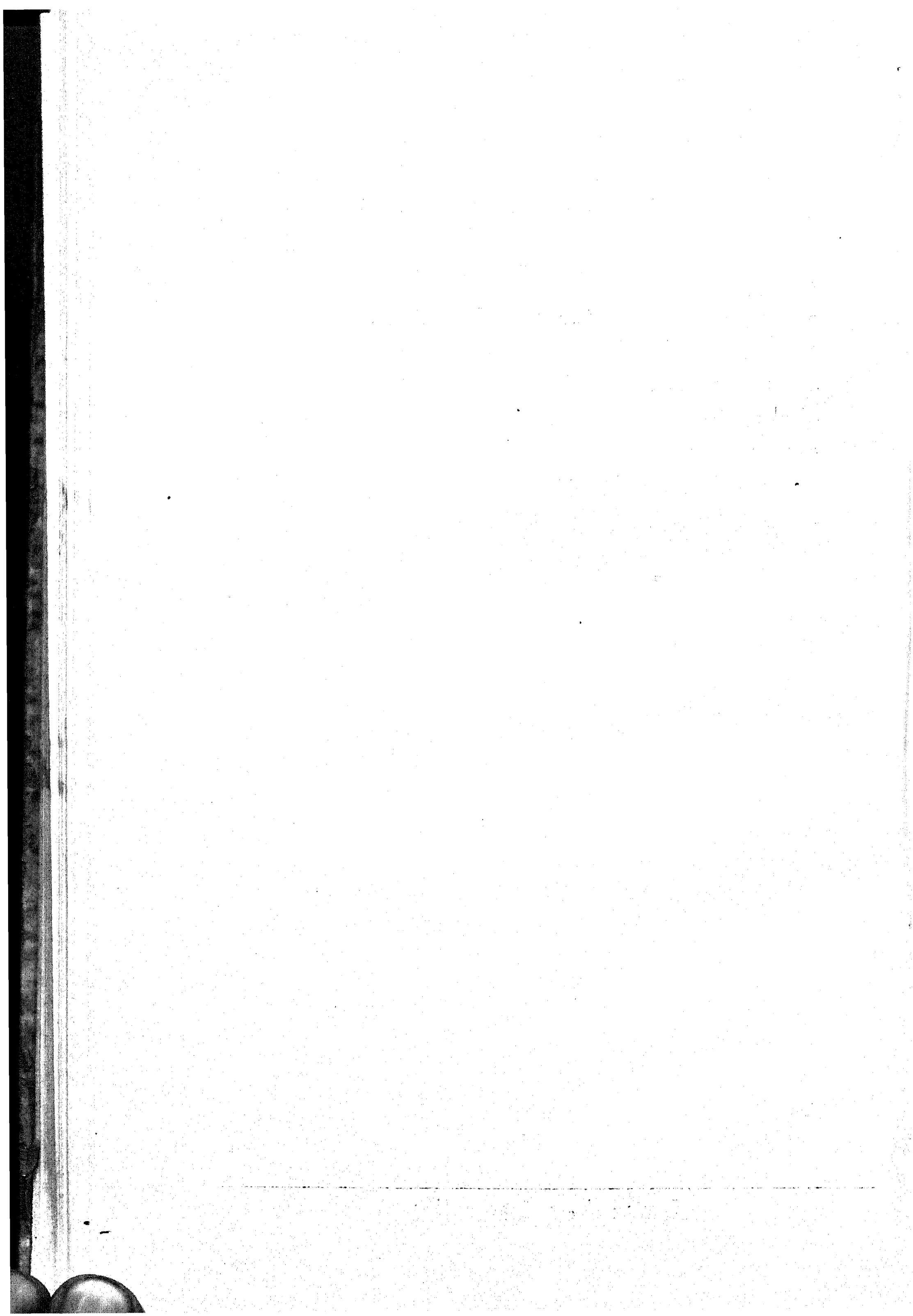
द्वितीय चरण

सार्वजनिक शिक्षा की आर्थिक सहायता

रूपरेखा :—

१. परिचय ।
२. सार्वजनिक शिक्षा की आर्थिक सहायता के कुछ सिद्धान्त ।
३. स्कूल बजट ।
४. स्कूल का खर्च ।
५. सार्वजनिक शिक्षा का क्रम ।
६. स्कूल की आय ।
७. स्कूलों में धन का विभाजन ।
८. उच्च शिक्षा को सार्वजनिक आर्थिक सहायता ।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह



आज की अमरीकी शिक्षाव्यवस्था को आर्थिक सहायता कई रूप से मिलती है हम उसी का वर्णन देने जा रहे हैं। खराब आर्थिक स्थिति के दिनों में बड़े-बड़े विचित्र तरीकों से धन लिया गया था। वैसे तो कर द्वारा शिक्षा की सहायता मानी हुई वस्तु थी किन्तु सन् १८२५ तक हर प्रकार की सम्पत्ति पर कर लगाना माना नहीं जा सकता था। कबरले (Cubberley) महोदय ने आधुनिक आर्थिक सहायता तक पहुँचने को 'कई युद्धों की विजय' कहा है। निम्न विजयों का वर्णन उल्लेखनीय है—

१. स्कूल खोलने के लिए समुदायों (Groups, Communities) को आज्ञा कि वह अपनी स्कूल की इकाई बना ले और उस क्षेत्र में कर लगा ले।
२. सभी पर स्थानीय कर, जिसमें व्यक्तिगत इच्छा तथा अनिच्छा का कोई ध्यान नहीं रक्खा गया।
३. स्कूल की इकाई की कानूनन स्थापना, जिस समय भी उसके लिए अनुरोध किया जाय।
४. राज्य-सरकारों की सहायता ताकि स्थानीय संस्थाएँ स्कूल चला सकें।
५. राज्य की सहायता को पूरा करने के लिए अनिवार्य स्थानीय कर।
६. स्थानीय करों को और पूरा करने के लिए काउन्टी तथा नगरों पर कर।
७. राज्य की बढ़ती हुई आर्थिक सहायता।
८. करों द्वारा प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्कूलों की सहायता तथा स्थापना।

डी यंग महोदय ने यह भी बताया है कि आज तो इस स्थिति में बहुत प्रगति हो चुकी है। क्योंकि कालेज तक की सहायता स्थानीय करों द्वारा की जा सकती है। धनवान क्षेत्रों द्वारा निर्धन क्षेत्रों के शिक्षा-केन्द्रों को सहायता दी जा सकती है।

आधुनिक सार्वजनिक आर्थिक सहायता के अन्तर्गत—

१. स्थानीय करों द्वारा स्थानीय शिक्षा-व्यवस्था की सहायता;
२. सामुदायिक तथा राजकीय आर्थिक सहायता जिसमें प्रारम्भिक से लेकर उच्च शिक्षासंस्थाएँ तथा किसी प्रकार से भी हीन (Handicapped) बालकों के लिए स्कूलों की व्यवस्था;
३. राज्य तथा केन्द्र दोनों के द्वारा स्थापित शिक्षा की व्यवस्था, जैसे लैण्ड ग्राण्ट कालेज;
४. केवल केन्द्रीय सहायता-प्राप्त शिक्षा की योजनाएँ—जैसे, युद्ध से लौटे व्यक्तियों की शिक्षा; तथा
५. स्थानीय, राज्य तथा केन्द्र तीनों की संयुक्त सहायता-प्राप्त संस्थाएँ; इत्यादि सभी आती हैं।

सार्वजनिक शिक्षा की आर्थिक सहायता के कुछ सिद्धान्त

१. सार्वजनिक स्कूल सार्वजनिक धन द्वारा ही चलने चाहिए। इस सिद्धान्त को व्यापक अर्थों में लेना चाहिए क्योंकि समाज तथा स्कूल परस्पर अन्योन्याश्रित हैं।
२. स्कूल का मुख्य ध्येय धन-प्राप्ति नहीं, शिक्षा देना होना चाहिए।
३. सार्वजनिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए क्योंकि यह अमरीकी नागरिक का जन्मजात अधिकार है।
४. मुख्यतः राज्य को शिक्षा के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
५. प्रत्येक राज्य में शिक्षा पर व्यय बराबर ही होना चाहिए और किसी राज्य की कमी को अन्य धनी राज्य के धन से पूरा कर देना चाहिए।
६. कुछ स्कूल आदर्श होने चाहिए जो अन्य स्कूलों को नवीन बातों से परिचित कराते रहें। इनका व्यय राज्य को देना चाहिए।
७. आर्थिक मामलों में स्कूलों को सतर्क होना चाहिए तथा गड़बड़ से सदैव ही सचेत रहना चाहिए।
८. अपव्यय शिक्षा में नहीं होना चाहिए, इसका यह अर्थ नहीं कि स्कूल को प्रयोग करने से रोक देना चाहिए या कम अध्यापक रक्खे जायें।
९. अधिक जिम्मेदारी का अर्थ अधिक व्यय होना चाहिए। यदि स्कूलों को अधिक काम करना है तो उन्हें धन भी अधिक ही मिलना चाहिए।
१०. स्कूल की अर्थव्यवस्था व्यापार की अर्थव्यवस्था से भिन्न होनी चाहिए क्योंकि स्कूल, व्यापार के विपरीत सार्वजनिक हित का ध्यान रखते हैं।
११. धनसम्बन्धी कार्य करने वाले व्यक्ति दक्ष होने चाहिए।
१२. धन का हिसाब रखना चाहिए।
१३. आर्थिक आयोजन अनिवार्य है।

स्कूल-बजट—इन सिद्धान्तों के जान लेने के पश्चात् यह कहना आवश्यक हो जाता है कि स्कूल का अपना बजट अवश्य ही बनना चाहिए। बजट के द्वारा ही आय, व्यय, योजना, विधियों में उन्नति इत्यादि का ज्ञान सम्भव है। बजट के चार मद होते हैं (१) तैयारी (२) पेश करना तथा मन्जूरी (३) व्यय तथा (४) जाँच। बजट की तैयारी मिला-जुला काम है इस का बनाना तथा सबको बता कर स्वीकृत कराना, सुझावों के आधार पर सुधार करना तथा तत्पश्चात् कार्यान्वित करना होता है। वार्षिक जाँच-पड़ताल (Audit) द्वारा औचित्य तथा अनौचित्य का पता लगाया जाता है।

स्कूल का खर्च—स्कूल का खर्च कई तरीकों से बताया जा सकता है—

१. स्कूल के विभिन्न क्षेत्रों में खर्च; जैसे अध्यापकों का वेतन, स्कूल के लिए जमीन की खरीदारी, स्कूल के लिए सामान इत्यादि;

२. भिन्न-भिन्न शिक्षा के स्तर के लिए खर्च; जैसे किंडरगार्टन, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा इत्यादि का व्यय;

३. वस्तुओं की खरीदारी;

४. स्कूल की व्यवस्था के खर्च के आधार पर खर्च; जैसे पुस्तकालय, स्वास्थ्य, अध्यापन, व्यवस्था इत्यादि;

५. फंड के आधार पर खर्च, कि कितना धन किस मद में खर्च करना है।

सार्वजनिक शिक्षा का व्यय—अपूर्व स्थिति में पहुँचा हुआ आधुनिक शिक्षा का व्यय लगभग प्रति छात्र प्रति दिन १ डालर (भारतीय ५ पये) है। निम्न आँकड़ों[1] से इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

वर्ष	प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	प्रति व्यक्ति भार	प्रति छात्र पर व्यय
१८७६	डालर ८३,०८२,५७८	डालर १.८८	डालर ६.३७
१८९६	डालर १८३,४९३,९९५	डालर २.५९	डालर १२.६६
१९१६	डालर ६४०,७१७,०५३	डालर ६.३६	डालर ३१.४८
१९३६	डालर १,९६१,१०३,७६५	डालर १५.२७	डालर ७४.३८
१९५६	डालर ७,०००,०००,०००	डालर ४३.२१	डालर २२५.८०

स्कूल की आय—

१. स्थानीय कर;
२. उत्पादन की विधियाँ;
३. आय की इकाइयों का विभाजन; तथा
४. अलग-अलग फंड के आधार पर आय।

उपर्युक्त चार प्रकारों में स्कूल की आय को बताया जा सकता है। यदि राष्ट्र में नहीं तो कम से कम राज्यों में तो आमदनी तथा व्यय दोनों में ही स्थानीय रूपों से अन्तर नहीं होना चाहिए।

सार्वजनिक शिक्षा की सहायता निम्न रूप से होती है—

१.	स्थानीय इकाइयों और काउन्टी द्वारा	५७.२ प्रतिशत
२.	राज्य द्वारा	३८.७ प्रतिशत
३.	केन्द्र द्वारा	३.१ प्रतिशत

कर तथा अन्य साधनों से भी शिक्षा की आय होती है। यह सत्य है कि करों के

1. De Young; An Introduction to American Public Education. P. 512

लिए जनता प्रायः तैयार नहीं होती फिर भी शिक्षा की आय का वह मुख्य साधन है। अन्य साधनों में बोंड, कर्ज इत्यादि सम्मिलित हैं। इन साधनों का प्रयोग तभी होता है जब धनाभाव होता है।

स्कूलों में धन का विभाजन—कभी-कभी धन का विभाजन बड़े-बड़े गलत तरीकों से होता है; इसलिए धन बाँटने के सिद्धान्त उचित होने चाहिए। कभी-कभी छात्रों की संख्या, अध्यापकों की संख्या, निश्चित आधार पर निश्चित सामग्री, तथा कभी-कभी वैसे ही स्कूलों की संख्या के आधार पर धन दे दिया जाता है।

प्रायः प्रत्येक राज्य को स्थानीय प्रेरणा तथा उसकी कमी की पूर्ति का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय लाभ के लिए होती है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र को उचित मात्रा में धन मिल जाय और राष्ट्र को हानि न हो। प्रत्येक की आवश्यकता का ध्यान रखकर ही केन्द्रीय सहायता मिलनी चाहिए। स्थानीय इकाइयों के धनी या निर्धन होने का जो प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है उसका ध्यान रखना केन्द्र तथा राज्य सरकारों का काम है। यद्यपि इस बात का ध्यान सदैव ही रखना चाहिए कि धन का उपयोग उचित रूप से होता है या नहीं।

उच्च शिक्षा की सार्वजनिक आर्थिक सहायता—उच्च शिक्षा के प्रेसीडेन्ट कमीशन ने उच्च शिक्षा की आर्थिक आय को चार भागों में बाँटा है—

१. दान;
२. फीस;
३. सरकारी सहायता;
४. तथा विविध प्रकार जिनमें वस्तुओं की बिक्री इत्यादि सम्मिलित हैं।

सार्वजनिक उच्च शिक्षा-संस्थाओं की फीस की आय कम होती है। प्रशिक्षण इत्यादि में राज्य की सहायता ही मुख्य रहती है। भविष्य के लिए उक्त कमीशन ने उच्च शिक्षा की सहायता के लिए निम्न परामर्श दिया है—

१. चालू खर्चे के लिए सार्वजनिक कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को सहायता देना;
२. सार्वजनिक कालेज या विश्वविद्यालय के स्थापन के व्यय के लिए धन देना;
३. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ जिनके लिए केन्द्र स्तर निर्धारित करे, राज्य द्वारा दी जानी चाहिए।

कहना न होगा कि संयुक्तराज्य में उच्च शिक्षा के लिए बहुत से विश्वविख्यात प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं जहाँ ऊँची फीस ली जाती है तथा प्रायः धार्मिक शिक्षा दी जाती है। केन्द्रीय सहायता अनुसंधान तथा अन्य आयोजनों (Projects) के लिए उन्हें मिल जाती है।

पूर्व-प्रारम्भिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र तक ये धार्मिक संस्थाएँ प्रबन्ध करती हैं। प्राइवेट सूत्रों से भी उन्हें धन मिलता रहता है जैसे फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा प्रौढ़-शिक्षा को विशेष सहायता मिल रही है।

इतनी प्रगति के पश्चात् भी शिक्षा के क्षेत्र में धनाभाव है क्योंकि शिक्षा के लिए धन अधिकतः स्थानीय सूत्रों से मिलता है जो प्रायः निर्धन हैं।

पंचम अध्याय

रूपरेखा :—

प्रथम चरण :—स्तरांकन अभिकरण (Accredition)

द्वितीय चरण :—भूमि-अनुदान महाविद्यालय ।

तृतीय चरण :—संयुक्तराज्य में परीक्षा-प्रणाली ।

चतुर्थ चरण :—शिक्षा के मूल प्रश्न और प्रवृत्तियाँ ।

प्रथम चरण

स्तरांकन अभिकरण

रूपरेखा :—

१. परिचय।

२. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।

३. परिभाषा।

४. माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों का स्तरांकन।

लेखक : प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह

स्तरांकन अभिकरण[1,2]

Accrediting Agencies ?

शिक्षा में समान स्तर की आवश्यकता संयुक्तराज्य में उसी समय से अनुभव होने लगी जब से प्रत्येक हाईस्कूल, जूनियर कालेज या लिबरल आर्ट्स कालेज इत्यादि अपने-अपने छात्रों को डिग्री देने लगे। विभिन्न स्तरों की उत्पत्ति ने एक प्रकार की अव्यवस्था (Chaos) उत्पन्न कर दी। विकेन्द्रीकरण और प्रजातन्त्र में अत्यधिक विश्वास के कारण वहाँ की शिक्षा-संस्थाएँ अपने अध्यापन को किसी अन्य प्रमाप के द्वारा निर्णीत नहीं देख सकतीं। इस प्रकार यह स्तरांकन-व्यवस्था अमरीकी जीवन और दर्शन की ही देन है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—फौजी स्कूलों को अपने यहाँ छात्रों को प्रवेश देने के लि स्तरांकित स्कूलों और कालेजों की सूची की आवश्यकता थी। विदेशी विश्वविद्यालय मुख्यतः जर्मनी के विश्वविद्यालय अपने यहाँ अमरीकी छात्रों को प्रवेश देने के लिए उचित योग्यता और स्तर वाले छात्र ही चाहते थे इन्हीं उक्त कारणों से स्तरांकन-कार्य प्रारम्भ हो गया। मिशीगन विश्वविद्यालय ने पहली बार सन् १८७२ में अपने यहाँ छात्रों का स्तर जानने के लिए माध्यमिक स्कूलों का स्तरांकन प्रारम्भ किया। स्तरांकन चाहे माध्यमिक स्कूलों का हो या उच्च विद्यालयों का, इसकी जिम्मेदारी राज्य और स्वतंत्र सहकारी अभिकरण (Independent Co-operative Agencies) की है। इंडियाना राज्य के शिक्षाविभाग ने सन् १८७३ में थम बार राज्य की ओर से सार्वजनिक स्कूलों का स्तरांकन प्रारम्भ किया।

केन्द्रीय सरकार की ओर से स दिशा में एक असफल कदम उठाया गया। १९११ में ब्यूरो आफ एजूकेशन ने अमेरिकन विश्वविद्यालयों के एसोसियेशन की सहायता से एक सूची तैय्यार की। उस सूची में कालेजों का वर्गीकरण भी हुआ था। किन्तु उस सूची पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो सके। इस प्रकार केन्द्र ने उस दिशा में पुनः चि नहीं ली। सन् १८९८ से १९२३ तक कई अन्य अभिकरणों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्तरांकन का कार्य प्रारम्भ किया। नेशनल एजूकेशन एसोसियेशन (१८९८) कार्नेजी फाउन्डेशन फार एडवान्समेन्ट आफ लर्निंग (१९०८) और एसोसियेशन आफ अमेरिकन यूनीवर्सिटीज़ (१९१४) इत्यादि ने इन वर्षों में कार्य करना प्रारम्भ किया था। उक्त तृतीय एसोसियेशन ने अचानक ही कार्य करना प्रारम्भ किया था क्योंकि जर्मन विश्वविद्यालय उसी के समर्थन

1. Encyclopedia of Educational Research (Revised Ed.) 1952. Edited by Walter S. Monroe pp. 1-6. The MacMillan Co. New York.
2. The New Era in Education by I.L. Kandel ; pp. 185-186. Houghton Mifflin Co. ; U.S.A.

पर छात्रों को प्रवेश देते थे । प्रथम सूची उक्त एसोसियेशन ने १६१२ में बनाई यद्यपि १६२४ में केवल पढ़ाई को ही स्तरांकन का प्रमाप मानना उसने बन्द कर दिया । इस प्रकार के आशय की सलाह अमेरिकन काउन्सिल ने दी थी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय (Regional) एसोसियेशन इस काम पर १६०८ में उतर आये और उसी वर्ष नार्थ सेन्ट्रल एसोसियेशन न उच्च शिक्षा-संस्थाओं की स्तरांकित सूची प्रकाशित की। १६१८ तक इन लिवरल आर्ट्स कालेजों के अतिरिक्त जूनियर तथा प्रशिक्षण कालेजों की सूची भी प्रकाशित हो गई। अन्य एसोसियेशनों ने इस क्षेत्र में निम्न क्रम से कार्य करना प्रारम्भ किया—नार्थ वेस्ट एसोसियेशन (१६१८), मिडिल स्टेट्स एसोसियेशन (१६२१) और सदर्न एसोसियेशन (१६२१)।

सामान्य कालेज या विश्वविद्यालय के अतिरिक्त विशेष विषयों की शिक्षा-संस्थाओं के स्तरांकन का कार्य भी प्रारम्भ हुआ जिसे प्रायः उस व्यवसाय के काम करने वाले लोगों की राय का ही आधार मिला। उन बहुत से एसोसियेशनों में से कुछ इस प्रकार हैं : अमेरिकन मेडीकल एसोसियेशन (१६०७), नेशनल ऐसोसियेशन आफ म्यूजिक (१६२५), अमेरिकन एसोसियेशन आफ टीचर्स (१६२७) इत्यादि; जो अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं।

न्यूयार्क राज्य के बोर्ड आफ रीजेन्टस् ने अपने राज्य तथा बाहर के स्तरांकन में बड़ा ही सक्रिय भाग लिया है। १६४४ के पश्चात् बहुत से राज्यों ने स कार्य को करना प्रारम्भ कर दिया है। सैनिक और सामान्य शिक्षा के विकास के कारण इस स्तरांकन का विकास होना प्रारम्भ हो गया है।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उक्त एसोसियेशन कार्य करते हैं। इन्होंने अपना कार्य निम्न क्रम से प्रारम्भ किया था—

सदर्न एसोसियेशन (१६१२), नार्थ वेस्ट एसोसियेशन (१६१८) और मिडिल स्टेट्स एसोसिएशन (१६२३)। न्यू इंग्लैंड एसोसियेशन ने स्तरांकन के केवल नियम बनाये हैं पर वह काम नहीं करता। एक वेस्टर्न एसोसियेशन भी है पर उसके स्थान पर केलीफोर्निया विश्वविद्यालय कार्य करता है।

भिन्न-भिन्न राज्य भिन्न-भिन्न नियमों का पालन करते हैं जैसे कुछ राज्य उन्हीं स्कूलों का स्तरांकन करते हैं जो स्तरांकित सूची में आना चाहते हैं।

परिभाषा—जुक और हेगर्टी राज्यों ने स्तरांकन की निम्न परिभाषा की है—

स्तरांकन इस प्रकार की मान्यता है जो किसी अभिकरण या संघटन द्वारा किसी शिक्षा-संस्था को संयुक्तराज्य में उसका नाम अपनी सूची में लिखकर दे देती है, जो मान्यता प्राप्त करने के प्रमाप (Standard) या माँगों को पूरा करते हैं जिन्हें किसी उक्त संस्था ने निश्चित किया था। (Accreditment is the recognition to an educational institution in the United States by means of inclusion in a list of insti-

tutions issued by some agency or organisation which sets up Standards or requirements that must be complied in the order to secure approval.)

माध्यमिक और उच्च विद्यालयों का स्तरांकन—माध्यमिक शिक्षा के केन्द्रों की स्तरांकन-सम्बन्धी बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी हैं। यद्यपि उक्त एसोसियेशन इस कार्य में समर्थ हैं, किन्तु हाई स्कूलों और व्यापक स्कूलों का क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है इसीलिए प्रमाप (Standard) की समस्या बढ़ती जा रही है। हम उन तीन ऐसोसियेशनों का वर्णन कर आये हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। १९४३ में मिडिल स्टट्स एसोसिएशन आफ कालेज एण्ड सेकेन्डरी स्कूल्स ने अपने वार्षिक अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि ९ सामान्य प्रमाप रहेंगे जो बड़े-बड़े ७ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे—वे क्षेत्र इस प्रकार हैं—(१) स्कूल का दर्शन (२) पढ़ाई का प्रोग्राम (३) पुस्तकालय (४) स्कूल की इमारत (५) स्कूल का कर्मचारी और अध्यापकवर्ग (६) व्यवस्था और (७) स्कूल तथा वहाँ के समाज का सम्बन्ध।

इस क्षेत्र में बहुत सी खोजें हो रही हैं किन्तु और भी खोजों की आवश्यकता है, कारण है कि अभी तो प्रमाप का भी प्रमाप निश्चित नहीं हो पाया है।

उच्च शिक्षा में भी स्तरांकन लगभग उसी आधार पर होता है जिस पर कि माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों का। यद्यपि राज्यों के नियम पर ही ये उच्च शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित होती हैं किन्तु उन्हें बोर्ड इतनी स्वतन्त्रता दे देते हैं कि उनका एक सा स्तर रखना असम्भव हो जाता है। फिर सामाजिक आलोचना का दोषपूर्ण प्रभाव भी उन पर हो जाता है। इस प्रकार इन सब कमियों को दूर करने के लिए स्तरांकन आवश्यक है, किन्तु स्तरांकन गुण (Quality) का नहीं, मात्रा (Quantity) होता है। अच्छे स्कूल की परिभाषा उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षकवर्ग, उनकी अधिक संख्या या स्कूल की अच्छी इमारत है, जबकि हम जानते हैं कि अच्छे स्कूल में ये आवश्यक गुण भी होने चाहिए किन्तु उसकी अच्छाई की परख जीवन के लिए योग्य विद्यार्थियों को तैयार करना है।

यह स्तरांकन-शैली केवल अमरीका की, अपनी अनोखी है। यद्यपि इसको ठीक करने की बहुत सी चेष्टाएँ हो रही हैं किन्तु अभी यह हो नहीं पाया है कि उचित कार्य प्रारम्भ हो गया हो।

द्वितीय चरण

भूमि-अनुदान महाविद्यालय (Land-Grant College)

रूपरेखा :—

१. राष्ट्रीय उत्थान में टैक्नीकल शिक्षा—अमेरिका में भूमि-अनुदान महाविद्यालयों का जन्म।

२. भूमि-अनुदान महाविद्यालय तथा अमेरिकन उच्च शिक्षा।

३. भूमि-अनुदान महाविद्यालय—स्वभाव, क्षेत्र, संगठन तथा कार्य।

४. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

(१)

राष्ट्रीय उत्थान में टैक्निकल शिक्षा

देश के उत्थान में नव-निर्माण के लिए टैक्नीकल शिक्षा नितान्त आवश्यक है। औद्योगिक देशों के विकास में तो टैक्नीकल शिक्षा आधारभूत कार्य करती है। नये-नये कल-कारखानों के लिए टैक्नीकल विशेषज्ञ सदैव ही चाहिए। डा० हैन्स के कथनानुसार, उपर्युक्त तथ्यों को समझने तथा उसे स्वीकार करने में इंग्लैण्ड को तो सौ वर्ष के लगभग लगे थे। यही कारण था कि १८६७ ई० में जहाँ इंग्लैण्ड में कुछ ही टैक्नीकल विद्यालय थे, वहाँ १९३७ ई० में अर्थात् ७० वर्ष के समय में, ७०० टैक्नीकल तथा औद्योगिक विद्यालय हो गए थे।

पीटर महान् के संरक्षण में, रूस में टैक्नीकल शिक्षा आरम्भ से ही विकसित हो रही थी। उन्नीसवीं शती के छठवें दशक में, विश्व को, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों द्वारा, रूस की टैक्नीकल कुशलता का उच्च स्तर ज्ञात हुआ था। मास्को उच्चतर टैक्नीकल विद्यालय की विधियों से, अमेरिका तो इतना अधिक प्रभावित हुआ कि पिछली शताब्दी के आठवें दशक में, तथाकथित "रूसी प्रणाली" ("Russian System") के नाम से देश में टैक्नीकल शिक्षा का जोरदार आरम्भ हुआ। डा० कैन्डेल के कथनानुसार भूमि-अनुदान महाविद्यालयों के जन्मदाता, १८६२ तथा १८९० ई० के मौरिल नियम (Morrill Acts), कृषि तथा मशीनरी-कुशलता को, शिक्षा के उच्चतर स्तर पर लाने के उद्देश्य से अनुप्राणित थे। और बाद के अन्य नियमों ने इसी दिशा में विविध रूपों में सहायता की।

इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि कृषि तथा टैक्नीकल शिक्षा को विशेष बढ़ावा देकर देश को शीघ्र बढ़ाने के अभिप्राय से, संघीय सरकार ने, राज्यों को शिक्षा में सहयोग देते हुए, १८६२ ई० के मौरिल नियम के अनुसार संयुक्तराज्य में 'भूमि-अनुदान महाविद्यालय' स्थापित किये।

(२)

भूमि-अनुदान महाविद्यालय तथा अमरिकन उच्च शिक्षा

अपने विशिष्ट कार्य, संगठन तथा उद्देश्यों के कारण, भूमि-अनुदान महाविद्यालयों ने अमेरिका की उच्च शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। संयुक्तराज्य में, इलीनॉइज, कैलीफोर्निया तथा मिनेसोटा जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तथा मिशीगन, मैसाचूसेट्स तथा टैक्सास में खोले गये कृषि महाविद्यालय, भूमि-अनुदान आन्दोलन के ही परिणाम हैं। इसी के कारण अनेकों शिक्षा-संस्थाओं, जैसे, विसकौन्सिन विश्वविद्यालय आदि की, शिक्षा-योजनाओं का पुनर्गठन हुआ। इस नए दृष्टिकोण ने सहशिक्षा को पर्याप्त

बढ़ावा दिया। भूमि-अनुदान महाविद्यालय अनुसंधानप्रधान होने, तथा कृषि तथा घरेलू अर्थशास्त्र पर बल देने के कारण 'प्रजातन्त्र के महाविद्यालय' (Democracey's College) कहे जाते हैं। और इस अर्थ में, अमेरिकन शिक्षा-दर्शन—महान् ड्यूई के उपयोगितावाद (Pragmation) का सच्चा प्रगतिशील प्रतिनिधि है।

(३)

भूमि-अनुदान महाविद्यालय : स्वभाव, क्षेत्र, संघटन तथा कार्य

भूमि-अनुदान महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा की वे उच्च संस्था हैं जिन्हें मौरिल नियमों से प्राप्त धन का उपयोग करने के लिए, राज्य सरकार की ओर से अनुमति प्राप्त है

१८६२ ई० के मौरिल नियम की विशेष बातें तीन थीं—

१. प्रत्येक राज्य को, कांग्रेस में उपस्थित, प्रति सिनेटर तथा प्रतिनिधि के हिसाब से ३०,००० एकड़ भूमि का अनुदान।

२. इस अनुदान से प्राप्त ब्याज से ऐसी शिक्षा चलाना, जिसके पाठ्य-क्रम में—
अ—कृषि तथा मशीनरी कुशलता पर जोर हो।
आ—साथ में वैज्ञानिक तथा अन्य विषय भी पढ़ाए जाएँ; तथा
इ—सैनिक शिक्षा दी जाय।

भूमि के इस प्रकार के अनुदान के कारण ही न महाविद्यालयों को भूमि-अनुदान महाविद्यालय कहा जाता है।

अध्यापकों के वेतन तथा शिक्षण के सात बड़े क्षेत्रों में, शिक्षण की सुविधा तथा सहायता के लिए इन विद्यालयों को आर्थिक सहायता संयुक्तराज्य के शिक्षा-कार्यालय से मिला करती है। प्रत्येक भूमि-अनुदान महाविद्यालय अपनी वार्षिक रिपोर्ट शिक्षा कार्यालय को भेजता है। जहाँ अर्थ के साधन का प्रश्न है, अधिकांश सहायता राज्य-सरकारों से प्राप्त होती है, संघ-सरकार से नहीं।

संयुक्तराज्य में ऐसे विद्यालयों की संख्या ६९ है और प्रसिद्ध विद्वान् डी. यंग (De Young) के मतानुसार इन्हें तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—

क्रम संख्या	विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों का स्वभाव
१	२४	स्वतन्त्र महाविद्यालय।
२	२८	विश्वविद्यालय जिनमें कृषि, इंजीनियरी तथा घरेलू अर्थशास्त्र का समन्वित पाठ्यक्रम चलता है
३	१७	नीग्रो लोगों के लिए उच्च शिक्षा-विद्यालय।

इन ६९ भूमि-अनुदान महाविद्यालयों में बहुत से सरकारी विश्वविद्यालय हैं। कृषि तथा टैक्नीकल शिक्षा के बहुत से महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय हैं। कुछ जनियर तथा शिक्षक महाविद्यालय भी हैं।

भमि-अनुदान महाविद्यालय के तीन धान अंग होते हैं—

१. विद्यालयगत अध्यापन।
२. प्रयोगात्मक केन्द्रों (Experimental Stations) द्वारा किया गया अनसन्धान।
३. प्रसार-सेवा (Extension Service)

इन विद्यालयों के अध्यापन में अनुसंधानों तथा सार-सेवा से प्राप्त अनुभवों का यथास्थान उपयोग किया जाता है। अनुसन्धान से समाज की विशिष्ट समस्याओं का पता तथा उन्हें हल करने के तरीकों का पता लगाया जाता है। इन हलों को जनता तक प्रसार-सेवा द्वारा पहुँचाया जाता है और यह देखा जाता है कि उनसे कुछ लाभ हुआ या नहीं, जो अनुभव इस तरह प्राप्त होते हैं उनका उपयोग अध्यापन में किया जाता है ताकि आगे के लिए विद्यार्थियों को तयार किया जाय।

इन विद्यालयों की, स्मिथ-लीवर नियम (१९१४) द्वारा स्थापित, प्रसार-सेवा (Extension Service) अत्यधिक प्रसिद्धि-प्राप्त है। स सेवा को कुशल लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। इन्हें चार भागों में रखा जा सकता है—

१. काउन्टी कृषि-प्रतिनिधि।
२. काउन्टी गृह प्रदर्शन-कार्यकर्त्ता।
३. लड़के तथा लड़कियों के क्लबों के कार्यकर्त्ता
४. अन्य विशेषज्ञ।

इस प्रकार उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में, इन भूमि-अनदान महाविद्यालयों ने, संयुक्तराज्य की शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त अनसन्धान, अध्यापन तथा प्रसार के त्रिभुज पर आधारित, शिक्षा तथा समाज में स्वस्थ सम्पर्क स्थापित करने वाले ये स्वस्थ महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, घरों और किसानों की उचित सेवा करने के कारण समाज के सच्चे सेवक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन महाविद्यालयों के देशव्यापी, नीग्रो तथा अनीग्रो संगठन इनकी प्रगति के लिए नित्य नई योजनाओं का सृजन करते रहते हैं।

तृतीय चरण

संयुक्तराज्य में परीक्षा-प्रणाली

रूपरेखा :—

१. भूमिका—परीक्षा का स्वरूप तथा भेद।
२. परीक्षा की आवश्यकता।
३. परीक्षा—वैज्ञानिक स्वरूप तथा उद्देश्य।
४. परीक्षा के विभिन्न क्षेत्र।
५. परीक्षा—संयुक्तराज्य और भारत—उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

(१)

प्रतिक्षण बदलते हुए विश्व में, समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताएँ भी बदलती रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों तथा दूसरों से प्राप्त शिक्षा द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करता है। इन प्रयत्नों में ही स्वयं के अनुभवों तथा दूसरों की दी हुई शिक्षा की परीक्षा होती है। उपयोगी अनभुव तथा शिक्षा ही सफल माने जाते हैं।

उपर्युक्त दृष्टिकोण को आगे रखकर, हम विद्यालय में स्थित विद्यार्थी की रोज की प्रगति के बारे में भी कह सकते हैं। इस बात की एक बड़ी आवश्यकता है कि विद्यालय को विद्यार्थी के भावी जीवन के निर्माण में सबसे बड़ा सहायक बनाने के लिए शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षण-प्रणाली, तथा विद्यार्थी की वैज्ञानिक परीक्षा सदैव होती रहें ताकि उसकी उपयोगिता का पूर्ण चित्र सदैव हमारे सामने रहे और आवश्यकता तथा समय के अनुसार यथास्थान उसमें परिवर्तन आदि भी किये जा सकें।

परीक्षा, वैसे तो जीवन के प्रत्येक पद पर होती है, किन्तु विद्यालय की परीक्षा का महत्त्व अधिक है। विद्यालय वह संस्था है जहाँ हम, समाज तथा संस्कृति-विकास के लिए, एक उचित नागरिक का निर्माण करते हैं। विद्यालय एक प्रयोगशाला है। हमने जो भी भोले शिशु को सिखाया, जिस ढंग से सिखाया, जिस ढंग तथा रुचि से विद्यार्थी ने सीखा, शिशु के घर ने कैसा सहयोग दिया——इन सबका ठीक मूल्यांकन होना अत्यन्त आवश्यक है। परीक्षा वह ही नहीं होती जो वर्ष में एक या दो बार, कक्षा में हुआ करती है; परीक्षा, एक व्यापक वस्तु है और सफल जीवन को उचित रास्ते पर चलाने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

(२)

छोटे-छोटे विद्यालयों से लेकर विश्व-विद्यालयों तक, सभी में परीक्षा हुआ करती हैं। कक्षा में उच्चतर कक्षा के लिए परीक्षा आवश्यक मानी जाती है। यह सब होते हुए भी, परीक्षाएँ वैज्ञानिकता से दूर होती चली गई हैं। विद्यालयों में इस बात की चेष्टा नहीं की जाती कि जो कार्य किया गया, उसका क्या परिणाम रहा? विद्यार्थियों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा क्या परिवर्तन किये गए, इसके विषय में कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया जाता।

परीक्षा की ओर से इस तरह की उपेक्षा तथा अज्ञान——इस सबका कारण क्या हो सकता है? बहुत से कारण हैं, किन्तु एक प्रमुख कारण यह भी है कि सभी जगह, कक्षा में चढ़ाने तथा उच्चतर विद्यालय में प्रविष्ट करने के लिए विशेष योग्यताओं (Credits) के संचय पर बल दिया जाता है। विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम

को पढ़ना, याद रखना, तथा पास करना आवश्यक है। यही कारण है पाठ्यक्रम को याद करना तथा परीक्षा की विधियों का अभ्यास करना, शिक्षा का उद्देश्य बन जाता है और यही उद्देश्य अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए एक-सा है।

संयुक्तराज्य में परीक्षाओं के ऊपर अनुसन्धान किये गये, और उन्हें अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने की चेष्टा की गई। अनेकों अनुसन्धानकर्त्ताओं के सहयोग के अतिरिक्त कुछ ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिन्होंने इस दिशा में आशातीत उन्नति की। इन संस्थाओं में प्रमुख निम्न हैं—

१. शिक्षा रिकार्डस ब्यूरो (Educational Records Bureau)
२. सहयोगी परीक्षा-सेवा (Cooperative Test Service)
३. उच्चतर विद्यालय-प्रवेश परीक्षाबोर्ड (College Entrance Examination Board)

उपर्युक्त संस्थाओं के दीर्घ अनुभव से परीक्षा तथा उसके क्रम के विषय में तीन प्रमुख अनुभव हमारे सामने आये—

१. विद्यार्थियों के अनुभवों तथा प्रगति का जो भी मूल्यांकन किया जाय, उसका विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों से सीधा सम्बन्ध होना चाहिए।
२. विद्यालय की सभी मूल्यांकन-योजनाएँ व्यापक (Comprehensive) होनी चाहिएं। इन योजनाओं में वे योजनाएँ भी हों जो विद्यालय के सभी प्रमुख उद्देश्यों की ओर की गई प्रगति के मूल्यांकन के विषय में हों।
३. मूल्यांकन के लिए जिन उपादानों की आवश्यकता होती है, उन सभी का निर्माण वहीं के अध्यापक स्वयं करें। यहाँ तक कि विद्यार्थी की प्रगति के लिखने के लिए उनके पत्रों तक का वहीं निर्माण हो।

(३)

परीक्षा के विषय में विद्यालयों तथा उच्च विद्यालयों में, साधारणतया निम्न बातें अपनाई जाती हैं—

१. विद्यार्थियों का श्रेणियों में विभाजन (Gradation);
२. अलग कक्षाओं और समूहों में विभाजन (Grouping);
३. ऊपर चढ़ाना (Promotion);
४. पितरों को रिपोर्ट भेजना आदि-आदि।

किन्तु उपर्युक्त उद्देश्य संकुचित हैं, उन्हें आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक बनाना चाहिए। आज के प्रमुख उद्देश्य, परीक्षा के विषय में निम्न हो सकते हैं—

१. विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण, ताकि उन स्थानों का पता लग सके जहाँ पर, योजना के अन्तर्गत, उन्नति हो सकती है।

२. शिक्षा की जिन मान्यताओं (Hypotheses) को लेकर विद्यालय चला है, उनकी जाँच करना। देखा यह गया है कि विद्यालय की प्रबन्ध-नीति तथा अन्य रीतियाँ कभी-कभी उद्देश्य से बिल्कुल मेल नहीं खातीं, किन्तु यह सब होते हुए भी वे बनी ही रहती हैं ।

३. विशिष्ट विद्यार्थियों के, प्रभावपूर्ण अधिनयन (Guidance) के लिए अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करना। विद्यार्थी के सर्वांगीण मूल्यांकन पर ही उसका अधिनयन आधारित है।

४. जन-सम्पर्क के लिए एक सुन्दर आधार की नींव डालना। दूसरों के साथ सहयोग तथा रचना पर आधारित दृष्टिकोण के विकास से अधिक और कोई वस्तु महत्त्वपूर्ण नहीं है।

(४)

उपर्युक्त उद्देश्यों को देखकर, यह समझना सरल है कि परीक्षा, आज के युग में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आज हमें बालक को उत्कृष्ट नागरिक बनाने के लिए,उचित सहायता देने के लिए, समय-समय पर उसकी प्रगति का अनुमान रखने के लिए, सर्वांगीण परीक्षा चाहिए। ऐसी परीक्षा जो व्यक्ति का सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने रख सके और जिसकी विधि एकदम वैज्ञानिक हो।

सर्वांगीण परीक्षा के अन्तर्गत, मनुष्य के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की जाती है। संयुक्तराज्य में प्रयोग के रूप में इस दिशा में प्रशंसनीय प्रयत्न हुए हैं। व्यक्तित्व के निम्न क्षेत्रों का अध्ययन सर्वांगीण परीक्षा में आवश्यक है।

अ—विचार-क्षेत्र।

आ—सामाजिक अनुभूति-क्षेत्र।

इ—सौन्दर्य-बोध-क्षेत्र।

ई—रुचि-क्षेत्र।

उ—व्यक्तिगत तथा सामाजिक सामंजस्य।

अ—विचार-क्षेत्र

उचित विचार करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। उचित विचार करने में चार बातें प्रमुख है—

१. तथ्यों से अर्थ निकालने की योग्यता।

२. विज्ञान के सिद्धान्तों के प्रयोग की क्षमता।

३. वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता।

४. प्रमाण के स्वभाव को समझने की योग्यता।

आ—सामाजिक अनुभूति-क्षेत्र

अनुभूति सोचने के ढंगों, रुचियों, दृष्टिकोणों तथा ज्ञान पर आधारित होती है। अतः सामाजिक अनुभूति के विशिष्ट क्षेत्र निम्न हैं—

१. सामाजिक विचार।
२. सामाजिक दृष्टिकोण।
३. सामाजिक जागरूकता (Awareness)
४. सामाजिक रुचियाँ।
५. सामाजिक जानकारी।
६. सामाजिक कार्यों में कुशलता।

इ—सौन्दर्य-बोध-क्षेत्र

विद्वान् कैरॉल (Carroll) के अनुसार सौन्दर्य-बोध में जानकारी, शैली के प्रति अनुभूति, 'गहरे अर्थ' का ज्ञान तथा संवेगात्मक प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है।

संयुक्तराज्य में, मूल्यांकन समिति (The Committee on Evaulation) ने सौन्दर्य-बोध की जाँच के लिए निम्न बातों को आवश्यक ठहराया—

१. प्रशंसित वस्तु में संतोष।
२. प्रशंसित वस्तु को और अधिक पाने की इच्छा।
३. प्रशंसित वस्तु को और अधिक जानने की इच्छा।
४. स्वरचनात्मकता को प्रकाशित करने की इच्छा।
५. प्रशंसित वस्तु से स्वयं की एकात्मकता-स्थापन की इच्छा।
६. प्रशंसित वस्तु द्वारा उठाई गई,जीवन की समस्याओं के विषय में विचारों को शुद्ध करने की इच्छा।
७. प्रशंसित वस्तु का मूल्यांकन करने की इच्छा।

ई—रुचि-क्षेत्र

उपर्युक्त समिति ने रुचियों को साधन तथा साध्य, दोनों ही माना।

साधन के अन्तर्गत, शिक्षक विद्यार्थियों की उन क्रियाओं को जानने का प्रयत्न करते हैं, जिनमें विद्यार्थियों की रुचि होती है। इन क्रियाओं का बाद में वे शिक्षा में यथा-सम्भव उपयोग करते हैं।

साध्य के अन्तर्गत, शिक्षकों को निम्न कार्य करने पड़ते हैं—

१. विद्यार्थियों की रुचियों के विकास के लिए किन कार्य-क्षेत्रों को विकसित किया जाय ?
२. व्यक्ति तथा समाज के कल्याणकारी क्षेत्रों में उन रुचियों को किस तरह लाया जाय ?

औद्योगिक रुचियाँ (Vocational interests) भी इन्हीं में शामिल हैं।

वैसे तो दोनों ही प्रकार की रुचियों का ज्ञान तथा विकास आवश्यक है, परन्तु रुचियों को साध्य मान कर विद्यार्थी की सहायता करना प्रमुख माना गया है।

उ––व्यक्तिगत तथा सामाजिक सामंजस्य

व्यक्ति की अपनी भावनाओं, सुख, तथा अन्तरंग विचारों के प्रति प्रतिक्रियाओं, तथा अन्य लोगों से सम्पर्क––चाहे वे अपने से बड़े, बराबर या छोटे हों––दूसरे लिंग के हों, समाज के नियमों और रीतियों के प्रति दृष्टिकोण आदि उसके 'उचित सामंजस्य के लिए आधार का कार्य करते हैं। इन दोनों सामंजस्यों को ठीक रखने में, निम्न बातों पर विचार आवश्यक है।

१. व्यक्ति की अपनी इच्छाएँ, जन्मजात आवश्यकताएँ हैं जिन्हें वह सन्तुष्ट करना चाहता है।
२. समाज की भी अपनी आवश्यकताएँ हैं। इन आवश्यकताओं के कारण व्यक्तियों से कुछ माँगें की जाती हैं। इन माँगों में, घर का स्तर, संस्कृति आदि भी सहायक होते हैं।

इन समस्याओं को जब व्यक्ति सुलझा नहीं पाता, उस समय उसके कार्य दो प्रकार के होते हैं। या तो वह अपनी इच्छाओं को मार कर चिंतित तथा मलीन हो उठता है या समाज के विरुद्ध विद्रोह करने लगता है क्योंकि उसे इच्छाओं का सन्तोष चाहिए।

उपर्युक्त क्षेत्रों में बालकों का उचित मूल्यांकन होना आवश्यक है और इसीलिए उसे पूरा करने को वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना नितान्त आवश्यक है। इन विधियों में निम्न प्रमुख हैं––

१. कागज-पैन्सिल-परीक्षा।
२. कक्षा-गोष्ठी।
३. स्वतन्त्र चुनाव से प्राप्त कार्यों का रिकार्ड।
४. स्वतन्त्र प्रतिक्रिया-परीक्षा।
५. प्रश्न-पत्र (Questionnaire)
६. इन्टरव्यू।
७. विद्यालय-परीक्षा।

(५)

उपर्युक्त विवेचन से, संयुक्तराज्य की शिक्षा-संस्थाओं में, परीक्षा के प्रति जो जागरूकता विद्यमान है, उसका पता चलता है। परीक्षा आज विषय तक ही सीमित नहीं है, जीवन को सफल बनाने के लिए उपयुक्त अधिनयन होने के कारण वह व्यापक बन रही है। परीक्षा की व्यापकता, यद्यपि अभी पूर्ण नहीं हो सकी है और काफी समय भी लगेगा, किन्तु यह प्रयोगात्मक पग उज्ज्वल भविष्य का सूचक है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

परीक्षा को व्यापक तथा सर्वांगीण बनाने के अतिरिक्त जो परीक्षा का पुराना स्वरूप है, वह भी, कुछ अर्थों में, अपने देश की परीक्षा-प्रणाली से विशिष्ट है।

संयुक्तराज्य में, परीक्षा ही, सब कुछ नहीं समझी जाती। अपने देश में ऐसी बात नहीं है। वहाँ कक्षा-प्रवेश तथा आगे बढ़ाने के लिए वर्ष में छः बार परीक्षाएँ होती हैं, अपने यहाँ की तरह एक बार नहीं।

इसके अतिरिक्त कक्षा-प्रगति के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण होना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। वहाँ विद्वत्ता तथा विषय-गत[1] दोनों ही प्रकार की परीक्षाएँ होती हैं। विषय-गत परीक्षाओं में चौदह विषय तक हैं और इनमें केवल तीन विषय में ही परीक्षा होनी आवश्यक होती है। उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण जैसी बात नहीं होती। उसी तरह, अपने यहाँ की तरह विद्यार्थी के पास अधिक विषयों का बोझ भी नहीं होता। यह अवश्य है कि परीक्षा-पत्रों का स्तर यहाँ के स्तरों से ऊपर ही होता है।[2]

---

1. a. Scholastic Aptitude Test (SAT)
   b. Achievement Test.
2. Examinations in U.S.A. Not All-important. (Article in the Hindustan Times, dated Jan. 15, 1958.)

चतुर्थ चरण

शिक्षा के मूल प्रश्न तथा प्रवृत्तियाँ

रूपरेखा :—

१. भूमिका।
२. नेतृत्व और उसका महत्त्व।
३. आवश्यक उद्यमों का विश्लेषण।
४. कार्यों की परिभाषा।
५. धन-सहायता की स्पर्द्धा।
६. शिक्षक और शिक्षा-नीति।
७. शिक्षा की योजना।
८. हमारे सहायक सिद्धान्त।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

(१)

आज के वैज्ञानिक युग में, प्रत्येक देश के जीवन तथा विकास के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने समस्त शक्ति-साधनों को ठीक समझे और उनसे यथोचित सहायता लेता हुआ, सहयोग के आधार पर, आगे बढ़े। देश के बहुमूल्य शक्ति-साधनों में से एक विद्यालय भी है। अतः देश के उत्थान का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व विद्यालयों पर है और यदि यह उत्तरदायित्व उचित रूप से न समझा गया तो देश का काफी अनिष्ट हो सकता है। यही कारण है कि आधुनिक शिक्षा के मूल प्रश्नों को देखा जाना तथा शिक्षा की नई प्रवृत्तियों का मूल्यांकन भावी योजनाओं के लिए आवश्यक है।

विद्यालय की वे योजनाएँ जो समाज की आवश्यकताओं से दूर हैं और जो परिवर्तन के विरुद्ध हैं, जिनका विस्तार अति संकुचित है और जो दूर से ही बड़ी कमजोर-सी दिखाई देती है, ये योजनाएँ अमेरिकन जन-शिक्षा के उद्देश्यों के बिल्कुल विरुद्ध हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय तथा समाज की अन्य प्रमुख संस्थाओं में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हो, ताकि समाज की उन्नति का ठोस और सीधा मार्ग तैयार हो सके।

(२)

नेतृत्व और उसका महत्त्व[1]

समाज की सभी संस्थाएँ मिलजुल कर काम करें, इस योजना में यह नितान्त आवश्यक है कि समाज तथा देश-विकास के मार्ग में नेतृत्व कौन करे? कौन नेता हो सकता है? राष्ट्र-विकास में शिक्षा-विद्यालय ही नेतृत्व कर सकते हैं। विद्यालय ही वह संस्था है जहाँ राष्ट्र के भावी नागरिकों का निर्माण होता है। व्यक्ति के चरमतम विकास के साधन यहाँ जुटाये जाते हैं। अतः विद्यालय के अधिकारी देश के बालकों की ओर से समाज की अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

संयुक्तराज्य में, राष्ट्र-विकास में विद्यालय प्रमुख हैं, यह तो मानने की प्रवृत्ति है किन्तु उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं है।

(३)

आवश्यक उद्यमों का विश्लेषण

युद्ध और शान्ति के काल में देश के बालकों की कौन-सी आवश्यकताएँ होती हैं? इन आवश्यकताओं को कैसी योजनाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है? शारीरिक,

1. Samuelson: In American Education in the Post War Period. p. 207.

मानसिक, सामाजिक तथा शिक्षा-विषयक आवश्यकताओं को विशिष्ट आवश्यकता कैसे बनाया जा सकता है ? इन प्रश्नों का उत्तर ही राष्ट्र-निर्माण की एक बड़ी योजना बन जायगा और उस बड़ी योजना को समाज की एक संस्था, चाहे वह सरकार ही क्यों न हो, पूरा नहीं कर सकती। दूसरी संस्थाओं का सहयोग नितान्त आवश्यक होगा। यहाँ पर यह देखना भी आवश्यक है कि इस योजना में विद्यालय के उत्तरदायित्व तथा कार्य कौन-से हैं ? यह एक बड़ा प्रश्न है और इसका स्पष्ट उत्तर अभी तक स्पष्टता से नहीं मिला है।

(४)

कार्यों की परिभाषा

विकास में अधिक से अधिक ठोस सहयोग के लिए यह आवश्यक है कि जो कार्य करने हैं, उनकी प्रक्रिया भली भाँति निश्चित हो। कार्यों की परिभाषा और उत्तरदायित्वों का वितरण, मूल समस्याएँ हैं। समाज की किस संस्था को अपराधी बालकों की देखभाल तथा सुधार के लिए उत्तरदायित्व दिया जाय ? किस संस्था की देख-रेख में चिकित्सागृहों, तथा बेकार लोगों को काम देने का भार सौंपा जाय ?

विद्यालयों के विषय में इतना कहा जा सकता है कि उन्हें जो उत्तरदायित्व या सेवाए मिलनी हों, उनका निश्चय शिक्षा के उद्देश्यों को सामने रखकर करना चाहिए।

(५)

आर्थिक-सहायता की स्पर्द्धा

समाज की अन्य संस्थाओं क अनुरूप ही शिक्षा का विकास भी अर्थ पर आधारित है। अर्थ कहाँ से लिया जाय ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। धन, शिक्षा के लिए चार स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है—

१. संघीय सरकार से;
२. राज्य-सरकारों से;
३. स्थानीय समाज से;
४. व्यक्तिगत रूप से ।

संयुक्तराज्य में, शिक्षा का अधिकार तथा उत्तरदायित्व, विधान के अनुसार राज्यों को प्राप्त है। राज्यों ने बहुत से अधिकार स्थानीय सरकारों को दे रखे हैं। किन्तु यह बात सत्य है कि शिक्षा की आवश्यकताओं को स्थानीय समाज तथा राज्य पूरा नहीं कर सकते। ४८ राज्यों में स्वयं ही आर्थिक दृष्टि से बड़ा वैषम्य है।

इसीलिए आरम्भ से ही विधान के दसवें संशोधन के अनुसार संघ-सरकार शिक्षाप्रसार में सहायता करती रही है। और आज तक शिक्षा को प्रयोगात्मक तथा वैज्ञानिक बनाने में, उसने काफी आर्थिक सहायता की है। औद्योगिक शिक्षा आदि की योजनाएँ जो देश-

व्यापी होती हैं संघ-सरकार के हाथ में हैं। इन कार्यों से संघ सरकार का सहयोग शिक्षा में बढ़ रहा है। यद्यपि केन्द्रीकरण के भय के कारण, विरोध की भी कमी नहीं है। अधिकांश लोग यह मानने लगे हैं कि संघीय सहयोग निम्न क्षेत्रों में परम आवश्यक है—

१. विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों के लिए।
२. प्रौढ़ शिक्षा के लिए।
३. प्रशिक्षण-शिक्षा के विकास के लिए।
४. शिक्षा में नए प्रयोगों के लिए।
५. विद्यालयों के भवनों के लिए।

संघ सरकार के बढ़ते सहयोग से अन्य कमियाँ भी उभर कर सामने आगई हैं, यथा—

१. सारे राष्ट्र की एक आधारभूत शिक्षा-योजना हो, ताकि कोई विद्यालय बिल्कुल पिछड़ा न रह सके।
२. स्थानीय शिक्षा-बोर्ड के समान ही राष्ट्रीय शिक्षा-बोर्ड भी होना चाहिए जो राष्ट्र की शिक्षा-योजनाओं को भली प्रकार कार्यान्वित कर सके।

इस प्रकार के राष्ट्रीय बोर्ड की आवश्यकता अवश्य है पर अभी तक कोई ऐसा शिक्षा-बोर्ड स्थापित नहीं हुआ है।

शिक्षा में व्यक्तिगत आर्थिक सहयोग का जहाँ तक प्रश्न है, वह आवश्यक है और उचित भी। संयुक्तराष्ट्र में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्रों में व्यक्तिगत विद्यालय कम हैं, परन्तु उच्च शिक्षा में उनका सहयोग प्रशंसनीय है। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों का तो यह मत है कि उच्च शिक्षा में सरकारी तथा व्यक्तिगत विद्यालय होना अमेरिका की अपनी सम्पत्ति तथा विशेषता है।

(६)

शिक्षक और शिक्षा-नीति

राष्ट्र-विकास के लिए, शिक्षा के नेतृत्व को सफल बनाने के लिए, शिक्षकों का योग्य होना परमावश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के लिए अनेकों ही शिक्षकों की आवश्यकता है। सुयोग्य शिक्षक बड़ी संख्या में प्राप्त हों—यह एक बड़ी समस्या है। इस विषय में निम्न सुझाव दिए गए हैं—

१. सम्मान (Recognition)—शिक्षण सम्मानित उद्यम होना चाहिए। जैसे भारत में प्राचीन काल में 'गुरु' का प्रयोग सम्मानसूचक रहा है।
२. अनुसन्धान (Research)—इस बात पर अनुसंधान किया जाय कि शिक्षक, शिक्षण क्यों छोड़ देते हैं ताकि शिक्षण की दुर्बलता मालूम हो सके।

३. भर्ती (Recruitment)—सुयोग्य शिक्षकों को भर्ती करने के लिए छात्रवृत्ति आदि का उचित प्रबन्ध होना चाहिए।

४. पुनर्गठन (Reorganization)—सेवारत शिक्षकों (In service teachers) को शिक्षा के लिए शिक्षा-योजना का पुनर्गठन होना चाहिए।

५. पारस्परिक सम्बन्ध (Reciprocity)—शिक्षकों को तैयार करने में, महाविद्यालयों, नगरों, राज्यों तथा राष्ट्र में आपसी सम्बन्ध बड़ी सहायता करेंगे।

६. नाम-पंजीकरण (Registration)—इससे शिक्षकों को प्राप्त करने में सुविधा होगी ।

७. पुनःसस्थापन (Reemployment)—देने से विश्राम-प्राप्त शिक्षकों को भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

८. पुनःशिक्षग (Reeducation)—पुनःशिक्षण की बहुत से अध्यापकों को आवश्यकता रहती है, ताकि वह फिर से ताजा हो जावें ।

९. पुनःस्वीकृति (Reconvention)—शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के हिसाब से, शिक्षकों को, जो अधिक होने से अलग कर दिये गए थे, स्वीकार किया जा सकता है।

१०. बनाए रखना (Retention)—शिक्षण को आकर्षक बनाए रखना आवश्यक है।

११. कटौती (Retrenchment)—छोटी कक्षाओं को तोड़कर तथा छोटे-छोटे विद्यालय-नगरों का पुनर्गठन करके, आवश्यकता में कटौती की जा सकती है।

१२. कमी (Reduction)—कक्षा-आकार घटा कर शिक्षकों के कार्य को हल्का कर उन्हें बनाये रखा जा सकता है।

१३. मनोरंजन (Recreation)—मनोरंजनों की आवश्यकता पर बल देकर बहुत से शिक्षकों को सहायता दी जा सकती है । क्योंकि बहुतों के मनोरंजन-साधन होते ही नहीं।

१४. मनबहलाव (Relaxation)—स्वास्थ्य तथा अधिक कार्य करने की क्षमता के लिए मनबहलाव का होना आवश्यक है।

१५. आराम (Rest) ।

१६. निवास (Residence) ।

१७. साधन (Resources)—पढ़ने, पढ़ाने के।

१८. क्रमिक परिवर्तन (Rotation) ।

१९. प्रतिनिधित्व (Representation) ।

२०. सुसम्बन्ध (Repport) ।

२१. विश्राम अवकाश (Retirement) ।

२२. वेतन—आकर्षक हो ।

२३. पुरस्कार (Rewards) ।

२४. पुनस्समर्पण (Rededication)

इसके अतिरिक्त एक आवश्यक प्रश्न यह भी है कि शिक्षण में राजनीति का हाथ होना चाहिए या नहीं ? क्या साम्यवादी शिक्षकों को भी शिक्षा देने को रखा जा सकता है ; देश की प्रवृत्ति यह है कि ऐसे शिक्षकों को शिक्षा में किसी भी दशा में न रखा जाय।

(७)

शिक्षा की योजना—शिक्षा की योजना किस प्रकार की हो ? इस विषय में एक नहीं, कई छोटे-छोटे प्रश्न हमारे सामने आते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्य-क्रम-प्रधान हो, या छात्र-प्रधान ? अनेकों ही तर्क इसके पक्ष तथा प्रतिपक्ष में दिये जाते हैं किन्तु आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा से अधिक प्रगतिशील रहेगी। प्रारम्भिक विद्यालय आज एक कार्य-विद्यालय (Activity School) बन चुका है। विद्यालय का कार्य सीखना ही है। आज अच्छे नागरिक के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह अच्छा ही हो, वरन् वह अच्छा करता भी हो।

विश्वविद्यालय की शिक्षा बुद्धि-प्रधान हो या अनुभवों और प्रयोगों पर आधारित वह निरन्तर विकासमयी हो ? राष्ट्र-निर्माण में उच्च शिक्षा का महत्त्व समझते हुए, निस्संदेह यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि उच्च शिक्षा का पाठ्य-क्रम उपर्युक्त दृष्टिकोणों से निश्चित होता है। शिकागो विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति रॉबर्ट एम्० हचिन्स विश्वविद्यालय की शिक्षा को बुद्धिप्रधान बनाने के पक्ष में हैं। प्लेटो, अरस्तू, लॉक आदि पुराने विद्वान् भी इसी पक्ष में लिये जा सकते हैं। दूसरे पक्ष के समर्थक प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता किल पैट्रिक महोदय हैं। जॉन ड्यूई भी इसी मत के समर्थक हैं।

शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्ति, इस विषय में क्या है? इसके उत्तर में इतना कहना पर्याप्त होगा कि अधिकांश लोग जॉन ड्यूई तथा किल पैट्रिक की ओर हैं और प्रयोगात्मक विकासवादी हैं। परन्तु इस तरह के मत-विरोध, केवल मानसिक विरोध हैं। वह बहुत पहले से चले आ रहे हैं और चलते भी रहेंगे। शिक्षा में दोनों का ही स्थान है। वह बौद्धिक भी है और विकासमयी होने से प्रयोगात्मक भी।

शिक्षा-योजना में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या रंग के अनुसार शिक्षा अलग-अलग हो ? गोरे विद्यार्थी और नीग्रो बालक, क्या अलग-अलग विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजे जाएं ?

यह समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी है। संयुक्तराज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने १९५४ ई० में यह महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया कि रंग-भेद (Seggregation) गैरकानूनी है; किन्तु उससे भी पहिले, संघीय, राज्यीय आदि सरकारों ने तथा विशिष्ट समाजों ने भी इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयत्न किये थे। और इस तरह रंग-भेद को मिटाना आरम्भ हो चुका था।

किन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रंग-भेद को अवैध मानने का अर्थ, यह नहीं कि रंग-भेद समाप्त हो गया। रंग-भेद आज का नहीं, पुराना सामाजिक तथ्य है; उसे हटाने के लिए सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तरीके अधिक उपयुक्त होंगे। ऐसी समस्याएँ विकास (Evolution) के द्वारा बदली जा सकती हैं, क्रान्ति (Revolution) के द्वारा नहीं। यही कारण है कि रंग-भेद अभी भी वर्तमान है। यद्यपि उसे मिटाने के प्रयत्न भी काफी जोरदार हैं। डा० हैन्स ने काले-गोरे की समस्या को जातीय समस्या मानना अनुचित बताया है और इस समस्या को शुद्ध सामाजिक समस्या कहा है।

(८)

हमारे सहायक सिद्धांत

अभी हमने अमेरिकन शिक्षा-प्रणाली के मूल प्रश्नों तथा शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियों का अवलोकन किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि शिक्षा की समस्याएँ अभी काफी हैं। दूसरे, प्रवृत्तियों का भी मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि विद्यालय अपने वैज्ञानिक चिन्तन तथा मार्ग से राष्ट्र के उत्थान में ठोस सहयोग प्रदान कर सकें। वैज्ञानिक चिन्तन तथा मार्ग के लिए कुछ विधायक सिद्धान्तों (Guiding Principles) का नीचे उल्लेख किया जाता है, ताकि राष्ट्रोत्थान की उचित योजना बन सके——

१. शिक्षा का उद्देश्य ऐसी योजना का विकास करना होता है जो आर्थिक कुशलता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति के चरम विकास में सहायक हो। विद्यालय, व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं को तो पूरा नहीं कर सकता, परन्तु उन्हें खोजने में सहायता अवश्य कर सकता है। विद्यालय-अधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे समयानुकूल विद्यालय के विकास, तथा उसके प्रशासन में परिवर्तन के लिए तैयार रहें।
२. स्थानीय आवश्यकताओं से शिक्षा को सदैव परिचित होना चाहिए और इसीलिए स्थानीय समाज की अन्य प्रमुख संस्थाओं से सहयोगात्मक निकट सम्पर्क होना चाहिए।
३. शिक्षा-योजनाएँ सदैव अपने उद्देश्यों तथा समस्याओं को देखकर ही निश्चित होनी चाहिएं।
४. जो भी कार्य किया जा चुका हो उसका मूल्यांकन होना चाहिए।

५. कार्य के लिए योजनाओं को निश्चित करने के लिए निरन्तर अनुसन्धान आवश्यक है ।

६. समान क्षेत्रों का, जो और लोगों तथा संस्थाओं को अनुभव हुए हों, उचित प्रयोग करना चाहिए।

७. इस बात पर सदैव बल देना चाहिए कि शिक्षकवर्ग सुयोग्य हो।

८. आर्थिक सहायता के लिए पर्याप्त अवसर तथा साधन प्राप्त हों।

९. अनुसन्धानों तथा अनुभवों को समाज तक पहुँचाकर, उनका हित करना, कभी नहीं भूलना चाहिए ।

षष्ठ अध्याय

रूपरेखा :—

प्रथम चरण :—अमेरिकी शिक्षा का मूल्यांकन तथा भारतीय शिक्षा पर उसका प्रभाव।

द्वितीय चरण :—भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ।

तृतीय चरण :—उपसंहार।

प्रथम चरण

अमेरिकी शिक्षा का मूल्यांकन तथा भारतीय शिक्षा पर इसका प्रभाव

रूपरेखा :—

अ. अमेरिकी शिक्षा का मूल्यांकन—

१. अ—प्रजातन्त्रीय। इ—सुनागरिक-निर्माण।
आ—अन्तर्राष्ट्रीय। ई—विचार-व्यापार की छूट।

२. अनुभव का सुगठित तथा सुविकसित दर्शन।

३. पठन-पाठन-गणित (3 Rs) के स्थान पर 'जीवनपर्यन्त शिक्षा' (3 Ls)

४. विकेन्द्रीकरण, विभिन्नता, विचार-व्यापार तथा प्रजातन्त्र (4 Ds—Decentralized, Diversity, Discussion, Democratic.) पर आधारित।

५. एक ही वेतन-प्रणाली (Single salary Schedule)

६. सरकारी तथा व्यक्तिगत उच्च शिक्षा।

७. उपसंहार।

आ. भारतीय शिक्षा पर उसका प्रभाव :—

१. अमेरिकी शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय स्वभाव—यूनेस्को-कार्यों में सहयोग।

२. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग —
अ—कृषि।
आ—विद्यार्थियों की शिक्षा।
इ—अध्यापक-प्रशिक्षण।
ई—विद्यालयों का पुनर्गठन।

३. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

(अ)

(१)

वैसे तो आरम्भ में ही हमने अमेरिकन शिक्षा की विशेषताएँ,'मूल तत्त्वों' के नाम से समझाने का प्रयत्न किया, किन्तु वह पुस्तक तथा उसके पठन का आरम्भ था। अधिकतर वस्तुएँ नई सी लगी होंगी। किन्तु इस समय तक, जब सभी वस्तुएँ, एक बार सामने आचुकी हैं, अमेरिकन शिक्षा की विशिष्ट बातों को पुनः संक्षेप में दुहराना लाभदायक ही होगा।

अमेरिका एक प्रजातन्त्र देश है, यहाँ की शिक्षा का आधार प्रजातन्त्र है। अमेरिकन क्रान्ति का आधार 'समानता' का सिद्धान्त था। शिक्षा में वही सिद्धान्त 'अवसर की समानता' के नाम से हमारे सामने है। इनके अतिरिक्त दूसरा सिद्धांत है 'सार्वभौम शिक्षा'। क्योंकि इस तथ्य को सभी मानते हैं कि प्रजातन्त्र के विकास के लिए व्यक्ति का विकास आवश्यक है और व्यक्ति-विकास का सबसे शक्तिशाली तथा स्वाभाविक साधन शिक्षा है।

प्रजातन्त्र का विकास और जीवन इस बात पर आधारित होता है कि उसके नागरिक कैसे हैं ? इसीलिए प्रजातन्त्रीय शिक्षा सुनागरिक बनाने का अनवरत प्रयत्न करती है। सुनागरिकता के चार बड़े सिद्धान्त हैं—

१. आत्म-विकास (Self Realization);

२. उचित मानव-सम्बन्ध;

३. आर्थिक सामर्थ्य (Economic Efficiency);

४. नागरिक उत्तरदायित्व।

किन्तु नागरिकता के सिद्धान्त जो ऊपर लिखे गए हैं, ऐसे व्यक्ति का निर्माण नहीं करते जो राष्ट्रीय चहारदीवारी में बन्द हो। वह अन्तर्राष्ट्रीय नागरिकों का निर्माण करते हैं इसीलिए अमेरिकन शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय भी है। 'रहो और रहने दो' का सिद्धान्त प्रजातन्त्रीय होने से अन्तर्राष्ट्रीय भी है। इसीलिए अमेरिकन सरकार तथा जनता अपने प्रयत्नों द्वारा, स्वतन्त्र रूप में तथा यूनेस्को आदि संस्थाओं द्वारा विश्व-शिक्षा, विश्वबन्धुत्व आदि के लिए दूसरे पिछड़े देशों को खुल कर सहयोग देती है।

अमेरिकन शिक्षा में दो और महत्त्वपूर्ण गुण हैं—सहनशीलता (Tolerance) तथा भिन्न मत रखने का अधिकार। इन दोनों का परिणाम यह है कि विचार-व्यापार (Discussion) शिक्षा का आधार बन गया है। शिक्षा की प्रणालियाँ, नीतियाँ वहाँ लादी नहीं जातीं, विचार-व्यापारों द्वारा निश्चित की जाती हैं।

(२)

शिक्षा ही नहीं, अमेरिका के जन-जीवन का दर्शन उपयोगितावाद (Pragmatism) है। इस मत को, यद्यपि महान विचारक तथा मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने आरम्भ किया था, किन्तु उसे जन-जीवन में उतार देने का सफल तथा अमूल्य श्रेय जॉन ड्यूई को है। डा० हैन्स के अनुसार जॉन ड्यूई का दर्शन मानवतावाद (Humanism) पर आधारित है। और मानवतावादी परम्परा के वही अन्तिम प्रतिनिधि हैं। जॉन ड्यूई का दर्शन, उपयोगितावादी था, मानवतावादी था और प्रयोगवादी था। डा० हैन्स लिखते हैं, "विचार को कार्य के आश्रित करने से, उनका दर्शन उपयोगितावादी है। मानव के अनुभवों की धारा में, सभी मूल्यों को स्थापित करने से वह मानवतावादी है। वैज्ञानिक प्रयोगात्मक विधियों की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने से वह प्रयोगात्मक है।"

अनुभवों के इस सुगठित तथा वैज्ञानिक दर्शन के ही कारण अमेरिका ने, फ्रान्स तथा इंगलैण्ड के प्रतिकूल, सांस्कृतिक परम्पराओं को बिना लिये भी आशातीत उन्नति की है और विश्व के विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपयोगिता को सिद्ध किया है।

(३)

इन सब बातों के कारण संयुक्तराज्य की शिक्षा, तथा उसके पाठ्य-क्रम का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पठन-लेखन तथा गणित (3 Rs Reading, Riting and Rithmetic) का अब चलन नहीं है क्योंकि शिक्षा और साक्षरता का अन्तर अत्यन्त स्पष्ट हो चुका है। प्रजातन्त्र में शिक्षा की आवश्यकता है जो सुनागरिक उत्पन्न करके, व्यक्ति का चरम विकास कर सके, साक्षरता को स्थान नहीं, जो जीवन को आगे बढ़ाने में पंगु हो। शिक्षा गतिशील (Dynemic) है, वह परिवर्तनशील है। और मनुष्य जब से उत्पन्न होता है, सीखना आरम्भ कर देता है और बराबर अन्तिम श्वास तक सीखता रहता है। इसीलिए शिक्षा को, पठन-लेखन तथा गणित के स्थान पर आज 'जीवनपर्यन्त' (Life Long Learning—3 Ls) माना जाता है।

(४)

जहाँ तक संयुक्तराज्य की शिक्षा के संगठन, प्रशासन तथा विकास का प्रश्न है, वहाँ की जनता 'गृह-व्यवस्था' (Home Rule) में अटूट विश्वास रखती है। अपनी चीजों का स्वयं प्रबन्ध करने का दृष्टिकोण पुराना है और अमेरिका के प्रथम निवासियों (Early Settlers) से ही चला आ रहा है। परिणामस्वरूप शिक्षा का प्रबन्ध विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित है। विधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों का है और राज्यों ने बहुत से अपने उत्तरदायित्व, स्थानीय सरकारों तथा जनता को दे रखे हैं। संघ-सरकार, विधान के दसवें संशोधन के अनुसार राज्यों को बहुत सहयोग देती है किन्तु प्रवृत्ति इसी ओर है कि 'केन्द्र का अधिकार हमारे ऊपर कहीं न हो जाय ?'

'गृह-व्यवस्था' होने के कारण शिक्षा का विकास अपनी आवश्यकताओं और साधनों के अनुसार हुआ है। यही कारण है कि एक बड़ी भिन्नता विद्यमान है। शिक्षा के नीति, विधि, संगठन तथा प्रशासन—किसी भी क्षेत्र में, सब राज्यों में क्या किन्हीं दो राज्यों में एकसापन नहीं मिलेगा। इस तरह की भिन्नता प्रजातन्त्री जीवन के सदैव अनुकूल है।

इसके अतिरिक्त प्रजातन्त्र तथा विचार-व्यापार के कारण अमेरिकन शिक्षा को 'चार डी' (4 Ds) वाला कहा जाता है। (Decentralization, Diversity, Discussion, and Demoeracy.)

(५)

राष्ट्र के विकास के लिए अच्छी शिक्षा जिस प्रकार आवश्यक है, अच्छी शिक्षा के लिए उसी प्रकार अच्छे, कुशल और योग्य शिक्षक आवश्यक हैं। अच्छे शिक्षकों को शिक्षा-क्षेत्र में लाने के लिए यह परम आवश्यक है कि शिक्षा-योजना रोचक और आकर्षक हो। इसके अतिरिक्त पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में, कुशल अध्यापकों की महती आवश्यकता है। इसीलिए अध्यापकों के वेतन निश्चित करने की एक ही प्रणाली है। इसके अनुसार वेतन, शिक्षक की योग्यता तथा अनुभव के आधार पर मिलता है, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाए या उच्च महाविद्यालय में। इस प्रणाली की यह सुन्दरता है कि शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र पूर्वप्रारम्भिक तथा प्राथमिक, अच्छे अध्यापकों से हीन नहीं है।

(६)

संयुक्तराज्य की यह प्रथा कि विश्वविद्यालय की शिक्षा—व्यक्तिगत (Private) तथा सरकारी दोनों ही है—अपनी एक विशिष्ट सम्पत्ति है। उच्च शिक्षा में अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक सामग्री अधिक मात्रा के कारण इतनी अधिक कीमती होती है, कि सरकार नहीं जुटा सकती। दूसरे उच्च शिक्षा में जहाँ विचार तथा अनुसन्धान की स्वाधीनता होनी चाहिए वह एक संस्था से शासित तथा चालित विश्वविद्यालयों में नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत उत्साह तथा सहयोग, शिक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्र में इतना अधिक है कि यदि अपने अलग विश्वविद्यालय स्थापित किये जायें, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता—ऐसा करने की उन्हें स्वाधीनता है। इन्हीं सब कारणों से उच्च शिक्षा के दो मूल स्रोत हैं—सरकार तथा व्यक्तिविशेष। और दोनों ही एक साथ रह सकते हैं। यह सहनशीलता (Tolerence) तथा प्रजातन्त्रीय दृष्टिकोण के सुन्दर उदाहरण हैं।

(७)

उपर्युक्त कथन से हमने देखा है कि संयुक्तराज्य की शिक्षा राष्ट्र को ऊपर उठाने वाले प्रमुख साधनों में एक है। शिक्षा को व्यक्ति-प्रधान बनाने में व्यक्ति तथा सरकार का

सहयोग प्रशंसनीय है और यह बात सत्य है कि व्यक्ति के उत्थान में, उसको सुनागरिक बनाने में, जिस प्रजातन्त्रीय वातावरण की अपेक्षा है, वह संयुक्तराज्य में यदि पूरी तरह नहीं तो एक बहुत बड़ी सीमा तक अवश्य उपस्थित है।

(आ)

(१)

भारतीय शिक्षा पर उसका प्रभाव

११ वर्ष पूर्व स्वाधीन हुए भारत को बहुत से कार्य करन हैं किन्तु इन सब में शिक्षा-पुनर्गठन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भारत के शिक्षा-पुनर्निर्माण में अन्य देशों की अपेक्षा संयुक्त-राज्य का सहयोग विशिष्ट रहा है। इस विशिष्ट सहयोग में जहाँ संयुक्तराज्य की शक्ति तथा साधनसम्पन्नता है, वहाँ उसकी शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय स्वभाव—जिसे हम ऊपर कह चुके हैं—भी है। संयुक्तराज्य ने, देश के निर्माण में स्वतन्त्र रूप से तथा यूनेस्को आदि के द्वारा भारत की शिक्षा को—उसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रशंसनीय सहायता प्रदान की है।

(२)

संयुक्तराज्य को जनता तथा सरकार का, भारत की शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग रहा है, उसे हम संक्षिप्त रूप से रखने का प्रयत्न करेंगे।

देश के निर्माण में कृषि तथा टैक्नीकल शिक्षा के स्थान को संयुक्तराज्य ने आज नहीं, १८६२ ई० के मॉरिल नियम को लागू करके ही सीख लिया था। इस नियम से स्थापित भूमि-अनुदान महाविद्यालय अमेरिकन जन-कल्याण में कितने अच्छे सिद्ध हुए, इसे हम देख ही चुके हैं। प्रजातन्त्र के ये विद्यालय समाज-विकास के लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं और कृषि तथा घरेलू अर्थशास्त्र में बड़ा सहयोग दिया है।

संयुक्तराज्य ने कृषि के इन अनुभवों, अनुसंधानों, विशिष्ट परामर्श आदि को अन्य देशों को देने में संकोच नहीं किया। कृषि-अनुसंधान में भारत को सहायता दी है। कृषि-शिक्षकों को विशेष शिक्षा के लिए संयुक्तराज्य में शिक्षा प्राप्त करने को अनेकों छात्र-वृत्तियाँ दीं। देश को इस क्षेत्र में अनेकों विशेषज्ञों का सहयोग प्रदान किया।

विद्यार्थियों की शिक्षा में जितना सहयोग संयुक्तराज्य देता है उतना विश्व का अन्य कोई देश नहीं। सैकड़ों विद्यार्थी भारत से प्रतिवर्ष अध्ययन के लिए, संयुक्तराज्य के धन पर ही वहाँ जाकर अध्ययन करते हैं। यही नहीं, विद्यार्थियों को शिक्षा देने के नये-नये ढंगों के प्रचार के लिए, संयुक्तराज्य से अनेकों विशेषज्ञ आये हुए हैं जो यहाँ के विद्यालयों में नई विधियों द्वारा शिक्षण का सफल प्रयोग कर चुके हैं।

'प्रसार-सेवा' (Extension Service) योजना के अन्तगत बहुत से सेमीनार (Seminar) विभिन्न विषयों तथा शिक्षा-प्रणालियों को लेकर किये गए, जिनसे यहाँ

के विद्यालयों के पुनर्गठन तथा अध्यापकों को मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा नई चेतना देने में अत्यन्त सफलता प्राप्त हुई है।

इस प्रकार धन, पुस्तकों, विशेषज्ञों के सहयोग तथा अन्य वस्तुओं द्वारा संयुक्तराज्य ने हमारी उठती हुई शिक्षा-योजना में बड़ा सहयोग दिया है। और भारत सके लिए सदैव आभारी रहेगा।

द्वितीय चरण

भारतीय शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ

रूपरेखा :—

१. भूमिका——राष्ट्र-निर्माण तथा शिक्षा। हमारी प्रगति।
२. प्रारम्भिक शिक्षा-क्षेत्र और हम।
३. माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र और हम।
४. उच्च शिक्षा-क्षेत्र और हम।
५. प्रशिक्षण-शिक्षा-क्षत्र और हम।
६. कक्षा-प्रवेश तथा विद्यार्थी-चुनावक्षेत्र और हम।
७. अन्य क्षेत्र तथा हम : प्रौढ़-शिक्षा, पितर-शिक्षा, अतिरिक्त बालक-शिक्षा, पूर्वप्रारम्भिक शिक्षा आदि।
८. शिक्षा और अर्थ-सहायता।
९. उपसंहार।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

(१)

डा० कैन्डेल के इस कथन में कि, "राष्ट्रीय कल्याण शिक्षा-सुविधाओं के प्रबन्ध पर आधारित है, क्योंकि वह, व्यक्ति की योग्यताओं की सीमा तक उसे आगे ले जाएगा।" में एक बड़ा सत्य निहित है, और वह यह कि देश के निर्माण में शिक्षा सबसे बड़े तथा समर्थ साधनों में से एक है। इस तथ्य की महत्ता हमारे देश के शिक्षा-कर्णधारों से छिपी नहीं है, क्योंकि शिक्षा के आँकड़े जो आज हैं, स्वाधीनता से पहिले के आँकड़ों से कहीं अधिक बढ़े-चढ़े हैं। वे सब इस बात की ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा-विकास पर देश-विकास आधारित है। हजारों विद्यालयों का खुलना, शिक्षा में नये अनुसन्धानों का होना, यनेस्को आदि के कार्यों में सक्रिय सहयोग, केन्द्र द्वारा टैक्नीकल तथा औद्योगिक शिक्षा के प्रसार में सफल प्रयत्न, शिक्षा के महत्त्व के प्रति हमारी जागरूकता के चिह्न हैं और देश-विकास के लिए यह सौभाग्य की बात है।

(२)

यूरोप में, डा० कैन्डेल के अनुसार, उन्नीसवीं शती में, शिक्षा-शास्त्र के इतिहास के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौम तथा अनिवार्य बनाना आदर्श माना गया है। वही आदर्श १९४७ ई० के बाद, देश के स्वाधीन होने पर हमने माना। देश के नये संविधान ने १४ वर्ष की आयु तक के बालकों को अनिवार्य शिक्षा के लिए घोषणा की।

प्राथमिक विद्यालय, देश में, स्वाधीनता से पहले भी थे। पाठ्यक्रम उनका पुराना था। जीवन की तैयारी पर वह ध्यान न देते थे और ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत कम थी। १९५३ ई० तक, प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री तथा स्वतन्त्र विचारक, प्रो० हुमायूं कबीर के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या २,२०,००० थी और एक करोड़ नव्वे लाख विद्यार्थी, इनमें पढ़ते थे। इन नये विद्यालयों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा-प्रणाली पर आधारित रहा है। और ऐसे विद्यालयों का आरम्भ, देश के भावी स्वास्थ्य का सूचक है। इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की आरम्भ में बड़ी कमी थी। इस कमी को पूरा करने के काफी प्रयत्न किये गए किन्तु प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना है। अभी भी करोड़ों बालक शेष हैं जिन्होंने विद्यालयों के शिक्षकों की आवाज़ नहीं सुनी। योग्य शिक्षक, उचित वेतन, शिक्षकों की अधिक संख्या में आवश्यकता, आदि बड़ी समस्याएँ हैं।

(३)

माध्यमिक शिक्षा को, भारतीय शिक्षा-शृंखला की 'सबसे कमजोर कड़ी' कहा गया है। ११ से १७ साल की आयु वाले बालकों की कुल संख्या का १०% भाग इस शिक्षा को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम उपयोगिता से टूटा केवल विचार-प्रधान है, कार्य-प्रधान

नहीं। अमेरिका, इंगलड, रूस आदि देशों में जहाँ माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण (Comprehensive) शिक्षा के रूप में हमारे सामने आती है और जीवन-यापन के लिए वह पर्याप्त सहायता कर देती है, वहाँ हमारी माध्यमिक शिक्षा ऐसी है कि जिसकी समाप्ति पर विद्यार्थी उतना ही अनिश्चित तथा अपूर्ण रहता है, जैसा कि वह माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करने के समय था।

ऐसी माध्यमिक शिक्षा देश के लिए घातक सिद्ध होगी---इस तथ्य को समझते हुए बहुत से प्रयत्न किये गए हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से अब तक लगभग तीन गुने विद्यालय और खोले गये हैं। पाठ्यक्रम बदला गया है तथा उसमें आवश्यक विषयों का समावेश किया गया है। कृषि, टैक्नीकल तथा औद्योगिक शिक्षा-प्रधान विद्यालयों को खोला गया है। उत्तर बेसिक विद्यालय (Post Basic School) के रूप में एक नया माध्यमिक विद्यालय आरम्भ किया गया है। इन बढ़ते विद्यालयों के बढ़ते हुए योग्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए हैं।

किन्तु इतने बड़े देश के लिए, यह सब कुछ ऐसा ही है जैसे भूखे मनुष्य के लिए रोटी का एक टुकड़ा।

(४)

उच्च शिक्षा देश की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होती है। अनुसन्धानों के बल पर देश का निर्माण तथा संस्कृति का विकास यहीं से आरम्भ होता है। उच्च शिक्षा का इतिहास भारतवर्ष में अद्वितीय रहा है। नालन्दा और तक्षशिला, यहाँ के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय रहे हैं।

विभाजन से पूर्व भारत में २१ विश्वविद्यालय थे। बाद में कुछ पाकिस्तान में चले गये। आजकल इनकी संख्या ३१ के लगभग है। बड़े देश की बड़ी जन-संख्या को ध्यान में रखते हुए ३१ विश्वविद्यालय पर्याप्त नहीं हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस आदि में जन-संख्या के हिसाब से, विश्वविद्यालय का औसत भारत के औसत से कई गुना अधिक है।

विश्वविद्यालय-शिक्षा में देश के सामने बहुत सी बड़ी समस्याएँ हैं। शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, कृषि, विज्ञान तथा टैक्नोलॉजी का विकास हो, शिक्षण का माध्यम, अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी हो या प्रादेशिक भाषा, य सब एसी समस्याएँ हैं जो एकदम नहीं सुलझाई जा सकतीं, किन्तु स्वस्थ समाधान अवश्य चाहती हैं; राजनैतिक पैंतरेबाजी नहीं।

(५)

यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्र-निर्माण में हमें शिक्षा-जगत स अधिक से अधिक योग मिल सके तो हमारे विद्यालय सुन्दर तथा स्वस्थ होने चाहिए। स्वस्थ विद्यालय ईंट और चूने से नहीं बनाये जाते---योग्य शिक्षक उनके प्राण ह। यही कारण ह कि उचित शिक्षा

के लिए उचित प्रशिक्षण-शिक्षा आवश्यक है। देश की प्रशिक्षण-शिक्षा ने प्रगति अवश्य की है, किन्तु अभी यह नहीं कहा जा सकता कि हम इतनी दूर चले आए हैं। आजकल प्रशिक्षण प्राथमिक, तथा माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्रों में है। किन्तु प्रशिक्षण इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र बड़े महत्त्व के हैं किन्तु, पूर्वप्राथमिक, प्रौढ़, उच्च पितर-शिक्षा तथा असाधारण बालकों की शिक्षा के क्षेत्र कुछ कम महत्त्व के नहीं हैं।

(६)

संयुक्तराज्य, रूस, इंगलैण्ड तथा अन्य देशों में, 'पाठ्यक्रम, बालक के लिए' माना जाता है। बालक की रुझान, रुचि, तथा योग्यता के अनुसार ही उसे विषय दिये जाने का क्रम है। परिणाम यह होता है कि बालक की अविकसित योग्यताओं का पूरा विकास होने की सम्भावना रहती है।

बालक की रुझान, रुचि तथा योग्यता का मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से पता लगाया जाता है। कक्षा के लिए विद्यार्थी-चुनाव एक बड़ी आवश्यकता है। डा० कैन्डेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक—Studies in Comparative Education—के उपसंहार में इस समस्या का हवाला दिया है और उनका कथन है कि यह समस्या अधिकांश देशों में अभी तक अछूती ही है। बहुत कुछ करने को शेष है। भारत के विषय में भी वही कहा जा सकता है कि जो योरप के अधिकांश देशों के विषय में; यद्यपि उन देशों में इस दिशा में, थोड़ा-बहुत अवश्य हुआ है। स विषय में यह आवश्यक है, कि देश के प्रत्येक नगर में, मनोविज्ञान तथा अधिनयन ब्यूरो (Guidance Bureau) खोले जाएँ जो विद्यालयों के विद्यार्थियों को, उनके विषय-चनाव में तथा औद्योगिक चुनाव में उचित सहायता कर सकें।

(७)

प्रौढ़-शिक्षा में भी देश ने काफी प्रगति की है। पठन और लेखन को शिक्षा साक्षरता के लिए पहिले दी जाती थी किन्तु इससे जीवन में अधिक सहायता नहीं मिल सकती थी। प्रौढ़-शिक्षा का यह पुराना पाठ्य-क्रम आज बदल चुका है। सामाजिक शिक्षा के नाम से आज उसका पाठ्यक्रम प्रगतिशील तथा उपयोगी है। इस पाठ्यक्रम में, पठन-लेखन के अतिरिक्त, स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान, आर्थिक उत्थान के लिए शिक्षा, नागरिक तथा नागरिकता, शिक्षा, मनोरंजन के क्षत्र में शिक्षा भी सम्मिलित है। इस योजना से १९४७ से १९५४ ई० तक एक करोड़ लोगों को साक्षर किया गया है।

फिर भी पूर्व प्राथमिक, असाधारण बालकों (Exceptional Children) की शिक्षा, पितर-शिक्षा (Parental) के क्षेत्र अभी बाकी हैं। समाज के स्वास्थ्य में इन क्षेत्रों का बड़ा हाथ है, किन्तु इन क्षेत्रों में हमारी प्रगति नहीं के बराबर रही है। आशा अवश्य है कि ` क्षेत्र अछूते नहीं रहेंगे।

(८)

शिक्षा-योजनाओं की सफलताएँ अर्थ-सहायता पर उसी तरह निर्भर रहती हैं जैसे जल पर पौधे का स्वास्थ्य। आर्थिक सहायता के साधन, व्यक्ति और सरकार, दोनों ही हैं; किन्तु देश-विकास के साथ शिक्षा की आवश्यकताएँ भी बढ़ती जाती हैं, हमारे देश में आर्थिक सहायता उतनी तेजी से नहीं बढ़ी।

१९४६-४७ में शिक्षा पर व्यय ४५.१ करोड़ रु०।

१९५२-५३ में शिक्षा पर व्यय १३५.० करोड़ रु०।

१९५३-५४ में शिक्षा पर व्यय १५०.० करोड़ रु०।

देश की शिक्षा-आवश्यकताओं के विकास के साथ व्यय बढ़ता रहा, सरकार की सहायता लगभग तिगुनी बढ़ गई किन्तु अभी इस तरह की आर्थिक सहायता अपर्याप्त ही है। अनुमानतः लगभग ४०० करोड़ रुपयों का शिक्षा-व्यय हमारी प्रगति के लिए पर्याप्त होगा।

इस प्रकार उपर्युक्त समस्याओं को देखकर यह अनुमान लगाना कि हमारी शिक्षा-प्रगति असन्तोषजनक है, सर्वथा अनुचित है। इन समस्याओं की सीमा हमारी मंजिल है जहाँ हमें पहुँचना है, हम चल चुके हैं, गति रुकेगी नहीं, मन्द नहीं पड़ेगी, हम उसे तेज करने का प्रयत्न करेंगे और कम से कम समय में वहाँ तक पहुँच कर रहेंगे।

तृतीय चरण

उपसंहार

रूपरेखा :—

१. तुलनात्मक शिक्षा का दृष्टिकोण।

२. हमारा उद्देश्य।

तुलनात्मक शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि, इस विषय के अन्तर्गत हम विभिन्न देशों की शिक्षा-प्रणालियों का अध्ययन और वर्णन करें और यह समझ लें कि कार्य पूरा हो गया। इस तरह के दृष्टिकोण तुलनात्मक शिक्षा-इतिहास के वर्णनात्मक काल में अवश्य थे, किन्तु, वे सब अवैज्ञानिक थे। अमेरिकन शिक्षा-प्रणाली का हम वर्णन कर आए तो क्या हमारा कार्य पूरा हो गया ? क्या तुलनात्मक शिक्षा के लिए यह पर्याप्त है ? बिल्कुल नहीं। प्रश्न है कि क्यों हम तुलनात्मक शिक्षा का अध्ययन करते हैं ?

यह बात कभी न भूलनी चाहिए कि शिक्षा एक जीवित वस्तु है। राष्ट्र की संस्कृति में छिपी शक्तियाँ, इस जीवित वस्तु के मूल्य और उपयोगिता को निर्धारित करती हैं। डा० कैन्डेल का उपर्युक्त निष्कर्ष एक वैज्ञानिक सत्य है।

शिक्षाध्ययन-विधियों की प्रवृत्तियाँ, पाठ्य-क्रम निर्धारित करने के ढंग, शिक्षा के एक सर्वमान्य दर्शन की ओर संकेत करते हैं, यद्यपि समस्याओं के निदान देशों के अलग-अलग हैं। तुलनात्मक शिक्षा का महत्त्व इस बात में नहीं है कि दुनिया के अन्य देश किस प्रकार रहते तथा सोचते हैं, बल्कि उन शक्तियों और कारणों के ज्ञान के विकास में है जो, देश के कल्याण के लिए, प्रत्येक देश को, एक विशिष्ट रूप देकर, शिक्षा के मूल्यांकन में सहायता करते हैं।

अमेरिकन शिक्षा-प्रणाली का एक स्वरूप उपस्थित करने में हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि हम यह जानें कि उनकी शिक्षा-प्रणाली कैसी है ? वहाँ कितने विश्वविद्यालय तथा भूमि-अनुदान विद्यालय हैं ?; बल्कि इस बात में है कि अमेरिकन राष्ट्र ने किस भाँति देश-निर्माण का उत्तरदायित्व विद्यालयों को सौंपा और अपने विभिन्न शिक्षा-क्षेत्रों में समस्याएँ हटाते हुए, उन विद्यालयों ने कैसे और कितना सहयोग प्रदान किया।

अमेरिका में, या इंगलैण्ड में शिक्षा-क्षेत्र में जो समस्याएँ रही हैं, वे प्रायः प्रत्येक देश की समस्याएँ रही हैं। उन्हें हल करने की उपयुक्त विधि कौन-सी है ? यह विचारणीय बात है।

प्रथम अध्याय में ही हमने यह संकेत किया है कि समस्याओं को हल करने के कई मार्ग हैं यथा—

१. औरों की नकल करके।

२. औरों की ओर से आँख बन्द करके, अपने आप ही।

३. उपयोगिता के आधार पर प्रयोगों द्वारा निश्चित करके।

अपनी शिक्षा-प्रणाली भारत पर लाद कर, उसे ही समर्थ समझने की, अंग्रेजों की यह भूल थी। शिक्षा-प्रणालियाँ लादी नहीं जातीं। डा० कैन्डेल नकल या लादने के बिल्कुल

विरुद्ध हैं। उसी तरह औरों की ओर से आँख बन्द करके आज के वैज्ञानिक युग में, विकास की सोचना, बालकों की कल्पना है।

तीसरी विधि ही उपयुक्त है। हम नकल के लिए और देशों को नकल न करें, और उनकी कोई भी वस्तु अपनाने से पहिले उसे प्रयोग में लाकर देखें कि वह हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि दुनिया के प्रमुख देशों की शिक्षा-प्रणालियों के बारे में हम अधिक से अधिक जानें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें।

सप्तम अध्याय

रूपरेखा :—

प्रथम चरण :—परिशिष्ट ।

द्वितीय चरण :—पुस्तक-सूची ।

प्रथम चरण

परिशिष्ठ

रूपरेखा :—

१. अमेरिकन जन-शिक्षा-सोपान ।

२. संयुक्तराज्य के शिक्षा-कमिश्नर ।

३. अमेरिका के राज्य तथा उनके भूमि-अनदान महाविद्यालय तथा विश्व-विद्यालय ।

४. भारतवर्ष के राज्य ।

५. भारतवर्ष का केन्द्रीय शिक्षा-संगठन ।

लेखक : प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान

अमेरिकन जनशिक्षा-सोपान :—

		आयु	कक्षा	सोपान	
जीवन पर्यंत शिक्षा		२७			
		२६			
		२५	पंचम वर्ष		
		२४	चतुर्थ वर्ष	ग्रेजुएट विद्यालय	उच्च शिक्षा
		२३	तृतीय वर्ष		
		२२	द्वितीय वर्ष		
		२१	प्रथम वर्ष	सीनियर कॉलेज	
	(अनिवार्य शिक्षा)	२०	चौदहवाँ ग्रेड		
		१९	तेरहवाँ ग्रेड	जूनियर कॉलेज	
		१८	बारहवाँ ग्रेड		
		१७	ग्यारहवाँ ग्रेड		
		१६	दसवाँ ग्रेड	सीनियर हाई०	माध्यमिक शिक्षा
		१५	नवाँ ग्रेड		
		१४	आठवाँ ग्रेड		
	(ऐच्छिक शिक्षा)	१३	सातवाँ ग्रेड	जूनियर हाई०	
		१२	छठा ग्रेड		
		११	पाँचवाँ ग्रेड		
		१०	चौथा ग्रेड	माध्यमिक	
		९	तीसरा ग्रेड		प्राथमिक शिक्षा
		८	दूसरा ग्रेड		
		७	पहला ग्रेड	प्राथमिक	
		६	नर्सरी किंडरगार्टन या घर		
		५			
		४		पूर्वप्राथमिक	
		३	नर्सरी किंडरगार्टन या घर		पूर्वप्राथमिक शिक्षा
		२			
		१	घर	घर	
			पूर्वोत्पत्ति सुरक्षा		

(२)

संयुक्तराज्य के शिक्षा-कमिश्नर

क्रम	शिक्षा-कमिश्नर	तिथि	अवधि (वर्षों में)
१	हेनरी बर्नार्ड	१८६७-१८७०	३
२	जान ईटन	१८७०-१८८६	१६
३	ऐन० ऐच० आर० डॉसन	१८८६-१८८९	३
४	विलियम टी० हैरिस	१८८९-१९०६	१७
५	ऐल्मर ई० ब्राउन	१९०६-१९११	५
६	फाइलॅन्डर पी. क्लॅक्सटन	१९११-१९२१	१०
७	जॉन जे० टिगर्ट	१९२१-१९२८	७
८	विलियम जे० कूपर	१९२९-१९३३	४·५
९	जार्ज ऐफ़० ज़ूक	१९३३-१९३४	१
१०	जॉन डब्ल्यू० स्टुडीबेकर	१९३४-१९४९	१५
११	अर्ल जे० मकग्राथ	१९४९-१९५३	४
१२	ली ऐम्० थर्स्टन	१९५३-१९५३	·२५
१३	सैमुअल ऐम० ब्राउनॅल	१९५३-	

(३)

अमेरिका के राज्य तथा उनके भूमि अनदान महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयः--

राज्यों की संख्या—४८ : आश्रित उपनिवेष--३

भूमि-अनुदान महाविद्यालय---६९

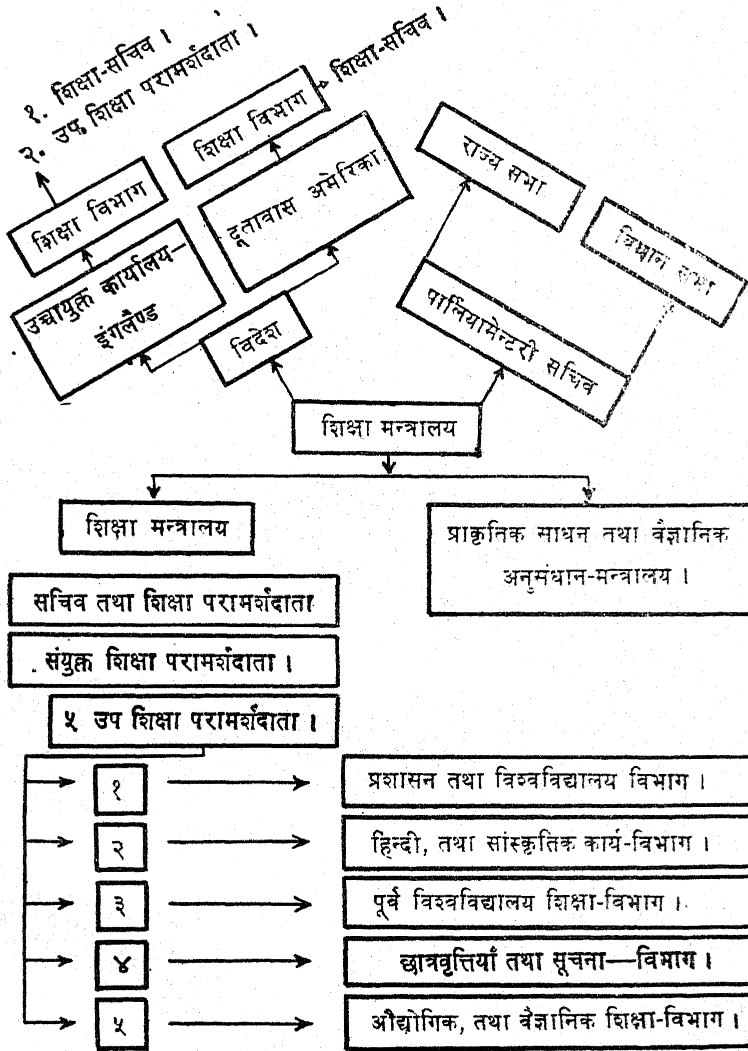
क्रम संख्या	राज्य	म.वि. संख्या		क्रम संख्या	राज्य	म.वि. संख्या
१	अलबामा	२		२७	न्यू हैम्पशायर	१
२	अरोजोना	१		२८	न्यूजर्सी	१
३	अर्कन्सास	२		२९	न्यू मैक्सीको	१
४	कैलीफोर्निया	१		३०	न्यूयॉर्क	१
५	कॉलोरॅडो	१		३१	नॉर्थ करोलिना	२
६	कनैक्टीकट	१		३२	नॉर्थ डकोटा	१
७	डलावर	२		३३	ओहियो	१
८	फ्लोरिडा	२		३४	ऑक्लाहोमा	२
९	जॉर्जिया	२		३५	ऑरेगॉन	१
१०	इडाहो	१		३६	पैन्सिलवानिया	१
११	इलीनॉयस	१		३७	रोड आइलैण्ड	१
१२	इन्डियाना	१		३८	साउथ करोलिना	२
१३	आयोवा	१		३९	साउथ डकोटा	१
१४	कन्सास	१		४०	टैनीसी	२
१५	कैन्टुकी	२		४१	टैक्सास	२
१६	लुसियाना	२		४२	यूटाह	१
१७	मॉन	१		४३	वर्मोन्ट	१
१८	मेरीलण्ड	२		४४	वर्जीनिया	२
१९	मैसाचुसेट्स	२		४५	वाशिंगटन	१
२०	मिशीगन	१		४६	वेस्ट वर्जीनिया	२
२१	मिनेसोटा	१		४७	विस्कॉन्सिन	१
२२	मिसीसीपी	२		४८	व्योमिंग	१
२३	मिसौरी	२	आश्रित उपनिवेश	१	अलास्का	१
२४	मॉन्टाना	१	आश्रित उपनिवेश	२	हवाई	१
२५	नॅब्रास्का	१	आश्रित उपनिवेश	३	प्यूर्टो रिको	१
२६	नेवादा	१				
					योग	६९

(४)

भारतवर्ष के राज्य : उनकी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल

क्रम	राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमीलों में)	जनसंख्या (लाखों में)
१	आन्ध्र	१,१०,२५०	३२·२
२	आसाम	८४,९२४	९·०
३	बिहार	६७,८३०	३८·९३
४	बम्बई	१,८८,२४०	४७·८
५	जम्मू तथा काश्मीर	९२,७८०	४·४
६	केरल	१४,९८०	१३·६
७	मध्यप्रदेश	१,७१,२००	२६·१
८	मद्रास	५०,१७०	३०·०
९	मैसूर	७२,७३०	१९·०
१०	उड़ीसा	६०,१४०	१४·६
११	पंजाब	४६,६१६	१६·०
१२	राजस्थान	१,३२,३००	१६·०
१३	उत्तरप्रदेश	१,१३,४१०	६३·२
१४	पश्चिमी बंगाल	३३,२७९	२६·१६

भारतवर्ष का केन्द्रीय शिक्षा-संगठन :—



द्वितीय चरण

पुस्तक-सूची

1. *Alexander and Taylor* :
Secondary Education Seventh Printing, 1956
Rinehart & Company Inc. Newyork.

2. *Brubacher, J. S.* :
A History of the Problems of Education.
Mc Graw Hill Book Company 1947.

3. *Conant, J. B.* :
Education and Liberty.
The New American Library, Newyork, 1952.

4. *Hutchins, R. M.* :
The Higher Learning in America.
Tale University Press, New Haven 1952.

5. *Henry, J. Otto* :
Elementary School Organization and Administration
3rd Edition.
Appleton-Century-Crofts Inc. Newyork, 1954.

6. *The Hindustan Times Weekly 7th Aug.* 1955 :
Article on Adult Education.

7. *The Hindustan Times daily.*
15th June 1958 : Article on—Examination in U.S.A.

8. *Jacks, M. L.* :
Total Education.
Kegan Paul, French, Trubner & Co. Ltd. London 1946.

9. *Kenneth, Richmond, K.* :
Education in U.S.A.
Alvin Redman Ltd. London 1956.

10. *Kempfer, Homer* :
Selected Approaches to Adult Education Bulletin No. 16. 1950.
Federal Security Agency. Office of Education U.S.A.

11. *Kandel, I. L.* :
The New Erain Education
Houghton Mifflin Company
The Riverside Press, Cambridge, U.S.A. 1955.

12. *Kandel, I. L.* :
Studies in Comparative Education
George G. Hanper & Co. London 1933.

13. *Kabir Humayun Prof.* :
Education in New India
George Allen & Uuwin, London 1955.

14. *Lee, G. C.* :
An Introduction to Education in Modern America.
Henry Holt & Co. New York, 1954.

15. *Lester Smiths, W. O.* :
Education in Great Britain, Second Ed.
Geoffrey Cumberlege, Oxford University Press 1956.

16. *Monroe, Walter S.* : *(Editor)*
Encyclopaedia of Educational Research. Revised Edition.
The Mc Millan Co. New York. 1952.

17. *Nelson B. Henry (Editor)* :
The Education of Exceptional Children
Fourtyninth Year Book of the National Society for the Study of Education.
The University of Chicago Press, Chicago 37 Illinoes 1953.

18. *Nelson B. Henry* (Editor) :
American Education in the Post War Period. Part II. Structural Reorganization.
Forty Fourth Year Book of the National Society for the Study of Education.
The University of Chicago Press, Chicago 37. Illinois 1948.

19. *Nicholars, Hans* :
Comparative Education
Routledge and Kegan Paul Ltd. London 1949.

20. *Pedley Robin* :
Comprehensive Education.
Victor Gollancz Ltd. 1956.

21. *Sadler Michael Sir & Others* :
Essays on Examinations.
Mc Millan and Company Ltd. London 1936.

22. *Smith and Taylor* :
Appraising and Recording Students Progress.
Harper and Brothers
New York & London 1942.

23. *Tocqueville, Alexis de* :
Democracy in America
(Translated by Henry Reeve)
Oxford University Press
Geoffrey Cumberlege, London 1946.

24. *Unesco Publication* 1952 :
International Directory of Adult Education
Printed in England.

25. *Young, Chris A. de* :
Introduction to American Public Education 3rd. Edition.
Mc Graw Hill Book Co. Inc.
New York. Toronto. London 1955.

26. *U.S.I.S.* (*Publication*) :
An outline of American History 1952.

27. *U.S.I.S.* (*Publication*) :
U.S.A—Its Geography and Growth.

28. *A Committee of the Country Women's Council of the U.S.A.*
The United States of America
Its People and Its Homes, 4th Edition 1950.